

वाषिक-रिपोर्ट
1983-84

वार्षिक रिपोर्ट

1983-84



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH
AND TRAINING

दिसंबर 1984
अप्रहायण 1906

P.D. 1T-RP. RNB

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1984

प्रकाशन विभाग में, श्री सी० रामचंद्रन, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा स्वतंत्र भारत
प्रेस, कूचा बुलाकी बेगम, एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली 110006 द्वारा मुद्रित।

कृतज्ञताज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् मार्गदर्शन के लिए अपनी अध्यक्ष श्रीमती शीला कौल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार तथा उपाध्यक्ष श्री पी० के० थुंगन, उप शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद् के कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने और इसकी मदद करने के लिए परिषद् प्रबंध समिति के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। परिषद् उन विशेषज्ञ विद्वानों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करती है जिन्होंने परिषद् की विभिन्न बैठकों तथा सभा समितियों को अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है और इसकी अन्य कई तरह से मदद की है। राज्य शिक्षा विभागों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों सहित उन सभी संस्थाओं और संस्थानों के हम आभारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की तमाम गतिविधियों को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है। परिषद् को 'यूनेस्को', 'यूनीसेफ', 'यू० एन० डी० पी०' तथा 'ब्रिटिश काउंसिल' द्वारा दी गई सहायता के लिए परिषद् उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद् अपने कर्मचारियों और सदस्यों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए कार्य का प्रशंसापूर्वक उल्लेख करती है। इन लोगों के सहयोग और लगन के बिना परिषद् के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया जा सकता था। परिषद् हजारों अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों, सामान्यजन के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 1983-84 के दौरान परिषद् के प्रकाशनों के विषय में इसकी विभिन्न शाखाओं को पत्र लिख कर अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया है। ये पत्र परिषद् के लिए बेहतर निष्पादन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं।

विषय-सूची

कृतज्ञताज्ञापन

v

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् : भूमिका एवं संरचना	1
2. वर्ष के उल्लेखनीय कार्य	11
3. आरंभिक बचपन की शिक्षा	17
4. प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण	25
5. वंचित वर्ग की शिक्षा	45
6. पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और सहायक पुस्तकें	52
7. शिक्षा और काम	74
8. अध्यापकों व अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण	80
9. शैक्षिक प्रौद्योगिकी	130
10. जनसंख्या शिक्षा	147
11. शैक्षिक मूल्यांकन	154
12. सर्वेक्षण, आंकड़ा संसाधन और प्रलेखन	162
13. अनुसंधान और नवाचार	170
14. प्रतिभा की खोज	192
15. विस्तार और राज्यों के साथ सहयोग-कार्य	198
16. अंतर्राष्ट्रीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध	203
17. प्रकाशन	212
18. प्रशासन, वित्त और कल्याणकारी गतिविधियाँ	229

परिशिष्ट

(क) व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सहायता देने की योजना	249
(ख) राज्यों में परिषद् के क्षेत्र-सलाहकारों के पते	256
(ग) समितियों की संरचना	259
(घ) समितियों द्वारा 1983-84 के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय	283

1

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् : भूमिका एवं संरचना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अ० और प्र० प०) की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी। संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860) के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है और शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के शैक्षणिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है।

भूमिका और कार्य-व्यापार

स्कूल स्तर की शिक्षा में अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय काफ़ी हद तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) की विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाता है। परिषद् का वित्त पोषण पूर्णतः सरकार करती है।

संस्था की विवरणिका के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के उद्देश्य हैं—शिक्षा, विशेषकर स्कूल स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में सलाह तथा सहायता प्रदान करना।

कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिषद् निम्नलिखित कार्यक्रम और गतिविधियाँ चलाती है—

- (क) स्कूल स्तर की शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान करती है अथवा करवाने के लिए सहायता देती है, उसे बढ़ावा देती है और उनमें समन्वय करती है।
- (ख) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेषकर उच्च स्तर के प्रशिक्षण आयोजित करती है।
- (ग) शैक्षिक पुनर्रचना में लगे हुए संस्थानों, संगठनों और माध्यमों के लिए विस्तार सेवाओं का आयोजन करती है।
- (घ) मुधरी हुई शैक्षिक विधियों, अभ्यासों और अभिनव परिवर्तनों को विकसित करती है और उन पर प्रयोग करती है।
- (ङ) शैक्षिक जानकारी को एकत्र करती है, उन्हें सम्पादित करती है और फिर उन्हें प्रचारित-प्रसारित करती है।
- (च) स्कूल-शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए बने कार्यक्रमों को विकसित करने अथवा लागू करने में राज्यों एवं राज्य-स्तर के संस्थानों, संगठनों और माध्यमों की सहायता करती है।
- (छ) यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करती है।
- (ज) अन्य देशों के शैक्षिक कमियों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करती है। और
- (झ) अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के शैक्षणिक सचिवालय के रूप में कार्य करती है।

अनुसंधान

स्कूल शिक्षा में अनुसंधान की सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था होने के नाते, रा० शै० अ० और प्र० प० की अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं—यथा शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध की व्यवस्था एवं पोषण करना और इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभाग, चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय और शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र पाठ्यक्रम, शिक्षण-सामग्री, शिशु विकास, शैक्षिक मनोविज्ञान, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण-साधन, अध्यापक-शिक्षा जैसे शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रम अपने हाथ में लेते रहते हैं।

व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता और शैक्षणिक अन्योन्यक्रिया प्रदान कर रा० शै० अ० और प्र० प० अनुसंधान को बढ़ावा देती है। पीएच० डी० के शोध प्रबंधों के प्रकाशन के लिए भी शोधार्थियों की सहायता की जाती है। परिषद् वरिष्ठ और कनिष्ठ फेलोशिप प्रदान करती है ताकि शैक्षिक समस्याएँ ढूँढ़ी जा सकें और निपुण अनुसंधान कर्मियों का दल बनाया जा सके। देश में शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित आधार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० समय-समय पर शैक्षिक सर्वेक्षण भी कराती है। आधार सामग्री के भंडारण, पुनःप्राप्ति और प्रक्रियन के लिए इसके पास कंप्यूटर टर्मिनल है। अंतर-देशीय शोध परियोजनाओं में यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग भी प्रदान करती है।

विकास

स्कूल शिक्षा में विकासात्मक गतिविधियाँ परिषद् के कार्य का प्रमुख भाग हैं। परिषद् समाज और स्कूल-शिक्षा की परिवर्तनशील पद्धति की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के विकास और शिक्षण-सामग्री के निर्माण का कार्य हाथ में लेती है। रा० शै० अ० और प्र० प० उत्कृष्ट शिक्षण-सामग्री, शिक्षण-साधनों, विज्ञान किटों, प्रयोगशाला उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों, वीडियो कैसेटों, रेडियो आलेखों आदि का निर्माण करती है और शिक्षण तथा मूल्यांकन की सुधरी हुई पद्धतियों पर कार्य करती है। अनौपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में, जहाँ अभी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है, परिषद् पाठ्यक्रमों और शिक्षण-सामग्रियों के निर्माण का कार्य करती है। यह परिषद् के विकासात्मक कार्यक्रमों में आता है। इस दिशा में अन्य उल्लेखनीय कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण

पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक स्तरों पर सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी परिषद् के महत्वपूर्ण कार्यों में है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा, मार्ग-दर्शन और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में नव परिवर्तन वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उनमें इस प्रकार के नवाचारीय कार्यक्रम शामिल हैं—विषय तत्त्व और शिक्षण विधि का एकीकरण, वास्तविक कक्षा में अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिए दीर्घकालीन इंटर्नशिप, सामुदायिक कार्यों में छात्रों और शैक्षिक कर्मचारियों की प्रतिभागिता। राज्यों एवं राज्य स्तर के संस्थानों के मुख्य कार्मिकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाता है। अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के शैक्षणिक सचिवालय के रूप में काम करते हुए एन० सी० ई० आर० टी० अध्यापक-शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए और सतत शिक्षा के केंद्रों के लिए पाठ्यचर्याओं के सुधार जैसे कार्यों में लगी हुई है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रसार

शिक्षा के प्रसार के लिए परिषद् के पास एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें अनेक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विविध विभाग, चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एवं राज्यों में कार्य कर रहे क्षेत्र कार्यालय लगे हुए हैं। राज्यों के विभिन्न संस्थानों के साथ एन० सी० ई० आर० टी० सीधे काम करती है। साथ ही वह महाविद्यालयों और स्कूलों में स्थापित अध्यापक प्रशिक्षण के प्रसार सेवा विभागों एवं केन्द्रों में गहन कार्य करती है ताकि शिक्षकों, पर्यवेक्षकों, प्रशासकों, प्रश्नपत्र निर्माताओं, पाठ्यपुस्तक लेखकों आदि को सहायता प्रदान कर सके। इसके लिए सभाएँ, सम्मेलन, कार्यगोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएँ आदि नियमित रूप से की जाती हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इन कार्यक्रमों को देहात में और पिछड़े इलाकों में किया जाए ताकि उन कार्मिकों तक पहुँचा जा सके जिन्हें इनकी जरूरत है और जहाँ विशिष्ट समस्याएँ अपना जाल डाले हुए हैं। समाज के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों और अपंगों की शिक्षा के लिए परिषद् के पास विशेष कार्यक्रम हैं। परिषद् के प्रसार कार्यक्रम सारे देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए काम कर रहे हैं।

प्रकाशन एवं विकीर्णन

रा० शै० अ० और प्र० प० स्कूल शिक्षा की सभी शाखाओं से संबद्ध विषयों पर अपने प्रकाशन निकालती है। इनमें कक्षा I से XII तक के लिए सभी स्कूल विषयों की पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शोध रिपोर्ट आदि शामिल हैं। देश में स्कूल-शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में अपने समग्र प्रयास के एक अंश के रूप में राष्ट्रीय परिषद् की पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास-पुस्तिकाएँ और अध्यापक-संदर्शिकाएँ अपने किस्म की आदर्श-पुस्तकें होती हैं। परिषद् के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे शोध और विकास के कार्यों के फलस्वरूप ही इन पुस्तकों का आविर्भाव होता है। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित परिषद् की पाठ्यपुस्तकें और सम्बद्ध सामग्री देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अधिसंख्य स्कूलों में इस्तेमाल होती हैं। सभी राज्यों को यह सुविधा दी गई है कि वे इन पाठ्यपुस्तकों को चाहे ज्यों का त्यों लगा लें या अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इन्हें अपने लिए अनुकूलित कर लें।

शैक्षिक जानकारी के विकीर्णन के लिए परिषद् चार पत्रिकाएँ प्रकाशित करती है। 'प्राइमरी शिक्षक' और 'प्राइमरी टीचर' प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सार्थक और प्रासंगिक सामग्री प्रकाशित करती हैं। इस सामग्री को सीधे कक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 'स्कूल साइंस' खुले मंच के रूप में सामने आती है। 'जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन' एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिस पर सामयिक रूप से प्रचलित शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करके शिक्षा में मौलिक विवेचना को बढ़ावा दिया जा सके। 'इंडियन एजुकेशनल रिव्यू' के माध्यम से एक ऐसे मंच का निर्माण किया गया है जहाँ शैक्षिक अनुसंधान और नव परिवर्तन के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुभवों का आदान-प्रदान होता है। 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' हिन्दी में प्रकाशित होने वाली शैक्षिक समस्याओं और जानकारी की विचारपूर्ण पत्रिका है। 'एन० सी० ई०

आर० टी० न्यूज लेटर' परिषद् की प्रमुख पत्रिका है जो हर महीने प्रकाशित होती है। इनके अलावा सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अपनी-अपनी पत्रिकाएँ प्रकाशित करते हैं।

मूल्यांकन एवं आदान-प्रदान कार्यक्रम

पाठ्यपुस्तकों और सम्बद्ध सामग्री का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के लिए निकष, उपकरण और तरीके बनाए जा चुके हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से मार्गदर्शी रेखाएँ और प्रणालियाँ निश्चित की जा चुकी हैं। जिन स्कूलों में ये पाठ्यपुस्तकें चलती हैं वहाँ से अनुभव जन्य सुझाव मिलते रहते हैं, जिनसे पाठ्यपुस्तकों का संशोधन-परिवर्धन होता रहता है।

प्रतिभा की खोज

हर साल राष्ट्रीय परिषद् 750 प्रतिभा-छात्रवृत्तियाँ देने के लिए (इनमें से 70 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए होती हैं), कक्षा X, XI व XII में पढ़ने वाले छात्रों की भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं में परीक्षाएँ लेती है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र विज्ञान, गणित अथवा सामाजिक विज्ञान में पीएच० डी० तक की पढ़ाई या अभियांत्रिकी अथवा चिकित्साशास्त्र की व्यावसायिक पढ़ाई कर सकते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के निमित्त राष्ट्रीय परिषद् को यूनेस्को, यूनिसेफ़, यू० एन० डी० पी और यू० एन० एफ० पी० ए० जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मिलती रहती है। इन संस्थाओं द्वारा माँगे जाने पर, परिषद् अपने शैक्षणिक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय सभाओं, परिचर्चाओं, कार्यगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजती है। इसी प्रकार विदेशियों के लिए भारत में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी परिषद् करती है।

शैक्षिक नवाचार और विकास के एशियाई केन्द्र के लिए राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में भी परिषद् कार्य करती है। स्कूल-शिक्षा के लिए विभिन्न देशों के साथ भारत सरकार जो द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के समझौते करती है उनके कार्यान्वयन के लिए भी परिषद् मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करती है। परिषद् अन्य देशों के साथ शैक्षिक सामग्री का विनिमय करती है।

संरचना और प्रशासन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की नीति निर्धारण की निकाय सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं और सभी राज्यों व संघ क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री उसके सदस्य हैं। इसके अलावा उसके अन्य सदस्य हैं—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति (हर क्षेत्र से एक-एक), कार्यकारी समिति के सभी सदस्य (जो ऊपर नहीं गिनाए गए हैं), और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद अन्य व्यक्ति जिनकी संख्या बारह से अधिक नहीं होगी और जिनमें से कम से कम चार को स्कूल शिक्षक होना चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की मुख्य शासी निकाय परिषद् की कार्यकारी समिति है। कार्यकारी समिति में निम्नलिखित आते हैं—परिषद् के अध्यक्ष (पदेन) के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (पदेन उप-अध्यक्ष), शिक्षा मंत्रालय के उपमन्त्री, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, परिषद् के निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, स्कूल-शिक्षा में गहरी रुचि लेने के लिए विख्यात चार शिक्षा-शास्त्री (जिनमें से दो को स्कूल-शिक्षक होना चाहिए), परिषद् के सह निदेशक, परिषद् की संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम दो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के होने चाहिए), शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा)।

कार्यकारी समिति निम्नलिखित स्थायी समितियों की सहायता से अपने कार्य करती है—

—कार्यक्रम सलाहकार समिति

—वित्त समिति

—स्थापना समिति

—भवन और निर्माण समिति

—शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

—क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की प्रबंध समितियाँ

परिषद् के मुख्यालय में आते हैं— (1) परिषद् का सचिवालय, और (2) लेखा शाखा। राष्ट्रीय शै० अ० और प्र० परिषद् के मुख्य कार्यकारी हैं—निदेशक, सह निदेशक और सचिव जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। वर्ष के दौरान इन पदों पर नीचे लिखे अधिकारी बने रहे—डा० पी०एल० मल्होत्रा—निदेशक (10 जून 1983 से)। डा० त्रिलोकनाथ धर—सह निदेशक (9 जून 1983 तक कार्यकारी निदेशक)। श्री विनोद कुमार पंडित, आई० ए० एस०—सचिव (4 मई 1983 तक)। श्री सी० रामचंद्रन, आई० ए० एस०—सचिव (5 मई 1983 से)।

शैक्षणिक कार्यों में निदेशक की सहायता के लिए तीन डीन भी हैं जिनके नाम, पद और उत्तरदायित्व नीचे दिए जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति 16 जनवरी 1984 से दो वर्षों के लिए की गई है।

नाम और पद	उत्तरदायित्व
प्रो० भा० स० पारख	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों के शैक्षणिक कार्यों में समन्वय रखना।
डीन (शैक्षणिक)	
प्रो० आत्मानंद शर्मा	अनुसंधान कार्यक्रमों में समन्वय रखना और
डीन (अनुसंधान)	शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार समिति का कार्य देखना।
प्रो० जी०एस० श्रीकांतिया	सेवा/उत्पादन विभागों, क्षेत्र कार्यालयों और
डीन (समन्वय)	क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कामों में समन्वय रखना।

परिषद् के अधीन हैं—(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, (ख) चार क्षेत्रीय शिक्षा महा-

विद्यालय, (ग) सत्रह क्षेत्रीय एकक, और (घ) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में सन् 1983-84 के दौरान निम्नलिखित घटक थे जो अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, प्रसार, मूल्यांकन और विकीर्णन के कार्य करते रहे हैं—

1. विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
2. सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
3. अध्यापक-शिक्षा विभाग
4. शिक्षण साधन विभाग
5. मापन एवं मूल्यांकन विभाग
6. प्रकाशन विभाग
7. वर्कशॉप विभाग
8. पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक
9. शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
10. शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
11. नियोजन, समन्वय एवं मूल्यांकन एकक
12. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक
13. जनसंख्या-शिक्षा एकक
14. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
15. सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रिया एकक
16. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक
17. शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक
18. शिशु अध्ययन एकक
19. स्त्री-शिक्षा एकक
20. पत्रिका प्रकोष्ठ
21. प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम प्रकोष्ठ
22. समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता में विकासात्मक गतिविधियाँ प्रकोष्ठ
23. प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
24. पाठ्यक्रम वर्ग
25. अनौपचारिक शिक्षा वर्ग
26. प्रसार एकक

नई दिल्ली में सन् 1973 ई० में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि शिक्षा के प्रसार के लिए संचार माध्यमों के इस्तेमाल के वास्ते रूपात्मकताओं का विकास किया जा सके। शैक्षिक फिल्मों के निर्माण, रेडियो कार्यक्रमों के विकास और सम्बद्ध शैक्षिक सामग्री के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में यह केंद्र अनुसंधान और विकास के कार्य करता है। यह केंद्र शैक्षिक दूरदर्शन और स्कूल के प्रसारण-कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के आयोजन भी करता है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय और क्षेत्र एक के

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय नीचे लिखे स्थानों पर हैं—
अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर।

इन महाविद्यालयों में निम्नलिखित कोर्सों की व्यवस्था है—

- बी. ए. (आनर्स) बी. एड.
- बी. एससी. (आनर्स)/(पास) बी. एड.
- बी. एड. आर्ट्स (एलीमेंटरी/सेकंडरी एजुकेशन)
- बी. एड. साइंस (एलीमेंटरी/सेकंडरी एजुकेशन)
- बी. एड. (एग्रीकल्चर/कामर्स/सोशल साइंस)
- बी. एड. (इंग्लिश/हिन्दी/उर्दू)
- बी. एड. (समर स्कूल-कम-कारेस्पॉडेंस कोर्स)
- एम. एड. (एलीमेंटरी सेकंडरी एजुकेशन)
- एम. एससी. एड. (फ़िजिक्स/कैमिस्ट्री/मैथेमेटिक्स/लाइफ साइंसेज)
- पीएच. डी. (एजुकेशन)

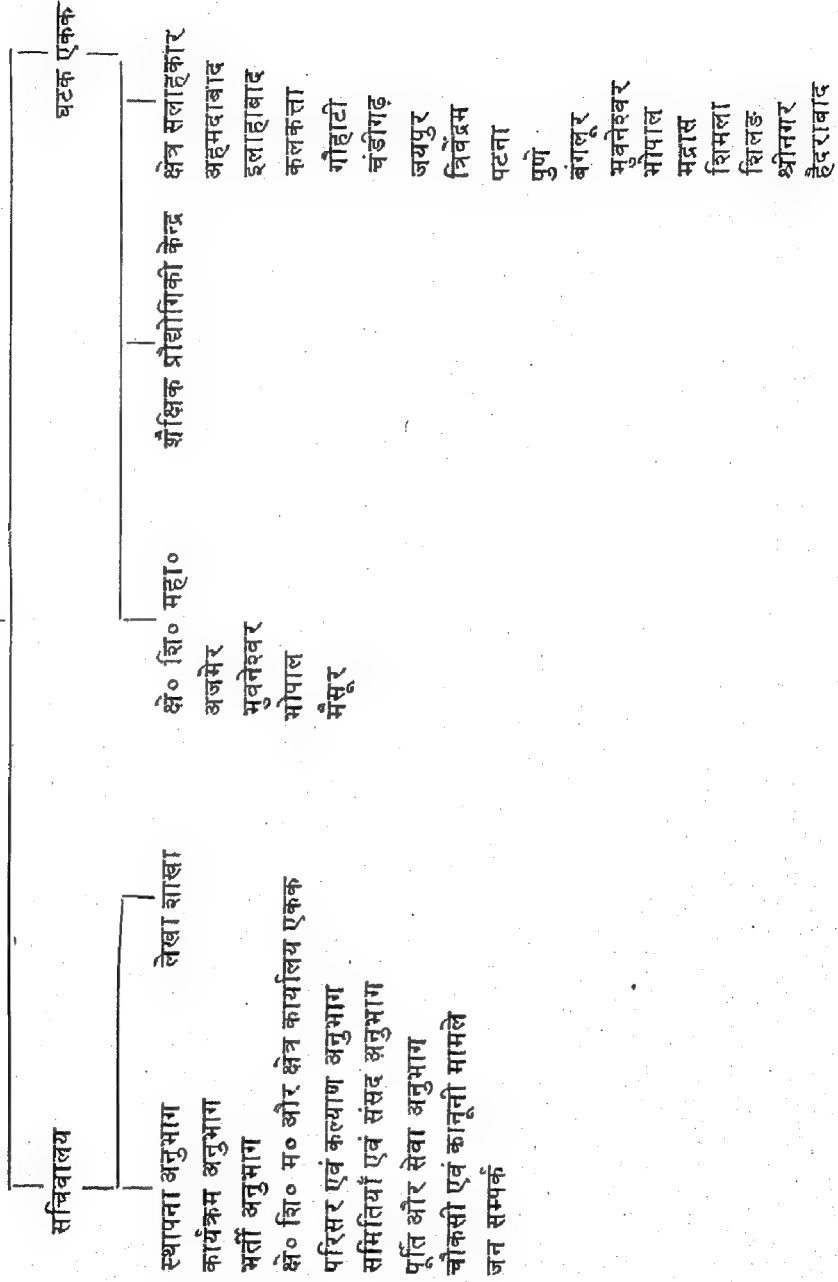
अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में केवल चार वर्षीय बी. एससी. बी. एड. कोर्स की व्यवस्था है जबकि भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में लाइफ साइंसेज में एम. एससी. एड. का प्रबंध है और मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में फ़िजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स में एम. एससी. एड. का प्रबंध है। चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में पीएच. डी. और एक वर्षीय बी. एड. तथा एम. एड. कोर्सों की व्यवस्था है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय आवासीय संस्थान हैं और इनमें प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था है। इन महाविद्यालयों में बहुदेशीय प्रदर्शन स्कूल भी हैं जहाँ नई विकसित शिक्षण पद्धतियों को व्यावहारिक तौर पर कक्षा स्थितियों में जाँचा जाता है।

निम्नलिखित स्थानों पर सत्रह क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है ताकि राज्य शिक्षा प्राधिकरणों एवं स्कूल शिक्षा के लिए काम कर रहे राज्य स्तर के शैक्षिक संस्थानों के साथ प्रभावी सम्पर्क बनाया जा सके—

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. अहमदाबाद | 9. पुणे |
| 2. इलाहाबाद | 10. बंगलूर |
| 3. कलकत्ता | 11. भुवनेश्वर |
| 4. गोहाटी | 12. भोपाल |
| 5. चंडीगढ़ | 13. मद्रास |
| 6. जयपुर | 14. शिमला |
| 7. त्रिवेंद्रम | 15. शिलङ |
| 8. पटना | 16. श्रीनगर |
| | 17. हैदराबाद |

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की संरचना
रा० शै० अ० और प्र० प०



राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

(शैक्षणिक)

- विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
- सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
- अध्यापक शिक्षा विभाग
- शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
- मापन एवं मूल्यांकन विभाग

(सेवा/उत्पादन)

- शिक्षण साधन विभाग
- प्रकाशन विभाग
- वर्कशॉप विभाग

(एकक/प्रकोष्ठ/वर्ग)

- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक
- नियोजन, समन्वय एवं मूल्यांकन एकक
- पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक
- शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक
- प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
- पत्रिका प्रकोष्ठ
- प्रसार एकक
- समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता में
- विकासात्मक गतिविधियाँ प्रकोष्ठ
- पाठ्यक्रम वर्ग
- अनौपचारिक शिक्षा वर्ग
- शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
- जनसंख्या शिक्षा एकक
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक
- शिशु अध्ययन एकक
- स्त्री शिक्षा एकक
- प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपग्राम एकक
- सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रिया एकक

2

वर्ष के उल्लेखनीय कार्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने अपने कार्यक्रमों में एकीकृत रूप से अनेक महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए जो सामान्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, प्रसार और विकीर्णन के अंतर्गत आ जाएंगे।

मूल्योन्मुखी शिक्षा के निमित्त मार्गदर्शी रेखाएँ बनाने के लिए प्रोफेसर दीलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा और मूल्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई। इसके कार्यकारी दल की एक बैठक अगस्त 1983 में हुई जिसमें अनेक बातों की सिफारिशें की गईं। मूल्योन्मुखी शिक्षा के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत नैतिक शिक्षा के बढ़ावे के लिए पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षण-सामग्री के निर्माण के लिए प्रारंभिक कदम उठाए गए। माध्यमिक स्तर के बच्चों के निमित्त दो सप्लीमेंटरी रीडरों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया जिनमें मूल्योन्मुखी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि बच्चे के बोधात्मक विकास और मूल्योन्मुखता के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, रा० शै० अ० और प्र० प० ने 'सीखने के लिए पढ़ना' नामक एक

बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—भारतीय बच्चों की दिलचस्पी वाले विस्तृत क्षेत्र में ऐसी पठन सामग्री प्रकाशित करना जो रोचक शैली में लिखी गई हो और सचित्र रूप में खूबसूरती के साथ छापी गई हो। इस परियोजना के अंतर्गत दो राष्ट्रीय कार्यगोष्ठियाँ की गईं। हिन्दी और अंग्रेजी में बच्चों के लिए ग्रेडेड सामग्री के निर्माण की विस्तृत मार्गदर्शी रेखाएँ इनमें बना ली गईं। इन कार्यगोष्ठियों में देश के अनेक सुप्रसिद्ध लेखकों, कवियों और विद्वानों ने भाग लिया। उन्होंने इस परियोजना के अंतर्गत बच्चों के लिए विशिष्ट साहित्य के सृजन का निश्चय किया।

नई पीढ़ी को भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से परिचित कराने के उद्देश्य से परिषद् ने एक बड़ी योजना हाथ में ली है जिसके अंतर्गत प्रथम स्वातंत्र्य संघर्ष (1857) से शुरू कर स्वाधीनता आंदोलन के जाज्वल्यमान इतिहास को दर्शाने वाली घटनाओं पर दृश्य सामग्री के लगभग 80 पैन्लों का एक एलबम तैयार कर प्रकाशित किया जायगा। यह सामग्री मूल स्रोतों से परिषद् के शोधार्थियों ने एकत्र की है।

यह भी महसूस किया गया कि भारत की आज की नई पीढ़ी को विख्यात विचारकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और राष्ट्रीय नेताओं की मूल रचनाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। अतएव परिषद् ने एक श्रेष्ठ-संकलन-माला को प्रकाशित करने का निश्चय किया और इसके अंतर्गत 'साइंस एंड मैन' नामक प्रथम पुस्तक का विमोचन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल के करकमलों द्वारा फरवरी 1984 में किया गया। इस श्रेष्ठ संकलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, प्रफुल्लचंद्र राय, सरोजिनी नायडू, जाकिर हुसैन, चंद्रशेखर वेंकट रामन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लियो तोल्स्टोय, अलबर्ट आइंस्टीन, वट्टेंड रसेल आदि की रचनाओं को संकलित किया गया है। इस साला की दूसरी पुस्तक का काम शुरू कर दिया गया है जिसमें जवाहरलाल नेहरू की मूल रचनाओं की चयनिका नवंबर 1984 तक प्रकाशित कर दी जायगी।

राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से परिषद् ने इतिहास और भाषाओं की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन की एक परियोजना शुरू की है। यह कार्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। मूल्यांकन की मार्गदर्शी रेखाएँ रा० शै० अ० और प्र० प० ने विभिन्न विषयों के उच्च विशेषज्ञों के सहयोग से बनाई थीं। अनेक राज्यों ने मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है और कइयों ने अपनी पाठ्यपुस्तकें संशोधित कर ली हैं।

वर्ष के दौरान शैक्षिक अभिनव परिवर्तनों वाले जिन प्रमुख क्षेत्रों में एन० सी० ई० आर० टी० ने काम शुरू किया उनमें एक है—स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रवेश। यह एक मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है जिसका नाम है 'स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (सी० एल० ए० एस० एस०)। यह परियोजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने चलाई है। मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह सारे देश में फैले 40 संसाधन केंद्रों के सहयोग से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्र पाठ्यक्रम का विकास करे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करे। साथ ही उसे शैक्षिक परि-

वर्तन के इस नए क्षेत्र में शैक्षिक सॉफ्टवेयर के विकास का काम भी करना है। कंप्यूटर साक्षरता के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए पहली राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी 26 से 27 मार्च 1984 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में आयोजित की गई।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के केन्द्रीय संस्थान एवं राज्यों के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों के माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एकीकृत कार्यक्रम लागू किए जाने का काम होता रहा। इसमें रेडियो और टेलिविज़न का इस्तेमाल भी शामिल है। इस एकीकृत कार्यक्रम में शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा दूर शिक्षा की उन प्रविधियों का इस्तेमाल होता है जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाती हैं और वर्तमान शिक्षा को फैलाती हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 'इनसैट वन बी' को इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट ट्रांसमिशन सर्विस का काम शुरू किया गया। दोनों राज्यों में प्रसारण के लिए 415 कार्यक्रमों के कंप्यूटर उपग्रह केन्द्रों को भेजे गए।

समीक्षाधीन वर्ष में परिषद् ने बारबडोस, वेस्ट इंडीज़, नेपाल, पाकिस्तान, थाइलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बाङ्लादेश, रूस, अमरीका, बेहरैन, फीजी, जापान, वियतनाम, मारीशस, तंज़ानिया और सोमालिया जैसे बीस से भी अधिक देशों के शिक्षाविदों और विशिष्ट व्यक्तियों को आतिथ्य प्रदान किया। एपीड (विकास के लिए शैक्षिक अभिनव परिवर्तनों का एशियाई प्रोग्राम) के सहयोगी केंद्र और राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में परिषद् इस वर्ष भी काम करती रही। केन्द्रीय शिक्षा सचिव, श्रीमती सरला ग्रेवाल राष्ट्रीय विकास दल की अध्यक्षता के रूप में एपीड की नवीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक की अध्यक्षता निर्वहित हुई। यह बैठक बैङ्काक में 20 से 26 मार्च 1984 तक हुई। रा० शै० अ० और प्र० प० के निदेशक, डा० पी० एल० मल्होत्रा ने वेर्लिग्टन में 4 से 12 अक्टूबर 1983 तक हुए यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन पाठ्यपुस्तकों और पठन सामग्री पर हुआ था। शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यगोष्ठियों/गोष्ठियों में भारत का प्रतिनिधित्व रा० शै० अ० और प्र० प० के अनेक वरिष्ठ शैक्षणिक कर्मचारियों ने किया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए, पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा एवं अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए चलाई जा रही अनेक परियोजनाओं को संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय समन्वयन एजेंसी की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व परिषद् का ही रहा है।

इन परियोजनाओं में ये शामिल हैं—(1) तीन से आठ वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षिक मूल्य वाले सस्ते, सादे और प्रभावी माध्यमों के निर्माण को प्रमुखता देने वाली शिशु माध्यम प्रयोगशाला; (2) नौ से चौदह वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों के प्रासंगिक, समस्या-केन्द्रित और कार्य आधारित विकेन्द्रीकृत पाठ्यक्रम एवं अधिगम सामग्री के निर्माण को प्रमुखता देने वाला प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम; (3) समुदाय की शैक्षिक जरूरतें पूरी करने वाली 3 से 6, 6 से 14 और 15 से 35 वर्ष के बीच वालों के लिए, शिक्षण सामग्री के निर्माण में संलग्न समुदायिक शिक्षा और प्रतिभागिता की विकासात्मक गतिविधियाँ; (4) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण के विभिन्न पक्षों और घटकों में राज्य स्तर के केन्द्रों में शिक्षकों, अध्यापक-शिक्षकों और पाठ्यक्रम निर्माताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्राथमिक

शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण; (5) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और परिवेशीय स्वच्छता जिसके अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और परिवेशीय स्वच्छता पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की जरूरतों के उपयुक्त शिक्षण सामग्री बनाई और स्कूलों में इस्तेमाल की जाती है।

ऊपर गिनाई गई परियोजनाओं को रा० शै० अ० और प्र० प० के मार्गदर्शन और यूनिसेफ के पोषण से राज्यों में जबकि लागू किया जा रहा था, तभी इस बात की कोशिशें भी हो रही थीं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लिए योजना कार्यक्रमों को राज्यों/संघ क्षेत्रों में वर्तमान संस्थागत प्रबंधों के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम से जोड़ दिया जाए। ऊपर गिनाई गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पाँच बाहरी एजेंसियों को नामित किया गया। दृष्टि यह थी कि मवाचार की विधियों, सामग्री और अभ्यासों के संस्थाकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना दिया जाए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उपयुक्त अनौपचारिक शिक्षण और अधि-गम तरीकों तथा सामग्री के निर्माण की कोशिशों को जारी किए रही। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक विकास में सामुदायिक प्रतिभागिता की प्रकृति और सीमा और उसकी प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए भी शोध एवं विकास की अनेक परियोजनाएँ शुरू की गईं। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर जनजाति के छात्रों के विषयवार निष्पादन का एक अध्ययन भी शुरू किया गया ताकि उनकी क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाया जा सके।

माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के शोध, विकास और मूल्यांकन की दिशा में एन० सी० ई० आर० टी० का मुख्य जोर इन बिंदुओं पर रहा — (1) माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, स्कूल शिक्षकों और छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पाठ्यचर्याओं और शिक्षण-सामग्री का संशोधन; (2) दस जमा दो प्रणाली की स्कूल शिक्षा के कार्यान्वयन एवं एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित शिक्षण सामग्री के अनुकूलन में लगे हुए राज्यों को तकनीकी सहायता का प्रावधान; और (3) अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता एवं पाठ्यक्रम नवीकरण के वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं और पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए शोध सहायता।

कक्षा I से X तक की सामान्य शिक्षा के स्तर पर 'पाठ्यक्रम बोर्ड' को तुरंत समझने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने एक कार्यदल गठित किया। सर्वेक्षण की पहली अवस्था में दिल्ली के संघ राज्य का ही सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ब्रिटिश काउंसिल द्वारा प्रवर्तित दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत यू० के० में विज्ञान और गणित के उच्च प्रशिक्षण के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से स्नातकोत्तर स्कूल शिक्षकों/अध्यापक शिक्षकों के चयन का उत्तरदायित्व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने परिषद् को सौंपा। समीक्षित वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों में गणित के 23 शिक्षकों/अध्यापक-शिक्षकों तथा भौतिकी, रासायनिकी और जैविकी के 20 शिक्षकों/अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित हुए शिक्षकों/अध्यापक-शिक्षकों की सहायता से रा० शै० अ० और प्र० प० ने त्रिवेन्द्रम और इलाहाबाद में दो प्रशिक्षण कार्यगोष्ठियाँ आयोजित कीं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन के साथ सहयोगी व्यवस्था करके सेकंडरी स्तर की

पाठ्यचर्याओं एवं पाठ्यपुस्तकों के संशोधन का काम भी रा०शै०अ० और प्र०प० ने शुरू किया। इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय गोष्ठियों व कार्यगोष्ठियों का आयोजन रा०शै०अ० और प्र०प० में किया गया। संशोधन के लिए पाठ्यचर्याओं और पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करते समय इस बात का ख्याल रखा गया कि पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा सरल रहे, सामग्री का प्रस्तुतीकरण सुधारा जाए। इस प्रकार की पाठ्यचर्याओं पर आधारित नई विकसित पाठ्यचर्याएँ और सामग्री छात्रों के बोध के स्तर के अनुरूप हों एवं कोर्स में लगाई गई सामग्री हर कक्षा के लिए वस्तुतः उपलब्ध पढ़ाई के घंटों में पढ़ाई जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रा०शै०अ० और प्र०प० द्वारा बच्चों के लिए आयोजित तेरहवीं वार्षिक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन लखनऊ में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 10 नवम्बर 1983 को किया। इस प्रदर्शनी का विषय था—‘उत्पादकता के लिए विज्ञान और शिल्पविज्ञान’। प्रदर्शनी में 27 राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 300 शिक्षकों तथा छात्रों ने भाग लिया। महासागर विकास विभाग द्वारा आयोजित ‘महासागर का विकास एवं महासागरों के संसाधन’ प्रदर्शनी में भी एन० सी० ई० आर० टी० ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में 4 नवम्बर 1983 को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उद्घाटित की गई थी।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए लड़कियों और स्त्रियों के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित घंटों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् ने भारत में सह-शिक्षा के एक अध्ययन को शुरू किया है। तेरह से अठारह वर्ष की लड़कियों के सामाजीकरण की समस्याओं से संबद्ध अनेक सप्लीमेंटरी रीडरों के लेखन का कार्य हाथ में लिया गया है जिनमें वहेज, स्त्रियों के कानूनी अधिकारों आदि की समस्याएँ भी ली जाएँगी।

राज्यों में जनसंख्या शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में इस्तेमाल करने के लिए जनसंख्या शिक्षा की अधिगम सामग्री के विकास के लिए भी राष्ट्रीय परिषद् ने कई काम शुरू किए। स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण की पाठ्यचर्याओं में जनसंख्या शिक्षा के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी रेखाएँ बनाई गईं।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के क्षेत्र में रा०शै०अ० और प्र०प० द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा जोर छात्रों और शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षण-सामग्री के निर्माण और विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध पहचानी गई न्यूनतम निपुणताओं के विकास पर दिया गया। इसी प्रकार समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के पाठ्यक्रम के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए।

मापन और मूल्यांकन की तकनीकों को सुधारने के प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के विभिन्न बोर्डों द्वारा कक्षा X, XI, XII के अंत में 1980 और 1981 के बाहरी परीक्षा-परिणामों का विश्लेषण तथा विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के बोर्डों द्वारा अपनाई गई पर्वे बनाने और पांडुलिपियों के मूल्यांकन की विधियों का अध्ययन किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 8 मई 1983 को भारत के 445 केंद्रों और बहरैन के एक केंद्र में ली गई। इस परीक्षा में कुल 74108 छात्र बैठे—कक्षा X में 42964, कक्षा XI में 5744

और कक्षा XII में 25400। इन छात्रवृत्तियों के लिए कुल 750 छात्र चुने गए जिनमें 75 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे।

कई राज्यों में लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन, प्राथमिक स्तर पर नामांकन और अवरोधन दरों पर सी०ए०आर०ई० की मदद से चलाए जा रहे दोपहर के भोजन के कार्यक्रम का प्रभाव तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्राथमिक स्तर पर निष्क्रियता और स्कूल छोड़ जाने वालों की दरों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कई सर्वेक्षण कराए।

रा०शै०अ० और प्र०प० द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए उपकरण ढूँढ़ लिए गए हैं। इन उपकरणों को कई चुने गए राज्यों में परखा जा चुका है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में रा०शै०अ० और प्र०प० ने एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की है—'टीचर एंड एजुकेशन इन दि एमर्जिंग इंडियन सोसायटी'। इस वर्ष रा०शै०अ० और प्र०प० ने अफगो की एकीकृत शिक्षा पर एक बड़ी परियोजना शुरू की।

राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों के आयोजन के साथ-साथ, रा०शै०अ० और प्र०प० ने सामुदायिक गायन की एक परियोजना भी शुरू की है। यह परियोजना सामुदायिक गायन में स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के एक जन आंदोलन का हिस्सा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के वृहद प्रचार-प्रभाव के निमित्त कैसेटों को बाँटा गया है जिनमें क्षेत्रीय भाषाओं के चुने हुए गानों को टेप किया गया है।

अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर बी०एड० की पाठ्यचर्याओं के संशोधन पर दिया गया। यह संशोधन निम्नलिखित कार्यक्रमों की सिफारिशों पर किया जा रहा है— अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम संरचना; क्षेत्रीय शिक्षा महा-विद्यालयों द्वारा चलाए गए नवाचारीय सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम; राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा स्थापित किए गए सतत शिक्षा के 77 केंद्रों के माध्यम से किए गए अल्प अवधि वाले सेवाकालीन कार्यक्रम।

अभी चल रही सभी योजनाओं और एन०सी०ई०आर०टी० की अन्य गतिविधियों का विस्तृत व्यौरा आगे दिए गए अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।

3

आरंभिक बचपन की शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्राक्-विद्यालय क्षेत्र में कई तरह के कार्य हाथ में लेती है जिसमें शैक्षिक सामग्री और शैक्षिक दृष्टिकोण का विकास, विविध स्तरों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण, चालू गतिविधियों और खेलों, चित्र पुस्तकों, श्रव्य टेप आदि का मूल्यांकन शामिल है।

'यूनिसेफ' की मदद से बच्चों के लिए बनाई गई शिशु माध्यम प्रयोगशाला इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रयोगशाला के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. तीन से आठ वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजनात्मक महत्त्व के प्रभावशाली और सस्ते माध्यम की खोज तथा विकास करना।
2. राज्य स्तर पर आरंभिक बचपन की शिक्षा के लिए एकक स्थापित करने में तथा उन एककों का विकास करने में राज्य शिक्षा विभागों की मदद करना।
3. प्राक्-विद्यालयीन बच्चों के लिए आधारभूत अधिगम सामग्री और खेल सामग्री विकसित करना।

हिस्सा लेने वाले राज्यों की संख्या 1983-84 के दौरान छः से बढ़ कर नौ हो गई। इस दौर में हिस्सा लेने वाले नए राज्य थे—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात।

अध्यापक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

आरंभिक बचपन की शिक्षा से संबंधित एक-एक माह की अवधि वाले तीन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए चलाए गए। इनका उद्देश्य बच्चे पर तथा बच्चे के विकास को आगे बढ़ाने में अध्यापक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना था, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, विशेष रूप से सहभागियों को बालविकास की प्रवृत्तियों से परिचित कराना और आरंभिक बचपन की शिक्षा में उनका इस्तेमाल करना था। इस प्रकार की प्रयोगात्मक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया जैसे रचनात्मक नाटक, कठपुतली नाट्य और रचनात्मक कला आदि। बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में राज्य स्तर के कार्यक्रम जैसे निरीक्षकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अध्यापकों के लिए शैक्षिक सामग्री का विकास, तथा बच्चों के लिए पुस्तकें जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। भाग लेने वाले कुछ राज्यों ने इस प्रकार से विकसित की गई सामग्री को मुद्रित भी किया। फरवरी-मार्च 1984 के दौरान महाराष्ट्र में 65 बालवाडियों के अभिभावकों की बैठकें आयोजित की गईं।

राज्यस्तर के स्रोत व्यक्तियों के लिए बाल

माध्यम संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम

जिन तीन राज्यों ने 1983-84 में आरंभिक बचपन की शिक्षा परियोजना में भाग लिया था इन सभी राज्यों के स्रोत व्यक्तियों के लिए, बाल माध्यम पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल माध्यमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रत्येक राज्य के छः-छः व्यक्तियों को अभिविन्यास किया गया जिससे वे अपने-अपने राज्यों में अध्यापकों और अध्यापक-प्रशिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकें।

अभिविन्यास कार्यक्रमों में निम्नांकित पर विचार किए गए :

1. कम कीमत वाली खेल सामग्री
2. बाल साहित्य
3. खेल और गीत तथा लययुक्त व्यायाम
4. कठपुतलियाँ तथा कठपुतली नाट्य
5. श्रव्य टेप तथा स्लाइड टेप का उत्पादन
6. रचनात्मक गतिविधियाँ
7. अपने-अपने राज्यों में स्रोत व्यक्तियों द्वारा उठाए जाने वाले भावी कदम।

आलेख लेखकों की कार्यशाला

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, परिसर में 20 से 29 सितंबर 1983 की अवधि में आलेख लेखन संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था हिंदी तथा तमिल

में पूर्व-विद्यालयीन छात्रों के लिए श्रव्य आलेख तैयार करना। दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से सोलह, यानी दोनों भाषाओं में आठ-आठ, सहभागियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। दल ने छोटे बच्चों के लिए श्रव्य कार्यक्रम तैयार करने के विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श किया। 23 सितंबर, 1983 से आलेख लेखन का कार्य शुरू किया गया। दोनों ही भाषाओं में प्रसिद्ध लेखकों, संपादकों तथा बच्चों के कार्यक्रम संबंधी पांडुलिपि तैयार करने वालों ने आलेखों पर बातचीत की और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कुल मिलाकर हिंदी तथा तमिल में 15 आलेख तैयार किए गए। इनके साथ ही हिंदी में 11 कविताएँ भी लिखी गईं। कार्यशाला में तरह-तरह के विषयों को लिया गया जैसे चिड़ियों में धोंसले बनाने की आदतें, पशुओं की खाद्य आदतें, हवा की विशेषताएँ, झूते पहनने का उद्देश्य, सजीव और निर्जीव वस्तुएँ, जानवरों के प्रति दया, रुचि का बोध, संगीत बाद्य, कुकुरमुत्ते, रंग, त्यौहार और राष्ट्रीय दिवस, आदि।

खेल सामग्री परियोजना

इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों में वर्तमान खेल सामग्री का सर्वेक्षण है तथा प्रचलित खेल और उपलब्ध खिलौनों की शैक्षिक क्षमता को बतलाने वाली पुस्तिका तैयार करना भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खेल सामग्री परियोजना पूरी की गई तथा पांडिचेरी में यह प्रगति पर है।

रेडियो संचारेक्षण परियोजनाएँ

आकाशवाणी के भोपाल, हैदराबाद और पांडिचेरी केंद्रों से छोटे बच्चों के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बच्चों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए रेडियो संचारेक्षण परियोजना आरंभ की गई थी। शीघ्र ही इन पर प्रतिवेदन लिख लिया जाएगा, ऐसी आशा की जाती है। कलकत्ता तथा मद्रास दूरदर्शन केंद्रों से बच्चों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों का दूरदर्शन संचारेक्षण भी आरंभ किया गया।

आदि रूप और स्लाइड टेप

पाँच श्रव्य आदि रूप हिंदी में तथा सात मराठी में तैयार किए गए। कार्यक्रम लगभग 15 मिनट अवधि के हैं और हर कार्यक्रम में 3 से 8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों की दिलचस्पी वाले गीत, खेल और कहानियाँ शामिल किए गए हैं। एक स्लाइड टेप कार्यक्रम तैयार किया गया जिसका शीर्षक था, 'चाय की कहानी'। इसमें चाय बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। महाराष्ट्र की खेल सामग्री के सर्वेक्षण के आधार पर अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका छापी गई और इसको महाराष्ट्र में ही वितरित किया गया।

पाँच चित्र पुस्तकें, पाँच इंद्रिय बोध पुस्तकें, दस वार्तालाप चार्ट, बोध प्रतिभा संबंधी छबोस कार्ड, मुद्रण के विभिन्न स्तरों पर थे।

आरंभिक बचपन की शिक्षा परियोजना के निदेशकों की बैठक

परियोजना के निदेशकों तथा प्रभारी अधिकारियों की एक बैठक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में 4 से 6 अक्टूबर 1983 तक हुई। इस बैठक में नौ राज्यों में से सात राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीन दिन की बैठक में बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य 1984 के लिए, परियोजना के प्रभारी अधिकारियों की सलाह से कार्ययोजना तथा बजट की अनुमानित रूपरेखा तैयार करना था।

प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के नए रूप

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने यूनेस्को के बैंकाक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से 'पूर्व विद्यालयीन' शिक्षा के विकास के नए रूप पर 25 से 30 अप्रैल 1983 तक अध्ययन दल की बैठक आयोजित की। इस बैठक के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (अ) क्षेत्र में प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के नए रूपों के बारे में प्राप्त अनुभवों का आदान-प्रदान।
 - (ब) सामूहिक क्रियान्वयन तथा प्रतिकूल वातावरण वाले बच्चों के खास संदर्भ में प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के नए रूपों का खाका बनाना और उसका विकास करना।
- यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों में से निम्नांकित देशों ने बैठक में भाग लिया—अफगानिस्तान, भारत (चार में से दो भागीदार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के थे), चीन, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल।

पर्यवेक्षकों में शामिल थे, यूनिसेफ, यू० एन० एच० सी० आर०, यूनेस्को, भारतीय प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा संगठन, लेडी इरविन कालेज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक को-ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकनामिक्स, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्। बैठक की विषय सूची में निम्नांकित बातें शामिल थीं—

- (i) क्षेत्र के देशों में प्रयोग में लाए जा रहे प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के नए रूप, आधार-भूत रूपरेखा, उसका प्रबंध पक्ष, रूपरेखा तथा क्रियान्वयन के स्तर पर इनकी शक्ति और सीमाएं।
- (ii) बच्चे के समग्र विकास के संदर्भ में उन बच्चों के लिए प्राक् विद्यालयीन शिक्षा की आवश्यकता जो पिछड़े हुए वातावरण से आए हैं।
- (iii) नए प्रकार के प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के लिए वैकल्पिक डिजाइन और माडल, वह शिक्षा जो बड़े पैमाने पर पिछड़े वातावरण के बच्चों तक पहुंचने में समर्थ हो।

इन कार्यक्रमों में चलते-फिरते शिशु केंद्रों को देखना भी शामिल था, साथ में राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बालविकास संस्थान को भी देखना शामिल था।

जनजातीय और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से संबंधित अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम—कम लागत वाली खेल सामग्री को ध्यान में रखकर

रिपोर्टीधीन वर्ष के दौरान कम लागत वाली खेल सामग्री तथा खेलों पर बच्चों के लिए पांच कार्यक्रम हुए जिनमें से हर कार्यक्रम दस दिन का था। इन कार्यक्रमों के स्थल थे— सोलन, बिनपुर, चांगलांग, एलांग और बोमडिला। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य थे—

- (i) पूर्व-विद्यालयीन बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाया तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनके साथ काम करना।
- (ii) अध्यापकों में रुचि जाग्रत करना जिससे वे कम लागत की खेल सामग्री बना सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें।
- (iii) इस जानकारी को दूसरे अध्यापकों और बच्चों के मां-बाप में प्रचारित करना।

बाल विकास और आरंभिक बचपन की शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

14-16 फरवरी, 1984 के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में बाल-विकास और आरंभिक बचपन की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था, हाल के वर्षों में आरंभिक बचपन की शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्य को संकलित कर उसका प्रचार-प्रसार करना। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों से आए हुए 28 सहभागियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया।

प्रमुख क्षेत्रों, जिनके विषय में सेमिनार में पर्चे पढ़े गए, का संबंध प्राक्-विद्यालयीन बच्चों का शोषण, छोटे बच्चों की समस्याएँ, अधिगम अयोग्यता, बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतें, बच्चों का साहित्य, संज्ञानात्मक विकास के पर्यावरणात्मक सह संबंध।

प्राक्-विद्यालयीन शिक्षक-शिक्षण पर राष्ट्रीय बैठक

22-29 नवम्बर, 1983 के मध्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्राक्-विद्यालयीन शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जो यूनेस्को प्रायोजित थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के 14 सदस्य और 24 बाहर के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। बाहर आने वाले सहभागियों में स्वैच्छिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आठ राज्य शिक्षा संस्थानों तथा एन० आई० पी० सी० सी० डी० के सदस्य थे। राज्य शिक्षा संस्थानों से आए आठ सहभागी वे थे जो राज्य स्तर पर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा योजना के कार्यान्वयन कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए थे।

इस बैठक में केन्द्रीय विषय आरंभिक बचपन के स्तर वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण था। इस बैठक की विशेष बातें इस प्रकार थीं:

- (क) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की मौजूदा हैसियत पर बहस तथा उनका विश्लेषण तथा इनकी तुलना में विभिन्न प्रकार के प्राक्-विद्यालय कार्यक्रम, और
- (ख) अगले दशक में देश में प्राक्-विद्यालयों के तेजी से बढ़ने वाली संख्या के भावी परि-

गामों का अनुमान तथा विभिन्न श्रेणियों के संलग्न व्यक्तियों के सेवापूर्व तथा सेवा-कालीन प्रशिक्षण, और विविध प्रकार के माडलों के नियोजन की सकारात्मक आवश्यकता।

विशेष रूप से आई० सी० डी० एस० के व्यक्तियों को ध्यान में रख कर सिफारिशें पेश की गईं, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के विभिन्न स्तर के कार्मिकों और शिशुग्रहों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रख कर सिफारिशें की गईं।

आंगनवाड़ी के माध्यम से समुदाय तक पहुँचना

पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित बिनपुर (II) प्रखण्ड एक जनजातीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक 'क्रिया अनुसंधान परियोजना' हाथ में ली है। इस परियोजना का नाम है, 'आंगनवाड़ी के माध्यम से समुदाय तक पहुँचना'। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित वर्तमान योजना 1978 से ही 'समग्र बाल विकास सेवा' के अंतर्गत बिनपुर प्रखण्ड में चल रही है। प्रखण्डों में स्थापित की गई विविध आंगनवाड़ियों के माध्यम से 0-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए बाल विकास योजना चलाई जाती है। 'आंगनवाड़ी के माध्यम से समुदाय तक पहुँचना' परियोजना का उद्देश्य है— आंगनवाड़ी को तरह-तरह की गतिविधियों का केंद्र बनाना, प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा, पूरक सूचना और अभिभावकों को शिक्षित करने जैसी गतिविधियों के द्वारा समुदाय तक पहुँचना।

अध्ययन के प्रथम चरण में अप्रैल 1983 में बिनपुर प्रखण्ड की आंगनवाड़ी के मौजूदा स्तर और उसकी समस्याओं के विषय में जांच की गई। प्रत्यक्ष अध्ययन के उद्देश्य से परियोजना प्रभारी स्वयं धूम-धूम कर आंगनवाड़ी का निरीक्षण करने गए। 1976 से इस क्षेत्र में 50 आंगनवाड़ियां काम कर रही हैं। कई आंगनवाड़ियां ऐसे सुदूर क्षेत्रों में स्थित हैं कि उन तक पहुँचने के लिए 15/16 कि० मी० पैदल चलना पड़ता है। आई० सी० डी० एस० परियोजना के अंतर्गत 46,000 जनसंख्या को लिया गया है। अप्रैल 1983 में 14 आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया गया।

पूर्व-विद्यालयीन अनौपचारिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए 'कम लागत वाली खेल सामग्री तथा खेल' संबंधी 10 दिन की एक कार्यशाला चलाई जानी चाहिए। 7 से 16 नवम्बर 1983 तक, भाङ्गग्राम जिला मिदनापुर में बिनपुर प्रखण्ड के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 'कम लागत वाली खेल सामग्री तथा खेल' पर एक कार्यशाला चलाई गई। इस कार्यशाला में 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया जहाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास को समृद्ध करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों से उपलब्ध सस्ती चीजों तथा फालतू सामानों से खेल सामग्री तथा शिक्षण सहायक सामग्री तैयार की गई। इसी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए संगीत, नृत्य, नाटक तथा अभिनय का भी आयोजन किया गया। भाग लेने में से हर एक ने अपने लिए एक-एक खेल सामग्री की पेटिका तैयार की तथा उसे अपने साथ ले गई। यह तीसरा चरण जनवरी 1984 में शुरू किया गया था।

छोटे बच्चों को कला का अनुभव

दिल्ली के निम्नांकित स्थानों में इस परियोजना पर कार्य चल रहा था—

1. बाल भारती एयर फोर्स स्कूल
2. अंधे बच्चों का विद्यालय
3. गूंगे-बहरों का विद्यालय
4. भट्टी गांव।

भट्टी गांव के श्री गुरुदेव आश्रम में सामान्य किंतु विकलांग बच्चों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से सामान्य तथा विकलांग बच्चों के लिए एक समग्र कार्यक्रम का विकास करना था।

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की खिलौने बनाने की प्रतियोगिता

राष्ट्रीय खिलौना बनाने की कार्यशाला 27 मार्च, 1984 से शुरू हुई। परियोजना की दो चरणों में पूरा किया जाता है—पहले चरण में राज्य स्तर पर तथा दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के क्षेत्र परामर्शदाताओं ने इस कार्यक्रम को पूरा किया तथा तीन निर्णायकों की समिति में खिलौनों का मूल्यांकन किया तथा प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान लोगों को पुरस्कार दिए गए।

प्रतियोगिता के लिए जो शर्तें रखी गई थीं, वे इस प्रकार थीं—

1. इस प्रतियोगिता में बनाया गया खिलौना अध्यापक की मौलिक कृति होनी चाहिए।
2. पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए इस खिलौने का शैक्षिक मूल्य होना चाहिए।
3. आसपास से उपलब्ध फालतू सामानों से अथवा एकदम कम लागत में बनाया जाना चाहिए।
4. इसके साथ खिलौने के विषय में एक संक्षिप्त लिखित परिचय होना चाहिए।

अनुसंधान

1. भारतीय बच्चों का संज्ञानात्मक विकास (2—13 वर्ष) : एक देशांतरीय अध्ययन

यह अध्ययन पियाजेशन मॉडल पर आधारित है, उसके अवयव हैं (i) अविचारित सोच (ii) रूढ़िवादिता (iii) कक्षा के संबंध (iv) स्थान, समय परिवर्तन, और गति की अवधारणा तथा (v) संवेदनात्मक नाड़ियों की संरचना। यह अध्ययन भारतीय बच्चों के संज्ञानात्मक स्तरों के निर्धारण के उद्देश्य से हाथ में लिया गया था। अधिकांश पाठ्यक्रम निर्माताओं ने पियाजेशन मॉडल को आधारभूत ढांचे के रूप में स्वीकार कर लिया है। आशा है कि वर्तमान अध्ययन से प्राप्त परिणाम भारतीय पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे।

इस परियोजना का काम अक्टूबर 1978 में आरंभ किया गया। आंकड़े एकत्र किए जिसका

आधार विपरीत वर्गीय और देशांतरिय पद्धतियों का समिश्रित डिजाइन था। ये आंकड़े चार आयु वर्ग के बच्चों के विषय में थे, वे आयु वर्ग थे 2, 5, 8, और 11 वर्ष। तीन वर्षों के निदर्श एकत्र किए गए जो चार परीक्षणों पर आधारित थे। इस परियोजना का प्रतिवेदन तैयार होने के दौर में है।

2. शिशु माध्यम प्रयोगशाला सामग्री का मूल्यांकन

एक अनुसंधान अध्ययन 1982 में आरंभ किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य था, स्कूल के बच्चों की भाषा तथा संज्ञानात्मक विकास पर, सी० एम० एल० की सामग्री के आधार पर, हस्तक्षेप के प्रभाव को जानना। यह परियोजना 1983 में पूरी कर ली गई। यह अध्ययन जनजातीय बच्चों, शहरी गंदी बस्तियों के बच्चों और गाँव के बच्चों के ऊपर की गई थी। इस अध्ययन के प्रमुख लक्ष्य निम्नांकित थे—

(1) प्राक्-विद्यालयीन बच्चों के भाषिक तथा संज्ञानात्मक विकास पर सी० एम० एल० की सामग्री के अधिकाधिक इस्तेमाल की प्रभावशालिता का आकलन करना, जिसमें चित्र पुस्तकें, गीत, खेल, चित्रकार्ड आदि का इस्तेमाल किया गया हो।

(2) इस संभावना का पता लगाना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में प्राक्-विद्यालयीन शिक्षा के प्रति दिलचस्पी पैदा की जा सकती है या नहीं, विशेषरूप से सी० एम० एल० सामग्री से उन्हें परिचित कराकर जिससे वे स्वयं स्थानीय उपलब्ध सामग्री को लेकर उसी तरह की गति-विधियों को आयोजित कर सकें।

पहले से उपलब्ध आधारिक संरचना का इस्तेमाल कर इन असुबिधाजनक क्षेत्रों में अध्ययन चलाया गया जैसे आंगनवाड़ियाँ, जिन्हें समग्र बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग चला रहा था। समग्र बाल विकास सेवा योजना की परियोजनाओं से निदर्श एकत्र किए गए। इनमें टोकपाल जिला बस्तर से जनजातीय अध्ययन के लिए, खानपुर, नई दिल्ली के समग्र बाल विकास सेवा योजना, परियोजना से शहरी गंदी बस्तियों के अध्ययन के लिए तथा सोनीपत (हरियाणा) के गान्धेर के समग्र बाल विकास सेवा योजना से ग्रामीण अध्ययन के लिए। इस अध्ययन में 400 बच्चों को शामिल किया गया था जिसका आधार था प्राक्-परीक्षण परीक्षणोत्तर डिजाइन जिसे एक प्रयोगात्मक नियंत्रण समूह ने बनाया था।

जनजातीय समूह के लिए प्रतिवेदन तैयार हो चुका है तथा अन्य दो समूहों के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

इस बात को मानते हुए कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण शैक्षिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इससे संबंधित एक बहुमुखी कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसमें अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम शामिल हैं। इन गतिविधियों को हाथ में लेने के उद्देश्य हैं—शामरी स्कूल के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण जो बच्चों की जरूरतों और जीवन शैली के लिए उद्देश्यपूर्ण तथा प्रासंगिक हो, विशेषरूप से उन बच्चों के लिए जो समाज के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन वर्ग के हैं; ऐसे अनुभव प्रदान करना जो औपचारिक शिक्षा तक पहुँचने में मददगार साबित होंगे। इसी के साथ औपचारिकतर शिक्षा संगठन को आगे बढ़ाना, उन लोगों के लिए जो औपचारिक शिक्षा पद्धति में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो स्थायी रूप से इससे अलग हो जाते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से तथा राज्य स्तर के शिक्षण संस्थानों के सहयोग से (इसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद् तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल हैं)। निम्नलिखित परियोजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखा, इसमें 'यूनिसेफ' का भी सहयोग है। इनमें से प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की युक्ति के किसी पक्ष विशेष की ओर निदेशित हैं।

- (i) प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण,
- (ii) प्राइमरी शिक्षा तक लोगों की व्यापक पहुँच,
- (iii) सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता संबंधी विकासात्मक गतिविधियाँ,
- (iv) पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यावरण संबंधी सफाई,
- (v) आरंभिक बचपन की शिक्षा/बच्चों की माध्यम प्रयोगशाला

जबकि (i) से (iii) कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई गतिविधियों पर इसी अध्याय में विचार-विमर्श किया गया है, (iv) और (v) पर दूसरे अध्यायों में चर्चा की गई है।

प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण

पाठ्यक्रम नवीनीकरण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न माध्यमों को अपना कर निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण कार्यक्रम चलाया गया है।

- (क) नवाचारी पाठ्यक्रम का विकास जो विभिन्न समूहों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर सके, खास तौर पर उन बच्चों की जरूरतों को जो समाज के सुविधाहीन वर्ग के हैं।
- (ख) बच्चे की जीवन शैली तथा उनके संभावित सामाजिक आर्थिक अवसरों के साथ पाठ्यक्रम का गुणात्मक रूप से सामंजस्य स्थापित करना।
- (ग) प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम में उन नवाचारी विचारों का धीरे-धीरे प्रवेश कराकर, जिन्हें परियोजना स्कूलों में प्रयोगात्मक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत परखा जा चुका है, वर्तमान प्राइमरी शिक्षा को और ज्यादा सार्थक बनाना।

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अपने प्राइमरी पाठ्यक्रम विकास कक्ष के जरिए परियोजना का संचालन करती है और 22 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन प्रदान करती है जो परियोजना के विस्तारकालीन चरण में भाग ले रहे हैं, उस परियोजना के जिसका श्रीगणेश 1979-80 में किया गया था। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अपने राज्य प्राइमरी पाठ्यक्रम विकास कक्षों के जरिए इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य-शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की मदद के लिए तथा परियोजना स्कूलों में चल रहे शैक्षिक कार्यों के निरीक्षण के लिए 198 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/पर्यवेक्षक संस्थानों को इस परियोजना में भाग लेने के लिए चुना गया है। 2480 प्राइमरी स्कूल इस परियोजना में भाग ले रहे हैं।

प्राइमरी शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण परियोजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं—

- सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को संगठित करना।

- एक नवाचारी पाठ्यक्रम योजना का विकास ।
- सार्थक तथा जरूरतों पर आधारित शैक्षिक सामग्री का विकास (जैसे पाठ्य पुस्तकें अभ्यास पुस्तकें, शिक्षक निर्देशिका आदि) तथा परियोजना स्कूलों में इनको आजमाना ।
- नवाचारी शिक्षण-अधिगम युक्तियों को खोजना ।
- शिक्षार्थी के विकास के मूल्यांकन के लिए उचित पद्धति का विकास करना ।
- शिक्षक प्रशिक्षकों, अध्यापकों तथा योजना से संबद्ध अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाग लेने वाले राज्य, केंद्र-शासित क्षेत्र तरह-तरह की क्रियात्मक युक्तियां अपना रहे हैं। परियोजना से स्कूल क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण से, सार्थक पाठ्यक्रम विकसित करने, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण-अधिगम गति-विधियां तथा युक्तियां विकसित करने के लिए काफी उपयोगी सामग्री उपलब्ध हुई। यह सर्वेक्षण परियोजना के आरंभ में ही किया गया था। कुछ क्षेत्रों में भिन्नताएँ इतनी स्पष्ट हैं कि उड़ीसा तथा राजस्थान जैसे राज्य अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री के अलग तरह के सेट विकसित कर रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों ने सामान्य या एक जैसी पाठ्यपुस्तकों का सेट रखने का निश्चय किया है, जिनके साथ कुछ विस्तृत विस्म की अध्यापक निर्देशिका रखेंगे जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण-अधिगम युक्तियां सुझाई गई होंगी। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा संस्थान ने क्षेत्रों के हिसाब से सात अलग-अलग अध्यापक निर्देशिकाएँ तैयार की हैं, साथ में सहायक सामग्री का विकास भी किया गया है।

कुछ प्रशासनिक तथा अन्य कारणों से भिन्न-भिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन कार्यक्रम अलग-अलग समय पर आरंभ किया गया। अलग-अलग राज्यों में क्रियान्वयन की गति भी अलग-अलग है। 1983 के शैक्षिक वर्ष के दौरान, विस्तार के चरण में बारह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने (आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश) कक्षा तीन के स्तर तक नई शिक्षण-सामग्री को इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने (कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश तथा पांडिचेरी) कक्षा एक में शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया है। अनेक कारणों से जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम के नवीनीकरण परियोजना के अन्तर्गत कक्षा एक के लिए शैक्षिक सामग्री के विकास/मुद्रण की विभिन्न अवस्थाओं तक ही पहुंचे हैं।

अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 1983-84 के दौरान भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अधिकारियों के लिए लगभग 230 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिनमें 8850 से भी अधिक लोग प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किए गए। इनके अलावा शैक्षिक सामग्री और पाठ्यक्रम योजनाओं के विकास के लिए लगभग 171 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में परियोजना स्कूलों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य शिक्षा संस्थानों और अन्य संस्थानों

से लगभग 3159 लोगों की भागीदारी रही ।

राज्यों को मार्गदर्शन

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के विभिन्न पक्षों पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भागीदार कर्मचारियों के अभिविन्यास का चक्र पूरा किया। वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सदस्यों के लिए 26 अभिविन्यास कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 643 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके ऊपर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राज्य प्राइमरी पाठ्यक्रम विकास कक्ष के नए सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन 14-21 नवंबर 1983 को उदयपुर (राजस्थान) में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। इस कार्यक्रम में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा दादरा और नागर हवेली) के 29 व्यक्तियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 1983-84 के दौरान नई दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता और हैदराबाद में भाग लेने वाले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की चार बैठकें आयोजित कीं। इनमें उन कालेजों के 169 प्राचार्यों ने हिस्सा लिया जो संस्थान परियोजना में हिस्सा ले रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के संयोजकों की राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक 2-8 सितंबर 1983 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नई दिल्ली परिसर में हुई। इस बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई तथा वर्ष 1984 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। परियोजना संयोजकों ने वर्ष 1985 के पहले तिमाही के लिए प्रयोगात्मक कार्यवाही योजनाएँ भी तैयार कीं। इसके अलावा परियोजना के बाधा रहित क्रियान्वयन के लिए संयोजकों ने कुछ सिफारिशें भी रखीं। प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना दल को पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न पक्षों में, शिक्षण सामग्री के विकास तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, विशेष रूप से बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तथा केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से मार्गदर्शन मिला। विशेषरूप से भेजे गए संसाधन व्यक्तियों के जरिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, तमिलनाडु को, राज्य शिक्षा संस्थान जम्मू को तथा राज्य शिक्षा संस्थान गोवा को अल्पकालीन परामर्शदात्री सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं।

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’

परियोजना के समन्वयकों का अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के समन्वयकों का लगातार आग्रह की वजह से, अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया गया। दिसंबर 1983 और जन-

वरी-फरवरी 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु में अध्ययन भ्रमण आयोजित किए गए। इन भ्रमणों की संख्या पांच थी। परियोजना समन्वयकों ने कतिपय नवाचारी शिक्षण अधिगम पद्धतियों को काम के दौरान देखा, विभिन्न गतिविधियों को वास्तविक परिवेश में देखने के साथ समन्वयकों ने संबंधित मामलों पर अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों से भी विचार-विमर्श किया कि प्राइमरी शिक्षा के नवीनीकरण को कार्यरूप देने में कौन-सी बाधाएं सामने आती हैं।

न्यूनतम अधिगम सातत्यक की समीक्षा के लिए कार्यदल की बैठक

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना की खास विशेषताओं में एक विशेषता है—क्षमता पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास। यद्यपि न्यूनतम अधिगम सातत्यक का दस्तावेज पाठ्यक्रम विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करता है, फिर भी ऐसा महसूस किया गया कि सभी राज्यों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, दस्तावेज की समीक्षा के लिए युक्ति तैयार की जानी चाहिए जिससे इसका आगे भी विकास किया जा सके। 6-8 दिसंबर 1983 के दौरान न्यूनतम अधिगम सातत्यक की समीक्षा की युक्ति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक बैठक आयोजित की। न्यूनतम अधिगम सातत्यक की समीक्षा, परीक्षण तथा विकास के लिए कार्यदल की बैठक ने क्रियात्मक योजना को अंतिम रूप दिया।

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के मूल्यांकन के लिए उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ के मूल्यांकन के लिए 30-31 मई 1983 को उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। समिति ने ‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना मूल्यांकन के प्रस्तावित प्रारूप की समीक्षा की, इस प्रस्ताव प्रारूप को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बनाया था। समिति ने इसको सुधारने तथा अंतिम रूप देने के लिए सुझाव दिए।

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना स्कूलों की वस्तु स्थिति और स्थिति के अध्ययन के लिए 1982-83 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक अध्ययन शृंखला आरंभ की। इन अध्ययनों की तैयारी के लिए एकत्र किए गए आँकड़ों का 1983-84 के दौरान विश्लेषण किया गया तथा निम्नांकित अध्ययन तैयार किए गए—

- (1) ‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना से संबंध दो वस्तु

स्थिति अध्ययन, जैसे—

(अ) जीवन शिक्षण प्राइमरी स्कूल, कारेगांव, पुणे (महाराष्ट्र)

(ब) पंचायत यूनिजन प्राइमरी स्कूल, अम्मूर, उत्तरी आरकाँय (तमिलनाडु)

बाकी वस्तु स्थिति अध्ययन तथा स्थिति अध्ययन प्रगति के दौर से गुजर रहे हैं।

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना की शिक्षण सामग्री का व्यापक स्तर पर निषेचन

अब तक गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा मिजोरम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने कुछ शिक्षण सामग्रियों और पाठ्यक्रम के दूसरे पक्षों के व्यापक निषेचन के लिए (अपनी शिक्षा प्रणाली में) ठोस कदम उठाए हैं/ निर्णय लिए हैं। इस सामग्री तथा पाठ्यक्रम को ‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया था। ‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना का ही यह नतीजा है कि कुछ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जो पहले से किसी अन्य प्रदेशों की शिक्षण सामग्री तथा पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, प्राइमरी स्तर की शिक्षा के लिए वे अब अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री का विकास करने लगे हैं। ‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के अंतर्गत विकसित नए पाठ्यक्रम के व्यापक निषेचन के लिए इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

गुजरात

गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्तर के अपने पाठ्यक्रम में सुधार किया है। अन्य बातों के साथ-साथ नया पाठ्यक्रम पर्यावरण पर अवलंबित शिक्षा पर तथा न्यूनतम अधिगम क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका जिक्र न्यूनतम अधिगम सातत्यक में किया गया है जिसे प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत विकसित पर्यावरण अध्ययन विषयक पाठ्यपुस्तक को राज्य में इस्तेमाल करने के लिए राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल ने स्वीकार कर लिया है।

हरियाणा

ऐसा तय किया गया है कि प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई शिक्षक निर्देशिका को राज्य भर के स्कूलों की एस० यू० पी० डब्ल्यू०, कता तथा हस्तशिल्प तथा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण में आरंभ किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश

राज्य शिक्षा संस्थान, सोलन द्वारा प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना

के अंतर्गत विकसित पाठ्यपुस्तकों को सत्र 1983-84 से सभी स्कूलों की प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

महाराष्ट्र

शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र ने अपने प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम में सुधार किया है, यह सुधार न्यूनतम अधिगम सातत्यक पर आधारित है। राज्य शिक्षा विभाग ने कक्षा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक पुस्तिका को व्यापक इस्तेमाल के लिए अपनाया है।

उड़ीसा

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के प्रथम चरण में विकसित पहली और दूसरी योजनाओं के सभी विषयों के लिए एक सामान्य शिक्षक निर्देशिका का उड़ीसा राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में आरंभ किया है। राज्य शिक्षा विभाग ने एक भाषा प्राइमर/रीडर और अंकगणित की पाठ्यपुस्तक भी रखी है। इनको योजना के अंतर्गत चुने हुए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों और औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों के विभिन्न समूहों के लिए विकसित किया गया है।

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के नए पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है। इसका विकास राज्य में प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर हुआ है। राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अधीन विकसित निम्नांकित शैक्षिक सामग्री को भी व्यापक इस्तेमाल के लिए अपना लिया गया है—

- (i) कक्षा एक और दो के लिए हिंदी अभ्यास पुस्तिका।
- (ii) कक्षा एक और दो के लिए गणित में अभ्यास पुस्तिका जिसमें शिक्षक निर्देशिका भी शामिल की गई है।
- (iii) कक्षा तीन से पांच तक के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति और एस० यू० पी० डब्ल्यू की अध्यापक निर्देशिका।
- (iv) कक्षा तीन से पांच तक के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संबंधी अध्यापक निर्देशिका।

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल ने इन पुस्तकों को प्रकाशित किया है।

सिक्किम

‘प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण’ परियोजना के अंतर्गत विकसित शैक्षिक सामग्री को सिक्किम सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा एक के लिए लागू कर दिया है। शैक्षिक सत्र 1984 से कक्षा 2 के लिए अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक और उसकी अभ्यास

पुस्तिका, जो इस योजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं, सभी प्राइमरी स्कूलों में चलाई जाएंगी।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने कक्षा एक और दो की गणित की पाठ्यपुस्तकों को व्यापक इस्तेमाल के लिए अपनाया है। इसको प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण, परियोजना के अन्तर्गत, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तैयार कराया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत बनाई गई शिक्षण सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में लागू करने का निश्चय किया है।

लक्षद्वीप

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के शिक्षा विभाग ने प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण परियोजना के अंतर्गत कक्षा एक और कक्षा दो के लिए भाषा (मलयालम) में शिक्षण सामग्री तैयार की है। यह सामग्री गणित, पर्यावरण अध्ययन, एस० यू० पी० डब्ल्यू० और रचनात्मक अभिव्यक्ति संबंधी विषयों में भी विकसित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मलयालम माध्यम वाले सभी स्कूलों में इन पुस्तकों को लगाया गया है।

मिज़ोरम

मिज़ोरम के शिक्षा विभाग ने मिज़ो पाठ्यपुस्तकों को कक्षा एक से पाँच तक तथा पर्यावरण अध्ययन (सामाजिक अध्ययन) की पुस्तकों को कक्षा तीन से पाँच तक के लिए स्वीकार किया है। इन पाठ्यपुस्तकों को 'प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण' परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है।

प्राइमरी शिक्षा तक अधिकाधिक लोगों की पहुँच

'प्राइमरी शिक्षा तक अधिकाधिक लोगों की पहुँच' परियोजना भारत सरकार की उस कोशिश का एक हिस्सा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा से अब तक वंचित बच्चों की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प निहित है तथा जिसमें 9-14 वर्ष के बच्चों को, जो विद्यालय नहीं जा सके हैं, औपचारिकतर शिक्षण कार्यक्रम द्वारा शिक्षित करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय दृष्टि से प्रासंगिक शैक्षिक सामग्री (शैक्षिक घटनाएँ) पर्याप्त मात्रा और विविधता में विकसित की जा रही है। अधिगम घटनाओं को प्रशिक्षण-उत्पादन पद्धति के जरिए विकसित किया जाता है। इनको प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में या प्राइमरी अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में तैयार किया जाता है। परिष्कार और सुधार के बाद अधिगम घटनाएँ प्रयोगात्मक अधिगम केंद्रों की संस्थाओं में काम में लाई जाएंगी। इनको भविष्य में स्थापित किया जाएगा तथा आरंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में

संबद्ध कर दिया जाएगा जो इस परियोजना में हिस्सा ले रही हैं। उसके बाद राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्यांकन केंद्र तथा प्रत्यायन सेवाएं स्थापित होंगी ताकि इन अधिगम केंद्रों पर सीखने वाले बच्चों को उनकी शैक्षिक योग्यता के लिए प्रमाण-पत्र दिए जा सकें।

परियोजना के उद्देश्य

परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं—(i) शिक्षा की औपचारिकेतर प्रणाली का विकास और बच्चों की भागीदारी को, औपचारिकेतर गतिविधियों में बढ़ाना, उन बच्चों की भागीदारी को जो समाज के कमजोर वर्ग के हैं। इन गतिविधियों को स्कूल के विकल्प के रूप में संगठित किया जाना है। (ii) लचीला, समस्या केंद्रित तथा कार्याधारित विकेंद्रित पाठ्यक्रम का तथा अधिगम सामग्री का विकास, जो विभिन्न समूहों के बच्चों के जीवन की स्थितियों और जरूरतों के संदर्भ में प्रासंगिक हों, न केवल औपचारिकेतर बल्कि औपचारिक शिक्षा की सारिणियों के लिए भी।

परियोजना के कार्यान्वयन की समय सूची

‘प्राइमरी शिक्षा तक अधिकाधिक लोगों की पहुंच’ परियोजना के अंतर्गत आधारभूत गतिविधियों को तीन चरणों में पूरा किया जाता है। प्रथम चरण में वह गतिविधियां शामिल हैं जिनके द्वारा पर्याप्त विविधता और मात्रा में अधिगम घटनाओं का विकास, उत्पादन तथा प्रकाशन होता है। द्वितीय चरण में वे गतिविधियां शामिल हैं जिनका संबंध अधिगम केंद्रों की स्थापना/उनको अपनाने तथा उनके संचालन से है। तीसरे चरण में वे सारी गतिविधियां आती हैं जिनसे मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना और प्रत्यायन सेवाएं संचालित होती हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों, अरुणाचल प्रदेश तथा पांडिचेरी के अलावा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता हो चुका है। लेकिन गतिविधियों की समय सूची में एकरूपता का अभाव है क्योंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजना की गतिविधियां एक ही समय में नहीं आरंभ हुई हैं। दस राज्यों तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने 1979 में अपनी गतिविधियां शुरू कीं, सात राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 1980 में, एक राज्य ने 1981 में, दो राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश ने 1982 में तथा एक राज्य ने 1983 में गतिविधियां चालू की गईं। त्रिपुरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली को अभी अपनी गतिविधियां आरंभ करनी हैं।

पूरी की गई अधिकांश गतिविधियां

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहाँ परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है, परियोजना के प्रथम चरण से संबद्ध गतिविधियां प्रगति पर हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान चलाई गई अधिकांश गतिविधियों में नीचे लिखी बातें शामिल हैं—

- प्रशिक्षण-उत्पादन पद्धति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्यों की बैठकें और अधिगम सामग्री प्रारूप का अध्यापक प्रशिक्षार्थियों द्वारा विकास।

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के अध्यापक शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा अधिगम घटनाओं की विकास प्रणाली में सेवाकालीन अध्यापकों का प्रशिक्षण ।
- उन शिक्षार्थियों के लिए जिनकी पठन योग्यता निम्न है अथवा जिनमें इसका नितांत अभाव है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के अध्यापक शिक्षकों का अधिगम सामग्री की विकास पद्धति संबंधी प्रशिक्षण और विभिन्न विषय क्षेत्रों और विभिन्न विषयों की क्षमताओं का अधिगम घटना से एकीकृत करने वाली पद्धति के बारे में प्रशिक्षण ।
- अधिगम घटनाओं के लिए चित्रों के विकास की पद्धति पर कला अध्यापकों और कलाकारों का प्रशिक्षण ।
- 'प्राइमरी शिक्षा तक अधिकाधिक लोगों की पहुँच' परियोजना के नियोजन और प्रबंध पर प्रखंड तथा जिला शिक्षा अधिकारियों का अभिविन्यास ।
- सुधार और परिष्कार के लिए अधिगम घटना प्रारूप की छटाई ।
- प्रकाशन के लिए चुनी गई अधिगम घटनाओं का संस्कार-सुधार ।
- प्रकाशन के लिए चुनी गई अधिगम घटनाओं के मूल्यांकन तथा उनको अंतिम रूप देने के लिए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सलाहकार मंडल की बैठकें ।
- अधिगम घटनाओं का मुद्रण/प्रकाशन ।

भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति

तीस राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/डी० एस० ई० आर० टी०/एस० आई० ई० आर० टी० और 980 प्राथमिक अध्यापक शिक्षण संस्थान/सेवाकालीन प्रशिक्षण केंद्र देश में 'प्राइमरी शिक्षा तक अधिकाधिक लोगों की पहुँच' परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के प्राचार्यों की 23 बैठकें हुईं। इन बैठकों का उद्देश्य था, अधिगम घटना के प्रारूप को विकसित करने के लिए प्रशिक्षार्थी अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण के साथ उत्पादन प्रणाली का आरंभिक मूल्यांकन करना। इन बैठकों में कुल मिलाकर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के 671 प्राचार्यों ने हिस्सा लिया। अधिगम घटनाओं की विकास प्रणाली में, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के 224 अध्यापक शिक्षकों और 368 सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के 220 अध्यापक शिक्षकों को अधिगम घटनाओं के परिष्कार प्रणाली में प्रशिक्षित किया गया तथा 448 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को ऐसे विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री विकसित करने में प्रशिक्षित किया गया जिनकी पठन क्षमता या तो बहुत निम्न है अथवा पठन क्षमता जिनमें है ही नहीं। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों से संबद्ध क्षमताओं को संयोजित करने की प्रणाली में भी प्रशिक्षित किया गया, जिन विषयों की अधिगम घटनाओं में आवश्यकता पड़ती है। इस परियोजना के नियोजन तथा प्रबंध में जिला स्तर के तथा प्रखंड स्तर के 351 अधिकारियों को अभिविन्यस्त किया गया। अधिगम घटनाओं के लिए चित्रों के विकास की पद्धति में 156 कला-

कारों/कला अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। 40 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवाकालीन शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया जिनकी संख्या 739 थी। इसका उद्देश्य अधिगम घटनाओं के प्रारूप को छांटकर चुनना था जिन्हें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवाकालीन अध्यापकों ने विकसित किया था। वर्ष 1983-84 के दौरान 67 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इनमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के 1106 अध्यापक शिक्षकों ने प्रकाशन के लिए चुनी गईं अधिगम घटनाओं के सुधार और परिष्कार में हिस्सा लिया। लगभग 300 प्रमाण प्रकाशन के लिए सुधारे तथा परिष्कृत किए गए। इन प्रमाणों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक प्रशिक्षार्थियों और सेवाकालीन अध्यापकों ने विकसित किया था। अधिगम घटनाओं का मूल्यांकन कर उन्हें स्वीकार करके अंतिम रूप देने के लिए, ताकि वे प्रकाशित की जा सकें, परामर्शदाता मंडल की राज्य स्तर पर 12 बैठकें हुईं। प्रतिवेदनकालीन अवधि के दौरान 474 अधिगम घटनाएं (कैप्सूल के रूप में) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम में प्रकाशित की गईं।

समुदाय शिक्षा और सहभागिता में

विकासात्मक गतिविधियां

परियोजना के उद्देश्य

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं—नए प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों का विकास और उनकी परीक्षा करना जो ऐसे बड़े समूहों की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति करने वाला संभाव्य माध्यम बन सके जो समूह वर्तमान समय में आंशिक या पूर्णरूपेण किसी भी तरह की शिक्षा से वंचित हैं। यह दृष्टिकोण इस प्रतिज्ञा पर आधारित है कि बच्चों की शिक्षा की सार्थकता इस बात में है कि इसका विकास तथा इसमें परिवर्तन बच्चों के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में परिवर्तन से मेल खाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति पूरे समुदाय को शिक्षित और प्रोत्साहित करके हो सकती है। इसका निहितार्थ यह है कि न केवल प्राक्-विद्यालयीन तथा विद्यालय के बाहर के बच्चों की, बल्कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा माताओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावशाली तरीके से की जाए।

इसी से संबद्ध उद्देश्य यह भी है कि इस बात की परीक्षा की जाए कि विद्यालय तथा समुदाय के द्वन्द्वात्मक विभाजन को समाप्त करने से क्या विद्यालय समुदाय का सहायक बन सकता है, ताकि समुदाय के अन्य क्षेत्रों में विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सके।

इसलिए यह परियोजना औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम को इस तरह संगठित करने की सोचती है कि यह आयु वर्ग 0-3 तथा माताएं, 3-6, 6-14 और 15-35 तथा वयस्कों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चुने गए समुदायों में से प्रत्येक में उपलब्ध सुविधाओं का कैसे प्रभावी उपयोग किया यह इस परियोजना के सामने चुनौती है। यह उपयोग उन कल्याणकारी संस्थाओं तथा विभिन्न विभागों द्वारा पहले से ही चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से होना है।

यह परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाए गए विस्तृत औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम नीति के अनुरूप है। इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित कार्यक्रम और गतिविधियां जनता के 'रहन-सहन और जीवन' को सुधारने के उदार उद्देश्य की पूर्ति करती है, यह उनकी स्वैच्छिक सहभागिता के आधार पर होता है। यह न्यूनतम अधिगम जरूरत पेटिकाओं को पूरा करने की क्षमता भी प्रदान करती है।

इस परियोजना के आयामों में एक आयाम है—समुदाय के सदस्यों में आवश्यक ज्ञान तथा दक्षता का विकास, जिससे वे विविध विकासात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। समुदाय की शैक्षिक गतिविधियों में ही विकासात्मक कार्यक्रम अनुभूत हैं। देश के प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से यह परियोजना बल प्रदान करती है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए, खासतौर से 6-14 और 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए औपचारिकतर शिक्षा की युक्तियों तथा सामग्री को विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्वीकृत/परिष्कृत कर सकते हैं।

यह परियोजना शिक्षा के प्रति समुदाय के सदस्यों में रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास को सुनिश्चित करती है। जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ कर चले गए हैं अथवा जिनको स्कूल जाने का कभी अवसर नहीं मिला, उनकी औपचारिकतर शिक्षा द्वारा मदद दी जाती है ताकि वे शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश कर सकें अथवा कार्यसाधक शिक्षा प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में प्रसवपूर्व मां की देख-भाल तथा प्रसवपूर्व बच्चे की हिफाजत, बाल अनुरक्षण तथा पोषण, कुछ आर्थिक गतिविधियां और गृह प्रबंध आदि बातें शामिल हैं। बच्चों के लिए प्राक्-विद्यालयीन कार्यक्रम उनमें स्कूल जाने की दिलचस्पी तथा उचित रख पैदा करने में मदद करते हैं। रचनात्मक गतिविधियों तथा खेल पद्धति के जरिए प्राक्-विद्यालयीन बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता है।

आयु वर्ग 6-14 वर्ष के औपचारिकतर कार्यक्रमों का लक्ष्य है—उन बच्चों को अंशकालिक शिक्षा प्रदान करना जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं अथवा स्कूल जाने का जिन्हें अवसर नहीं मिल सका है। यह आशा की जाती है कि बच्चे अकादमिक शिक्षा में दक्षता और ज्ञान हासिल करेंगे और इसके साथ ही सामाजिक रूप से उपयोगी तथा उत्पादक कार्य और पारिवारिक पेशे में भी वे कुशल बनेंगे। यदि इनमें से कुछ बच्चे औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश करना चाहते हैं तो इससे उनको मदद मिल सकती है।

स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य है कि उनमें पढ़ने-लिखने की योग्यता और दक्षता पैदा हो और साथ में हिसाब-किताब की कार्यसाधक साक्षरता हो। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम है; स्वस्थ रहन-सहन की जानकारी देना, कृषि तथा कृषि से इतर प्रकार का ज्ञान प्रदान करना तथा उनमें विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति अनुकूल रख पैदा करना। इस प्रकार यह परियोजना सामुदायिक कार्य द्वारा सामाजिक रूपांतरण के लिए अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना, जो विभिन्न समूहों को ध्यान में रख कर बनती हैं, और विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का विकास आदि को, स्थानीय पर्यावरण तथा शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर हाथ

में लिया जाता है। इसके लिए समुदाय का पहले विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है।

परियोजना का कार्यान्वयन

मूलतः यह परियोजना 1976 में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षण के तौर पर हाथ में ली गई थी। इस काम के लिए राज्यों में सामुदायिक केंद्र खोले गए। यह केंद्र अत्यंत गरीब, ग्रामीण, जनजातीय तथा पहाड़ी इलाकों में तथा नगर के गरीब क्षेत्रों में स्थित हैं। इस परियोजना के नतीजों से प्रोत्साहित होकर 1981 में सामुदायिक केंद्रों की संख्या बढ़ाकर चौदह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2 से 4 या 5 कर दी गई। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़ कर जिसने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया) में प्रत्येक में दो सामुदायिक केंद्र स्थापित किए गए। इस प्रकार सामुदायिक केंद्रों की संख्या 28 से बढ़ कर 102 हो गई ताकि सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले बड़े समूह को शिक्षित किया जा सके और प्रत्येक समुदाय की आवश्यकता के अनुकूल औपचारिकतर शिक्षा का उचित प्रतिदर्श विकसित किया जा सके। दिसंबर 1983 तक इनमें से 99 केंद्र स्थापित किए जा चुके थे। इनके अतिरिक्त 9 और केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति मिल चुकी है, तमिलनाडु में 5, मध्य प्रदेश में 3 और उड़ीसा में 11, इनमें काम करने वाले समुदाय कार्यकर्त्ताओं के मानदेय का बोझ राज्य सरकारों को उठाना था। इनमें से चार केंद्र यानी तीन मध्य प्रदेश में तथा एक उड़ीसा में पहले से ही अस्तित्व में आ चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि 1984 तक तमिलनाडु के सामुदायिक केंद्र भी काम करने लग जाएंगे।

विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए, जो इस परियोजना में आते हैं, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तरह-तरह के औपचारिकतर शिक्षा के प्रतिरूप विकसित किए जा रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों की जरूरत के मुताबिक तथा सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित करके इन प्रतिरूपों को बनाया गया है। इन केंद्रों में विकसित प्रणाली और सामग्री को उपलब्ध प्रतिपुष्टि आंकड़ों के आधार पर सुधारा जा रहा है।

भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परियोजना संयोजकों और समुदाय कार्यकर्त्ताओं के लिए तीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य था परियोजना के विभिन्न पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। केंद्रों की वास्तविक तस्वीर पेश करने के लिए समुदाय कार्यकर्त्ताओं को इन पाठ्यक्रमों में आमंत्रित किया गया जिसमें उनको विभिन्न आयु वर्ग की गतिविधियों और कार्यक्रमों के संगठन के बारे में, तथा केंद्रों की दिक्कतों के बारे में सूचना देनी थी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर प्रखंड अधिकारियों और परियोजना संयोजकों के तीन अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें शिक्षा और विकास कार्यक्रमों से संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। इस बात को सुनिश्चित करना इन सबका उद्देश्य था कि विकासात्मक गतिविधियों में जनता की अधिकाधिक भागीदारी हो सके।

कई केंद्रों पर केंद्र की गतिविधियों में समुदायों ने दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी है। कुछ राज्यों में केंद्रों के लिए विकसित की गई सामग्री को औपचारिकतर शैक्षिक कार्यक्रमों में व्यापक इस्तेमाल के लिए अपनाया जा रहा है।

परियोजनाओं का संचारेक्षण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का सामुदायिक शिक्षा दल इस परियोजना का राष्ट्रीय स्तर पर संचारेक्षण करता है तथा राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तथा ग्राम स्तर के अधिकारियों द्वारा राज्यों में इसको क्रियान्वित किया जाता है। एक दम आधारभूत स्तर के कर्मचारी जैसे अध्यापक, सामुदायिक कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य, सामुदायिक विकास केंद्रों में कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में लगे रहते हैं।

परियोजना का मूल्यांकन

इस समय परियोजना का आंतरिक मूल्यांकन चल रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने मूल्यांकन के उपकरण विकसित किए हैं, जिसको आवश्यक परिष्कार के साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना के बाहरी मूल्यांकन का काम पहले ही एक बाहरी संस्था को सौंपा गया है।

औपचारिकेतर शिक्षा

जुलाई 1978 में परिषद् ने औपचारिकेतर शिक्षा का काम हाथ में लिया। इस क्षेत्र में मुख्य जोर निम्नांकित बातों पर रहा है—अनुसंधान करना, अवधारणात्मक और शैक्षिक सामग्री का विकास, बैठकें और अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन और 'औपचारिकेतर शिक्षा' समाचार पत्र द्वारा सूचनाओं का प्रचार प्रसार और औपचारिकेतर शिक्षा के संसाधन केंद्रों द्वारा सूचनाओं का प्रसार। परिषद् मूलसामग्री भी तैयार करती है। देश के विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश इस समय इनका उपयोग कर रहे हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने औपचारिकेतर शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित कार्य संपन्न किए।

अनुसंधान

हिंदी शब्दावली का संकलन और भाषिक विश्लेषण

परियोजना के संबंध में 1982 में रिपोर्ट तैयार की गई और विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं में वितरित की गई। वही प्रेस को भी दी गई है। वर्ष 1983-84 के दौरान 15,197 शब्दों की विशाल सूची तैयार करवा कर वितरित की गई है। इसमें 12 प्रकार की बारंबारता का निर्देश है जिसका आधार शब्दावली के प्रकार, स्तर, क्षेत्र तथा लिंग हैं। दूसरी बड़ी सूची वर्णक्रम से तैयार की जा रही है इसमें बारंबारता का आधार दूसरे प्रकार का है। इस परियोजना के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों में 32 और सूचियों को शामिल किया गया है। इनको उनके शब्दों के वैयाकरणिक, संरचनात्मक तथा अर्थवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर इसमें लिया गया है। इस बात की उम्मीद की जाती है कि ये सूचियां विशेषज्ञ पाठकों, शैक्षिक सामग्री के लेखकों, परीक्षण निर्माताओं तथा अनुसंधान करने वालों के लिए उपयोगी होंगी।

औपचारिकेतर शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन

औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई शैक्षिक सामग्री के मूल्यांकन के लिए उपकरणों का विकास करना इस परियोजना का उद्देश्य है। इसके लिए निम्नांकित उपकरण विकसित किए गए हैं। 5 तथा 6 जुलाई 1983 को हुई नियोजन दल के सदस्यों के सुझाव के आधार पर इनमें सुधार किया जा रहा है।

- (i) विश्लेषण के लिए प्रोफार्मा।
- (ii) विश्लेषण प्रोफार्मा को भरने के लिए निर्देश पुस्तिका।
- (iii) मूल्यांकन के पहलू और कसौटी।
- (iv) अध्यापकों के लिए साक्षात्कार सारणी।
- (v) पुस्तक की पहचान का ब्योरा।

यह भी सुझाया गया है कि एक परिचय पुस्तिका तैयार कराई जानी चाहिए जिसमें निम्नांकित सामग्री होगी—

- (i) औपचारिकेतर शिक्षा की अवधारणा और उसका स्वरूप।
 - (ii) औपचारिकेतर शिक्षा के प्रति विभिन्न दृष्टियाँ।
 - (iii) शैक्षिक उद्देश्य अध्यापन का उद्देश्य।
 - (iv) शिक्षण सामग्री के मूल्यांकन की पद्धति और प्रक्रिया।
 - (v) मूल्यांकन के उपकरण।
 - (vi) आंकड़ों की व्याख्या तथा आंकड़ों का उपयोग।
- परिचय पुस्तिका को तैयार किया जा रहा है।

औपचारिकेतर शिक्षा की विभिन्न दृष्टियों/व्यक्तियों की पहचान

इस परियोजना का उद्देश्य औपचारिकेतर शिक्षा की विभिन्न दृष्टियों/परंपराओं की पहचान करना है जिसका अनुपालन हिंदी भाषी उन राज्यों में किया जा रहा है जो 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित औपचारिकेतर शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं—

निम्नांकित व्यक्तियों से आंकड़े एकत्र करने के लिए पांच प्रश्नावलियाँ बनाई गई हैं—

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निदेशक/संसाधन व्यक्ति।
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी।
3. औपचारिकेतर शिक्षा के प्रभारी अधिकारी।
4. पर्यवेक्षक।
5. केंद्र के अध्यापक।

प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर इन प्रश्नावलियों को संशोधित किया गया है। बाद में राज्यों के शिक्षा विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामुदायिक केंद्रों में वितरित किया गया। आंकड़ों के आधार पर तीन अलग-अलग प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं।

विकास

मिडिल स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की औपचारिकेतर

शिक्षा की शिक्षण सामग्री का विकास

नवंबर, 1982 में औपचारिकेतर शिक्षक के मिडिल स्तर का पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास के लिए परिषद् ने एक परियोजना हाथ में ली। परियोजना का मुख्य कार्य शिक्षण सामग्री का निर्माण (जिसमें पाठ्यक्रम शामिल है), हिंदी, प्राकृतिक विज्ञान, समाज-विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान तथा एस. यू. पी. डब्ल्यू. में अधिगम सामग्री तथा सहायक सामग्री तैयार करना है। औपचारिकेतर शिक्षा संबंधी (विशेष) दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है जिसमें लक्ष्य समूह के स्तर, अध्यापक की पृष्ठभूमि, समय की सीमा तथा उपलब्ध संसाधनों की ओर ध्यान दिया गया है। समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए समाज विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान में 82 समग्र पाठ तैयार किए गए हैं। समाज विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान के 52 पाठ विषय की दृष्टि से तैयार कराए गए। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के लिए गणित के 9 पाठ तैयार हैं। साल के हिसाब से सामग्रियों को संयोजित किया गया है। भाषा की पुस्तकों की योजना पहले ही बन चुकी है तथा पाठ तैयार किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में सीखने वाले के अनुभव की अविरलता पर बल दिया गया है। जीवन तथा रहन-सहन की विकसित प्रक्रिया तथा तकनीक से सीखने वाले का साक्षात्कार करना, विविध अधिगम क्षेत्रों की ऊर्ध्वाधर तथा क्रमागत एकता, विषयों की गुणात्मक एकता द्वारा पाठ्यक्रम के मात्रात्मक दबाव को कम करना जैसी बातों पर भी इसमें बल दिया गया है। इन अधिगम सामग्रियों की कुछ नवाचारी अथवा प्रवर्तनकारी विशेषताएँ नीचे दी गई हैं—

- तरह-तरह की रचना विधाओं को आधार बनाकर सामग्री विकसित की गई है; जैसे, कहानी, वार्तालाप, यात्रावृत्त, कविता, वर्णन, अनुभव तथा गतिविधि पर आधारित प्रस्तुतीकरण।
- सीखने वाले के स्तर और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सामग्री की भाषा का चुनाव किया गया है।
- मूल्यांकन वाले प्रश्नों में निम्नांकित बातें शामिल हैं—विषय वस्तु से संबंध रखने वाले सवाल, ज्ञान को व्यावहारिक स्तर पर प्रस्तुत करने वाली गतिविधियाँ तथा भाषा की योग्यता को जांचने के लिए अभ्यास।
- इससे ऐसे अवसर उपलब्ध होते हैं जिसमें बच्चे अपने अवधारणात्मक ज्ञान को रोजमर्रा की गतिविधियों से एक करके उसका अर्थ समझता है। विभिन्न विषयों में आपसी एकता स्थापित होती है तथा विषय और भाषा के बीच ऐक्य स्थापित होता है।

प्रारंभिक स्तर के लिए उर्दू में औपचारिकेतर

शिक्षा की शिक्षण सामग्री का विकास

औपचारिकेतर शिक्षा दल ने प्रारंभिक स्तर की औपचारिकेतर शिक्षण सामग्री तैयार करने

की परियोजना हाथ में ली है। दस पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं, इनमें समस्या और जरूरतों पर आधारित पाठ्यक्रम, अध्यापक निर्देशिका, तीन भाषा रीडर तथा उनकी निर्देशिकाएं, गणित की पुस्तक तथा प्रशिक्षण निर्देशिका शामिल हैं। इनमें से 9 पुस्तकें प्रकाशित भी की जा चुकी हैं। समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए 1983-84 के दौरान दूसरी पुस्तकें जिनमें भाषा विषयक पाठ, समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान शामिल हैं, तैयार की जा रही थीं।

प्रशिक्षण

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों के क्षेत्र कमियों के लिए संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम 17 फरवरी से 3 मार्च 1984 तक आयोजित किया गया। राज्य में औपचारिकतर शिक्षा के लिए काम करने वाले सरकारी और स्वैच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय था, काम चलाऊ उपागमों/उक्तियों पर विचार-विमर्श करना जिसे प्राइमरी स्तर पर भाषा, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान तथा सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य के लिए अपनाया जाना था। इस कार्यक्रम में एक स्तर संबंधी पत्रा तैयार किया गया जिसमें प्राइमरी स्तर के विभिन्न औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों में विषयों के अध्यापन की चर्चा थी। कार्यदल ने मिडिल स्तर की शिक्षा के विषय में भी थोड़ा बहुत विचार-विमर्श किया और अस्थाई रूपरेखा भी तैयार की गई।

विस्तारण

औपचारिकतर शिक्षा पत्रिका संसाधन केंद्र

औपचारिकतर शिक्षा पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशन है। पत्रिका का उद्देश्य है, अनुभवों का आदान-प्रदान करना, विभिन्न नवाचारी प्रथाओं और विचारों के विषय में सूचनाएं प्रसारित करना तथा औपचारिकतर शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं, मुद्दों को विशेष महत्व देना। एक वर्ष के दौरान पत्रिका के चार अंक प्रकाशित हुए। पुस्तक समीक्षाओं, शोध संक्षेपण, औपचारिकतर शिक्षा संबंधी सूचनाओं के अतिरिक्त चारों अंकों में लेख भी प्रकाशित किए गए जैसे औपचारिक तथा औपचारिकतर शिक्षा के मध्य की शृंखलाएं 'औपचारिकतर शिक्षा की समस्याएं और मुद्दे' मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के औपचारिकतर शिक्षा संबंधी अनुभव।

औपचारिकतर शिक्षा संसाधन केंद्र, भारत तथा भारत के बाहर शिक्षण संस्थाओं तथा अभिकरणों से मिलने वाली शिक्षण सामग्रियों तथा प्रतिवेदन का रख-रखाव करता है। महत्वपूर्ण सूचनाओं और सामग्री को इस्तेमाल करने योग्य रूप में संहिताबद्ध किया गया है ताकि औपचारिकतर शिक्षा में काम करने वाले लोग और अनुसंधान करने वाले इसका सही उपयोग कर सकें।

समायोजन

औपचारिकतर शिक्षा की समायोजन समिति की दो बैठकें वर्ष 1983-84 के दौरान हो

चुकी है। पहली बैठक 13 सितंबर 1983 को तथा दूसरी बैठक 30 दिसंबर 1983 को हुई। पहली बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की विभिन्न इकाइयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ और इसने कार्यक्रम परामर्श-दात्री समिति के समक्ष सिफारिशें रखीं। दूसरी बैठक में नीति और देश में औपचारिकेतर शिक्षा के कार्यक्रम विकास संबंधी मसलों पर विचार किया गया।

वार्षिक सम्मेलन

28 और 29 फरवरी 1984 को औपचारिकेतर शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, एन०सी० ई०आर०टी० में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य के औपचारिकेतर शिक्षा के प्रभारी संयुक्त निदेशकों तथा प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों आदि से एक-एक अधिकारी को आमंत्रित किया गया। प्राइमरी तथा मिडिल स्तर की समस्याओं और मुद्दों पर विचार किया गया और सम्मेलन में अनेक बहुमूल्य सिफारिशें सामने आईं। औपचारिकेतर शिक्षा पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन, जिसमें राज्यों के कार्यक्रमों का विवरण था, सम्मेलन में रखा गया।

‘प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण’ कार्यक्रम का संचारेक्षण और मूल्यांकन

पहले से चली आ रही एक परियोजना के अंग के रूप में ‘प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण’ कार्यक्रम के संचारेक्षण और मूल्यांकन के लिए उपकरणों का विकास किया गया है। वर्तमान आधारित ढांचे के भीतर और स्वाभाविक स्थितियों में इन उपकरणों की प्रभाविता और उपयोगिता को अभी परखा जाना है। इस बात को ध्यान में रखकर पूर्व परियोजना का अनु-परीक्षण कार्य जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में हाथ में लिया गया। इन उपकरणों के प्रयोग के लिए तीन राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक जिले को चुना गया—जम्मू और कश्मीर में बड़गांव जिला, उड़ीसा का नयनगढ़ जिला तथा राजस्थान का उदयपुर जिला। उपकरणों के प्रयोग के लिए इन जिलों के चुनाव का मुख्य आधार इनका पिछड़ा-पन था।

वर्तमान उपक्रम में स्कूल/औपचारिकेतर शिक्षा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जिला और राज्य स्तर पर शिक्षा के औपचारिक तथा औपचारिकेतर दोनों ही क्षेत्र शामिल थे। औपचारिकेतर शिक्षा केंद्रों के अलावा समस्त संचारेक्षण कार्यों का समय तथा सूचना हर स्तर पर त्रैमासिक बरकरार रही। औपचारिकेतर शिक्षा केंद्रों के कार्यक्रमों का संचारेक्षण मासिक आधार पर करने का प्रयास किया गया लेकिन यह केवल प्राथमिक स्तर पर ही किया गया। प्रखंड तथा उससे आगे के स्तर पर औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम का संचारेक्षण कार्य भी त्रैमासिक आधार पर हो सका।

इस योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रवर्तन पक्ष हर स्तर पर त्रैमासिक बैठकों का आयोजन था—इन्हीं बैठकों में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक अधिकारी ने अपने ऊपर के अधिकारी को संचारेक्षण प्रतिवेदन दिया जिन लोगों ने इन बैठकों का संयोजकत्व किया। इन

बातों के अलावा लिखित संप्रेषण तथा मौखिक बहसों, जिनमें समस्याओं और कठिनाइयों तथा उन पर काबू पाने के लिए उपायों पर विचार किया गया, काफी उपयोगी साबित हुई; खास तौर पर दिक्कतों के निदान में तथा उनके उपचार के लिए तत्काल उठाए कदमों की दृष्टि से, साथ में पहले की नीतियों में सुधार लाने और निर्णयों को बदलने या नए निर्णय करने की दृष्टि से इनकी अधिक उपयोगिता थी। कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर से 612, उड़ीसा से 311, राजस्थान से 557 लोगों ने 3 योजनाओं, 8 अभिविन्यासों, 2 मासिक समीक्षाओं तथा 9 त्रैमासिक बैठकों में भाग लिया जो तीन राज्यों में जिला स्तर तथा प्रखण्ड स्तर पर हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली परिसर में 12 तथा 13 अक्टूबर 1983 को उन राज्यों के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक हुई जो इस परियोजना में शामिल थे। बैठक के दौरान ऐसा महसूस किया गया कि मौजूदा आधारित ढांचे के अंतर्गत उपकरण काफी उपयोगी, सही और बाधारहित साबित हुए थे। इसमें यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो बस इस बात की, कि इसके विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं का एक दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया जाए।

अनुसंधान अध्ययन

(1) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विभिन्न शैक्षिक धाराओं और परंपराओं का अध्ययन (1947-80)

यह अध्ययन निम्नलिखित विभिन्न चार (शैक्षिक वैचारिक) धाराओं से संबंधित है:

1. हिंदू योग साधना शैक्षिक विचार।
2. मनोविश्लेषणात्मक विचार।
3. गांधीवादी शैक्षिक विचार।
4. मार्क्सवादी शैक्षिक विचार।

निम्नलिखित तीन विचार सारणियों के साहित्य का अध्ययन पूरा कर लिया गया है:

1. हिंदू योग साधना शैक्षिक विचार।
2. मनोविश्लेषणात्मक विचार।
3. गांधीवादी शैक्षिक विचार सारणी।

मार्क्सवादी विचार सारणी से संबंधित साहित्य तैयारी के दौर में है।

(2) प्राइमरी स्तर की विज्ञान, समाज विज्ञान तथा भाषा की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की सुबोधता पर मनोसामाजिक घटकों के प्रभाव का अध्ययन

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे—पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की सुबोधता पर सामाजिक, आर्थिक हैसियत तथा प्रतिभा का प्रभाव देखना। कक्षा तीन के बच्चों के भाषा के बोध को जाँचने के लिए विज्ञान, समाज विज्ञान तथा हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर तीन

पृथक-पृथक परीक्षण तैयार किए गए। इन परीक्षणों को नमूने के तौर पर 200 बच्चों के ऊपर किया गया और अंतिम रूप से राजस्थान राज्य के 400 बच्चों के ऊपर इनको आजमाया गया। राजस्थान सरकार ने पाठ्यपुस्तकें तैयार कराकर पाठ्यक्रम में लगवाई थीं।

इन बच्चों की प्रतिभा को मापने के लिए रेवेन का 'प्रगतिशील सांचा' (रंगीन) इस्तेमाल किया गया। एस०पी० कुलश्रेष्ठ का सामाजिक आर्थिक स्तर मापक पैमाना इन बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्तर जानने के लिए लागू किया गया। नमूने के तौर पर दोनों लिंगों के 50% बच्चों को लिया गया। इन बच्चों में आधे ग्रामीण क्षेत्रों के और आधे नगरों के बच्चे थे। आंकड़ों को संगणक में परखा जा चुका है तथा इसकी रिपोर्ट तैयार होने की प्रक्रिया में है।

आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि ग्रामीण तथा नगरीय बच्चों की उस भाषा की समझदारी में काफी अंतर है जो तीनों विषयों की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में इस्तेमाल की गई हैं। फिर भी लिंग भेद का भाषा की समझ-स्तर पर कोई असर नहीं है। प्रतिभा के कारण उच्च, मध्यम तथा निम्न स्तर के बच्चों में भाषा की समझदारी के बारे में महत्वपूर्ण अंतर सामने आए हैं। इन तीनों वर्गों में आपस में भी 't' मूल्य के .01 स्तर पर महत्वपूर्ण फर्क दिखाई पड़ते हैं। इनमें सबसे अधिक अंतर भाषा की पाठ्यपुस्तकों का, उसके बाद समाज विज्ञान और अंत में विज्ञान की पुस्तकों को समझने का है। इन तीनों विषयों की भाषा की समझदारी पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों का कोई असर नहीं है। इसी तरह अभिभावकों की आय का भाषा की समझदारी से गहरा ताल्लुक नजर आता है। लेकिन परिवार का प्रकार, संयुक्त परिवार छात्रों की भाषा समझ के स्तर को किसी भी तरह प्रभावित करते नजर नहीं आते हैं।

आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण, जो इस समय चल रहा है, पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की समझदारी के बारे में आगे चलकर संयुक्त चरों के प्रभाव को स्पष्ट कर सकती है।

5

वंचित वर्ग की शिक्षा

समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा, विशेषरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हमारी शैक्षिक चिंता का प्रमुख विषय रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इन बच्चों के इस्तेमाल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता रहा है तथा शिक्षण सामग्री बनाता रहा है और शोध भी कराता रहा है। उसने वंचित वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा सहायक सामग्री तैयार कराई।

परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों में इन बच्चों की समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। 'प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण' नामक पूर्ववर्ती अध्याय में इस बात की पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विशेषरूप से जहाँ पर पी० ई० सी० आर० परियोजना का संदर्भ आया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने कई विशेष प्रकार के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। इन कार्यक्रमों से समस्या वाले क्षेत्रों को जानने में मदद मिली है। इनसे

बच्चों की अधिगम समस्याओं का जानने तथा उचित शिक्षण सामग्री विकसित करने में भी मदद मिली है। विभिन्न स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भी यह सहायक रहा है।

(अ) अनुसंधान कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान निम्नांकित अध्ययन या तो हाथ में लिए गए अथवा उन्हें पूरा किया गया —

जनजातीय क्षेत्रों में औपचारिकतर कार्यक्रमों की पद्धतियों/ प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अध्ययन

पांच राज्यों, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में यह अध्ययन हाथ में लिया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि जनजातीय क्षेत्रों में औपचारिकतर शैक्षिक कार्यक्रम को चलाने में इन राज्यों में क्या पद्धतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ अपनाई जाती हैं। यह अध्ययन पूरा किया जा चुका है।

नागालैंड में अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास में समुदाय की हिस्सेदारी तथा उसकी प्रभाविता का स्वरूप तथा उसकी मात्रा

नागालैंड के कोहिमा जिले के पन्द्रह प्राइमरी, मिडिल, हाई/सेकेंडरी स्कूलों में इसका अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (i) शैक्षिक विकास कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी के स्वरूप और मात्रा का पता लगाना,
- (ii) शैक्षिक विकास में सामुदायिक भागीदारी की प्रभाविता का पता लगाना,
- (iii) शैक्षिक विकास कार्यक्रम में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के लिए जनजातीय समुदाय के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के रास्ते सुझाना। यह अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है।

जनजातियों की शिक्षा तथा उनकी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के अंतर्संबंधों का अध्ययन

निम्नांकित बातों का पता लगाना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं—(i) किस सीमा तक अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास हो चुका है, (ii) अनुसूचित जनजातियों में कहाँ तक सामाजिक आर्थिक गतिशीलता है, (iii) यदि सामाजिक आर्थिक गतिशीलता और शिक्षा के बीच कोई सह संबंध है तो उसका पता लगाना। यह अध्ययन कार्य बिहार राज्य के खारिया, मुण्डा तथा ओरांव जनजातियों के बीच चलाया जाएगा। आंकड़ा संकलन के उपकरण तैयार कर लिए गए हैं।

जनजातीय और जनजात्येतर क्षेत्रों की प्राइमरी पाठशालाओं की भौतिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन

इस अध्ययन का लक्ष्य यह है कि इसके माध्यम से इस बात का पता लगाया जाए कि

जनजातीय क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उन सुविधाओं की गैर-जनजातीय प्राइमरी पाठशालाओं को प्राप्त सुविधाओं से तुलना की जाए। आठ जिलों की बयालीस तहसीलों से आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं। इनमें चार जिले मध्य-प्रदेश और उड़ीसा के हैं। आंकड़ों के विश्लेषण तथा रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर था।

प्राइमरी स्तर के जनजातीय छात्रों के कमजोर और सबल बिंदुओं के निर्धारण के लिए उनके विषयवार निष्पादन का अध्ययन

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं—प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विषयवार निष्पादन का आकलन और उनके सबल और कमजोर बिंदुओं का निर्धारण करना, जिससे प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इस अध्ययन के लिए पाँच राज्यों—आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा को तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों—मिजोरम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को चुना गया। आंकड़ा संकलन का पहला चरण आरम्भ किया जा चुका है। उड़ीसा के आंकड़े संकलित हो चुके हैं तथा अन्य राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है।

उपचार के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से जनजातीय लड़कियों के निम्न नामांकन के कारणों का निर्धारण

इस अध्ययन का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना है जिससे जनजातीय लड़कियों का नामांकन बहुत कम हो पाता है, जिसके आधार पर इनको दूर करने के लिए उपचार सुझाए जा सकें। आठ राज्यों के तेरह जिलों में अध्ययन का यह कार्य किया जाएगा। इसके उपकरणों की तैयारी प्रगति पर थी और शीघ्र ही आंकड़े एकत्र करने का काम चालू हो जाएगा।

(ब) विकास कार्यक्रम

‘आंध्र प्रदेश के जनजातीय छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास का विश्लेषण’ के लिए कार्यदल की बैठक

हैदराबाद में कार्यदल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य था प्राइमरी स्तर पर प्रचलित वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना तथा आंध्र प्रदेश गोंड जनजाति के प्राइमरी स्कूल के छात्रों को ध्यान में रखकर एक सुधरे हुए पाठ्यक्रम का विकास। कार्यदल की बैठक 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 1983 तक हुई तथा इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधिकारी तथा आंध्र प्रदेश शिक्षा निदेशालय के शिक्षा विशेषज्ञ, राज्य शिक्षा संस्थान, आंध्र प्रदेश, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा जनजातीय संस्कृति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद के शिक्षाविद् थे। एक संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया गया और आंध्र प्रदेश सरकार के पास अगली आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

जनजातीय छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों की रचना

उड़ीसा की साओरा जनजाति के कक्षा II के बच्चों के लिए एक प्राइमर बनाने के उद्देश्य से 21 से 30 दिसंबर 1983 तक उड़ीसा राज्य के बरहामपुर में कार्यदल की एक बैठक आयोजित की गई। कार्यदल की बैठक में 23 लोग उपस्थित थे, इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त अध्यापक क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक भी थे। कार्यदल की बैठक के दौरान रावरा बोली में दो भागों में भाषा तथा गणित में एक पाण्डुलिपी तैयार की गई। इसकी लिपि उड़िया थी। साओरा जनजाति के बच्चों के लिए कक्षा II की प्राइमर को अंतिम रूप देने के लिए, दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 16 से 30 जनवरी 1984 तक कार्यदल की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया।

औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों के जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री की तैयारी

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल में 9 से 13 फरवरी 1984 के बीच कार्यदल की एक बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों के संथाल विद्यार्थियों के लिए एक प्राइमर को अंतिम रूप देना था। इस कार्यदल की बैठक में संथाली भाषा के आठ विशेषज्ञों तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लोगों ने भाग लिया।

जनजातीय क्षेत्रों की औपचारिकतर शिक्षा के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पेटिकाओं की तैयारी

देश में जनजातीय क्षेत्रों के औपचारिकतर शिक्षा के सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् जनजातीय क्षेत्रों की शिक्षा समस्याओं के विविध पक्षों पर एक प्रशिक्षण पेटिका बनाने जा रही है। इसको औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों के सभी अध्यापकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लेखकों द्वारा इस विषय के विविध पक्षों पर तैयार किए पत्रों को 26 मार्च से 28 मार्च 1984 के मध्य होने वाली कार्यदल की बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

(स) प्रशिक्षण कार्यक्रम

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 5 से 11 जनवरी 1984 तक जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय शिक्षा की समस्याओं और जनजातीय जीवन तथा संस्कृति से अध्यापक शिक्षकों को परिचित कराना था। आठ राज्यों के बीस लोगों ने इस प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया। ये राज्य थे—बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा।

जनजातीय क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में 3 से 9 फरवरी 1984 के मध्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अध्यापक शिक्षकों को जनजातीय क्षेत्रों की शैक्षिक समस्याओं तथा जनजातीय जीवन और संस्कृति से परिचित कराना था। नौ राज्यों के 27 अध्यापक शिक्षक इस पाठ्यक्रम में उपस्थित थे। वे राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा।

जनजातीय क्षेत्रों के औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

जनजातीय क्षेत्रों के औपचारिकतर शिक्षा के प्रमुख व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने दो अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। पहला पाठ्यक्रम 5 से 11 जनवरी, 1984 के बीच शिलांग में आयोजित किया गया। इसमें तीन राज्यों से 9 व्यक्तियों ने भाग लिया। दूसरा पाठ्यक्रम क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, भोपाल में 3 से 9 फरवरी 1984 के बीच आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों के 22 प्रमुख व्यक्ति इसमें उपस्थित थे। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य था—जनजातीय जीवन और संस्कृति में प्रमुख व्यक्तियों को अभिविन्यस्त करना और जनजातीय क्षेत्रों में औपचारिकतर शिक्षा को संगठित करने में अभिविन्यस्त करना।

साओरा प्राइमर के इस्तेमाल के लिए साओरा जनजाति के अध्यापकों का अभिविन्यास पाठ्यक्रम

परलेखमुंडी (उड़ीसा) में 3 तथा 4 अगस्त 1984 को परलेखमुंडी तथा गुनुपुर के दो शिक्षा जिलों के नमूने के स्कूलों के साओरा जनजाति के अध्यापकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कुल 104 शिक्षकों ने भाग लिया। साओरा प्राइमर को इस्तेमाल करने के लिए इनको अभिविन्यस्त किया गया (साओरा बोली में इस पाठ्यपुस्तक को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने तैयार किया था)। इस पाठ्यपुस्तक को जिले के नमूने के लिए चुने गए स्कूलों में लगाया गया था।

जनजातीय क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ने जनजातीय क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों के लिए दो अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। एक पाठ्यक्रम का आयोजन 16 से 30 जनवरी 1984 के बीच किया गया और इसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान से आए लोगों ने भाग लिया। दूसरा पाठ्यक्रम 16 फरवरी से 1 मार्च 1984 के दौरान आयोजित किया गया तथा इसमें 5 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये राज्य थे—गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

जनजातीय बोलियों में लिखी गई पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक डिजाइन तैयार करने के उद्देश्य से, गुजरात विद्यापीठ में 13 और 14 दिसंबर 1983 को एक बैठक हुई।

वंचित वर्ग के बच्चों की अधिगम समस्याओं के लिए

प्रमुख व्यक्तियों की राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने दिल्ली में 15 से 24 दिसंबर 1983 के बीच दस दिनों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य था बच्चों की अधिगम की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना, खासतौर पर वंचित वर्ग के बच्चों की समस्याओं को जानना। इसका उद्देश्य उन समस्याओं को पहचानने की समझ विकसित करना और प्रमुख व्यक्तियों को राज्यों में प्रशिक्षित करना भी था जो अपने राज्यों में अध्यापक शिक्षकों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर सकें। इसमें बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और चण्डीगढ़ के 11 वरिष्ठ अध्यापक शिक्षकों ने भाग लिया। उन्होंने प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा की ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा पाने वाले बच्चों की आवश्यकताओं और अधिगम समस्याओं को समझ सकें विशेष रूप से वंचित वर्ग के बच्चों की कुछ आधारभूत अवधारणाओं पर भी उन्होंने विचार किया। वंचित वर्ग के बच्चों की विशेषताओं पर विचार किया गया और उन वंचक तत्वों के प्रभाव से उन्हें मुक्त करने के उपायों पर भी विचार किया गया।

वंचित वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में पद्धति सिद्धांत को अपनाने की सिफारिश की गई। इस पद्धति का अर्थ लिया गया—दो या दो से भी अवयवों का एक अवयव के रूप में काम करना। निर्मांकित को आवश्यक उप-पद्धति के रूप में रेखांकित किया गया—प्रशासनिक उप-प्रणाली, शैक्षिक पाठ्यक्रम उप-प्रणाली, पोषणात्मक उप-प्रणाली, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा उप-प्रणाली, अभिभावकों का संबद्ध होना उप-प्रणाली, समुदाय का संबद्ध होना उप-प्रणाली।

छास तरह के अध्यापक छात्र व्यवहार को विकसित करने के लिए पूर्व-सेवा और सेवा-कालीन दोनों ही प्रकार के कार्यक्रम को वांछनीय माना गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण में 'पद्धति एप्रोच' की आवश्यकता होगी। इसमें क्षमता प्रतिभा पर आधारित कार्यक्रमों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हर व्यक्ति के व्यवसाय को उसके कार्य और आवश्यक योग्यता के हिसाब से परिभाषित किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के विषय थे—भाषा प्रतिभा के विकास की पद्धतियाँ और तकनीकें, गिनती की प्रतिभा तथा शिक्षण शैलियाँ।

उन्होंने, कक्षा को कैसे प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित किया जाए, यथार्थपरक तरीके से अनुशासन की समस्या से कैसे निपटा जाए तथा उनकी विविध उपलब्धियों (पहचान या संज्ञान संबंधी, प्रभाव संबंधी तथा मनोचालन संबंधी) को कैसे मापा जाए, आदि विषयों पर व्याख्यान दिए।

हिंदी भाषा का इस्तेमाल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने संथाल, मुण्डा, ओरांव तथा गोंड जनजातियों के लिए उनकी अपनी बोलियों और हिंदी में सहायक पुस्तकें तैयार कराई हैं। ये सहायक पुस्तकें इस समय प्रेस में छपने की प्रक्रिया में हैं।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और सहायक पुस्तकें

पाठ्यक्रम का विकास एक सतत और प्रवाहमान प्रक्रिया है और इसे नई और उभर कर सामने आने वाली जरूरतों के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा तथा इसे देश और विश्व की बदलती परिस्थितियों के साथ भी आगे बढ़ना होगा। पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं की समीक्षा करने और उन्हें उन्नत बनाने का काम, विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और उन्हें बेहतर बनाने के काम भी जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है, जारी है साथ ही और भी जोर-शोर से किया जा रहा है। कार्यक्रम के दबाव के सिलसिले में तथा अन्य क्षेत्रों में भी अध्ययन का काम चल रहा है। बढ़ती जरूरतों के साथ कदम मिला कर चलने की जरूरतों के अंतर्गत स्कूलों में कम्प्यूटर-चेतना के विकास जैसे नये क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वातावरण से संबंधित प्रशिक्षणों पर जोर दिया जाना जारी है। शिक्षा को मूल्यबोधी दिशा प्रदान करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

पाठ्यक्रम का विकास और अनुसंधान

स्कूली शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों

पर पाठ्यक्रम का दबाव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने छात्रों पर पाठ्यक्रम के दबाव के मसले की पड़ताल करने के लिए निदेशक डॉ० पी० एल० मलहोत्रा की अध्यक्षता में एक अध्येता-ग्रुप गठित किया। इस ग्रुप ने अध्ययन का काम दो चरणों में करने का फैसला किया। पहले चरण में सिर्फ केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली का अध्ययन किया जाना था, जबकि दूसरे चरण में छः और राज्यों के अध्ययन का प्रस्ताव था। केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में प्रत्यक्ष/गोचर-सर्वेक्षण के काम को अंजाम देने के लिए पाँच प्रश्नावलियाँ तैयार की गईं। माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के प्राधानाध्यापकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जो अध्ययन के नमूने में शामिल हैं। आंकड़े इकट्ठे करने का काम चल रहा है। अध्ययन की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में विचार-विमर्श किया जाएगा, और अगर जरूरी समझा गया तो पाठ्यक्रम में सुधार किए जायेंगे।

शिक्षा के प्रशिक्षणात्मक, विकासात्मक

तथा सामाजिक उद्देश्य के संदर्भ में

10+2 स्तर पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

आरम्भिक अध्ययन के लिए 15 अक्टूबर 1983 से “शिक्षा के प्रशिक्षणात्मक, विकासात्मक तथा सामाजिक उद्देश्य के संदर्भ में 10+2 स्तर पर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन” नाम से एक समर्थित प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य पाठ्यक्रम में संशोधन और सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना है। प्रोजेक्ट के खास उद्देश्य हैं—

- (i) यह निर्धारित करना कि क्या चालू पाठ्यक्रम से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है।
- (ii) शिक्षा के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में अभी इस्तेमाल की जा रही शिक्षण-पद्धतियों का मूल्यांकन। और
- (iii) छात्रों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की पड़ताल।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विषयानुसार प्रशिक्षणात्मक, विकासात्मक और सामाजिक उद्देश्यों की दृष्टि से दस स्कूली विषयों की पाठ्यवस्तु उन विषयों के शिक्षकों की सहायता से तैयार की गई। इन्होंने दस कार्यकारी ग्रुपों द्वारा हर विषय पर अलग-अलग आयोजित बैठकों में भी हिस्सा लिया, जो 24 जनवरी से 8 मार्च 1984 तक चलीं। प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से 28 शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

स्कूल-पाठ्यक्रम का कारगर इस्तेमाल

कुछ साल पहले “स्कूल-पाठ्यक्रम का कारगर इस्तेमाल” नामक एक विकास वे

अनुसंधान प्रोजेक्ट शुरू की गई और अब यह एकत्रित तथ्यों के विश्लेषण के आखिरी चरण में है। प्रोजेक्ट के विकासात्मक चरण के दौरान ठीक-ठाक मात्रा में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें कई प्रकाशित सामग्री हैं ; जैसे (i) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्य, (ii) पाठ्यक्रम और बच्चे का मनोविज्ञान, (iii) छात्रों के विकास के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण/शिक्षण-मनन के तौर-तरीके, (iv) स्कूल-पाठ्यक्रम के कारगर इस्तेमाल में सहयोगी गतिविधियों के बारे में, (v) स्कूल-पाठ्यक्रम के कारगर इस्तेमाल के शिक्षण-कौशल और (vi) छात्रों के विकास का मूल्यांकन। प्रयोगात्मक चरण में एक समानान्तर अध्ययन ग्रुप गठित किया गया, जिसका काम इस चीज का पता लगाना था कि प्रारम्भिक चरण में तैयार सामग्री में जो दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ठीक से व्यवहार में उतार पाते हैं या नहीं और कि ये बच्चों के विकास में, उन्हें बेहतर 'अध्येता', बेहतर 'व्यक्ति', बेहतर 'नागरिक' और बेहतर 'मेहनतकश' बनाने में कितना योगदान कर पाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु का अध्ययन—

यह अध्ययन बिल्ली और उसके आस-पास के विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों पर आधारित नहीं है

बच्चों को बेहतर 'व्यक्ति', बेहतर 'नागरिक' और बेहतर 'मेहनतकश' बनाने के लिए जरूरी वांछित, प्रभावी/भावनात्मक और क्रियात्मक विकास से जुड़ी क्षमताओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदतों और व्यवहारों के विकास में सहयोग की दृष्टि से स्कूल-पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु का यह अध्ययन शुरू किया गया। इस अध्ययन से इस तरह के पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु का स्तर और इसके प्रति शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों के रवैये, इस टाइप की अंतर्वस्तु के लागू करने में आने वाली दिक्कतें और इसे दूर करने के उपाय का पता चलने की उम्मीद है।

विभिन्न राज्यों में 10+2 शिक्षा-प्रणाली

के अन्तर्गत पाठ्यक्रम की स्थिति

तीन राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश (गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली) में स्कूली शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। प्रश्नावलियों और साक्षात्कारों आदि के माध्यम से इन राज्यों से जरूरी आंकड़े इकट्ठे किये जा चुके हैं। चारों राज्यों के कुछ चुने हुए स्कूलों का अध्ययन भी किया जा चुका है। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण हो चुका है और रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट का मसौदा संबंधित राज्यों के शिक्षा-अधिकारियों के पास उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए भेजा जा चुका है।

पाठ्यक्रम अनुसंधान केन्द्र और बुलेटिन

पाठ्यक्रम अनुसंधान केन्द्र देश और देश के बाहर की विभिन्न शैक्षिक एजेन्सियाँ और संगठनों से लगातार सम्पर्क बनाए हैं। पाठ्यक्रम पर काम करने वालों और शोधकर्ताओं के फायदे के लिए देश और देश के बाहर की विभिन्न पाठ्यक्रम एजेन्सियों से महत्वपूर्ण सूचनाएं और सामग्रियाँ एकत्र करके रखी गई हैं। केन्द्र के पास इस समय सारे राज्यों की तकरीबन सारी पाठ्यचर्याएं उपलब्ध हैं। ये संदर्भ और सूचना-प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। केन्द्र ने एक विशेष विवरणिका (ब्रोशर) निकाला है, जिसमें स्कूल-पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपयोगी सूचनाएं दी गई हैं। 1983-84 के दौरान तीन विवरणिकाएं (विवरणिका संख्या—6,7,8) निकाली गईं। “एन० सी० ई० आर० टी० के पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रोजेक्ट” नामक विवरणिका संख्या-6 में तालिकाबद्ध तरीके से एन० आइ० ई० के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे पाठ्यक्रम संबंधी कामों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। “विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पाठ्यचर्याओं का विश्लेषण” नामक विवरणिका संख्या-7 में राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पाठ्यचर्याओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों राज्यों की पाठ्यचर्याओं का विश्लेषण विवरणिका संख्या-8 (हिंदी) में दिया गया है।

पाठ्यक्रम बुलेटिन, जो शैक्षिक कार्यकर्ताओं में स्कूल-पाठ्यक्रम सम्बन्धी विचारों को फैलाने में उपयोगी औजार की तरह काम करती रही है, 1983-84 में अपने प्रकाशन के चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है। इस साल भी बुलेटिन के चार अंक प्रकाशित किए गए। इन चार अंकों में पुस्तक-समीक्षाओं, शोध कार्यों के सार-संक्षेप आदि के अलावा ‘पाठ्यक्रम शोध’, ‘पारिवारिक जीवन की शिक्षा’, ‘नैतिक शिक्षा’, आदि जैसे लेख भी छपे।

प्राथमिक स्तर पर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में कला की भूमिका का विस्तार

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कलाओं की पढ़ाई के लिए एक कलास रूम शिक्षण-प्रशिक्षण नीति का व्यवस्थित विकास है, जिससे शिक्षण की “प्रक्रिया-अनुभव” पद्धति के आधार पर कलाओं का अन्य विषयों के साथ तालमेल बैठाया जा सके। इस सिलसिले में दस स्थानीय प्राथमिक स्कूलों का चुनाव किया गया है, जिन्हें अन्य स्कूली विषयों के साथ कला-विषयों का तालमेल बँठाने वाली शिक्षण इकाई की तरह विकसित किया जाएगा। दिसम्बर, 1983 में इन स्कूलों के शिक्षकों और अन्य विशेषज्ञों की दो बैठकें बुलाई गईं, जिनमें सम्भावित क्षमताओं और अमली नतीजों के नजरिये से नमूने के तौर पर वर्ग चार, पांच के लिए शिक्षण इकाईयाँ विकसित की गईं। इस सिलसिले में जनवरी/फरवरी 1984 में प्रशिक्षण व दिशा-निर्देशन हेतु शिक्षकों और प्राधानाध्यापकों की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

शिक्षा के अलग-अलग स्तरों पर कला-विषयों के अलग-अलग क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के मसौदे का विकसित किया जाना

दृश्य/चित्र कलाओं के पाठों की रिपोर्ट के मसौदे को, जिन्हें 1982-83 के दौरान विकसित किया गया था, अन्तिम रूप दे दिया गया है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कलाओं के शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षणात्मक सामग्रियों का निर्माण

1982-83 से ही लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। प्रशिक्षणात्मक सामग्रियों पर तैयार किए गए दो मसौदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। सामग्री का पुस्तक-चित्रण और बच्चों की कला-पुस्तिकाओं का पुनर्मुद्रण जारी है।

समाज-विज्ञान और मानविकी पाठ्यक्रम विकास

आठवें दशक के मध्य में जब 10+2 शिक्षा-पद्धति शुरू की गई तो एन० सी० ई० आर० टी० ने इसका पाठ्यक्रम विकसित किया था। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि अब एन० सी० ई० आर० टी० सामान्यतया पाठ्यचर्याओं में और खासकर पाठ्यपुस्तकों में संशोधन करे। दो राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित किए गए—एक समाज-विज्ञानों के लिए और दूसरा भाषाओं के लिए। इन वर्कशॉपों में भाग लेने वालों में विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, शिक्षा-शास्त्री, शिक्षक, पाठ्यक्रम-विशेषज्ञ और इन दोनों क्षेत्रों में एन० सी० ई० आर० टी० के लिए पाठ्यपुस्तक लिखने वाले लेखकगण शामिल थे। वर्कशॉप ने यह मौका प्रदान किया कि कक्षा एक से बारह तक की एन० सी० ई० आर० टी० की पाठ्यचर्याओं पर दुबारा नजर डाली जा सके और प्राप्त उन अनुभवों के आधार पर इनमें जरूरी सुधार किए जा सकें, जो अनुभव छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, विशेषज्ञों और शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोगों से इन्हें प्राप्त हुए।

नैतिक शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जिन्हें आम तौर पर अब लोग मूल्य-बोधी शिक्षा के नाम से जानते हैं। कक्षा नौ से बारह तक को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है।

पाठ्यपुस्तकों का संशोधन/विकास

इस साल के दौरान निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया गया है, काफी दिनों से इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया था और ये संशोधित पुस्तकें प्रेस के हवाले कर दी गई हैं :—

—भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (कक्षा XI के लिए)

—इन्डिया ऑन द मूव—आर्थिक सूचक की पाठ्यपुस्तक (माध्यमिक स्कूलों के लिए, कक्षा X के लिए)

—भारती, भाग-I —कक्षा VI

—समाजशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक—कक्षा XI और XII के लिए।

एन० सी० ई० आर० टी० ने समूची स्कूली शिक्षा के लिए यानी कक्षा I से XII तक के लिए मातृभाषा के तौर पर उर्दू की पाठ्यपुस्तकें विकसित करने का कार्यक्रम पहली बार शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा VI और VII की पाठ्यपुस्तकों की (मूल पाठ) पांडुलिपि को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

कुछ और किताबों की सूची नीचे दी जा रही है, जो या तो तैयार कर ली गई हैं या विकसित की जा रही हैं—

व्याकरण की किताबें

हिंदी में क्रियात्मक व्याकरण (कक्षा I से V के लिए)

संस्कृत व्याकरण (कक्षा V से VIII के लिए)

पूरक पाठ्यपुस्तकें

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन

कालिदास और उनकी कृतियाँ

कक्षा I के लिए हिन्दी में चार पूरक पुस्तिकाएँ

शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देशक पुस्तकें

“रीडिंग कॉम्प्रिहेन्सन” पर एक पुस्तक

स्वस्ति संदेशिका—कक्षा V से VIII तक के लिए संस्कृत शिक्षकों की दिशा-निर्देशक किताब।

अभ्यास पुस्तिका

स्वस्ति अभ्यास पुस्तिका—संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका—कक्षा V के लिए

संस्कृत काव्यों का श्रव्य-टेप भी तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण और विस्तार

केरल में द्वितीय भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाये जाने के लिए जरूरी अनिवार्य ज्ञान के लिए एन० सी० ई० आर० टी० ने 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 50 लोगों ने हिस्सा लिया।

एन० सी० ई० आर० टी० ने दिल्ली नगर निगम के हिंदी शिक्षकों के लिए भी छह-छह दिनों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम में तकरीबन एक सौ शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

एन० सी० ई० आर० टी० ने एटमी ऊर्जा आयोग के स्कूलों को हिंदी और अंग्रेजी के

शिक्षण में उनके शिक्षकों को दिशा-निर्देश देने के काम में सहयोग दिया।

अनुसंधान और प्रयोग विधि

“स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के तरीके” नामक प्रोजेक्ट पर यह विभाग लगातार काम करता रहा है।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली के स्कूलों का प्रारम्भिक अध्ययन पूरा किया जा चुका है।

देश के तमाम राज्यों में स्कूल स्तर पर लागू भूगोल की पाठ्यचर्याओं के अध्ययन के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में बारह राज्यों ने हिस्सा लिया।

विशेष प्रोजेक्ट

समाज विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में एन० सी० ई० आर० टी० ने कई सारे विशेष प्रोजेक्ट चलाए। हरेक प्रोजेक्ट की एक संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है—

(i) मूल्य-बोधी शिक्षा

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मुख्यतः नैतिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने की दृष्टि से की गई थी, लेकिन अब इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है और अब लोग इसे “मूल्य-बोधी शिक्षा” के नाम से जानते हैं। डॉ० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई, जिसका काम राष्ट्रीय पैमाने पर चलाये जा रहे इस कार्यक्रम में तालमेल बैठाना और इसे दिशा-निर्देश देना था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेखकों को लिखने के लिए दो किताबों के नाम दिए गए। इनमें से एक किताब की पांडुलिपियों के मसौदे पर एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कक्षा IX से XII तक के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के विषय-क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नागरिक और वैज्ञानिक मूल्य आते हैं। इस तरह इसके साथ ही वैज्ञानिक संस्कार विकसित करना भी इसका उद्देश्य है।

(ii) सीखने के लिए पढ़ना

इस परियोजना की शुरुआत मूलतः बड़े बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य इसे एक विशाल आन्दोलन का रूप देना था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दो ही भाषाओं—हिन्दी और अंग्रेजी पर काम करने के विचार के साथ की गई थी। प्रोजेक्ट के अंतर्गत मूलतः पांच से आठ साल की उम्र के बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद ही कहीं जाकर आगे के बारे में सोचा जाएगा। इसे दोनों ही तरह के छात्र-समुदाय को ध्यान में रख कर चलना होगा, एक जिनकी यह मातृभाषा है और दूसरे जो इसे द्वितीय भाषा की तरह पढ़ रहे हैं। काफी तेजी से ज्ञान

के नये क्षेत्रों के विस्तार और नए आयाम उद्घाटित होते जाने को दृष्टि में रखने से यह जरूरी हो जाता है कि बच्चे अपने व्यक्तित्व के विकास की आरंभिक मंजिल पर ही पढ़ने की आदत डाल लें। इसके लिए यह जरूरी होगा कि पर्याप्त मात्रा में पाठ्य-सामग्री उपलब्ध हों, जो सरल और असरदार भाषा में लिखी गई हो और जो अन्धथा आकर्षक भी हो। और भी अधिक जरूरी तो यह है कि ये सामग्री शहरी और देहाती दोनों ही इलाकों में सीमित साधनों वाले बच्चे और उसके मां-बाप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। दरअसल प्रोजेक्ट को उन लोगों की जरूरतों के इर्द-गिर्द काम करना होगा, जो देहाती इलाकों से आते हैं और पिछड़े तथा सुविधाहीन वर्गों के हैं।

टेलीविजन और जन-संचार के अन्य दृश्य माध्यमों की बढ़ती हुई आक्रामक भूमिका को देखते हुए प्रोजेक्ट के महत्त्व में एक और आयाम जुड़ जाता है; क्योंकि ये चीजें नई पीढ़ी का काफी ज्यादा वक्त ले लेती हैं और उनके पास किताबें पढ़ने के लिए अपेक्षाकृत कम समय बच रहता है।

परिषद् द्वारा इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा महत्त्व दिये जाने के कारण दो राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी—एक हिन्दी और एक अंग्रेजी के लिए—बनाई गई हैं, जिनमें प्रख्यात विद्वान, बच्चों के कलाकार, शिक्षाशास्त्री और चिल्ड्रेन्स बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ इंगलिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, स्टेट इन्स्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की गईं, जिनमें से दो दिल्ली में एक हिन्दी और एक अंग्रेजी के लिए; तथा एक अंग्रेजी के लिए हैदराबाद में आयोजित की गई।

जरूरी सामग्रियां तैयार करने की कसौटी क्या हो, इस सिलसिले में वर्कशॉप ने व्यापक विचार-निर्देश दिए। सामग्री किस तरह की होगी, इसका भी ठोस जायजा लिया गया। योजना की कार्य-पद्धति क्या हो, तथा इस सामग्री को तैयार करने और अन्तिम रूप देने के बारे में विचार-विमर्श किया गया। ऐसी सामग्रियों को कम कीमतों पर तेजी से वितरित किए जाने के उपाय किए जा रहे हैं। वर्कशॉप ने कथा-साहित्य और गैर-कथा-साहित्य दोनों ही के लिए मजमून, प्रतिपाद, विषय आदि निर्धारित किए। यह सुझाव दिया गया कि तक-रीबन साठ प्रतिशत सामग्री कथा-साहित्य (फिक्शन) की श्रेणी के चालीस प्रतिशत गैर-कथा-साहित्य की श्रेणी के होने चाहिए। सामग्री में इस हद तक असरदार कथा-तत्त्व और रचना-त्मक निखार की जरूरत और उम्मीद महसूस की जा रही है, ताकि वह युवा पाठकों को जबरदस्त तरीके से आकृष्ट कर सके और साथ ही वह सरल और सुबोध भी हो। ये चीजें पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों में बाहर से काम चलाऊ ढंग से जोड़े जाने की जरूरत नहीं हैं, बल्कि उसे अन्दर से विकसित किया जाना है।

(iii) स्वाधीनता आन्दोलन के चित्रफलक का निर्माण

एन० सी० ई० आर० टी० पिछले ढाई साल से इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है और अब कहीं जाकर 50 चित्रफलकों को अन्तिम रूप देने में कामयाब हो पाया है; इनमें 100

साल से कहीं अधिक लम्बे असें में फैले स्वाधीनता आन्दोलन की विभिन्न घटनाओं, प्रतिपाद्य विषयों और ऐतिहासिक मोड़ों को समेटा गया है। मूल फोटोग्राफ, तस्वीरें, अखबारी कतरने, विवरणात्मक चित्र, कार्टून आदि के अलावा खासी तादाद में मूल दस्तावेज भी खोजे और जमा किए गये हैं। इन दस्तावेजों का चयन करते समय इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि ये चीजें स्कूली बच्चों में विशेष आकर्षण पैदा करने में सक्षम हों और उनमें देशभक्ति, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा कर सकें। ये दस्तावेज चित्रफलकों के पृष्ठ भाग पर मुद्रित किये जायेंगे, ताकि ये शिक्षकों और ऐसे अन्य पाठकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकें, जो हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के बारे में अतिरिक्त जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी रखते हों।

(iv) पर्यावरण शिक्षा के लिए एक प्रतिरूपक/ नमूना/साइड्यूल का निर्माण

इस प्रोजेक्ट के लिए फंड यूनेस्को दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक नमूना तैयार किया जा रहा है। इस नमूने की एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करके यूनेस्को मुख्यालय पेरिस भेजा गया। उन्होंने बिना किसी फेरबदल के इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। नमूना, जो तकरीबन अस्सी पृष्ठों का है, करीब-करीब तैयार हो चुका है और शीघ्र ही यूनेस्को भेज दिया जायगा।

(v) हिंदी में संदर्भ सामग्री

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस प्रोजेक्ट पर पिछले दो साल से काम कर रही है। 'विद्यार्थी हिंदी साहित्य कोश' शीर्षक से एक पुस्तक की योजना तैयार की गई है। इसमें स्तरीय हिंदी रचनाओं से संबंधित सूचनाएं होंगी, जिनकी जानकारी हाई स्कूल के छात्रों के लिए जरूरी है। साथ ही इसके माध्यम से उनका परिचय हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, उपन्यास, गद्य, लघु कहानी, नाटक, एकांकी और आलोचना के प्रख्यात साहित्यिक विभूतियों से होगा। प्रविष्टियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए और इन विषयों पर छोटे-छोटे लेख तैयार करने के लिए उपयुक्त लेखकों के नाम तय करने के उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसमें कुल मिलाकर 3000 प्रविष्टियां होंगी।

(vi) संस्कृत में संदर्भ सामग्री

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् संस्कृत विषय में भी इसी दिशा में कार्य कर रही है और नीचे लिखी दो पुस्तकें प्रकाशित करने की इसकी योजना है—

- (1) विद्यार्थी संस्कृत साहित्य संदर्भ कोश
- (2) बाल संस्कृत शब्दकोश

(vii) अंग्रेजी में बहुमाध्यमी पेटिका

भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के आग्रह पर यह परियोजना आरंभ की गई है। चूंकि यह आम शिकायत रही है कि समूचे देश में अंग्रेजी का स्तर गिरता चला जा रहा

है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि इस प्रवृत्ति को उलटने का लिए तत्काल कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा के अंतिम स्तर पर छात्रों में आवश्यक भाषा क्षमता उत्पन्न हो, यह तय किया गया है कि छोटे-छोटे सेतु पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं। स्कूलों तथा अध्यापकों के लिए ये पाठ्यक्रम उपचार के रूप में उपयोगी साबित होंगे। अध्यापक के काम के बोझ को कम करने के लिए बहुमाध्यमी पेटिका विकसित करने का प्रस्ताव है। एक कार्यशाला इस उद्देश्य से आयोजित की गई कि इसकी समस्याओं के हर आयाम को जाना जाए तथा एक उचित कार्य योजना तय की जाए। जिन सामग्रियों का विकास किया जाना है उसकी जिम्मेदारी उचित विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को सौंप दी गई है तथा उसी के मुताबिक अब सामग्री तैयार होने के दौर में है।

स्कूलों में नवाचार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इस विषय पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें देश के विभिन्न भागों से 99 प्रविष्टियाँ उपलब्ध हुई हैं। दो समीक्षकों के दल ने अलग-अलग इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया। इनमें से कुल 24 प्रविष्टियों को योग्यता के प्रमाण-पत्र तथा 500/- रु० के नगदी इनाम के लिए चुना गया था।

सभी पुरस्कार पाने वालों की दिल्ली में, चार दिनों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विजेता नवाचारों की खोजों तथा रिपोर्टों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर का इन रिपोर्टों को संपादित करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया ताकि अधिक मात्रा में वितरित करने के लिए इनको छापा जा सके।

अखिल भारतीय बाल साहित्य प्रतियोगिता

हर दूसरे वर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। फिर भी इस परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ कठिनाईयों के प्रकाश में इसके नियम, कानूनों तथा कार्य करने की पद्धति में सुधार किया गया तथा इस योजना में आवश्यक सुधार किए गए। 1980-82 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियाँ आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन और विज्ञप्तियाँ दी जा रही हैं। इसके साथ ही इस योजना के अन्तर्गत अप्रकाशित पाण्डुलिपियाँ भी स्वीकार की जा सकती हैं। ये भारतीय मुक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखी होनी चाहिए। प्रत्येक 5000 रु० के 36 पुरस्कार होंगे। इनमें 16 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए दो-दो पुरस्कार होंगे और हिन्दी के लिए चार पुरस्कार होंगे।

शैक्षिक अभिलेखागार का निर्माण

गत वर्ष यह परियोजना चालू की गई थी और इस वर्ष भी यह जारी है।

राज्यों के साथ कार्य

अरुणाचल प्रदेश

केन्द्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अंग्रेजी और हिंदी की पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए गम्भीरता से काम कर रही है। इस वर्ष के दौरान तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की एक पाठ्य-पुस्तक 'अरुण भारती भाग-III' तैयार करके प्रेस भेज दी गई है। इसी कक्षा के लिए अभ्यास पुस्तिका तैयार हो रही है। पुस्तकों की पांडुलिपियों की योजना और समीक्षा के लिए दो कार्यशालाएं—एक ईटानगर में और एक दिल्ली में, आयोजित की गईं। निम्नलिखित अंग्रेजी की तीन पुस्तकों को विकसित किया गया।

1. डॉन रीडर्स—कक्षा I के लिए पाठ्यपुस्तक
2. डॉन रीडर्स—कक्षा I के लिए सहायक पुस्तक
3. डॉन रीडर्स—कक्षा I के लिए अभ्यास पुस्तिका

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के आग्रह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक साथ ही प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला का आयोजन किया। यह कार्यक्रम द्वितीय भाषा के रूप में भी हिन्दी लोगों की दिलचस्पी का विषय बना रहा। पोर्ट ब्लेयर में 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जम्मू और कश्मीर

सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों में राज्य में प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में सरकार के आग्रह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने जम्मू और कश्मीर सरकार की सहायता की। इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई थी कि जम्मू और कश्मीर ने यह निर्णय किया था कि राज्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बनाई गई पाठ्यपुस्तकों को लगाया जाएगा।

मेघालय

सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को संशोधित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राज्य शिक्षा संस्थान, मेघालय की सहायता की। इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषय शामिल थे।

राजस्थान

प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम संशोधन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद् ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर की मदद की।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आग्रह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने समाज विज्ञान और हिन्दी के पाठ्यक्रम के संशोधन तथा कुछ अन्य पाठ्यपुस्तकों की पाँडुलिपियों की समीक्षा में भाग लिया।

हरियाणा

नव साक्षरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने हरियाणा राज्य की सहायता की। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया ताकि नवसाक्षरों की हालत पुनः निरक्षरों जैसी न हो जाए। इसके बाद की कार्यवाही के रूप में कुछ उचित विषयों को छोटी-छोटी पुस्तिकाएं लिखने के लिए चुना गया। इसकी एक विशेषता ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास किया जाना था। इसमें निम्नांकित सामग्री शामिल थी—प्राइमर, अभ्यास पुस्तिका, अध्यापक निर्देशिका और पहेलियों तथा कहानियों से युक्त सहायक पुस्तकें।

मध्य प्रदेश

पिछले पाँच वर्षों से प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री के विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, मध्य प्रदेश राज्य के साथ सहयोग करती चली आ रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान परिषद् ने जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने में मदद की। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन चीजों को तैयार किया गया वे हैं; एक प्राइमर, एक अभ्यास पुस्तिका, एक शिक्षक निर्देशिका और कविता तथा कहानियों की एक सहायक पुस्तक।

विज्ञान और गणित

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 1983-84 में एक बहुमुखी कार्यक्रम हाथ में लिया। इस कार्यक्रम में शामिल बातें इस प्रकार थीं : विज्ञान शिक्षा संसाधन के रूप में पर्यावरण, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा का प्रचार-प्रसार, विज्ञान के सभी विषयों में पाठ्यक्रम की समीक्षा, गणित में पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन, पर्यावरण शुद्धता, पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा का उन्नयन, राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आदि।

पर्यावरण शिक्षा

महिला बेसिक प्रशिक्षण संस्थान, वाराणसी (उ० प्र०) में अप्रैल 1983 के पहले सप्ताह में प्राइमरी स्तर के पर्यावरण अध्ययन में छात्रों के मूल्यांकन हेतु सामग्री तैयार करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सामग्री का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया

ताकि आगे उसमें सुधार परिष्कार किया जा सके तथा उसे प्रकाशित किया जा सके।

पर्यावरण अध्ययन के संसाधन व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु राज्य की ओर से 18 से 30 जुलाई 1983 के बीच कार्यशाला तथा पाठ्यक्रम का संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 लोगों की भागीदारी थी। उन लोगों को, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में विकसित की गई शिक्षण सामग्री तथा कार्यक्रम के दर्शन से परिचित कराया गया।

सेंट जॉन वेस्ट्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्रिची में 5 से 9 मार्च 1984 के दौरान कक्षा I तथा II के अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में पांच दिनों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन तमिलनाडु के जनजाति कल्याण तथा आदि द्रविड निदेशालय के सहयोग से किया गया था। इसमें स्कूल शिक्षा निदेशालय तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, मद्रास ने भी सहयोग दिया था। इस कार्यशाला में भाग लेने वाले अध्यापकों की संख्या पचास थी।

प्राइमरी स्तर के पर्यावरण शिक्षा विषय में छात्रों के मूल्यांकन की सामग्री विकसित करने के उद्देश्य से, फरवरी 1984 के अन्तिम सप्ताह में छतरपुर, मध्य प्रदेश में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भौतिकी की शिक्षा

“भौतिकी शिक्षा के शिक्षण सहायक सामग्री पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन” में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने भाग लिया। यह सम्मेलन 22 से 24 फरवरी 1984 के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा मद्रास नगर में ही आयोजित किया गया था। “भौतिकी शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की शैक्षिक सहायक सामग्री विषयक गतिविधियाँ” विषय पर एक पर्चा पढ़ा गया।

माध्यमिक स्कूल स्तर तक विज्ञान की शिक्षा

कक्षा VI से X तक के विज्ञान पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए मेघालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को दस दिनों की कार्यशाला आयोजित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सहायता प्रदान की। विज्ञान के अध्यापकों तथा अध्यापक शिक्षकों के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम निर्देशिका तैयार की गई।

1983, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राजकीय केंद्रीय शैक्षिक संस्थान, इलाहाबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विषय था, “समग्र विज्ञान पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन का गहन अध्ययन”। भाग लेने वालों ने पाठ्यक्रम संशोधन पर काम किया ताकि विभिन्न विज्ञान शाखाओं को एक साथ जोड़कर इसे अधिक समग्र बनाया जा सके।

माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान में प्रयोगों तथा गतिविधियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, जनवरी 1984 के दूसरे हफ्ते में विज्ञान केंद्र, करोल बाग, नई दिल्ली में, एक कार्यशाला आयोजित की गई।

यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैकॉक के साथ एक अनुबंध के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान

और प्रशिक्षण परिषद् ने एक देशी-पर्चा तैयार किया जिसका विषय था, “भारत में विज्ञान शिक्षा की दशा”। यह पर्चा स्वतंत्रता के बाद भारत में स्कूलों में विज्ञान शिक्षण की संवृद्धि का विस्तार से विवरण प्रस्तुत करता है।

जनवरी 1984 के अंतिम सप्ताह में उदयपुर में मिडिल स्कूलों के विज्ञान पाठ्यक्रम के संशोधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसे राजस्थान एस० आई० ई० आर० टी० ने किया था तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इसमें मदद की थी।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (विज्ञान एकक), गुड़गांव (हरियाणा) ने एक कार्यशाला राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की मदद से आयोजित की। जिस परियोजना के अंतर्गत यह आयोजन किया गया उसका शीर्षक था, “विद्यालयों में विज्ञान के समग्र पाठ्यक्रम क्रियान्वयन का गहन अध्ययन”।

स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा

दिल्ली में मार्च, 1984 के प्रथम सप्ताह में प्राइमरी कक्षाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- (i) वर्तमान स्वास्थ्य, विशेष रूप से स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों को जानना।
- (ii) पाठ्यक्रम का ऐसा ढांचा विकसित करना जो छात्रोन्मुखी हो, अध्यापकोन्मुखी नहीं और स्पष्ट रूप से इसमें रचनात्मक दृष्टि अपनाई गई हो।
- (iii) पाठ्यक्रम को रोगोन्मुखी के बजाए स्वास्थ्योन्मुखी बनाना।
- (iv) स्वास्थ्य संबंधी आदतें बनाने के लिए सामान्य बुद्धि को विकसित करने वाली गति-विधियों को शामिल करना।

बारह सामान्य उद्देश्यों वाली एक सूची को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद कक्षा के विविध स्तरों पर जैसे I से V, सामान्य उद्देश्यों पर आधारित विशेष उद्देश्यों को खोजा गया। संपूर्ण प्राइमरी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के लिए विशेष उद्देश्यों पर आधारित प्रमुख तथा गौण विचारों को तलाशा गया।

पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता

पांच राज्यों में 1976 में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था, ये राज्य हैं—गुजरात, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल ने इसको छोड़ दिया। 1982 में दस और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने इस परियोजना को अपनाया। वे हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

जिन पुराने केंद्रों (क्षेत्रीय केंद्रों) की 1976 में शुरुआत हुई थी, 1983 तथा उसके बाद उन केंद्रों से आशा की जाती थी कि अपने-अपने राज्यों के प्राइमरी के स्कूलों के मौजूदा पाठ्यक्रमों में पोषण; स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता को शामिल करके उसके

क्षेत्र का विस्तार करेंगे। उनसे इस बात की भी आशा की जाती थी कि पड़ोसी राज्यों जहाँ इस परियोजना को बाद में हाथ में लिया गया था, उनके लिए ये राज्य संसाधन केंद्र का काम देंगे।

इनमें कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसने प्राइमरी कक्षा के स्तर के पाठ्यक्रम के साथ पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम को जोड़ा हो। इसके बदले कुछ ने (तमिलनाडु विशेष रूप से) बाद वाले, इसके अलावा कम लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी प्रदर्शित किया गया। भाग लेने वालों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, भारत, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के प्रतिनिधि शामिल थे।

9 से 30 मई, 1983 के बीच दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के लिए +2 स्तर के भौतिकी शिक्षकों का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। भागीदारों को "व्यक्तिगत स्तर पर निर्देशित शिक्षण पद्धति" के विषय में स्पष्ट किया गया।

रसायन शास्त्र की शिक्षा

विभिन्न राज्यों के रसायनशास्त्र के पाठ्यक्रम के विश्लेषण के लिए तथा एक केंद्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 6 से 9 अप्रैल 1983 के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली परिसर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक कार्यशाला आयोजित की।

अप्रैल 1983 के प्रथम सप्ताह में मथुरा तेल शोधक परियोजना परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कक्षा XII के लिए रसायनशास्त्र में अवधारणा केंद्रित प्रयोगों का विकास करना इसका उद्देश्य था। कार्यशाला के दौरान कठिन अवधारणाओं का पता लगाया गया तथा उनके लिए प्रयोगों को डिजाइन किया गया। कुछ प्रयोगों की व्यावहार्यता पर भी विचार-विमर्श हुआ।

जीव विज्ञान की शिक्षा

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए, प्रयोगशाला और क्षेत्रीय गतिविधियों पर एक संसाधन पुस्तिका तैयार करने के उद्देश्य से, अप्रैल 1983 के पहले सप्ताह में एक कार्यशाला आयोजित की गई। लगभग 200 प्रयोगों/गतिविधियों का पता लगाया गया। ऐसा प्रस्ताव है कि एक अन्य कार्यशाला में तथा स्कूल परीक्षाओं में इस सामग्री की समीक्षा की जाए।

विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों तथा अध्यापक शिक्षकों के लिए 'नए जीव विज्ञान' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इनको नए जीव विज्ञान की अवधारणाओं तथा शिक्षण में अभिविन्यस्त किया गया।

अध्यापक शिक्षकों तथा प्रमुख व्यक्तियों के लिए 'नए जीव विज्ञान' में एक अन्य अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया गया। इसका आयोजन 1984 के जनवरी महीने में किया गया था।

गणित की शिक्षा

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए गणित की एक निर्देश पुस्तिका तैयार करने के लिए अप्रैल 1983 के प्रथम सप्ताह में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में निर्देश पुस्तिका तैयार करने के लिए आरंभिक कार्य हाथ में लिया गया।

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के सिलवासा में मई 1983 में गणित अध्यापकों का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में चलनकलन की कठिन अवधारणाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

अणुशक्ति पढ़ाने वाले प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक अन्य अभिविन्यास कार्यक्रम तथा कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। यह आयोजन मई 1983 में जदुगुडा के केंद्रीय विद्यालय में किया गया था।

मई 1983 में अणुशक्ति नगर बंबई के अणुशक्ति केंद्रीय विद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित किया गया। कामेट (CAMET) प्रशिक्षित अध्यापकों की मदद से अंतर्वस्तु को संपन्न बनाने वाली सामग्री तथा गणित के व्यवहार को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की गई। अपने-अपने क्षेत्र के नामी विज्ञान वेत्ताओं और अभियंताओं को इन क्षेत्रों में गणित के व्यवहार संबंधी विषयों की व्याख्या के लिए भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।

जनवरी 1984 के तीसरे सप्ताह में, मद्रास में कक्षा VIII की गणित की पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन के लिए एक कार्यशाला चलाई गई। पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के साथ ही मिडिल स्कूल स्तर वाले गणित के पाठ्यक्रम पर भी विचार-विमर्श हुआ।

फरवरी 1984 में +2 स्तर के गणित के मौजूदा पाठ्यक्रम के संशोधन पर विचार करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

गणित अध्ययन की सामान्य अभिरूचि में गिरावट पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा बुलाई गई बैठक में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने भाग लिया जिसको अधिक स्कूलों में फैलाने का प्रयास किया गया है तथा प्रयोग के तौर पर और ज्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

अब तक इस परियोजना का मूल्यांकन भारत पोषण फाउण्डेशन द्वारा किया गया है। इसके प्रतिवेदन को प्रचारित नहीं किया गया है।

निम्नांकित गतिविधियों को 1983 के दौरान अधिकांश नए केंद्रों ने पूरा कर लिया है। वे गतिविधियां नीचे दी गई हैं—

- (i) राज्यों के विभिन्न परिस्थितिकीय क्षेत्रों (तटीय, जनजातीय, शहरी, अल्प सुविधा प्राप्त आदि) के लिए पोषण, स्वास्थ्य और सफाई की आदतों का आधारभूत सर्वेक्षण करना;
- (ii) सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर प्राइमरी स्कूलों के लिए शैक्षणिक पेटिकाओं का विकास;
- (iii) उपयुक्तता और गुणवत्ता के बारे में लोगों की सलाह जानने के लिए इस पेटिका का कुछ प्राइमरी स्कूलों में परीक्षण;

- (iv) अध्यापक शिक्षकों और निरीक्षकों के लिए अभिविन्यास;
- (v) एक सौ प्रयोगात्मक स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण;
- (vi) प्रयोगात्मक स्कूलों में सामग्री के इस्तेमाल की शुरुआत;
- (vii) मूल्यांकन तथा सामग्री में पुनः संशोधन;
- (viii) अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों में महत्त्वपूर्ण संदेशों से परिचय ताकि बांछित पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में सूचनाओं की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके।

सभी नए राज्यों की प्रगति एक जैसी नहीं है। कुछ राज्य जैसे असम, कर्नाटक तथा उड़ीसा 1984 के दौरान भी उपर्युक्त गतिविधियों को पूरा करने में लगे रहे हैं।

1983 के दौरान विविध स्तरों के लिए बजट के आवंटन की दृष्टि से मिजोरम का सूची में सबसे ऊपर स्थान है। इसकी प्रतिशत उपयोग दर 98.8% है। राजस्थान का स्थान दूसरा है जिसकी प्रतिशत उपयोग दर 86.1% है।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी

लखनऊ में 10 से 16 नवंबर 1983 के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सत्ताईस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 157 छात्र तथा 136 अध्यापक जिसमें 36 छात्र शिक्षक लखनऊ के थे, इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। चुनी हुई 146 वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की गईं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अतिरिक्त हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, केंद्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान तथा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल सेंटर ने अपनी गतिविधियों से संबंधित सामग्री का प्रदर्शन किया।

इसी समय दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में दूसरी प्रदर्शनी लगाई गई जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के करकमलों से संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी का विषय था, "सामुद्रिक विकास और समुद्र से प्राप्त संसाधन"। इस प्रदर्शनी में निम्नांकित संस्थानों/विभागों ने भाग लिया—

- (i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- (ii) समुद्र विकास विभाग
- (iii) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान।

अखिल भारतीय विज्ञान और गणित शिक्षा परियोजना

अखिल भारतीय विज्ञान और गणित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संगोष्ठी और साक्षात्कार का एक मिला-जुला कार्यक्रम आयोजित किया गया। यू० के० के 'कामेट' कार्यक्रम के अंतर्गत गणित शिक्षा की उन्नत पद्धति में प्रशिक्षण पाने के लिए शिक्षकों और अध्यापक-शिक्षकों का चुनाव करना इसका लक्ष्य था। नयी-नयी बनाई गई यह चयन प्रक्रिया थी। भाग लेने वालों का परीक्षण किया गया तथा गणित शिक्षा से संबद्ध विषयों पर उनसे बुलवाया गया। इसके बाद चयन समित ने उनका अन्तिम साक्षात्कार लिया। चयन के लिए

यह प्रयोग अप्रैल 1983 में किया गया।

अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण परियोजना के लिए प्रत्याशियों के चयन का दूसरा प्रयोग 23 से 30 मई 1983 के बीच किया गया। इसमें यू० के० के लिए भौतिकी, रसायन-शास्त्र तथा जीव विज्ञान में शिक्षकों/अध्यापक शिक्षकों को प्रशिक्षण में भेजने के लिए उनका चुनाव करना था। इस चुनाव प्रयोग का उद्देश्य था—उन अध्यापकों को चुनना जिनके पास अकादमिक योग्यता अच्छी हो तथा जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो तथा जिनके पास अच्छी संप्रेषण क्षमता हो ताकि यू० के० से प्रशिक्षित होकर वापस आने पर वे अच्छे संसाधन व्यक्ति का कार्य कर सकें। इस चयन प्रयोग में कई बातें शामिल थीं। सबसे पहले स्तर पर राज्यों में प्रत्याशियों का साक्षात्कार लिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली में एक संगोष्ठी मिश्रित साक्षात्कार का आयोजन किया गया। उनको एक उपलब्धि परीक्षण से भी गुजरना पड़ा। उनकी पाठ-योजनाओं में से एक पर समूह में विचार-विमर्श किया गया तथा विज्ञान शिक्षा से संबंध किसी एक विषय पर उनसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया। इसके बाद उनका साक्षात्कार लिया गया। इस चुनाव प्रयोग में ब्रिटिश काउंसिल तथा चेल्सी कॉलेज के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अंतिम साक्षात्कार में बाहर के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीस शिक्षक/अध्यापक शिक्षक चुने गए।

अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अकादमिक क्षेत्र के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के एक विज्ञान शिक्षक को तीन महीने की अध्ययन यात्रा के लिए नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य था कि ये लोग अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण परियोजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

नवंबर 1983 के दौरान लखनऊ में हुई बच्चों की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी से कुछ माडलों को चुनकर, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 71 वें अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाई गई जो 7 जनवरी 1984 के बीच बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची में हुई।

प्रदर्शन के लिए आमंत्रित चुने हुए छः माडलों में से पांच कार्यकारी माडलों को प्रदर्शित किया गया। वे पांच माडल इस प्रकार थे—

प्रदर्शित वस्तु का नाम	स्कूल का नाम
1. अंतर्हीन ऊर्जा परियोजना	श्री रेनुक हाई स्कूल, बरदपुर जिला : बीद (महाराष्ट्र)
2. हाथीबाड़ा पत्ते से रेशे बनाने की मशीन	भुवन हाई स्कूल, पो० भुवन, जि० : ढेंकानाल (उड़ीसा)
3. शक्ति उत्पादन तथा बहुउद्देश्यीय कार्यवाली मशीन	स्वरूप हाई स्कूल, पो० स्वरूपपुर, जिला : मुंशिदाबाद (प० ब०)

4. आधुनिक बहुउद्देशीय चूल्हा

एस० टी० एस० हाई स्कूल, लेलगुबालू
पो० चिलकनहट्टी, हेसपेट
जि० : बेल्लारी (कर्नाटक)

5. सौर ऊर्जा चालित कार

सेठ समत रामजी डूगर हायर से० स्कूल,
पो० सरदार शहर,
जि० : चुरू (राजस्थान)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पण्डाल में प्रदर्शित इन माडलों को देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग आए। विभिन्न माडलों के कार्यों में अधिकांश प्रतिनिधियों ने बड़ी गहरी दिलचस्पी दिखाई। इनके कार्यों का विवरण उन माडलों को बनाने वाले छात्रों ने ही दिया जिन्हें इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

संगठक के प्रति स्कूलों में जागरूकता

स्कूलों में संगठक के प्रति जागरूकता लाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है। इसके लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है तथा स्कूलों में संगठक शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की रजत जयंती 1 सितम्बर 1986 से आरम्भ होगी। इस अवसर पर प्रमुख विकास कार्यक्रम के रूप में एक विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। विज्ञान केन्द्र गणित और विज्ञान शिक्षा के विभाग से सम्बद्ध किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, नई दिल्ली में स्थित होगा।

विज्ञान केन्द्र का उद्देश्य सामान्य रूप से स्कूल शिक्षा के और विशेष रूप से देश में विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए परिषद् की गतिविधियों के जोर को प्रकाश में लाना होगा। इस योजना को अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक सलाहकार समिति बनाई है। इसकी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रो० डी० एस० कोठारी ने अपनी सहमति दे दी है।

स्त्री शिक्षा

स्कूल पाठ्यक्रम के द्वारा स्त्रियों की हैसियत को ऊपर उठाने, और उनको व्यावसायिक/मुख्य बनाने तथा लड़कियों की शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य से परिषद् विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेती है। इस वर्ष के दौरान हाथ में ली गई कुछ प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं।

1. अनुसंधान कार्य

एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तकों तथा उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में लिंग विषयक रूढ़िबद्ध धारणाओं का पता लगाने के लिए एक अध्ययन चलाया गया तथा उसे पूरा भी कर लिया गया। यह अनुसंधान इन देशों के गौण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोतों तक सीमित था। यह यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम था।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रमसंख्या 16 के नतीजों का आंध्र प्रदेश की ओर से अध्ययन शुरू किया गया तथा उसे पूरा भी कर लिया गया। स्त्रियों की शिक्षा के सार्वजनीकरण और व्यावसायीकरण के परिणामों पर विचार किया गया। पिछड़े हुए जिलों का पता लगा कर उनमें पिछड़ेपन की मात्रा का भी पता लगाया गया। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में माडल बनाने के लिए यह एक तरह का प्रयोग था। जो अन्य अनुसंधान चल रहे हैं, वे इस प्रकार हैं—

(अ) 'घुमंतू समुदाय के लिए जरूरत पर आधारित और परिस्थिती द्वारा निर्धारित परिवर्तनोन्मुख शिक्षा प्रणाली' (ई० आर० आई० सी० परियोजना)

(ब) 'शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए लड़कियों तथा महिलाओं के लिए क्षेत्रीय, स्थानीय और आवश्यकता पर आधारित व्यवसायों की पहचान' (ई० आर० आई० प०)

(स) लड़कियों के लिए (सामाजिक रूप से अक्षम लड़कियों सहित) गणित विषय में अल्पोपलब्धि के निर्धारक (ई० आर० आई० सी० परियोजना)

(द) 'भारत में सहशिक्षा के स्तर का अध्ययन' नामक अनुसंधान योजना का कार्य समाप्त हो चुका है।

2. विकास कार्य

संबद्ध विषय में निम्नांकित विकास कार्य रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हाथ में लिए गए। यूनेस्को के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसका शीर्षक था, 'शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पाठ्य-पुस्तकों से लिंग विषयक रूढ़िबद्ध धारणाओं को पहचानने और समाप्ति के लिए क्षेत्रीय निर्देश पुस्तिका'।

आंध्र प्रदेश के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम (सोलहवां सूत्र) के निहितार्थ पर संगोष्ठी में चर्च के लिए एक 'एप्रोच पेपर' तैयार किया गया। हरियाणा की प्रौढ़ महिलाओं के लिए गिनती पाठ तैयार किए गए।

समाजशास्त्र में +2 स्तर की पाठ्यक्रम की रूपरेखा को संशोधित किया गया। 'क्षेत्रीय असमानता का अध्ययन संस्थान' द्वारा पटना में आयोजित 'शैक्षिक तथा क्षेत्रीय असमानता के चौथे वार्षिक सम्मेलन' के लिए 'स्त्री शिक्षा और ग्रामीण विकास' पर एक पर्चा तैयार किया गया।

गृह अर्थशास्त्र विषय में +2 स्तर के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया। दो फिल्मी पट्टियां (i) संख्याओं की समझ (ii) सर्वोच्च संख्या की अवधारणा पूरी की गई। मातृ भाषा तथा द्वितीय भाषा की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन तथा चयन के लिए मानदण्डों का विकास भी किया गया। परीक्षकों के लिए उपकरण, निर्देश पुस्तिकाओं को आजमाया गया,

उनका मूल्यांकन कर उन्हें अन्तिम रूप दिया गया।

निम्नांकित विषयों पर विकास का कार्य चल रहा है—

- (1) लड़कियों के (13-18 वर्ष) के उचित सामाजीकरण के लिए सहायक पुस्तक
- (2) दहेज विरोधी दो सहायक पुस्तकें
- (3) स्कूल पाठ्यक्रम के अंग के रूप में वैधानिक साक्षरता (सजगता)
- (4) प्राइमरी स्तर के लिए शिक्षण सहायक सामग्री तथा अध्यापक निर्देशिका की रचना
- (5) स्त्रियाँ और कानून।

3. प्रशिक्षण और प्रसार

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए काम करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका विषय था, 'पाठ्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए अध्यापक निर्देशिका'।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काम करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक अन्य अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका भी विषय पहले कार्यक्रम जैसा ही था।

महिला कालेजों की प्राचार्याओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने संसाधन व्यक्ति प्रदान किए। यह परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की थी।

निम्नांकित अभिकरणों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने परामर्श सेवाएं प्रदान कीं :

1. 'ग्रामीण विकास के शैक्षिक अवयव' (यूनेस्को प्रायोजित परियोजना) पर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान को।
2. केरल और तमिलनाडु में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के सुदृढीकरण के आकलन में शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय को।
3. 'शैक्षिक असमानता के सूचकों का विकास' के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान को।
4. 'ग्रामीण महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' समिति के जरिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को।
5. महिलाओं की हैसियत की दृष्टि से कक्षा VIII की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन में एस० आई० ई० आर० टी०, उदयपुर, राजस्थान को।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम 1981 से ही चलाया

जा रहा है। इस कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण किया गया है और पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन कार्यक्रम राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने हाथ में ले लिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इसका संयोजन कर रही है। बहुत से राज्य इस कार्य को पूरा करके पाठ्यपुस्तकों का संशोधन कर चुके हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन राज्यों में इस कार्य की गति धीमी है, उनसे इसे शीघ्र पूरा कराया जाए। जून 1984 के अन्त तक काम पूरा करने के लिए उनसे आग्रह किया गया है। उनसे 1984-85 शैक्षिक सत्र में नई पाठ्यपुस्तकें लगाने के लिए भी कहा गया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर और सिक्किम इस श्रेणी के राज्य हैं। पश्चिम बंगाल ने भी इस कार्यक्रम को अब हाथ में लिया है जिसने अब तक इसको नहीं माना था। इस प्रकार सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश (उनको छोड़कर जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें अथवा पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकें चलाते हैं) पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन कार्यक्रम के लिए सहमत हो गए हैं।

7

शिक्षा और काम

शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायीकरण का मूल उद्देश्य है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक कुशलताओं और ज्ञान से लैस करना ताकि वे समुदाय के लिए आवश्यक अनेक व्यवसायों/सेवाओं के लिए अधिक रोजगार योग्य बन सकें। इस तरह के गंभीर उद्देश्य के लिए आवश्यक है एक अच्छा और अर्थपूर्ण व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम जो संस्थाओं के लिए अच्छे पाठ्यक्रम, दक्ष अध्यापक, समुचित अनुदर्शी सामग्री और आधारभूत सुविधाएं आदि जुटाकर ही संभव है। प्रसंगवश, राज्यों में व्यावसायिक कार्यक्रम लागू करते वक्त स्थिति यह थी कि उपरोक्त लागतों का लगभग पूरा अभाव था और केवल आशा की गयी थी कि कालांतर में ये सभी लागतें उपलब्ध करायी जा सकेंगी। इन परिस्थितियों में रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् के लिए यह स्वाभाविक था कि वह इस शून्य को भरने के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के अनुसार ही अपने कार्यक्रमों/गतिविधियों को नियोजित करे। इसी की संगति से, समीक्षित वर्ष में गतिविधियों का मुख्य बल व्यावसायिक छात्रों और अध्यापकों के लिए

अनुदर्शी सामग्रियों का और पहचानी गयी न्यूनतम दक्षताओं के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास करने पर रहा है।

अनुदर्शी सामग्री

+2 स्तर पर व्यावसायिक कोर्स बिना समुचित अनुदर्शी/पाठ्य सामग्री के इस पूर्वानुमान पर आरंभ किये गये थे कि अध्यापक और छात्र पहले से विद्यमान संदर्भ-सामग्री का इस्तेमाल कर रहे होंगे जो विश्वविद्यालयों के सामान्य अकादमिक प्रकार के और स्नातक कोर्सों के छात्रों के लिए, लगभग सभी प्रमुख विषयों में उपलब्ध थे। पिछले 6-7 वर्षों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि विभिन्न कारणों—कठिन भाषा, व्यवसायों के लिए अल्प प्रासंगिकता, भारी लागत, औसत स्कूल पुस्तकालय में अप्राप्यता, आदि के कारण ये संदर्भ सामग्रियां व्यावसायिक छात्रों के लिए अपर्याप्त हैं। ये ही परिस्थितियां थीं जिनमें परिषद् ने स्व-व्याख्यायी अनुदर्शी सह-प्रायोगिक पुस्तिकाओं, अध्यापक-दिग्दर्शिकाओं, पूरक पाठ्य सामग्रियों और परीक्षण आइटमों का विकास व्यावसायिक छात्रों के लाभ के लिए करने का एक महत्वाकांक्षी और दिलेर कार्यक्रम आरंभ किया, और इस सावधानी के साथ कि यह सामग्री आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रायोगिक फील्ड अनुभव वाले विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों के विद्वानों एवं कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों की सहायता से तैयार की जाए। व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुदर्शी सामग्री के विकास के लिए जिन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया उनका विवरण निम्नानुसार है।

कृषि में, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर में 12 से 17 जनवरी और 21 से 23 जनवरी, 1984 तक, जिनमें फल-संरक्षण, फल उत्पादन, शाक-प्रसार, शाक फसलों, पुष्प-उत्पादन और पौध-संरक्षण पर 6 पुस्तिकाओं की तैयारी उद्यान विज्ञान व्यावसायिक कोर्सों के लिए की गयी।

उसी स्थान पर 18 से 22 जनवरी, 1984 तक आयोजित एक अन्य कार्यशाला में, फसल उत्पादन कोर्स के लिए पहले तैयार की गयी तीन पुस्तिकाओं की समीक्षा करके उनको अंतिम रूप दिया गया, जिससे वे छपे हुए रूप में व्यापक वितरण के लिए उपलब्ध हो सकें।

प्रौद्योगिकी में, टी० टी० टी० आई०, चंडीगढ़ में 1 से 8 दिसंबर 1983 तक आयोजित एक कार्यशाला में लाइनमैन व्यावसायिक कोर्स के ग्रेड XI के लिए तीन पुस्तिकाएं तैयार की गयी थीं जिनकी समीक्षा और संपादन का कार्य रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 30 जनवरी से 2 फरवरी, 1984 तक आयोजित एक अन्य कार्यशाला में संपन्न हुआ। इसी कोर्स के ग्रेड XII के लिए तीन पुस्तिकाओं का एक सेट ए० बी० टी० आई०/आई० टी० आई०, फरीदाबाद में 24 फरवरी से 2 मार्च, 1984 तक आयोजित एक कार्यशाला में तैयार किया गया। इनकी समीक्षा और संपादन का कार्य रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 9 से 12 मार्च, 1984 तक आयोजित एक अन्य कार्यशाला में संपन्न हुआ।

इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लायंसेज एंड रीवाइडिंग कोर्स के लिए तीन प्रयोगशाला दिग्दर्शिकाओं की तैयारी रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 6-13 जनवरी, 1984 को आयोजित एक कार्यशाला में संपन्न हुई।

परा-चिकित्सा क्षेत्र में, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कालेज, भणिपाल में 2-11 फरवरी, 1984 को आयोजित कार्यशाला में, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स के लिए एक दिग्दर्शिका तैयार की गयी। रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 19-25 मार्च, 1984 को आयोजित एक कार्यशाला में उसकी समीक्षा की गयी।

बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स के लिए पूरक रीडर की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए, रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 27 मार्च से 3 अप्रैल, 1984 तक आयोजित कार्यशाला में एक रीडर तैयार की गयी।

वाणिज्य में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 26-31 मार्च, 1984 तक आयोजित एक कार्यशाला में कार्यालय व्यवहार कोर्स के लिए एक प्रायोगिक दिग्दर्शिका तैयार की गयी।

न्यूनतम व्यावसायिक दक्षताओं पर आधारित पाठ्यक्रम

अध्ययन और प्रयोग की एक समुचित योजना के अतिरिक्त, एक अच्छे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की विशेषता है कि वह किसी व्यवसाय में उपलब्ध रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखे, रोजगारों का वर्णन करे और वांछित ज्ञान, कुशलताओं और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करे। परीक्षण योजना, संदर्भ आवश्यक उपकरण आदि समेत किसी व्यवसाय के बारे में सारी व्यापक सूचना भी उस पाठ्यक्रम को जुटानी चाहिए। आज विद्यमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम शायद ही इन आवश्यकताओं को पूरा करते हों, और इस कारण से अध्यापकों और छात्रों दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपयोगिता को लेकर अच्छा-खासा भ्रम पाया जाता है। इस शून्य को भरने और राज्यों को आदर्श व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिषद् ने, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के विज्ञान की सहायता से, निम्न कार्यशालाओं का आयोजन किया—

(i) वल्लभ विद्यानगर में 16 से 20 अप्रैल 1983 तक, आठ (कृषि, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और गृहविज्ञान, प्रत्येक में दो-दो) व्यावसायिक कोर्सों के लिए।

(ii) रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 20 से 24 जून, 1983 तक वाणिज्य-आधारित व्यावसायिक कोर्सों—बैंकिंग, विपणन और विक्रय-कुशलता के लिए।

(iii) एन० डी० आर० आई०, करनाल में 12 से 16 दिसंबर 1983 तक, डेयरिंग एंड एनिमल हूबैड्री कोर्स के लिए।

(iv) टी० टी० टी० आई०, भोपाल में 20 से 24 दिसंबर, 1983 तक दो वाणिज्य-आधारित और दो प्रौद्योगिकी-आधारित कोर्सों—बीमा, परचेजिंग और स्टोर कीपिंग, कंप्यूटर तकनीक और एयर कंडीशनिंग व रेफ्रीजरेशन के लिए एक कार्यशाला।

(v) अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में 27-31 मार्च, 1984 को आटो-इंजीनियरिंग टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लायंसेज एंड रीवाइंडिंग कोर्सों के लिए।

(vi) केंद्रीय मत्सयकी शिक्षा संस्थान, बंबई में 19 से 24 मार्च, 1984 तक इनलैंड फिशरीज और फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कोर्सों के लिए।

हरियाणा सरकार की प्रार्थना पर परिषद् ने रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 9 से 12 सितंबर, 1984 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य में तत्काल लागू करने के लिए 20 व्यावसायिक पाठ्यचर्याओं का विकास एवं पुनर्निरीक्षण किया गया।

रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 22 नवंबर, 1983 को आयोजित कार्यशाला में व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए सामान्य अनुस्थापन कोर्स की पाठ्यचर्या का विकास किया गया जो पूरे देश में लागू किये जाने के लिए अनुमोदित की गयी है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में 28-30 नवंबर, 1983 को एक अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में व्यावसायिक कार्यक्रम आरंभ करने वाले राज्यों के लिए, एक कार्यवाही-योजना तैयार करना था।

अल्पावधि अध्यापक-प्रशिक्षण

अध्यापकों की व्यावसायिक विशेषज्ञता और दक्षताओं को आधुनिकतम बनाने के लिए और शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के दर्शन से उनको परिचित कराने के लिए, जिससे वे +2 स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित उद्देश्य पूरा करने में सहायक हों, परिषद् विशेषीकृत अधिगम की संस्थाओं में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अल्पावधि अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है और उनमें सर्वोत्तम उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, व्यावसायिक शिक्षकों को उनके व्यवसाय-क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराया जाता है, उनको व्यवसायों के कार्यक्षेत्र से परिचित कराया जाता है, और व्यावसायिक विषयों के अध्यापन की उचित विधियों का ज्ञान उनको दिया जाता है।

समीक्षित वर्ष में, महाराष्ट्र और प० बंगाल में फ्रेश-वाटर फिश कल्चर और फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के व्यावसायिक कोर्स पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक अल्पावधि अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन परिषद् ने किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, बंबई में 24 मई से 20 जून, 1983 तक चला। प्रशिक्षणार्थियों ने मत्स्य फार्मों, मत्स्य-पालन-गृहों, प्रोसेसिंग संयंत्रों और प्रयोगशालाओं में कार्य किया। उनको, गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने की क्रियाओं में भाग लेने के लिए, जलयान सरस्वती पर भी ले जाया गया।

अभिविन्यास कार्यक्रम

राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन भी परिषद् द्वारा किया जाता है। इन कार्यक्रमों में भागीदारों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की नीति को उचित ढंग से समझने और व्याख्यायित करने में सहायता दी जाती है। समीक्षित वर्ष में परिषद् ने निम्न समूहों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया और भागीदारों में पहले से व्यावसायिक कोर्स चला रहे राज्यों के अधिकारी तो थे ही, निकट भविष्य में +2 स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रम आरंभ करने वाले राज्यों के अधिकारी भी थे।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव में 23-25 सितंबर, 1983 को हरियाणा के

प्रमुख व्यक्तियों के लिए।

2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में 27-30 सितंबर, 1983 को आंध्र प्रदेश के स्कूलों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए।
3. क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर में 22-25 अक्टूबर, 1983 को उड़ीसा के प्रमुख व्यक्तियों के लिए।
4. बी० एस० समुदाय विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद में 13-17 दिसंबर 1983 को गुजरात के प्रमुख व्यक्तियों के लिए।

परामर्श-कार्य और अन्य अधिकरणों के साथ समन्वय

राज्यों के विभिन्न संगठनों को परिषद् बराबर अपनी विशेषज्ञता और सहयोग उपलब्ध कराती है और इसके लिए, उनके अनुरोध पर, +2 स्तर पर स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यूनेस्को, यूनिसेफ, पंजाब शिक्षा सुधार आयोग, राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य शिक्षा बोर्डों, नीपा आदि संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हमारे परिषद् की भागीदारी व्यावसायिक शिक्षा को समुन्नत और लोकप्रिय बनाने में बहुत ही सहयोगी होगी। एक यूनिसेफ कार्यक्रम के अंतर्गत, विज्ञान किट्स के विकास और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए भूटान को विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध करायी गयी।

सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य

राज्यों में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की स्थिति का आकलन करने के लिए परिषद् ने रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली में 11-13 अप्रैल, 1983 को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के भागीदारों ने स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सा० ह० उ० उ० का० की शिक्षा सुधारने के बारे में ठोस सुझाव दिये। निम्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों के लिए सा० ह० उ० उ० का० से संबंधित दो अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया—

1. मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन में 22-26 अगस्त 1983 को, जिसमें भागीदारों को सा० ह० उ० उ० का० की अनेक गतिविधियों से परिचित कराया गया। राज्य में जारी कार्याभिमुख कार्यक्रमों— 'कमाते हुए पढ़ो' हस्तकौशल शिक्षा, और कार्यानुभव— को सा० ह० उ० उ० का० के दायरे में लाने की विधियां निर्धारित की गयीं।

2. दक्षिणी क्षेत्र के लिए, 27-31 जनवरी, 1984 को एर्णाकुलम् में, जिसमें प्रमुख बल उन क्षेत्र-विशिष्ट और आवश्यकतामूलक गतिविधियों पर दिया गया जिनको स्कूलों में सा० ह० उ० उ० का० की अवधारणा और दर्शन की पूर्ण संगति में, प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है।

पंजाब सरकार के अनुरोध पर राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ में 7-10 दिसंबर, 1983 को सा० ह० उ० उ० का० के पाठ्यक्रम-विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन परिषद् ने किया जिसमें एक विस्तृत पाठ्यक्रम का विकास किया गया। इस पाठ्यक्रम में, अन्य बातों के

अलावा, स्कूलों में सा० २० उ० उ० का० के क्रियान्वयन की एक योजना भी दी गयी है।

परामर्श-कार्य और अन्य अधिकरणों के साथ सहयोग

यूनेस्को, राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, नीपा और सामान्य स्कूल शिक्षा के अंग रूप में सा० २० उ० उ० का० की उन्नति के लिए कार्यरत अन्य संगठनों/अधिकरणों को परिषद् ने अपनी विशेषज्ञता और सहयोग प्रदान किया। यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित थाइलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया के अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम के लिए परिषद् ने अपने भागीदारों को भेजा कि वे इन देशों के स्कूली पाठ्यक्रमों में कार्य-शिक्षा के अवयव का अध्ययन करें।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने गये एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में परिषद् ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा।

भारत में कार्यानुभव/सा० २० उ० उ० का० का एक गहन अध्ययन भी परिषद् ने किया और इसके परिणामों को तीन खंडों में प्रकाशित किया जो 1. नीतियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा, 2. परियोजनाओं की निर्देशिका, और 3. इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की निर्देशिका से संबंधित हैं। यह परियोजना ए० पी० ई० आई० डी० के अंतर्गत एक गतिविधि के रूप में एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय (यूनेस्को), बैंकाक के तत्वावधान में चलायी गयी।

अध्यापकों व अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण

स्कूली पाठ्यक्रम में वांछित परिवर्तनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है कि, अन्य बातों के साथ अध्यापक-शिक्षण का भी एक संगत—सेवा-पूर्व और सेवाकालीन—कार्यक्रम चलाया जाए। सिर्फ यही आवश्यक नहीं कि अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन कार्यक्रमों के साथ-साथ चले बल्कि उनको इन कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के पहले आना चाहिए। अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता मुख्यतः इसके शिक्षकों और इस शिक्षण से संबंधित अन्य शैक्षिक अभिकर्मियों पर निर्भर है। साथ ही, इसके लिए समुचित अनुदर्शी सामग्री और पर्याप्त अनुसंधान का आधार होना अति आवश्यक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रयास अध्यापक-शिक्षण संबंधी एक व्यापक शोध, विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में जारी हैं। कुछ वर्ष पहले आरंभ होने वाले अन्तर्वर्त शिक्षा केन्द्र भी अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही अपंगों की एकीकृत शिक्षा के नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी आरंभ

किया गया है। परिषद् का अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् के अकादमीय और प्रशासनिक सचिवालय का कार्य भी करता है।

विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में आरंभ किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों का वर्णन नीचे किया गया है।

विकास कार्यक्रम

अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों/हस्तपुस्तकों का विकास

इस संदर्भ में निम्न कार्य सम्पन्न किए गए—

स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व खेलकूद की पाठ्यपुस्तक

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नयी दिल्ली में क्रमशः 26 से 30 सितम्बर 1983 और 12 से 16 मार्च, 1984 की अवधियों में लेखकों की दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में विभिन्न संस्थाओं के 16 व्यक्तियों ने भाग लिया। पाठ्यक्रम की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई और संबंधित पुस्तक को अब प्रकाशन के लिए अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

आरंभिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

पुस्तक की पांडुलिपि तैयार है और अब उसका संपादन कार्य चल रहा है।

कोर अध्यापन-कौशल—व्यष्टि शिक्षण दृष्टि

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम ढाँचे के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने 'कोर अध्यापन-कौशल—व्यष्टि शिक्षण दृष्टि' शीर्षक से एक हस्तपुस्तक तैयार की है। इस पुस्तक के मूल्यांकन के लिए 9-12 अगस्त, 1983 की अवधि में परिषद् के परिसर में 14 अध्यापक-शिक्षकों की एक आरंभिक कार्यशाला आयोजित की गई। यूजर एसेसमेंट शीड्यूल की तकनीक के द्वारा प्रत्येक शिक्षक ने पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का मूल्यांकन किया। प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों द्वारा पुस्तक की समीक्षा के लिए नीति निदेशक सिद्धांत भी निश्चित किये गये और उनको प्रशिक्षक अध्यापकों को दिया गया जिससे वे प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों से सूचनाएं एकत्र कर सकें।

अध्यापक-शिक्षण हेतु एम० एड० के प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम

अध्यापक-शिक्षण से संबंधित एम० एड० के प्रश्नपत्र का एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 3-8 अक्टूबर, 1983 की अवधि में एक छः दिवसीय कार्यशाला दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत में आयोजित की गयी। एम० एड० छात्रों के उपयोग के लिए इस पाठ्यक्रम पर आधारित, अध्यापक-शिक्षण संबंधी एक संसाधन पुस्तक की तैयारी की योजना भी इस कार्यशाला में निर्धारित की गयी।

प्रश्न बैंक का विकास

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम ढाँचे के अनुरूप बी० एड० के नए पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न बैंक विकसित करने का कार्य भी परिषद् ने हाथों में लिया है। 'उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक और शिक्षा' के प्रश्नपत्र से संबंधित प्रश्न बैंक विकसित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में 26 से 29 अक्टूबर, 1983 तक की अवधि में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया।

विस्तार

बी० एड० पाठ्यक्रम का अनुसंधान

चूँकि रा० अ० शि० परिषद् के पाठ्यक्रम ढाँचे के अनुसार बी० एड० पाठ्यक्रम का संशोधन एक प्राथमिकता-प्राप्त लक्ष्य रहा है, परिषद् ने समीक्षित वर्ष में इस विषय पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये निम्नांकित हैं—

(i) आगरा और मेरठ विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रमों के संशोधन के लिए 7 से 11 नवम्बर 1983 तक मेरठ कालेज, मेरठ में। इस कार्यशाला में तीस से अधिक अध्यापक-शिक्षकों ने भागीदारी की।

(ii) जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर और रीवा विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रमों के संशोधन के लिए 17 से 21 जनवरी, 1984 तक हवावाग महिला प्रशिक्षण कालिज, जबलपुर में। इस कार्यशाला में 29 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया।

(iii) मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रमों के संशोधन के लिए 13 से 17 फरवरी, 1984 तक सागर विश्वविद्यालय में। इस कार्यशाला में 23 अध्यापक-शिक्षक सम्मिलित हुए।

(iv) तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के लिए 13 से 17 फरवरी, 1984 तक मदुरै में। प्रांत के शिक्षाशास्त्र के कालिजों के प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ अध्यापक-शिक्षकों ने इसमें भाग लिया।

राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व

प्रशिक्षण परिषदों के निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन

अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में एक नियमित प्रसार गतिविधि है राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों के निदेशकों को एक मंच प्रदान करना, जिससे वे अपनी गतिविधियों और समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें। इन निदेशकों का एक वार्षिक सम्मेलन प्रति वर्ष परिषद् द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह सम्मेलन 21 से 23 फरवरी, 1984 तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में आयोजित किया गया। इसमें उपरोक्त संस्थानों और परिषदों के 16 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ और इन संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।

अध्यापक-शिक्षकों के लिए सेमिनार वाचन कार्यक्रम

यह परिषद् का एक नियमित वार्षिक कार्यक्रम है। इसके लक्ष्य हैं नवाचार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और अध्यापक-शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि वे अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा की समस्याओं पर प्रयोग, अध्ययन और रचनात्मक चिंतन के अनुभवों के बारे में लिखें। इस कार्यक्रम में ऐसे साधन भी दिए जाते हैं जिनसे प्रयोग, अनुसंधान और रचनात्मक चिंतन के परिणामों का देश भर के अध्यापक-शिक्षकों तक विकीर्णन किया जा सके और उनके आगे रखा जा सके। दसवीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए अध्यापक-शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों, अध्यापक-शिक्षकों और समन्वयकों से आलेख आमंत्रित किए गए। तीन परीक्षकों के एक पैनल ने इन आलेखों का मूल्यांकन किया। माध्यमिक स्तर के दस आलेख और आरंभिक स्तर के सात आलेख पुरस्कार के लिए चुने गए।

अभिविन्यास कार्यक्रम

रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षकों के लिए निम्न अभिविन्यास पाठ्यचर्याओं का आयोजन किया जिससे उनको संशोधित पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत विभिन्न सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों का प्रभावी ढंग से अध्यापन कर सकने में सहायता मिले—

- (i) 'उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक और शिक्षा' नामक कोर प्रश्नपत्र में आंध्र प्रदेश के अध्यापक-शिक्षकों के अभिविन्यास के लिए, अप्रैल 1983 में वाल्टेयर में 6 दिन का एक कार्यक्रम।
- (ii) महाराष्ट्र के कनिष्ठ शिक्षा महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए पूणे में अगस्त 1983 में 6 दिन का एक कार्यक्रम।
- (iii) दक्षिणी राज्यों के भागीदारों के लिए 9 से 13 जनवरी, 1984 तक त्रिवेंद्रम में एक कार्यक्रम।
- (iv) 6 से 11 फरवरी 1984 तक गांधीग्राम में एस० यू० पी० डब्लू० के अध्यापन हेतु राज्य स्तर के संसाधन-व्यक्तियों को अभिविन्यासित किया गया।
- (v) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 5 से 10 मार्च, 1984 तक। इसमें 17 भागीदार उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

द्वितीयक स्तरीय अध्यापक-शिक्षण के लिए लघुस्तरीय अध्यापन कार्यक्रम को स्थिरता प्रदान करने में प्रशिक्षण-एवं-अनुसंधान रणनीति को प्रभावशाली पाया गया। अब इस रणनीति को आरम्भिक स्तरीय अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवहृत किया जा रहा है। समग्र लघु-स्तरीय अध्यापन विधि की प्रभावशालिता का सत्यापन करने, और साथ ही प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों की सामान्य अध्यापन क्षमता के विकास के संदर्भ में इसके अवयवों में होने वाले परिवर्तनों की प्रभावशालिता का अध्ययन करने के लिए, एक प्रशिक्षण-एवं-अनुसंधान परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है। 'उपअध्ययनों का नियोजन और निवारण' पर

पहली कार्यशाला का आयोजन 16 से 21 अगस्त, 1983 तक परिषद् के परिसर में किया गया। 20 आरम्भिक अध्यापक-शिक्षा संस्थाओं से 28 भागीदारों ने, जो 10 राज्यों और दिल्ली संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के प्रमुख लक्ष्य थे—प्रथम, आरम्भिक शिक्षा के चरण से सम्बन्धित पांच अध्यापन कुशलताओं और उनके व्यवहारगत अवयवों की पहचान और सुधार करना। दूसरे, मास्टर प्रोजेक्ट डिजाइन की व्याख्या और उस पर विचार-विमर्श करना और ऐसे विशिष्ट उपअध्ययनों का नियोजन एवं निर्धारण करने के सम्बन्ध में अध्यापक-शिक्षकों की सहायता करना जिनको वे अपनी-अपनी संस्थाओं में चला सकें। अपनी-अपनी संस्थाओं में भागीदारों ने ये प्रयोग किये। दूसरी कार्यशाला राज्य शिक्षा संस्थान, बंगलौर में 21 से 24 मार्च, 1984 में आयोजित की गयी। इसका लक्ष्य आंकड़ों के विश्लेषण, परिणामों की व्याख्या और परियोजना की रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में अध्यापक-शिक्षकों की सहायता करना था।

अध्यापन प्रारूप

माध्यमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 1983 तक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में किया गया। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य था तीन अध्यापन प्रारूपों—जांच-प्रशिक्षण प्रारूप, व्याख्यात्मक अध्यापन प्रारूप एवं प्रवीणता अधिगम प्रारूप—के परीक्षण के लिए अध्यापक-शिक्षकों का अभिविन्यास करना था। प्रत्येक भागीदार को एक व्यापक 'शिक्षण पेटिका' दी गयी जिसमें अध्ययन गाइडशीटें, वर्कशीटें और स्वपरीक्षण शीटें थीं। अध्यापक-शिक्षण विभाग में तैयार सामग्री की 3 से 6 अगस्त, 1983 तक नयी दिल्ली में 6 अध्यापक-शिक्षकों के एक कार्य समूह द्वारा समीक्षा की गयी।

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में 26 से 31 दिसम्बर, 1983 तक अनुसंधान प्रविधि सम्बन्धी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 34 व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रकाशन

इस अवधि में हमारे प्रकाशन निम्नलिखित हैं—

- (i) उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक एवं शिक्षण (माध्यमिक स्तर)।
- (ii) भारत में माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण का तृतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण।
- (iii) माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण 1982-83—विचार एवं प्रयोग (अनुलिखित)।

हमारे निम्न प्रकाशन इस समय प्रेस में हैं—

- (i) भारत में माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार, खंड 4।
- (ii) पाठ्यक्रम और मूल्यांकन (माध्यमिक स्तर)।
- (iii) शैक्षिक मनोविज्ञान।
- (iv) माध्यमिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं में गणित-शिक्षा की अंतर्वस्तु एवं प्रविधि।
- (v) आरम्भिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं में गणित-शिक्षा की अंतर्वस्तु एवं प्रविधि।

- (vi) सामान्य अध्यापन कौशल ।
- (vii) प्रारम्भिक अध्यापक का मनोविज्ञान (प्रारम्भिक स्तरीय अध्यापक-शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक) ।

निम्नलिखित पांडुलिपियों को इस समय छपने के लिए अन्तिम रूप दिया जा रहा है—

- (i) प्रारम्भिक स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा ।
- (ii) माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में नवाचार, खंड 5 ।
- (iii) भारत में अध्यापक-शिक्षण के क्षेत्र में अध्ययन एवं पड़ताल ।
- (iv) माध्यमिक अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन एवं खेलकूद की पाठ्यपुस्तक ।
- (v) उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक एवं शिक्षण (प्रारम्भिक स्तरीय) ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद्

रा० अ० शि० प० की स्थायी अकादमीय समितियाँ इस प्रकार हैं—

1. संचालन समिति,
2. स्कूल-पूर्व व प्रारम्भिक अध्यापक-शिक्षण सम्बन्धी समिति,
3. माध्यमिक एवं महाविद्यालयी अध्यापक-शिक्षण समिति,
4. शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अल्पविकसित व्यक्तियों के विशेष स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी समिति ।

जबकि ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए प्रायः मिली रहती हैं, रा० अ० शि० प० की मीटिंग वर्ष में एक बार इन समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और नीतिगत विषयों पर दिशानिर्देश देने और प्रतिवेदन करने के लिए होती है। कार्यशालाएँ, सेमिनार, अभिविन्यास कार्यक्रम, उपरोक्त समितियों की उप-समितियों या कार्यसमूहों की मीटिंगें, रा० अ० शि० प० के इन नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप होती हैं। समीक्षित वर्ष में रा० अ० शि० प० के तत्वाधान में निम्न मीटिंगों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम का नाम	दिनांक	भागीदारों की संख्या
1. एस० यू० पी० डब्ल्यू० के प्रमुख व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सिलचर ।	25-31 मई, 1983	27
2. रा० अ० शि० प० की माध्यमिक शिक्षा समिति की मूल्यबद्ध अध्यापक-शिक्षण विशेषज्ञ समिति की मीटिंग, रा० शि० संस्थान परिसर, नई दिल्ली ।	27-29 जुलाई, 1983	9

- | | | |
|--|--------------------|----|
| 3. उदीयमान भारतीय समाज में
अध्यापक-शिक्षण के लिए संसाधन-
व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम,
राज्य शिक्षा संस्थान, पूणे । | 3-8 अगस्त, 1983 | 49 |
| 4. नेत्रहीनों के अध्यापक-शिक्षण
संस्थाओं के सन्निध तैयार करने
के लिए कार्य समूह की मीटिंग,
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, नई
दिल्ली । | 12-15 सितंबर, 1983 | 17 |
| 5. रा० अ० शि० प० की माध्यमिक
एवं महाविद्यालय स्तरीय अध्यापक-
शिक्षण समिति की सातवीं मीटिंग,
रा० शि० सं० परिसर, नई दिल्ली । | 20 सितम्बर, 1983 | 14 |
| 6. रा० अ० शि० प० के पाठ्यक्रम
समस्याओं व सम्भावनाओं पर
राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन की
रूपरेखा पर विचार करने के लिए
माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय
अध्यापक-शिक्षण समिति की एक
उपसमिति की मीटिंग, रा० शि०
संस्थान परिसर, नई दिल्ली । | 19 दिसम्बर, 1983 | 10 |
| 7. प्रतिवेदनों का वर्गीकरण उन एजेंसियों
के अनुसार करने के लिए जो उन पर
कार्य करेंगी, इन प्रतिवेदनों के
क्रियान्वयन की व्यावहारिक रूपरेखा
निर्धारित करने के लिए और एम०
एड० के स्तर पर शैक्षिक नियोजन
और प्रबन्ध की तरह वैकल्पिक
प्रश्नपत्र के रूप में भविष्यविज्ञान की
पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए राज्य
अध्यापक-शिक्षण परिषद् की एक
तीन-सदस्यीय उपसमिति की मीटिंग,
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली । | 20 दिसम्बर, 1983 | 6 |
| 8. विशेष स्कूलों (शारीरिक रूप से
विकलांग, गूंगे-बहुरे-नेत्रहीन और मानसिक
रूप से अल्पविकसित लोगों के स्कूलों) के | 21 दिसंबर, 1983 | 6 |

अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित
अकादमीय स्थायी समिति की
पांचवीं मीटिंग, रा० शिक्षा संस्थान परिसर,
नई दिल्ली।

9. रा० अ० शि० परिषद् की स्कूल-पूर्व और 17 व 19 जनवरी, 1984 10
प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा समिति की सातवीं
मीटिंग, बंगलौर।
10. रा० अ० शि० परिषद् की जनरल बाडी 31 दिसंबर, 1984 46
मीटिंग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षण परिषद् की समितियों के निर्णयों और कार्यक्रमों की रिपोर्टों को योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद्, विश्वविद्यालयों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों, राज्य शै० अ० एवं प्र० परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थानों, फील्ड सलाहकारों (रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद्) और अध्यापक शिक्षण के राज्य बोर्डों जैसे अधिकरणों को दिशानिर्देश एवं क्रियान्वयन के लिए भेजा जाता है।

अनवरत शिक्षा केंद्र

अनवरत शिक्षा केंद्रों का उद्देश्य माध्यमिक स्कूल अध्यापकों और प्राथमिक स्कूल अध्यापक-शिक्षकों का अभिविन्यास करना है। इस समय देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 77 ऐसे केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों को दिए जाने वाले अनुदान का भार केंद्र और संबंधित राज्य सरकार के बीच आधा-आधा बंट जाता है। देश के विभिन्न राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों में ऐसे और केंद्र खोले जाने का भी प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् को राज्य में खोले जाने के लिए 12 नये केंद्रों की सूची भेजी है।

अपंगों की एकीकृत शिक्षा

अपंगों की एकीकृत शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् से की जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए और विशेष शिक्षा पर रा० अ० शि० परिषद् की स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर वांछित कार्य के रूप में, रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार है—

अपंगों की एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या को अन्तिम रूप देना

अपंगों की एकीकृत शिक्षा हेतु एक अर्धवार्षिक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का विकास अप्रैल 1983 में किया गया था। यह पाठ्यचर्या तीन-तीन माह की दो अवधियों के लिए है। पहली अवधि में दृश्य-अपंगुता, मानसिक अल्पविकास, विकलांगता और श्रव्य कठिनाईयों को लिया

जाता है। अपंगों के मनोविज्ञान पर पाठ्यचर्याएं, पाठ्यक्रम और अध्यापन, और अपंगों की एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन एवं प्रबंध को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरी अवधि में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा अपंगुता के चार क्षेत्रों में से किसी एक का विशेष ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है।

दृश्य-अपंगुता के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यचर्या का विकास

दृश्य-अपंगों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक-वर्षीय पाठ्यचर्या का विकास करने के लिए रा० अ० शि० परिषद् की स्थायी समिति ने एक कार्यकारी दल बनाया। दल की 18-25 सितंबर, 1983 की मीटिंग में ऐसी एक पाठ्यचर्या विकसित हुई। 'विशेष शिक्षा हेतु अध्यापकों की तैयारी' से संबंधित स्थायी समिति के सामने यह पाठ्यचर्या रखी गयी। अब इस पाठ्यचर्या को दृश्य-अपंगों के शिक्षण के लिए विशेष अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं के पास भेजा जा चुका है।

दृश्य-अपंगों के अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सन्नियमों का विकास

दृश्य-अपंगों के अध्यापक प्रशिक्षित करने के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के लिए, अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ सन्नियमों का विकास भी किया गया है। इन सन्नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अब रा० अ० शि० परिषद् का विशेष शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के आगे रखा जाना है।

बी० एड० के लिए विशेष शिक्षा की पाठ्यचर्या का विकास

रा० श० अ० एवं प्र० परिषद् ने बी० एड० के लिए विशेष शिक्षा हेतु एक पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे को इलाहाबाद में 27 से 30 दिसंबर, 1983 तक आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में अंतिम रूप दिया गया। इस पाठ्यचर्या को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और दूसरे विश्वविद्यालयी विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे बी० एड० में विशेष शिक्षा के लिए अपनी-अपनी पाठ्यचर्याओं का नियोजन कर सकें। कुछ विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ विशेष शिक्षा के विभाग खोलने की अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही दे रखी है। इन विशेष शिक्षा विभागों की आवश्यकता इस पाठ्यचर्या से पूरी हो सकेगी।

5 से 16 मार्च, 1984 तक रा० शि० संस्थान, नयी दिल्ली के परिसर में यूनेस्को के तत्वा-बधान में दृश्य-अपंगों की एकीकृत शिक्षा से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इसमें 30 लोग उपस्थित रहे जिनमें अधिकांश नेत्रहीनों की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापक-शिक्षक थे।

व्यवहार संशोधन संबंधी कार्यशाला

तंत्रिकीय-मांसपेशीय एवं बाह्य विकलांगता पर एक व्यवहार संशोधन कार्यशाला का

आयोजन 19 से 21 जुलाई, 1983 तक रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने किया। इसमें 30 लोगों ने भाग लिया जिनमें अपंगों की एकीकृत शिक्षा के प्रशिक्षणार्थी, परिषद् के स्टाफ के सदस्य और स्पैस्टिक सोसायटी आफ इन्डिया (उत्तरी क्षेत्र) के स्टाफ के सदस्य भी सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति बीच ट्री हाउस, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक श्री माल्कोम जोस थे।

विशेष शिक्षा पर पुस्तक-प्रदर्शनी

विशेष शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ की चेतना का विकास करने के लक्ष्य से 19 और 20 सितंबर, 1983 को विशेष शिक्षा संबंधी पुस्तकों की एक दो-दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने किया। पुस्तक व्यापार के अनेक अधिकरणों ने इस प्रदर्शनी में भागीदारी की। रा० शि० संस्थान पुस्तकालय, ब्रिटिश कौंसिल और यूनेस्को की विशेष शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी प्रदर्शित की गयीं।

अपंगों की एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यचर्या

अपंगों की एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का आयोजन रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने किया। यह पाठ्यचर्या 12 सप्ताह की थी और 30 मई, 1983 से आरंभ हुई। परिषद्, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों, राज्य शै० अ० एवं प्र० परिषदों और राज्य शिक्षा संस्थानों, एवं उत्तर भारत की स्पैस्टिक सोसायटी से 20 व्यक्तियों ने इस सफल कार्यक्रम में भाग लिया। अपंगुता के चार रूपों—दृश्य अपंगुता, वाणी और श्रव्य की कठिनाइयाँ, शारीरिक विकलांगता और मानसिक अल्पविकास के बारे में भागीदारों को व्यावहारिक ज्ञान और क्षमता प्राप्त हुई। लेकिन, एक भागीदार ने एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की। इस पाठ्यचर्या का व्यावहारिक पक्ष भी था क्योंकि कुल समय का 50% दिल्ली की एकीकृत शिक्षा संस्थाओं समेत विभिन्न संस्थाओं के विकलांग बच्चों के साथ व्यतीत हुआ।

भारत में विशेष शिक्षा संबंधी शोध-सर्वेक्षण

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध-सर्वेक्षण के लिए इ० आर० आइ० सी० परियोजना आरंभ की गयी है। सर्वेक्षण का उद्देश्य 1984 तक की व्यक्तिगत एवं संस्थागत परियोजनाओं के सार-संक्षेपों का संग्रह करना है। क्षेत्रवार शोध-समीक्षा और अनुसंधानों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करना भी प्रस्तावित है।

सूचना-प्रसार गतिविधियाँ

रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने अपंगों की एकीकृत शिक्षा से संबंधित एक त्रैमासिक बुलेटिन का भी प्रकाशन आरंभ किया है जो सूचना प्रसार केंद्र की तरह कार्य करेगा। इसका पहला अंक सितंबर 1983 में सामने आया। दूसरे और तीसरे अंक क्रमशः दिसंबर 1983 और मार्च 1984 में प्रकाशित हुए। परिषद् और उससे संबद्ध कालिजों व साथ ही राज्यों के बीच

अपंगों की एकीकृत शिक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान इस बुलेटिन के माध्यम से हो सकेगा।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

अजमेर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय उत्तरी क्षेत्र के राज्यों— राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ व दिल्ली के संघ शासित क्षेत्रों—की अध्यापक-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

नामांकन

इस वर्ष बी० एड०, एम० एड० और बी० एस-सी० (आनर्स/पास) बी० एड० की नियमित कक्षाओं में 367 छात्रों का महाविद्यालय में नामांकन हुआ। कक्षावार विवरण इस प्रकार है—

एम० एड०	17
बी० एड० (विज्ञान)	55
बी० एड० (कृषि)	25
बी० एड० (वाणिज्य)	26
बी० एड० (अंग्रेजी)	27
बी० एड० (हिन्दी)	38
बी० एड० (उर्दू)	29
बी० एस-सी० प्रथम वर्ष	57
बी० एस-सी० (आनर्स/पास) बी० एड० प्रथम वर्ष	65
बी० एस-सी० (आनर्स/पास) बी० एड० द्वितीय वर्ष	28
योग	367

बी० एड० (ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम) में नामांकन 136 है।

परिणाम

1983 में बी० एड० (ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम) में उत्तरी क्षेत्र के 156 अप्र-शिक्षित अध्यापक सम्मिलित हुए।

प्रसार सेवा विभाग

महाविद्यालय का प्रसार सेवा विभाग उत्तरी क्षेत्र के राज्यों द्वारा भेजे गए सुझावों और

महाविद्यालय संकाय द्वारा राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर दिये गये प्रस्तावों के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन करता है। समीक्षित अवधि के कार्यक्रम निम्नलिखित हैं—

- (i) अजमेर में एस० एस० सी० सी० के पत्राचार अंश के लिए पाठ्य लेखन (चरण I) पर कार्यशाला, 7-14 जनवरी, 1984।
- (ii) अजमेर में संस्थागत नियोजन पर एक सेमिनार एवं कार्यशाला, 21-24 फरवरी, 1984।
- (iii) विज्ञान क्लब की गतिविधियों पर अजमेर में एक कार्यशाला, 5-10 मार्च, 1984।
- (iv) लखनऊ में बी० एड० एस० एस० सी० सी० के पत्राचार अंश के लिए पाठ्य लेखन (चरण II) पर एक कार्यशाला, 21-26 मार्च, 1984।
- (v) लखनऊ में एस० यू० पी० डब्ल्यू० (फल संरक्षण) संबंधी शिक्षक निर्देशिका की तैयारी पर एक कार्यशाला, 29 मार्च-7 अप्रैल, 1984।

सी० ए० पी० ई० परियोजना

इस परियोजना से संबंधित अधिकांश राज्य इस वर्ष प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के माध्यम से स्व-अधिगम सामग्री को अधिगम पैकेज माड्यूलों और कैपसूलों के रूप में लाने में और अंतिम रूप प्राप्त सामग्री को छापने में व्यस्त रहे हैं। इस महाविद्यालय की सी० ए० पी० ई० टीम के सदस्य समय-समय पर विभिन्न राज्यों में—विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश—में जाते रहे कि विकसित सी० ए० पी० ई० सामग्री को अंतिम रूप देने में सहायता और अधीक्षण-सेवा प्रदान कर सकें। राजस्थान में 89 कैपसूलों पर आधारित 13 माड्यूलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब वे छपने की प्रक्रिया में हैं। उत्तर प्रदेश में 77 कैपसूलों पर आधारित 13 माड्यूलों को अंतिम रूप देकर छपने के लिए भेजा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य के शिक्षा संस्थानों ने अर्धसाक्षर बच्चों के लिए सी० ए० पी० ई० सामग्री तैयार करने हेतु जिन कार्यशालाओं का आयोजन किया उनमें भी टीम के सदस्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में सक्रिय रहे।

मूल्यबद्ध शिक्षा

अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मूल्यों के विकास की आवश्यकता पर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय बल देता रहा है और उसने चार्टों की तैयारी और विशेष लेक्चरों के आयोजन के द्वारा एक व्यावहारिक कार्यक्रम भी आरंभ किया है, जिससे महाविद्यालय के छात्रों में मूल्यों की शिक्षा के प्रति चेतना बढ़ रही है। बी० एड० कक्षाओं से व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहने की उपयोगिता से छात्रों को परिचित कराया गया। इसके अतिरिक्त मूल्यबद्ध शिक्षा संबंधी प्रसार लेक्चरों की एक योजना भी तैयार की गयी है। इस योजना में 11 अक्टूबर, 1983 को “आधुनिक युग में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता” पर एक लेक्चर का आयोजन भी किया गया।

व्यापकेतर उपयोग के लिए “शिक्षा में मूल्यों का महत्त्व” पर एक पांडुलिपि की तैयारी

चल रही है। रेडियो वार्ताओं के द्वारा इस कार्यक्रम का विकीर्णन करने के लिए आल-इंडिया रेडियो से भी महाविद्यालय संपर्क कर रहा है।

कृषि विभाग

नियमित अध्यापन कार्य के अतिरिक्त विभाग ने निम्न शोध/विकास गतिविधियों का आयोजन भी किया —

- (अ) छात्रों और कृषकों के लाभ के लिए महाविद्यालय के फार्म पर चारे से संबंधित प्रदर्शन और अनुसंधान परीक्षण किए गये। इसमें जाड़ों में ओट की खेती संबंधी परीक्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस शुष्क भूभाग के लिए हरा चारा उपयोगी सिद्ध हुआ है।
- (ब) छात्रों और कृषकों के लाभ के लिए महाविद्यालय के फार्म पर मस्टर्ड की विभिन्न प्रजातियों पर अनुसंधान-परीक्षण किये गये।
- (स) विज्ञान चतुर्थ वर्ष के छात्रों की संस्थागत आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए महाविद्यालय के फार्म पर एक उद्यान लगाया गया।
- (द) महाविद्यालय परिसर में एक केंद्रीय उद्यान वैज्ञानिक नर्सरी का विकास किया गया जिससे पाट कल्चर एवं सजावटी उद्यानरोपण/किचन उद्यान रोपण के क्षेत्र में एस० यू० पी० डब्ल्यू० की अवधारणा का विकीर्णन किया जा सके।
- (य) परिसर के सुंदरीकरण का एक गहन कार्यक्रम चलाकर नये लान बनाये गये, नये पौधे लगाये गये और उद्यानों की वर्तमान रूपरेखा को संशोधित किया गया।

कृषकों के लाभ के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने में और कृषकों की उपज के लिए पुरस्कारों की घोषणा में विशेषज्ञ रूप में, कृषि विभाग के स्टाफ ने स्थानीय कृषि ज्ञान केंद्र को भी अपना सहयोग दिया जो कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का एक अंग है।

विज्ञान विभाग

नियमित अध्यापन कार्य के अतिरिक्त, विज्ञान विभाग ने 7 जून, 1983 को विश्व पर्यावरण दिवस पर, पर्यावरण शिक्षा पर एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया।

ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम

1983-84 के सत्र में 136 प्रशिक्षणार्थी अध्यापक इस पाठ्यक्रम में नामांकित किये गये। नियमित विश्वविद्यालय परीक्षाओं में हुई देरी के कारण यह पाठ्यक्रम जून मास में ही आरंभ हो सका। अकादमीय सत्र के आरंभ होने के कारण, जुलाई मास में शिक्षकों का अपने-अपने स्कूलों से अवकाश प्राप्त करना कठिन था।

विभिन्न चुने हुए केंद्रों पर तीन सप्ताह का एक अनवरत आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। महाविद्यालय अधीक्षक प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के 42 पाठों का निरीक्षण व मूल्यांकन करते हैं। इस वर्ष 18 अगस्त से 7 सितंबर, 1983 तक निम्न केंद्रों पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया—

दिल्ली
अजमेर
चंडीगढ़
इलाहाबाद
मथुरा/रेवा
रोहतक।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों और गोवा, दमन, द्यू एवं दादरा और नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों की अध्यापक-प्रशिक्षण की आवश्यकताएं क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल पूरी करता है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए महाविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

महाविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं—

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. एम० एड० | विज्ञान-शिक्षा, अध्यापक-शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं दिशानिर्देश में विशेषज्ञता सहित। |
| 2. एम० एड० | प्रारंभिक शिक्षा। |
| 3. बी० एस-सी० बी० एड० | चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। |
| 4. बी० ए० बी० एड० | विशेष विषय के रूप में अंग्रेजी सहित चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। |
| 5. बी० एड० | भाषा, विज्ञान और वाणिज्य में एक वर्षीय पाठ्यक्रम। |
| 6. बी० एड० | प्रारंभिक शिक्षा में एक वर्षीय पाठ्यक्रम। |
| 7. बी० एड० | ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम। |

नामांकन

1983-84 के सत्र में महाविद्यालय में कुल 586 छात्र नामांकित थे। कक्षा-वार एवं राज्य-वार आंकड़े वक्तव्य 1 में दिये गये हैं।

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, द्यू, दादरा और नागर हवेली के छात्रों के नामांकन की स्थिति असंतोषजनक है, यह देखकर महाविद्यालय ने इन राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष प्रयास भी किये हैं। राज्य शिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र, पूणे, फील्ड सलाहकार कार्यालय, पूणे, और वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, अहमदाबाद में भी, इन राज्यों के छात्रों के लिए विशेष सुविधा के रूप में प्रवेश-प्रार्थनापत्र उपलब्ध कराये गये। 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त हुए सत्र के लिए राज्यवार नामांकन और परिणाम वक्तव्य 2 में दिये गये हैं।

विस्तार कार्यक्रम

समीक्षित वर्ष में महाविद्यालय में निम्न सेवाकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया—

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	प्रविधि	स्थान	भागीदारों की संख्या	
				आम- त्रित	उप- स्थित
1.	मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षकों के लिए दृश्य-श्रव्य सहायक साधनों के उपयोग और ग्राफिक्स के उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए कायशाला	8-13 अगस्त, 1983	भोपाल	31	27
2.	माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के प्रविधि मास्टर्स के लिए सेमिनार-एवं-कार्य-शाला (रसायन शास्त्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए)	25-30 अगस्त, 1983	भोपाल	27	16
3.	रा० अ० शि० परिषद् के पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र 1 में संशोधन के लिए कार्यशाला	5-10 सितंबर, 1983	बल्लभ विद्यानगर	35	12
4.	बी० टी० आई० कैरियर मास्टर्स (म० प्र०) के लिए प्रारंभिक स्तरीय शक्षिक और व्यक्तिगत दिशानिर्देश अभिविन्यास	12-17 सितंबर, 1983	भोपाल	30	17
5.	महाराष्ट्र के माध्यमिक विद्यालयों के +2 स्तर, विज्ञान के प्रविधि मास्टर्स के लिए सेमिनार-एवं-कायशाला	19-24 सितम्बर, 1983	नागपुर	30	14
6.	क्षेत्र के विस्तार सेवा विभागों के समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 अक्टूबर- 1 नवम्बर, 1983	भोपाल	44	25
7.	कृषि के क्षेत्र में प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	7-11 नवंबर, 1983	भोपाल	35	18

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	स्थान	भागीदारों की संख्या	
				आस- उप-	त्रित स्थित
8.	त्वरित अध्यापन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आदिवासी स्कूल अध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	19-26 नवंबर, 1983	भोपाल	30	19
9.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के प्रारम्भिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	25-30 नवम्बर, 1983	पंजिम	35	23
10.	स्वअधिगम कार्डों के उत्पादन के लिए कार्यशाला	13-17 दिसंबर, 1983	अमरकंटक	30	23
11.	गतिविधि-प्रविधियों के सेवाकालीन कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों का सम्मेलन	5-10 जनवरी, 1984	भोपाल	35	25
12.	अध्यापन कुशलताओं की पहचान और अध्यापन में पर्यावरण एप्रोच के प्रयोग की रणनीतियों पर कार्यशाला	10-14 जनवरी, 1984	भोपाल	30	23
13.	पाईगेशियन मनोविज्ञान पर माध्यमिक अध्यापक-शिक्षकों की कार्यशाला	27 फरवरी-3 मार्च, 1984	भोपाल	45	21
14.	विकलांगों के शिक्षण पर संसाधन व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास-एवं-प्रशिक्षण कार्यक्रम	5-28 मार्च, 1984	भोपाल	46	11

वक्तव्य ।

1983-84 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की स्थिति

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बी० एस-सी० बी० एड० तृतीय वर्ष	—	14 33	47	—	1 —	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
बी० ए० बी० एड० प्रथम "	3 3	— 19	25	—	2 2	4	—	—	—	—	—	—	1 1	2	31	
" " द्वितीय "	1—	5 20	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	32	
" " तृतीय "	1 2	6 14	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
बी० एड० (विज्ञान)	—	5 11	16	4 1	6 3	14	—	1 —	1	1 —	2 —	2	—	—	—	33
बी० एड० (वाणिज्य)	—	8 3	11	9 —	20 —	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
बी० एड० (प्रारंभिक)	— 2	— 12	14	9 —	6 1	16	—	2 1	3	3 —	—	—	—	—	—	33
बी० एड० (ग्री० स्कूल एवं प० पा०)	2 —	40 3	45	8 —	42 3	53 3	—	40 5	45	48 —	27 14	41	—	—	—	187
योग	10 9	118 220	357	32 1	81 10	134 3	—	44 6	50	53 —	29 14	43	7 2	9	—	586

संकेताक्षर : क = कमजोर वर्ग य = योग प = पुरुष
सा = सामान्य वर्ग स = स्त्री

वस्तु 2

वर्ष 1983 के परिणाम (1982-83 में नामांकित छात्रों के लिए)

पाठ्यक्रम की नाम	मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र		गुजरात		गोवा आदि		अन्य राज्य		योग		परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या
	सा	क	सा	क	सा	क	सा	क	व	देश	सा	क		
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
एम० एड०	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10	7
एम० एड० (प्रारम्भिक)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	3
बी० एस० सी० बी० एड० प्र० वर्ष	64	4	2	—	—	—	—	—	1	—	67	4	66	54
" " द्वितीय वर्ष	49	1	1	—	—	—	—	—	—	—	50	1	50	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बी० ए० बी० एड० प्रथम वर्ष	26	1	—	—	6	32 1	32	26
” ” द्वितीय वर्ष	21	3	—	—	—	21 3	23	21
बी० एड० (भाषा)	27	3	11	7	—	44 10	53	48
बी० एड० (विज्ञान)	19	2	11	4	—	38 6	39	37
बी० एड० (वाणिज्य)	15	3	11	4	—	30 8	38	38
२९ बी० एड० (प्रारम्भिक)	12	2	3	15	—	19 25	42	41
बी० एड० (ग्री० स्कूल एवं प० पा०)	52	22	62	6	—	197 48	245	224
योग	300	41	101	36	72	20	601	535

संकेताक्षर : सा = सामान्य वर्ग क = कमजोर वर्ग

समीक्षित वर्ष में आयोजित सेवाकालीन कार्यक्रमों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है—

क्रम सं०	राज्य	कार्यक्रमों की संख्या	भागोदारों की संख्या	
			आमंत्रित	उपस्थित
1.	मध्य प्रदेश	5	151	109
2.	महाराष्ट्र	1	30	14
3.	गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा	1	35	18
4.	क्षेत्रव्यापी	7	269	128
	योग	14	485	269

शोध परियोजनाएं

महाविद्यालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति इस प्रकार है—

(i) प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण एप्रोच के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कुशलताओं और प्रशिक्षण रणनीति के निर्धारण हेतु शोध अध्ययन (प्रमुख अन्वेषक—डा० जे० एस० राजपूत)।

मध्य प्रदेश के स्कूलों में कक्षा III, IV और V में पर्यावरण विज्ञान 1 एवं 2 के अध्यापन के लिए, इस परियोजना में एक व्यापक निर्देशिका हिंदी में तैयार करके प्रकाशित की गई है। इस सामग्री में प्रमुख हैं, एक विस्तृत यूनिट-वार अध्यापक निर्देशिका और मूल्यांकन-प्रश्न। पर्यावरण चेतना परीक्षण के दो समानांतर रूपों का विकास करके उनको एक प्रमाणिक रूप दिया गया है और निर्देशक सामग्री के परीक्षण के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण एप्रोच के लिए उपयोगी कुछ अध्यापन कुशलताओं और उनके अलग-अलग अवयवों का एक कोष तैयार किया गया है। विशिष्ट यूनिटों से इन कुशलताओं को जोड़ने का कार्य चल रहा है।

(ii) ताजे पानी पर एक अध्ययन—जीवविज्ञान अध्यापकों के लिए दिग्दर्शिका की तैयारी के संबंध में (प्रमुख अन्वेषक—डा० जी० के० लाहिड़ी)।

1983-84 में अपर लेक, लोअर लेक और चूना भट्टी लेक से पानी के नमूने एकत्रित किये गये। तापमान, फास्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, घुली हुई आक्सीजन, जैव-रासायनिक तत्वों, आक्सीजन मांग और पी-एच० स्तर की दृष्टियों से इन तीनों झीलों से लिये गये पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसी काल में जूप्लांकटन और फाइटोप्लांकटन के विभिन्न प्रकारों की जांच के लिए इन नमूनों का आगे विश्लेषण भी किया गया। भावी जांच के लिए अपर लेक और लोअर लेक से मछलियां भी एकत्रित, वर्गीकृत और

व्यवस्थित की गयीं ।

(iii) अनौपचारिक केंद्रों और औपचारिक स्कूलों के छात्रों की उपलब्धियों का तुल्यंक ज्ञात करने के लिए उपकरणों और तकनीकों का विकास (प्रमुख अन्वेषक—डा० जे० एस० राजपूत) ।

यह परियोजना पूरी हो चुकी है और तैयार सामग्री प्रेस में है ।

(iv) मध्य प्रदेश के जीवविज्ञान अध्यापकों के लिए संसाधन सामग्री तैयार करने की दृष्टि से भोपाल के पौधों का अध्ययन (प्रमुख अन्वेषक—डा० पी० के० खन्ना) ।

मध्य प्रदेश के जीवविज्ञान अध्यापकों के लिए संसाधन सामग्री तैयार करने की दृष्टि से एरिक के तत्वाधान में भोपाल के पौधों के अध्ययन संबंधी यह परियोजना चल रही है । दो कनिष्ठ परियोजना अध्येता भोपाल में प्राप्य पौधों के नमूने एकत्र करने, पहचानने और सुरक्षित रखने में लगे हैं । कक्षा IX, X एवं XI की पाठ्यपुस्तकों में उदाहरण रूप में उद्धृत पौधों की एक व्यापक सूची तैयार की जा चुकी है । परियोजना की समाप्ति पर तैयार सामग्री माध्यमिक स्तर के जीवविज्ञान शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगी ।

(v) पश्चिमी क्षेत्र के अध्यापकों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता पर पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रदत्त अध्यापक प्रशिक्षण (बी० एड० उपाधि) का प्रभाव : एक तुलनात्मक अध्ययन (प्रमुख अन्वेषक—डा० डी० सी० उपरेटी) ।

प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक अध्यापकों की गतिशीलता पर ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रदत्त बी० एड० प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ही इस परियोजना का उद्देश्य है । पारिवारिक पृष्ठभूमि, कार्यस्थल, रोजगार संबंधी महत्वाकांक्षा आदि चलनों का उच्चतर ग्रेड व स्थिति में अध्यापकों की पदोन्नति पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है, इस अध्ययन का उद्देश्य यह भी जानना है । तथ्य और आंकड़े एकत्रित किये जा चुके हैं और अब उनको विश्लेषित किया जा रहा है ।

(vi) विज्ञान में कुछ एकीकृत प्रक्रियाओं (उपमान, भविष्यवाणी, परिकल्पना-विकास और परिकल्पना-परीक्षण) के विकास के लिए स्व-अधिगम प्रक्रिया पर आधारित सामग्री की प्रभावशालिता का परीक्षण, सत्यापन और वृद्धि (प्रमुख अन्वेषक—डा० (श्रीमती) ए० ग्रेवाल) ।

इस परियोजना के तहत प्रक्रिया-आधारित मल्टीपल च्वायस टेस्ट आइटमों का विकास किया गया है । यह परीक्षण 46 टेस्ट आइटमों पर आधारित है और 125 छात्रों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है । ये आइटम वर्गीकरण, उपमान, भविष्यवाणी, परिकल्पना-विकास और परिकल्पना-परीक्षण की प्रक्रियाओं पर आधारित हैं । परीक्षण सैंपलों को अंकबद्ध किया जा रहा है । अध्ययन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं के मापांकन और कार्य-प्रणाली की व्याख्या करने वाली अनुदेश सामग्री तैयार की जा चुकी है । परिकल्पना के विकास और उपमान की प्रक्रियाओं से संबंधित सामग्री का पहला मसौदा भी माड्यूल रूप में तैयार हो चुका है ।

विकासात्मक परियोजनाएं

(i) हरियाणा राज्य के लिए अनुदेश सामग्री की तैयारी

महाविद्यालय ने 22 से 27 मार्च, 1984 तक फार्म यांत्रिकी संबंधी एक अनुदर्शी सह-व्यवहारात्मक पुस्तिका की तैयारी के लिए एक छः दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसके लिए हरियाणा सरकार ने रा० श्रै० अ० एवं प्र० परिषद से अनुरोध किया था। आशा है कि +2 (उच्चतर माध्यमिक) स्तर में कृषि की व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए यह पुस्तिका उपयोगी होगी।

(ii) विशेष शिक्षा परियोजना

महाविद्यालय ने "विकलांगों के शिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों हेतु एक अभिविन्यास सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम" का भी आयोजन किया। ब्रिटिश कौंसिल के सहयोग से ग्रेट ब्रिटेन में विशेष शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय के दो प्राध्यापक भी भेजे गये हैं।

(iii) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

पश्चिमी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों के संकाय प्रमुखों के अभिविन्यास के उद्देश्य से 14-15 नवम्बर, 1983 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उपस्थित भागीदारों की संख्या 15 थी।

मध्य प्रदेश के अध्यापक-शिक्षकों के अभिविन्यास हेतु 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1983 तक एक कार्यशाला भी आयोजित की गयी। इसमें 13 अध्यापक-शिक्षक उपस्थित रहे।

अनौपचारिक शिक्षा परियोजना

राज्य सरकार के सहयोग से महाविद्यालय परिसर में 'बालवाड़ी' नाम से एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहा है। खेलकूद और शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त बच्चों को कुछ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा के जो केन्द्र रा० शि० संस्थान की प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत आरम्भ किये गये उनके कार्यकलापों की आखरी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम

महाविद्यालय से सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय प्रदर्शन स्कूल में सामुदायिक गायन कार्यक्रम चल रहा है। इस स्कूल के पाँच अध्यापक सामुदायिक गायन का प्रशिक्षण पा चुके हैं। ऐसा ही प्रशिक्षण दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को दिया जायेगा।

राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से कक्षा I से VIII तक की उर्दू पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय ने संसाधन व्यक्ति भी प्रदान किये हैं।

अनवरत शिक्षा केन्द्र

अनवरत शिक्षा केन्द्रों के संसाधन व्यक्तियों के लिये पिछले सत्र में आयोजित दो सेवा-कालीन कोर्सों की रिपोर्ट भी महाविद्यालय ने प्रकाशित करके पूरे क्षेत्र में वितरित की है।

राष्ट्रीय कैंडेट कार्प्स

बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए एन० सी० सी० की कम्पनियां तैयार करने की स्वीकृति निदेशक, एन० सी० सी०, मध्य प्रदेश, भोपाल से प्राप्त हो चुकी है। इन दो अलग-अलग यूनिटों के साथ बालिकाओं के लिए एक (बालिका डिवीजन) और बालकों के लिए एक (वरिष्ठ डिवीजन) यूनिट ने भी इस सत्र में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

संकाय सुधार कार्यक्रम

पी-एच० डी० उपाधियाँ : स्टाफ के निम्न सदस्यों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से पी-एच० डी० की उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं—

1. श्री एस० एल० एन० भार्गव, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग को 'ए स्टडी आफ सम काग्निटीव प्रॉसेसेज इन साइंस लर्निंग विद रेफरेंस टू फिजीक्स फार स्टूडेंट्स आफ हायर सेकंडरी बलासेज' पर शोध कार्य के लिए।
2. श्री राजेन्द्र दीक्षित, रीडर, अंग्रेजी विभाग को 'ई० ई० कॉमिक्स ऐज ए डेविएंट पोएट' पर शोध कार्य के लिए।
3. श्री एस० पी० मिस्त्री, कार्य-अनुभव अध्यापक को 'रोल एंड इंपैक्ट आफ वीमेन लीडरशिप इन सोशल, पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स आफ मध्य प्रदेश' पर शोध कार्य के लिए।
4. श्री ए० के० बनर्जी, स्नातकोत्तर अध्यापक को 'फ्रीक्वेंट चेंजेज इन इन्डियन म्यूजिक' पर शोध कार्य के लिए।

पी-एच० डी० कार्यक्रम

एक कनिष्ठ शोध अध्येता ने शोध छात्र के रूप में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शोध कार्य हाथ में लिया है। परियोजना की रूपरेखा उन्होंने तैयार कर ली है। निदर्शन और आइटमों के पूर्व-परीक्षण का कार्य चल रहा है।

परिसरेतर गतिविधि

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के सहयोग से भोपाल नगर के विभिन्न स्कूलों में प्रत्येक सप्ताह फिल्म शो का आयोजन महाविद्यालय करता रहा है।

प्रदर्शन स्कूल

सत्र 1982-83 में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की स्थिति और 1983-84 में घोषित परिणाम इस प्रकार हैं—

कक्षा	छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	प्रतिशत
I	84	84	100
II	77	77	100
III	72	72	100
IV	79	79	100
V	82	78	95
VI	83	73	88
VII	81	66	81
VIII	62	57	92
IX	68	54	80
X	55	49	80
XI	19	19	100
XII	20	16	80

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की अध्यापक-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है।

1. नामांकन

समीक्षित अवधि में महाविद्यालय ने 1557 प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों और सेवारत अध्यापकों को नियमित अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया। अन्य अल्पावधि कोर्सों के द्वारा 226 अध्यापकों/अध्यापक-शिक्षकों का अभिविन्यास भी किया गया। महाविद्यालय से सम्बद्ध डी० एम० स्कूल ने प्राथमिक से +2 स्तर तक के 1065 छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की।

2. सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

गुणवत्ता से पूर्ण ऐसे अध्यापक तैयार करने के लिए जो स्कूल शिक्षा में वांछित परिवर्तन ला सकें, महाविद्यालय ने उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निम्न नियमित कोर्सों का आयोजन किया—

(अ) +2 स्तरीय छात्रों के लिए बी० एस-सी० (आनर्स) बी० एड० और बी० ए० (आनर्स) बी० एड० उपाधियों के हेतु एक चार-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम।

(ब) कला, विज्ञान व वाणिज्य के स्नातकों व परास्नातकों के लिए बी० एड० (माध्यमिक) उपाधि के हेतु एक-वर्षीय पाठ्यक्रम।

(स) कला व विज्ञान के स्नातकों/परास्नातकों के लिए बी० एड० (प्रारम्भिक) उपाधि हेतु एक-वर्षीय कार्यक्रम।

(द) शिक्षा में स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्तियों के लिए एम० एड० उपाधि हेतु एक-वर्षीय पाठ्यक्रम।

(य) विज्ञान स्नातकों के लिए एम० एस-सी० (लाइफ साइंस) एड० उपाधि हेतु एक दो-वर्षीय पाठ्यक्रम।

नामांकन

समीक्षित वर्ष में कोर्स-वार नामांकन की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है—

क्रम संख्या	कोर्स का नाम	नामांकन
1.	बी० ए० बी० एड० भाग I	54
2.	बी० ए० बी० एड० भाग II	31
3.	बी० ए० बी० एड० भाग III	44
4.	बी० एस-सी० बी० एड० भाग I	83
5.	बी० एस-सी० बी० एड० भाग II	68
6.	बी० एस-सी० बी० एड० भाग III	52
7.	बी० एड० विज्ञान (माध्यमिक)	100
8.	बी० एड० कला (माध्यमिक)	60
9.	बी० एड० विज्ञान (प्रारम्भिक)	13
10.	बी० एड० कला (प्रारम्भिक)	10
11.	बी० एड० वाणिज्य (माध्यमिक)	20
12.	एम० एड०	21
13.	एम० एस-सी० (लाइफ साइन्स) एड० भाग I	20
14.	एम० एस-सी० (लाइफ साइन्स) एड० भाग II	20
15.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) माध्यमिक वर्ष I	251
16.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) माध्यमिक वर्ष II	175
17.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) प्रारम्भिक वर्ष I	98
18.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) प्रारम्भिक वर्ष II	71
योग		= 1,191

जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है, विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं में छात्रों के कार्यकलापों में काफी सुधार इस वर्ष देखने को मिला है—

क्रम सं०	कोर्स का नाम	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र प्रतिशत
1.	बी० ए० बी० एड० भाग I	34	31 91.2
2.	बी० ए० बी० एड० भाग II	44	41 93.2
3.	बी० एस-सी० बी० एड० भाग I	73	69 94.5
4.	बी० एस-सी० बी० एड० भाग II	53	42 79.3
5.	बी० एड० विज्ञान (मा०)	103	81 78.6
6.	बी० एड० कला (मा०)	73	45 61.6
7.	बी० एड० वाणिज्य (मा०)	13	11 84.6
8.	बी० एड० कला (प्रा०)	13	11 84.6
9.	बी० एड० विज्ञान (प्रा०)	8	3 37.5
10.	एम० एस-सी० (लाइफ साइन्स) एड०	16	परिणाम प्रतीक्षित
11.	एम० एड०	—	—
12.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) मा०	194	113 58
13.	बी० एड० (एस० एस०/सी० सी०) प्रा०	84	60 71

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सेवारत अध्यापकों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए ये कार्यक्रम आरम्भ किये गये और इनमें (1) ग्रीष्म स्कूल-एवं-पत्राचार पाठ्यक्रम, और (2) विस्तार कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

(अ) ग्रीष्म स्कूल-एवं-पत्राचार पाठ्यक्रम

उत्कल विश्वविद्यालय की बी० एड० उपाधि प्रदान करने वाला यह कोर्स पूरी तरह अप्रशिक्षित स्नातक/परास्नातक अध्यापकों के लिए है जिनको पूर्वी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक/पूर्व माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अध्यापन का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

(ब) शिक्षा का व्यावसायीकरण

डी० एम० स्कूल में + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने के लिए महाविद्यालय ने प्रयास आरम्भ कर दिये हैं। इस कार्यक्रम में निम्न कोर्स चलाये जायेंगे—

(1) मूलभूत इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी,

(2) फ़ैब्रीकेशन प्रौद्योगिकी।

फ़ैब्रीकेशन प्रौद्योगिकी, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं है, के लिए पाठ्यचर्या तैयार है और संबद्धता संबंधी आवश्यक अनुमोदन के लिए भेजी जानी है। उपरोक्त दो क्षेत्रों में और (1) रेडियो इलेक्ट्रानिक सेवा और रखरखाव, और (2) यांत्रिक सेवा और रखरखाव के क्षेत्रों में निर्देशक सामग्री तैयार करने का कार्य भी चल रहा है।

उपकेन्द्र

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के अनुरोध पर, महाविद्यालय ने इंफाल में ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए एक उपकेन्द्र भी खोला है ताकि इस क्षेत्र में शेष बचे अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जा सके। इस उपकेन्द्र की गतिविधियाँ निम्न रही हैं—

प्रवेश-प्राप्त छात्रों की संख्या

कोर्स	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
माध्यमिक	129	134
प्रारंभिक	103	एक भी नहीं

छात्रों का निष्पादन

सम्मिलित छात्रों की संख्या	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	योग	प्रतिशत
137	—	58	58	42

(अ) विस्तार का कार्यक्रम

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और अधीक्षण/प्रशासनिक कमियों के सेवाकालीन शिक्षण के लिए महाविद्यालय ने गहन कार्यक्रम भी चलाये हैं। समीक्षित वर्ष में चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत सूचना वक्तव्य 3 में दी गयी है। इन कार्यक्रमों से क्षेत्र के 226 अध्यापकों/अध्यापक-शिक्षकों को लाभ पहुंचा है।

(ब) जनसंख्या शिक्षा परियोजना

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तक विस्तारित राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, इस महाविद्यालय में 1983 के उत्तरार्द्ध में आरंभ हुई। उसके बाद से, जनवरी 1984 में जन-

संख्या शिक्षा पर प्रथम क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया और इसमें भागीदार शिक्षा संकायों के अधीक्षकों ने जनसंख्या-शिक्षा की एक पाठ्यचर्या तैयार की जो विभिन्न विश्व-विद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रमों में लागू की जायेगी। उन्होंने एम० एड० के लिए एक अलग प्रश्नपत्र की पाठ्यचर्या भी तैयार की है। एक प्रलेखन केंद्र भी स्थापित किया जा चुका है।

अनुसंधान

आरंभ की गयी परियोजनाएं

महाविद्यालय ने कुछ शोध अध्ययन भी आरंभ किये हैं जो विभिन्न वित्तदाता संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं। इनकी विस्तृत सूचना इस प्रकार है—

वित्तदाता संस्था	विभाग			परियोजनाओं की कुल संख्या
	विज्ञान	शिक्षा	सामान्य शिक्षा	
ई० आर० आई० सी०	1	3	—	4
यू० जी० सी०	—	—	1	1
सी० एस० आई० आर०	1	—	—	1

उन्नत स्तरीय शोध का निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान और मानविकी में आचार्य और आचार्येतर उपाधियों के हेतु उन्नत शोधकार्य की सुविधाएं भी महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। जो शोध अध्येता और शिक्षक अध्येता विभिन्न विभागों से संबद्ध हैं, उनकी सूचना इस प्रकार है—

विभाग का नाम	आचार्य उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या	इस समय शोध-रत छात्रों की संख्या (आचार्य उपाधि के लिए)	आचार्येतर उपाधि के लिए नामांकित छात्रों की संख्या
शिक्षा	3	25	—
विज्ञान	—	9	—
मानविकी	2	6	—

वक्तव्य 3

1983-84 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित विस्तार सेवा कार्यक्रम

1	2	3	4	5
क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम, स्थान, समय	संबंधित राज्य	भागीदारों के प्रकार	भागीदारों की संख्या
1.	कम लागत के शिक्षण सहायक उपकरणों के विकास पर कार्यशाला, क्षेत्र शि० म०, भुवनेश्वर, 28 नवंबर से 5 दिसंबर, 1983	उड़ीसा, प० बंगाल, सिक्किम, मेघालय और असम	माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूलों के अध्यापक-शिक्षक एवं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के वरिष्ठ अध्यापक	24
2.	एस० यू० पी० डब्ल्यू० संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र शि० म०, भुवनेश्वर, 12-23 दिसंबर, 1983	उड़ीसा	माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	9
3.	माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में काव्य-शिक्षण की नवाचारी प्रवृत्तियां, क्षेत्र शि० म०, भुवनेश्वर, 5-10 दिसंबर, 1983	उड़ीसा एवं बिहार	माध्यमिक स्तर के सेवारत शिक्षक	16
4.	पूर्वी राज्यों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए शोध-प्रविधि, क्षेत्र शि० म०, भुवनेश्वर, 9-21 जनवरी, 1984	पूर्वी राज्य	प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षक	29
5.	द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी-शिक्षण, क्षेत्र शि० म०, भुवनेश्वर, 25-30 जनवरी, 1984	पूर्वी राज्य	अंग्रेजी-शिक्षण में रत प्रमुख व्यक्ति	26

1	2	3	4	5
6.	अपवाद-रूप बच्चों की शिक्षा संबंधी कार्यशाला, क्षेत्र ० म०, मुवनेश्वर, 20 फरवरी से 3 मार्च, 1984	पूर्वी राज्य	विशेष व एकीकृत स्कूलों के अध्यापक	40
7.	सेवारत अध्यापक-शिक्षकों (प्राथमिक शिक्षा) के लिए शारीरिक शिक्षा अभिविवन्यास कोर्स, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, कटक, 17-25 फरवरी, 1984	पूर्वी क्षेत्र	प्राथमिक शिक्षा के अध्यापक-शिक्षक	27
8.	हाई स्कूलों के सेवारत अध्यापकों के लिए शारीरिक शिक्षा, अभिविवन्यास कोर्स, शारीरिक शिक्षा विभाग, कल्याणी विश्वविद्यालय, 1-10 मार्च, 1984	पूर्वी क्षेत्र	हाई स्कूलों के शारीरिक शिक्षा अध्यापक	25
9.	पूर्वी राज्यों के अनवरत शिक्षा केंद्रों के समन्वयकों का सम्मेलन, राज्य शिक्षा संस्थान, इम्फाल, 1-2 मार्च, 1984	पूर्वी राज्य	पूर्वी राज्यों के अनवरत शिक्षा केंद्रों के समन्वयकगण	12
10.	माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान-शिक्षण-पुस्तकों का परीक्षण, क्षेत्र ० शिक्षा म०, मुवनेश्वर, 14-24 मार्च, 1984	पूर्वी क्षेत्र	प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षक	18

शोध और प्रकाशन

1. प्रो० के० सी० पंडा और श्रीमती एन० पंडा ने 'मैथमैटिक एक्टीविटीज एंड प्रोजेक्टिंग—ए रिव्यू आफ रिसर्च विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस' शीर्षक से एक मोनोग्राफ प्रकाशित कराया।

2. प्रो० के० सी० पंडा के मार्गदर्शन में प्रौढ़ अधिगम, मापांकन और भारतीय शिक्षा का इतिहास के क्षेत्रों में तीन शोधकर्मियों ने उत्कल विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में अपने शोध प्रबंध जमा किये।

3. डा० एस० के० महापात्र, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र, ने उड़ीसा के स्कूलों व महाविद्यालयों के लिए +2 स्तर की एक रसायन शास्त्र की पाठ्यपुस्तक सहलेखक के रूप में प्रकाशित कराई है।

4. विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए 'न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स' पर तीन शोध-आलेख डा० एन० खत्तार, रीडर, जन्तु विज्ञान, ने भेजे हैं।

5. डा० वी० पी० पंडा, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, बंगाली, को इस संस्था में साहित्य के दो-वर्षीय उन्नत अध्ययन कार्य के लिए यू० जी० सी० ने फेलोशिप प्रदान की थी। इस अवधि के पूरा होने पर यू० जी० सी० ने फेलोशिप की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है जिससे वे अपनी शोध परियोजना 'मध्यकालीन बंगाली साहित्य में उड़िया कवियों का योगदान' पूरी कर सकें।

6. भ्रूण-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौधों के विकास और संरचनात्मक जनन के अध्ययन हेतु सी० एस० आई० आर० की एक परियोजना प्रो० एम० वी० रामजी और उनके शोध-सहकर्मियों ने ली है।

अकादमीय व अन्य सम्मान

1. महाविद्यालय के शिक्षा-विभाग के प्रवक्ता श्री एम० डी० पंडा को महाविद्यालय-प्राचार्य डा० जी० बी० कानूनगो के निर्देशन में शोध के लिए पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गयी है।

2. डा० पी० सी० दास, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग को ब्रिटिश काउंसिल तकनीकी प्रशिक्षण फेलोशिप के लिए चुना गया है और वे गणित-शिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन रवाना हो चुके हैं।

3. कामेट (CAMET) कार्यक्रम के लिए गणित विभाग के प्राध्यापक डा० डी० सी० साहू चुने गये हैं और वे गणित-शिक्षण में 9 मास के उच्चतर अध्ययन के लिए ग्रेट ब्रिटेन रवाना हो चुके हैं।

4. भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक डा० जे० के० महापात्र ने मलेशिया में 19 से 29 दिसंबर, 1983 तक आयोजित यूनेस्को उपक्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया जिसका उद्देश्य भौतिक-विज्ञान और रसायनशास्त्र में चुनी हुई प्रयोगशाला तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना था।

5. शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० सी० पंडा ने, यू० जी० सी० के शिक्षा-एवं-संस्कृत

संबंधी भारत-अमरीका उप-आयोग के तत्वावधान में, एस० एन० डी० टी० महिला विश्व-विद्यालय, बंबई द्वारा आयोजित अपंग-शिक्षा पर एक सेमिनार (12-17 फरवरी, 1984) में भाग लिया, और "इंटीग्रेशन एंड मेनस्ट्रीमिंग" और "इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च" नामक दो आलेख प्रस्तुत किये।

6. अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डा० पी० के० दास ने गृह अर्थशास्त्र की +2 स्तरीय पाठ्य-चर्या की तैयारी हेतु हिसार में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया।

प्रयोगशालाएँ

समीक्षित अवधि में छात्रों के अनुदर्शन के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सामान्य शिक्षा, वाणिज्य और कृषि विभागों की प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का पूरा-पूरा उपयोग किया गया।

महाविद्यालय के छात्रों को फसल और उद्यान वैज्ञानिक परियोजनाओं से संबंधित कार्य-नुभव देने के लिए लगभग 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नर्सरी और छात्रों के एक प्रायोगिक भूखंड का विकास महाविद्यालय के कृषि विभाग ने किया है। इसके अतिरिक्त, लान, बाग और फलों के पौधों के पूरे, लगभग 1.00 हेक्टेयर के क्षेत्र का भी शैक्षिक उपयोग किया जाता है। प्रदर्शन और प्रायोगिक कार्य के लिए इससे संबद्ध एक छोटी सी दुग्धशाला और गोबर गैस संयंत्र भी हैं।

पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र कार्यालयों और राज्यों से सहयोग

समीक्षित वर्ष में महाविद्यालय स्टाफ के सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने में क्षेत्र के फील्ड सलाहकारों को सहयोग भी दिया।

फिर, अपनी बारी में, फील्ड सलाहकारों ने भी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ भी महाविद्यालय को दीं जिससे वह क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समुचित कार्यक्रम निर्धारित कर सके।

छात्र-गतिविधियाँ

महाविद्यालय की महिला टीम ने टेबुल टेनिस की विश्वविद्यालय चैंपियनशिप जीत ली है। तीन महिला टेबुल टेनिस खिलाड़ियों ने उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व किया और अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय महिला खेलकूद समारोह में भाग लिया।

छात्र और समुदाय

बी० एड० का पाठ्यक्रम संशोधित हो चुका है। इस पाठ्यचर्या के प्रश्नपत्र IX के अनुसार छात्रों को समुदाय में कोई परियोजना लेनी पड़ती है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों ने निम्न चार महत्वपूर्ण कार्य पूरे किये हैं।

(अ) रक्तदान शिविर

उड़ीसा रेड क्रॉस रक्त बैंक, कटक की सहायता से एक रक्तदान शिविर का आयोजन महाविद्यालय में 9 दिसंबर, 1983 को किया गया। चूंकि रक्तदान के इच्छुक सारे छात्र उस दिन रक्तदान न कर सके, एक अन्य शिविर का आयोजन 13 दिसंबर, 1983 को करना पड़ा। कुल मिलाकर 109 बोतल रक्त उड़ीसा रेड क्रॉस रक्त बैंक, कटक को दान किया गया।

(ब) सफाई कार्य

महाविद्यालय परिसर में दिसंबर 1983 में छात्रों ने सफाई कार्यों का आयोजन किया।

(स) पारिवारिक सर्वेक्षण

नंदन कानन और खंडगिरि नामक पड़ोसी गांवों में जनवरी 1984 में परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। बी० एड० कक्षाओं के लगभग 200 छात्रों ने सफलतापूर्वक कम से कम चार परिवार प्रत्येक का सर्वेक्षण किया।

(द) सामुदायिक अनौपचारिक शिक्षा

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र से कम से कम एक निरक्षर को साक्षर बनाने का अनुरोध किया गया। छात्रों ने संतोषजनक ढंग से यह कार्य पूरा किया।

बहुउद्देशीय प्रदर्शन स्कूल

महाविद्यालय के विभिन्न अध्यापक-शिक्षण कोर्सों में नामांकित प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रायोगिक स्कूल के रूप में यह स्कूल कार्य करता है। यहां शिक्षण की सुधरी हुई और प्रवर्तक विधियों का परीक्षण किया जाता है। वर्तमान सत्र में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 1,065 है।

1983-84 में नामांकन

कक्षा	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
छा. सं.	91	79	82	81	106	107	113	84	87	120	71	44

योग = 1,065

परिणाम-1983

परीक्षा का नाम	छात्रों की संख्या		प्रतिशत
	सम्मिलित	उत्तीर्ण	
अखिल-भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा	49	47	96
अखिल-भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा	114	114	100

1983 की बोर्ड परीक्षाओं के उत्तम परिणामों के अलावा, स्कूल के दो छात्रों को रा० शै० अ० एवं प्र० प० ने +2 कोर्स के लिए दो-वर्षीय एन० टी० एस० छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। केंद्रीय सामान्य ज्ञान अधिगम संस्थान, दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में स्कूल के तीन छात्रों ने पदक भी पाये हैं। यूनिवर्स, कटक और नेहरू यूथ अफेयर्स, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित साहित्यिक-सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया और चैंपियनशिप जीती है।

एन० सी० सी० के जूनियर डिबीजन आर्मी विंग ने भुवनेश्वर में 1983 के लिए मुख्यमंत्री की सर्वोत्तम-दल गणतंत्र दिवस शील्ड भी जीती है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर

दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पांडिचेरी—की अध्यापक-प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर पूरी करता है।

सेवापूर्व कार्यक्रम

सत्र 1983-84 में महाविद्यालय ने अध्यापक-शिक्षण संबंधी निम्न सेवापूर्व कोर्सों का आयोजन किया—

(i) एम० एस-सी० एम० एड० (गणित/भौतिक विज्ञान/रसायनशास्त्र) : चार सेमेस्टर के ये परास्नातक, कोर्स संबंधित विषय की परास्नातक स्तरीय विषयवस्तु और प्रासंगिक शिक्षाशास्त्रीय पक्षों से उसके संबंधों में दक्ष अध्यापकों की एक सेना तैयार करते हैं। इस तरह के प्रवर्तक कोर्सों की स्वीकृति से संबंधित समस्याओं के बावजूद, इन कोर्सों में उपाधि-प्राप्त व्यक्ति परास्नातक अध्यापकों/प्राध्यापकों के रूप में और शोध संस्थाओं में लिये जा रहे हैं।

(ii) एम० एड० : यह दो सेमेस्टर्स का एक कोर्स है जिसकी पाठ्यचर्या मैसूर विश्व-विद्यालय के एम० एड० कोर्स जैसी ही है और इसमें आरंभिक शिक्षा और विशेष शिक्षा

में विशेषता की व्यवस्था है। विशेषज्ञता के दूसरे मान्यता प्राप्त क्षेत्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शैक्षिक प्रशासन हैं।

(iii) बी० एड० : यह दो सेमेस्टरों का कोर्स है जिसमें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और साथ ही प्राथमिक शिक्षा के अध्यापन की विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। इस कोर्स की रूपरेखा रा० अ० शि० परिषद् के अनुमोदनों के अनुसार निर्धारित की गयी है, ताकि इस क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के लिए, उनके अध्यापक-शिक्षक पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना के कार्य में, यह एक प्रारूप का काम कर सके।

(iv) बी० एड० (ग्रीष्म स्कूल-एवं-पत्राचार पाठ्यक्रम) : यह कोर्स 1966 में आरंभ किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्र के अप्रशिक्षित बचे माध्यमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है। चूंकि यह लक्ष्य अब प्राप्त किया जा चुका है, इस वर्ष से इस कोर्स को समाप्त किया जा रहा है।

(v) बी० एस-सी० बी० एड०/बी० ए० बी० एड० : यह 8 सेमेस्टरों का एक कोर्स है जो बी० एस-सी०/बी० एड० उपाधियों के और विज्ञान एवं गणित/अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान के अध्यापक तैयार करने हेतु बी० एड० के शिक्षाशास्त्रीय कोर्स को एकीकृत करता है। भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन ने और देश की लगभग सारी संस्थाओं ने अध्यापक रूप में सेवाकार्य के लिए और उच्चतर अध्ययन के लिए इन कोर्सों को बी० एस-सी०/बी० ए० और बी० एड० उपाधियों के समकक्ष माना है।

ये सेवापूर्व कोर्स सेमेस्टर प्रणाली से चलाये जाते हैं। इनकी उपाधियां पाने वालों को देश की विभिन्न शिक्षा व शोध संस्थाओं में कुल मिलाकर अच्छा-खासा महत्व दिया जाता है।

विभिन्न कोर्सों में नामांकन की स्थिति और उनकी परीक्षाओं के परिणामों को निम्न दो तालिकाओं में दर्शाया गया है—

सत्र 1983-84 में छात्रों का नामांकन

कोर्स का नाम	पुरुष	स्त्री	योग
1. एम० एस-सी० एड० भौतिक विज्ञान प्रथम वर्ष	10	06	16
द्वितीय वर्ष	09	04	13
रसायन शास्त्र प्रथम वर्ष	08	16	24
द्वितीय वर्ष	11	11	22
गणित प्रथम वर्ष	03	14	17
द्वितीय वर्ष	05	08	13
2. एम० एड० —	13	05	18
3. बी० एड० माध्यमिक	58	70	128
प्राथमिक	10	07	17

1	2	3	4
4. बी० एस-सी० एड०	23	36	59
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष	17	38	55
तृतीय वर्ष	18	27	55
चतुर्थ वर्ष	23	31	54
5. बी० ए० एड०	08	22	30
प्रथम वर्ष			
द्वितीय वर्ष	08	23	31
तृतीय वर्ष	05	14	19
6. बी० एड० (ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम)	159	34	193

वर्ष 1983-84 में महाविद्यालय के विभिन्न कोर्सों का परिणाम

कोर्स का नाम	उत्तीर्ण छात्र		
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1. एम० एस-सी० एड० अंतिम गणित	4	6	—
भौतिक विज्ञान	5	4	1
रसायन शास्त्र	10	4	—
2. बी० एड० अंतिम			
प्राथमिक	21	2	—
माध्यमिक	81	88	—
3. एम० एड० अंतिम	—	18	—
4. बी० एस-सी० एड० अंतिम	— 17	[1	18
5. बी० ए० एड० अंतिम	—	—	—
(बी० ए० एड० के छात्र अंतिम परीक्षा मई 1985 में देंगे।)			
6. बी० एड० (ग्री० स्कूल एवं प० पा०) —	28	124	33

सेवाकालीन शिक्षण एवं विस्तार

महाविद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षण पर प्रमुख रूप से बल देता है। क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके महाविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में सेवाकालीन अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिनके लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेष-ज्ञता उपलब्ध हो। इस वर्ष निम्न प्रमुख क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है—

- (अ) विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में अन्तर्वस्तु का समुद्धीकरण।
- (ब) भाषा-शिक्षण की कुशलताएं।
- (स) विज्ञान में अन्वेषी परियोजनाओं का विकास।

- (द) व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रमों का विकास ।
- (य) अपंगों की एकीकृत शिक्षा ।
- (र) जनसंख्या शिक्षा ।
- (ल) मूल्यांकन की रणनीतियां ।
- (व) राष्ट्रीय प्रतिभा खोजी परीक्षाएं ।
- (क) रा० अ० शि० परिषद् के अनुमोदन के अनुसार अध्यापक-शिक्षण पाठ्यक्रम का पुनर्गठन ।

समीक्षित वर्ष में आयोजित सेवाकालीन कार्यक्रमों की सूची निम्न तालिका में दी गयी है ।

1983-84 में आयोजित सेवाकालीन कार्यक्रम

क्रम सं०	कार्यक्रम का शीर्षक	भागीदारों की संख्या	समय	स्थान
1	2	3	4	5
1.	कक्षा VI और VII में नयी पाठ्यचर्या के अध्यापन के संबंध में आंध्र प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	40	16-21 मई, 1983	हैदराबाद
2.	स्कूल प्रशासन की नयी प्रवृत्तियों और स्कूल पाठ्यक्रम की उदीयमान प्रवृत्तियों के बारे में शैक्षिक प्रशासकों और हेड-मास्टर्स के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	23	26-28 मई, 1983	क्ष० शि० म०, मैसूर
3.	शिक्षण कार्यक्रम में बी० एस-सी० एड० आंतरिक प्रशिक्षण के लिए आंतरिक प्रशिक्षण-पूर्व सम्मेलन	22	20-22 जुलाई, 1983	क्ष० शि० म०, मैसूर
4.	चुम्बकत्व और विद्युत-चुम्बकीय प्ररण के लिए सहायक शिक्षण सामग्री के विकास पर कार्यशाला	16	8-12 अगस्त, 1983	क्ष० शि० म०, मैसूर
5.	केंद्रीय विद्यालयों के परास्नातक अध्यापकों के लिए विशिष्ट सापेक्षता संबंधी अनुदर्शी सामग्री के परीक्षण पर कार्यशाला	15	16-20 अगस्त, 1983	क्ष० शि० म०, मैसूर

1	2	3	4	5
6.	दक्षिणी क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा के और व्यावसायिक शिक्षा के निदेशकों की मीटिंग	19	3 अक्टूबर, 1983	मद्रास
7.	विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों का सम्मेलन	17	18 सितंबर, 1983	क्षे० शि० म०, मैसूर
8.	शिक्षण कार्यक्रम में बी० एड० आंतरिक प्रशिक्षण के सहयोगी अध्यापकों का सम्मेलन	44	10-12 नवंबर, 1983	क्षे० शि० म०, मैसूर
9.	कर्नाटक के हाई स्कूल अध्यापकों के लिए प्रेक्षण खगोलशास्त्र का अभिविन्यास कार्यक्रम	33	26-29 दिसंबर, 1983	क्षे० शि० म०, मैसूर
10.	केरल के प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए माइक्रो-शिक्षण का प्रशिक्षण कोर्स	35	16-21 जनवरी, 1984	त्रिचूर
11.	दक्षिणी क्षेत्र के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए विशेष शिक्षा संबंधी अभिविन्यास कार्यक्रम	16	21-24 फरवरी, 1984	क्षे० शि० म०, मैसूर
12.	दक्षिणी क्षेत्र के सेंट्रल स्कूल अध्यापकों के लिए प्रेक्षण खगोलशास्त्र का अभिविन्यास कोर्स	24	6-9 मार्च, 1984	क्षे० शि० म०, मैसूर
13.	रा० अ० शि० प० के अनुमोदना-नुसार क्षेत्र में अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम (माध्यमिक) के पुनर्गठन पर सम्मेलन	13	15-17 मार्च, 1984	हैदराबाद
14.	दक्षिणी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों के +2 स्तरीय अध्यापकों के लिए रसायनशास्त्र की अन्वेषी परियोजनाएं तैयार करने हेतु कार्यशाला	20	19-23 मार्च, 1984	क्षे० शि० म०, मैसूर
15.	तमिलनाडु के अध्यापकों के लिए प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी के संभाषण कौशल के विकास हेतु पैकेज तैयार करने के लिए कार्यशाला	4	19-23 मार्च, 1984	क्षे० शि० म०, मैसूर

शोध

सेवापूर्व और सेवाकालीन कार्यक्रमों की थका देने वाली प्रवृत्ति के बावजूद, महाविद्यालय शैक्षिक अनुसंधान की गतिविधियों में भी सक्रिय है। महाविद्यालय संकाय के मार्गदर्शन में शोधरत तीन कनिष्ठ शोध अध्ययताओं के अलावा, संकाय सदस्य भी विभिन्न प्रकार की शोध गतिविधियों में लगे हुए हैं। महाविद्यालय में जारी शोध गतिविधियों और उनकी प्रगति की सूचना नीचे दी गयी है—

1. एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड इंपैक्ट आफ आर० सी० ई० (मैसूर) प्रोग्राम्स (एरिक परियोजना) : तथ्य संग्रह के उपकरण तैयार किये जा चुके हैं।
2. ऐन एक्सपेरिमेंटल माडल फार ए को-भापरेटिव रिमेडियल सेंटर इन ऐन इंस्टीट्यूशनल कैंपस, आर० सी० ई०, मैसूर (एरिक परियोजना) : परिसर के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ पहचानी जा चुकी हैं।
3. ए कंपेरिजन आफ साइको-सोशल डवलपमेंट आफ प्राइमरी (I टू IV) चिल्ड्रेन विद एंड विदाउट दि बैक ग्राउंड आफ प्री-प्राइमरी एजुकेशन : शोध कार्य के विषयकों की पहचान हो चुकी है और उन पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण किये जा रहे हैं।
4. चिल्ड्रेन हू फेल इन दि एलीमेंट्री ग्रेड्स एंड देयर पैरेंट्स : ऐसे बच्चों की पहचान की जा चुकी है और उनकी जीवन विषयक सामग्री एकत्र की जा रही है।
5. ऐन एनेलिटिकल स्टडी आफ सम कोरिलेट्स इन दि एकजीबीशन आफ साइंस कांसेप्ट्स इन स्कूल चिल्ड्रेन (पी-एच० डी० शोध) : तथ्य संग्रह लगभग पूरा हो चुका है।
6. ऐन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई बेरियस पैटर्न्स आफ फैमिली लाइफ इन इंडिया : शोधकार्य समाप्त होने वाला है।
7. ऐन इन्वेस्टिगेशन टू एसेस दि एक्सपर्टाइज इन पापुलेशन एजुकेशन आफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम परसोनेल इन पांडिचेरी एंड इट्स रिलेशन-शिप टू ऐटीट्यूड्स टूवर्ड्स सच प्रोग्राम (एन० सी० ई० आर० टी० रिसर्च फेलोशिप) : उपकरण तैयार किये जा रहे हैं।

8. प्रोग्राम आफ हेल्थ एंड फिजीकल एजुकेशन फार दि सेकंडरी स्कूल्स आफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड देहली (पी-एच० डी० शोध) : शोध समाप्त हो चुका है और शोध ग्रंथ अब जमा किया जाने वाला है।
9. डवलपमेंट आफ ए कंपीटेंसी बेस्ड क्यूरीक्यूलम डिजाइन फार दि मेथोडोलॉजी आफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड इट्स वैलिडेशन : शोध समाप्त हो चुका है, शोध ग्रंथ अब लिखा जा रहा है।
10. होम लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज एंड एजुकेशनल परफार्मेंस—एन इंपिकल स्टडी आफ शीड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रेन आफ डिफरेंट सोशल क्लासेज (एन० सी० ई० आर० टी० रिसर्च फेलोशिप) : भाषायी योग्यता परीक्षकों और उपलब्धि परीक्षकों का निर्माण और प्रमाणीकरण चल रहा है।
11. फौट फाइंडिंग सर्वे आन एजुकेशन आफ दि डिसएबल्ड चिल्ड्रेन इन दि सदर्न रीजन : तथ्य संग्रह का कार्य आरंभ हो चुका है।
12. ए कंप्रेहेन्सिव स्टडी आफ दि ओपेन-एंडेड एप्रोच इन परफार्मिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स वर्सस ट्रेडीशनल एप्रोच ऐट हायर सेकंडरी स्टेज (एन० सी० ई० आर० टी० रिसर्च फेलोशिप) : यह परियोजना मैसूर नगर के दो महाविद्यालयों के पी० यू० सी० प्रथम वर्ष के 200 छात्रों को लेकर चल रही है। मापन, यांत्रिकी, ध्वनि और द्रवों के क्षेत्रों में दोनों समूहों पर भौतिकी के प्रयोगों और तथ्य संग्रह जारी हैं।

अन्य प्रमुख कार्यक्रम

1. जनसंख्या शिक्षा : शिक्षा के विभिन्न स्तरों—दक्षिणी क्षेत्र के महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में शिक्षा में एम० फिल० और पी-एच० डी० कोर्सों, माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण परास्नातक स्तरों—पर जनसंख्या शिक्षा के संस्थानीकरण कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को अब इस महाविद्यालय तक भी विस्तारित किया गया है।

समीक्षित अवधि में निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है—

- (अ) दक्षिणी क्षेत्र के विश्वविद्यालय के शिक्षा संकायों के प्रोफेसरों और संकाय प्रमुखों का सम्मेलन, 17-19 नवंबर, 1983।
- (ब) शिक्षा महाविद्यालयों में उपयोग के लिए शिक्षक निर्देशिका विकसित करने हेतु जनसंख्या शिक्षा संबंधी अनुदर्शी सामग्री की तैयारी पर एक कार्यशाला, 9-13 जनवरी, 1984।
- (स) तयार अनुदर्शी सामग्री को अंतिम व परिष्कृत रूप देने और अध्यापक निर्देशिका को

अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला, 20-24 फरवरी, 1984। यह निर्देशिका अब प्रेस में है।

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी : महाविद्यालय ने कंप्यूटर साक्षरता का एक कार्यक्रम आरंभ किया है जो एक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र है। एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र स्थापित किया जा चुका है और महाविद्यालय को कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने वाले केंद्र का रूप देने के लिए अब उसका आगे विकास किया जा रहा है।

3. सामान्य शिक्षा में प्रौद्योगिकी पर यूनेस्को परियोजना: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने महाविद्यालय को "सामान्य शिक्षा में प्रौद्योगिकी" पर एक परियोजना की स्वीकृति दी है। इस परियोजना का लक्ष्य है विज्ञान-शिक्षण के द्वारा प्रौद्योगिक डिजाइन प्रक्रिया के ऐसे निहितार्थों को और समस्या-समाधान की ऐसी कुशलताओं को सामने लाना जो हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान-प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से लागू किये जा सकें। यह परियोजना एशिया के कुछ अन्य देशों को भी स्वीकृत की गयी है, और इस संस्था में अब तक किये गये कार्य को संग्रहित करके बीजिंग (चीन) में आयोजित सम्मेलन में रखा गया जिसमें डा० ए० एन० माहेस्वरी ने भाग लिया। महाविद्यालय संकाय और स्कूल ऐसे छात्र हस्तपुस्तिका, अध्यापक हस्तपुस्तिका और किट्स के विकास के लिए उत्तरदायी रहे हैं जो कुछ चुने हुए विषयों—ऊर्जा और सरल यंत्र, घर्षण, प्रकाश के लिए ज्वलन, घरेलू विद्युत और विद्युत-चुम्बकीय उपाय - से संबंधित हैं। प्रदर्शन स्कूल में इन सामग्रियों का परीक्षण किया जायेगा जिससे परियोजना के व्यापकेतर विकीर्णन के लिए उनकी प्रभावशालिता का निश्चय किया जा सके।

4. क्षेत्र के राज्य शिक्षा विभागों व अन्य अधिकरणों के साथ संकाय का सहयोग: हालांकि अधिकांश आरंभ किये गये कार्यक्रम महाविद्यालय के परिसर में ही चलाये जाते हैं, लेकिन राज्य शिक्षा विभागों व अन्य अधिकरणों के साथ सहयोगपूर्ण गतिविधियों, सलाह आदि के लिए संकाय सदस्यों को क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर भी नियुक्त किया जाता है।

5. महाविद्यालय/स्कूल को संकाय को प्राप्त सम्मान :

(i) गणित-शिक्षण व विज्ञान-शिक्षण में उन्नत प्रशिक्षण के लिए निम्न संकाय सदस्य ब्रिटिश कौंसिल द्वारा चुने गये और वे ग्रेट ब्रिटेन में नौ मास तक प्रशिक्षणरत रहे —

(अ) श्रीमती एस० वसंत, प्राध्यापक, गणित विभाग।

(ब) श्री बी० सी० बास्ती, प्राध्यापक, गणित विभाग।

(स) डा० एस० सी० जैन, रीडर, शिक्षा विभाग।

(द) डा० एल० श्रीकांतप्पा, रीडर, जन्तु विज्ञान विभाग।

(ii) डा० सी० शेपाद्रि, प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-I ने "अध्यापकों की बहुआयामी भूमिका" पर विशेषज्ञ आलेख लिखने के लिए आमंत्रित किया। आयोग की 23-25 जनवरी, 1984 की दिल्ली मीटिंग में उन्हें अपना आलेख पढ़ने के लिए निर्मंत्रित किया गया।

(iii) रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् की "सेमिनार रीडिंग कार्यक्रम" योजना के अंतर्गत स्टाफ के निम्न सदस्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया —

1. डा० एस० दंडपाणि
2. श्री ए० नागराज
3. श्रीमती एच० पी० श्यामला
4. श्रीमती एस० के० श्यामला।

प्रदर्शन स्कूल

महाविद्यालय के पास एक स्कूल भी है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली से संबद्ध है। यह स्कूल महाविद्यालय और उसके नवाचार कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला का कार्य करता है। नामांकन और परिणामों की सूचना नीचे की तालिका में दी गयी है।

बहुउद्देश्यीय प्रदर्शन स्कूल में नामांकन व परिणाम 1983-84

कक्षा	नामांकन	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
I	90	88
II	84	75
III	84	81
IV	91	81
V	80	71
VI	86	74
VII	84	76
VIII	90	81
IX	82	74
X	65	62
XI	29	24
XII	23	19

समीक्षित वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरस्कारों और विशिष्टताओं से स्कूल का सम्मान बढ़ा है। संस्कृति, साक्षरता, सामान्य ज्ञान, खेल-कूद और क्रीड़ा के क्षेत्रों में इस स्कूल और अन्य स्थानीय स्कूलों द्वारा आयोजित अंतर-हाई स्कूल प्रतियोगिताओं में हमारे छात्रों को अपनी-अपनी रुचि के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर मिला।

छात्रों के सराहनीय प्रयासों से विभिन्न कार्यक्रमों में अनेक संस्थागत और व्यक्तिगत पुरस्कार मिले हैं।

हिंदी का प्रचार

महाविद्यालय के सारे अहिंदीभाषी स्टाफ सदस्यों में हिंदी सीखने और उसका अधिकाधिक व्यवहार करने की चेतना उत्पन्न हुई है।

कर्मचारियों के लाभ के लिए महाविद्यालय में हिंदी की कथाएं आरंभ की जा चुकी हैं। प्रबोध परीक्षा में 11 और प्रवीण परीक्षा में 10 कर्मचारी सम्मिलित हुए। प्राज्ञा परीक्षा में 25 कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

शैक्षिक मनोविज्ञान

प्रशिक्षण

निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अध्यापक-शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के क्रियान्वयन और परीक्षाओं की व्याख्या का प्रशिक्षण कोर्स

इस कोर्स का अल्पावधि लक्ष्य है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के व्यवहार, अंकगणना, व्याख्या और संचार की कुशलताओं में अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जिससे वे छात्रों की योग्यता, रुचि और व्यक्तित्व को ठीक-ठीक समझ सकें। बच्चों की योग्यताओं के अनुसार शिक्षा देने के संबंध में अध्यापकों की क्षमता इस तरह बढ़ेगी और कक्षा में अध्यापक-छात्र अन्तर्क्रिया की गुणवत्ता में भी इससे सुधार होगा। इसका दीर्घावधि लक्ष्य बी० एड० स्तर के सेवापूर्व कोर्सों में मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा कुशलताओं का विस्तार करना है। यह कोर्स बहुत अधिक प्रायोगिक है और इसकी अवधि 8 दिनों की है।

1983-84 में निम्न तीन कोर्स चलाये गये—

राज्य	स्थान	अवधि	भाग्यदारी की संख्या
1. पश्चिमी उ० प्र०	दिल्ली	12-19 दिसंबर, 1983	16
2. राजस्थान, म० प्र० एवं जम्मू-कश्मीर	दिल्ली	16-23 जनवरी, 1984	12
3. म० प्र० व उ० प्र०	दिल्ली	28 मार्च 4 अप्रैल, 1984	12

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, कुछ महाविद्यालयों ने भी अपने बी० एड० कोर्सों में मनो-वैज्ञानिक परीक्षण प्रायोगिकी आरम्भ कर दी है।

माध्यमिक अध्यापक-शिक्षण संस्थाओं और राज्य शिक्षा संस्थाओं/रा० शि० अ० एवं प्र० परिषद् के अभिकर्मियों के लिए अधिगम एवं विकास पर समृद्धीकरण कोर्स

अनुदर्शन पर बल देते हुए भी अध्यापक प्रायः अधिगमकर्त्ता की ओर से उदासीन हो जाते हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की कोई रूपरेखा उनके मानस में होती है लेकिन कुछ न्यूनतम तत्परता, विकास और प्रवेश से युक्त छात्रों की आवश्यकताएं समझते वे नहीं लगते जबकि

वे प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण-अधिगम स्थितियों में इन व्यवहारों का फलप्रद उपयोग कर सकते हैं। पुरस्कार एवं प्रबलन के सिद्धांतों को अधिगम स्थितियों के प्रबंधन में अनदेखा कर दिया जाता है।

जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए दिल्ली में 16-25 जनवरी, 1984 की अवधि में एक कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में 15 व्यक्ति सम्मिलित हुए और भागीदारों के ही मूल्यांकन के अनुसार यह कोर्स बहुत ही प्रायोगिक और उपयोगी रहा।

प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षण संस्थाओं और राज्य शिक्षा संस्थानों/रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् के स्टाफ सदस्यों के लिए अधिगम एवं विकास पर समृद्धीकरण कोर्स

प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के अधिगम और विकास में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु प्रायः ही उनके पास अधिगम और विकास प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान नहीं होता। इसके अतिरिक्त, वे बच्चों को प्रोत्साहन देने और उनके लिए स्कूल को आकर्षक स्थान बनाने के उद्देश्य से प्रबलन के सिद्धांतों को सही ढंग से लागू करने में अक्षम होते हैं। कक्षा का प्रबंध भी प्रायः बहुत ही व्यक्तिवादी होता है।

केरल और तमिलनाडु राज्यों के लिए पहले कोर्स का आयोजन 2 से 11 जनवरी, 1984 तक त्रिचूर (केरल) में किया गया। इसमें 27 व्यक्तियों ने भाग लिया।

दूसरे कोर्स का आयोजन प० बंगाल और उड़ीसा के लिए राहड़ा (24 परगना, प० बंगाल) में 20 से 29 फरवरी, 1984 तक किया गया जिसमें 19 भागीदार थे।

प्रारंभिक स्कूल स्तर के अध्यापक-शिक्षकों के लिए स्कूल-वातावरण में व्यवहार-संशोधन तकनीकों के उपयोग पर कार्यशाला

व्यवहार-संशोधन के सिद्धांत व व्यवहार से अध्यापक-शिक्षकों को परिचित कराना, उसके प्रायोगिक उपयोग का प्रदर्शन करना और कक्षा की स्थितियों में आसानी से लागू किए जा सकने वाली कुछ आसान तकनीकों का प्रशिक्षण उनको देना इस कार्यशाला के लक्ष्यों में थे।

दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पहली, लखनऊ में 27 जनवरी से 5 फरवरी, 1984 तक और दूसरी, नौगांव में 19 मार्च से 28 मार्च, 1984 तक। उत्तर प्रदेश और असम क्रमशः 18 और 10 व्यक्तियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

राज्य शै० अ० एवं प्र० परिषद्, पटना में बिहार सरकार ने, रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् के साथ सलाह करके, व्यवहार-संशोधन संबंधी एक यूनिट आरंभ की है। व्यवहार-संशोधन तकनीकों पर कुछ और क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्सों की योजना तैयार की जा रही है।

विकास कार्यक्रम

रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् के पास निम्न विकास कार्यक्रम हैं—

(i) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से संबंधित संदर्भ-सामग्री उपलब्ध कराना,

- (ii) मनोविज्ञान-शिक्षण के लिए उपलब्ध अनुदर्शी सामग्री में सुधार करना,
- (iii) स्कूल, घर और सामान्य जगहों में समायोजन के लिए मार्गदर्शन सेवाएँ जुटाना,
- (iv) प्राथमिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए व्यवहार-संशोधनों की निर्देशिका का विकास करना।

समीक्षित वर्ष में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है—

राष्ट्रीय परीक्षण विकास पुस्तकालय (एन० टी० डी० एल०)

परिषद् द्वारा स्थापित यह पुस्तकालय (i) संदर्भ परीक्षण पुस्तकालय, (ii) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए एक सूचना केंद्र, (iii) सभी प्रकाशित परीक्षणों की आलोचनात्मक समीक्षाओं संबंधी अधिकरण, और (iv) परीक्षणों के विकास में रही कमियों की पहचान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका संचालन एक सलाहकार समिति करती है जिसके सदस्य देश के शीर्षस्थ मनोविज्ञान मापन विशेषज्ञ हैं।

इस पुस्तकालय की केंद्रीय सलाहकार समिति की पांचवीं मीटिंग 26 मार्च, 1984 को हुई।

पी-एच० डी० कार्यक्रमों के अंग के रूप में विकसित या प्रयोग किये गये 577 प्रकाशित और 233 अप्रकाशित परीक्षण अब तक इस पुस्तकालय ने एकत्र किये हैं।

पुस्तकालय ने अब तक निम्नलिखित 3 बुलेटिनों का प्रकाशन किया है—

एन० टी० डी० एल० बुलेटिन :

अंक 13 { अप्रकाशित भारतीय परीक्षणों से संबंधित सूचना
(सितंबर 1983) { (बुद्धि, रचनात्मकता, उन्मुखता और सांख्यिक वातावरण)

अंक 14 { प्रकाशित भारतीय बुद्धि परीक्षणों की समीक्षाएं (बुद्धि)
(दिसंबर 1983) {

अंक 15 { प्रकाशित भारतीय व्यक्तित्व परीक्षणों की समीक्षाएं (व्यक्तित्व)
(मार्च 1984) {

“गाइडलाइंस फार टेस्ट रिव्यूज” नाम से एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी है।

मानसिक मापन वार्षिकी : पिछले वर्ष तैयार परीक्षण-समीक्षाओं को एक संपादक मंडल ने अंतिम रूप दिया है। मानसिक मापन वार्षिकी के रूप में उनको प्रकाशित करने की कार्यवाही चल रही है। इसमें 34 बुद्धि परीक्षण समीक्षाएं और 48 व्यक्तित्व परीक्षण समीक्षाएं सम्मिलित हैं।

परीक्षण-समीक्षाएं : इस वर्ष रुचि-कोषों और प्रवृत्ति मापकों की समीक्षा की गयी। 27 से 30 सितंबर, 1984 तक एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इसमें उपस्थित 10 समीक्षकों ने 30 परीक्षणों की समीक्षा की। जनवरी-मार्च, 1984 की अवधि में दो और कार्य-शालाओं का आयोजन हुआ और उनमें 29 परीक्षणों की समीक्षाएं हुईं। साथ में, 9 व्यक्तित्व परीक्षणों की समीक्षाएं भी की गयीं।

परीक्षण-रचना पर सेमिनार

व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण रचना पर एक सेमिनार मार्च 1984 में हुआ जिसका लक्ष्य था पिछली व्यक्तित्व परीक्षण समीक्षाओं में देखी गयी कमियों के प्रकाश में व्यक्तित्व परीक्षणों की रचना संबंधी विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों की समझदारी बढ़ाना जिससे वर्तमान परीक्षणों में सुधार किया जा सके, और भारतीय समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में व्यक्तित्व मापन की नयी अवधारणाओं पर विचार-विमर्श करना। विचार-विमर्श 14 आलेखों पर हुआ और 17 अनुमोदित किए गए।

बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षणों के समीक्षकों के संपादक मंडल की मीटिंगें अगस्त और अक्टूबर 1983 में हुईं जिनमें व्यक्तित्व परीक्षण की 42 और बुद्धि परीक्षण की 16 समीक्षाओं को संपादित करके अंतिम रूप दिया गया।

कक्षा XI और XII के लिए मनोविज्ञान प्रायोगिकी निर्देशिका का विकास

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा XI और XII के लिए मनोविज्ञान प्रायोगिकी की दो निर्देशिकाएँ रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने तैयार की हैं। विशेषज्ञों द्वारा इनकी समीक्षा का कार्य चल रहा है।

मनोवैज्ञानिक सेवा केंद्र

स्कूल जाने वाले बच्चों की समायोजन और अधिगम, कोर्सों का चुनाव आदि की समस्याएँ सुलझाने और अंततः उनको चिकित्सात्मक और सूचनात्मक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए इस केंद्र की स्थापना हुई है। केंद्र ने 9 पंजीकृत केसों पर कार्य किया है।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए आवर्ष पाठ्यचर्या (मनोविज्ञान) की तैयारी

पिछले एक या दो दशकों में मनोविज्ञान की निरंतर परिवर्तनशील अंतर्वस्तु से सामंजस्य बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि विभिन्न राज्यों की स्कूली शिक्षा के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की मनोविज्ञान-पाठ्यचर्याओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाए। इस परियोजना का उद्देश्य है विभिन्न राज्यों की मनोविज्ञान-पाठ्यचर्याएँ एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना, उनके सुधार के लिए सुझाव देना, और राज्यों के लिए एक परिष्कृत, समया-नूकूल पाठ्यचर्या का मसौदा तैयार करना। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। विभिन्न राज्यों की पाठ्यचर्याएँ भी एकत्र की जा चुकी हैं।

स्कूल शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के अध्यापकों के लिए स्कूल-वातावरण में व्यवहार संशोधन तकनीकों के उपयोग पर अनुदर्शी पुस्तिका का विकास

कक्षागत व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया जा चुका है।

शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन

जुलाई 1983 से एरिक परियोजना के रूप में 'साइकोलाजिकल कैरेक्टरस्टिक विज-ए-विज एजुकेशनल एंड वोकेशन प्लानिंग आफ शीड्यूल्ड कास्ट एंड नान-शीड्यूल्ड कास्ट हाई स्कूल ब्वायज' पर एक अध्ययन आरंभ हो चुका है। यह अध्ययन 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 के अंतर्गत आता है। हरियाणा के 33 राजकीय विद्यालयों से, जो इस अध्ययन के सैम्पलिंग ग्रेड में सम्मिलित हैं, तथ्य संग्रह का कार्य पूरा हो चुका है। (यह एक अनवरत एरिक परियोजना है।)

'एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लानिंग, एकेडमिक एचीवमेंट एंड सेलैक्टिड साइकोलाजिकल एंड होम बैक ग्राउंड बेरिगबुलस आफ ट्राइबल हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन एंड एराउंड शिलांग (मेघालय)' नाम से भी एक अध्ययन चल रहा है। यह भी नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 के अंतर्गत आता है। (यह भी एक अनवरत एरिक परियोजना है।)

'रिसर्च आन फर्स्ट जेनेरेशन लर्नर्स इन क्लास I' नामक परियोजना के लिए अतिरिक्त बहुचालक सांख्यिकीय विश्लेषण भी इस वर्ष संपन्न हुए और उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों से भिन्न शिक्षार्थियों के लिए और स्कूलों के लिए परिवर्तनशील विकास-स्तरों की अंतर्देशीय तुलनाओं से संबंधित तीन पूरक अध्ययन भी संपन्न हुए। इन तीनों की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और दो को प्रकाशन के लिए पत्रिकाओं में भेजा गया है। कक्षा X स्तर के अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट के तीन अन्य खंड भी पूरे हो चुके हैं।

'फैक्टर्स अफेक्टिंग कैरियर च्वायसेज आफ एडोलसेंट्स' नामक परियोजना पर आगे भी कार्य हुआ है। आंकड़ों को छिद्रण के लिए भेजा गया है।

'दि एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लानिंग आफ ब्वायज विद सुपीरियर स्कालैस्टिक एबिलिटी' नामक परियोजना के सांख्यिकीय विश्लेषण पूरे हो चुके हैं और उन पर आधारित दो रिपोर्ट तैयार हैं।

'ए स्टडी आफ दि सेल्फ-कॉन्सेप्ट आफ ब्वायज विद सुपीरियर स्कालैस्टिक एबिलिटी' नामक परियोजना के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण और तालिका में उनको व्यवस्थित रूप देने का कार्य पूरा हो चुका है। सांख्यिकीय विश्लेषण का कुछ कार्य संपन्न हो चुका है और आंशिक रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। स्वावधारणा कोष निर्देशिका का मसौदा भी तैयार किया गया है।

'एडजस्टमेंट पैटर्न आफ ब्वायज विद सुपीरियर स्कालैस्टिक एबिलिटी' नामक परियोजना का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार है।

शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन का 22 वां डिप्लोमा कोर्स 22 अगस्त, 1982 को आरंभ होकर 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त हुआ। इस कोर्स में 29 छात्र थे जिनमें से 2 मणिपुर और नागालैंड सरकारों द्वारा (प्रत्येक एक) भेजे गए थे। कोर्स में आने वाले 29 प्रशिक्षणार्थियों में से 4 बीच में ही छोड़ गए। अनुसूचित जाति के 5 छात्रों समेत 25 छात्रों को 250 रु० प्रतिमाह का भत्ता दिया जाता रहा है। परीक्षा में सम्मिलित इन 25 छात्रों में से 23 उत्तीर्ण हुए।

शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन का 23 वां डिप्लोमा कोर्स 1 अगस्त, 1983 से आरंभ हो चुका है। इसमें 32 छात्र हैं जिनमें 7 छात्र मध्य प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, और राजस्थान सरकारों द्वारा भेजे गये हैं।

मन्त्रीमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्त्वाधान में, आयोजित "एक्सेलेंस इन साइंस" पर एक सेमिनार में दो संकाय सदस्य भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए। यह सेमिनार सितंबर 1983 में हुआ।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोगों के संबंध में अध्यापक-शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, राज्य शिक्षा संस्थान, गुजरात की सहायता एक संसाधन-व्यक्ति भेजकर की गयी।

सी० आई० आर० टी० ई० एस०, पूसा, नई दिल्ली द्वारा जिला रोजगार अधिकारियों के लिए आयोजित सेवाकालीन कार्यक्रमों में भी संसाधन-व्यक्ति भेजे गए।

मिजोरम के 9 हाई स्कूल अध्यापकों के लिए नई दिल्ली में चार सप्ताह का और अरुणाचल प्रदेश के अध्यापकों के लिए भी राज्य शिक्षा संस्थान, चांगलांग में चार सप्ताह के कैरियर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1984 में आयोजित किए गए।

सूचना के लिए निवेदन करने वाले स्कूलों को सूचना और मार्गदर्शन सामग्री प्रदान की गयी। देश भर के अनेक शोधकर्त्ताओं और व्यावसायिक सूचना के इच्छुकों ने गाइडेंस लैबोरेटरी का, विशेषकर उसके व्यावसायिक सूचना कुंज का भ्रमण करके लाभ प्राप्त किया।

कैरियर टीचर्स के लिए बुक आफ रीडिंग्स के कुछ अध्यायों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पुस्तक का प्रकाशन-पूर्व मसौदा मिमियोग्राफ रूप में सुरक्षित किया जा चुका है।

ग्रेड 10 के फर्स्ट जेनेरेशन लर्नर्स के लिए पहले जो हस्तक्षेप कार्यक्रम चलाया गया था उसकी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा चुका है।

समायोजन-मनोविज्ञान, व्यावहारिक परामर्श, शोध प्रविधि और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्लासरूम अध्यापन के प्रबलन के लिए परामर्श-प्रशिक्षणार्थियों को अंतर्व्यक्तिक कुशलताओं और कम खर्च वाले सहायक अध्यापन साधनों का प्रशिक्षण देने के लिए नवाचारी विधियों का विकास करने में भी रा० शै० अ० एवं प्र० परिषद् ने अपना योगदान दिया है।

माध्यमिक कक्षाओं की बालिकाओं के लिए परिषद् एक मार्गदर्शन कार्यक्रम के विकास में रत था। सामूहिक मार्गदर्शन के एक कार्यक्रम का परीक्षण एक स्थानीय स्कूल में किया गया। कक्षा 10 की बालिकाओं से प्राप्त कुछ आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

'सामाजिक संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य प्रबंध और चिकित्सीय देखभाल' पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में दो संकाय सदस्यों ने अपने आलेख (शीर्षक—'कौंसिलिंग एडोलसेंट्स इन दि एजुकेशनल कांटेक्स्ट' और 'कौंसिलिंग आफ गर्ल्स फार कैरियर्स एंड एजुकेशन') पढ़े। जर्नल आफ कंपैरेटिव एंड एजुकेशन रिव्यू को प्रकाशन के लिए एक शोध-रिपोर्ट भेजी गयी जिसका शीर्षक था 'वेरिएशन वेटिविन स्कूल्स—एक्रास एरियाज डिफरिंग इन लेविल आफ डवलपमेंट, एंड इट्स इंपैक्ट आन फर्स्ट जेनेरेशन लर्नर्स'।

जर्नल आफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज को प्रकाशन के लिए एक शोध-रिपोर्ट भेजी

गयी जिसका शीर्षक था 'फस्ट जेनेरेशन लर्नर्स एक्रास एरियाज डिफरिंग इन लेविल आफ डवलपमेंट'।

भारतीय व्यावहारिक मनोविज्ञान अकादमी के वार्षिक सम्मेलन की स्मारिका (मार्च 1983) में 'ए स्टडी आफ सेल्फ-कांसेप्ट इन रिलेशन टू एडजस्टमेंट, वैल्यूज, एकेडमिक एचीवमेंट, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेट्स एंड सेक्स आफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स' नामक आलेख का सार-संक्षेप प्रकाशित हुआ।

गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स—इंट्रोडक्टरी रीडिंग्स शीर्षक से एक पुस्तक मिमियोग्राफ रूप में प्रकाशित की गयी है।

उपरोक्त संदर्भित मामलों में परामर्श-सेवा की सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी गयीं।

मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम नियोजित और आरंभ करने के संबंध में कुछ स्थानीय संस्थाओं को सलाहकार सेवाएँ भी प्रदान की गयीं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र में बढ़ती हुई मांगों के साथ गति बनाए रखने के लिए बहु-आयामी कार्यक्रम शुरू किए हैं। सॉफ्ट-वेयर तथा दूसरी दिशाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए प्रयास जारी हैं। विभिन्न एजेंसियों के साथ सहयोग जारी है। उपयुक्त स्टूडियो कॉम्प्लेक्स बनाकर तथा उपकरण प्राप्त करके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यशिविर और अभिविन्यास पाठ्यक्रम

(i) 31 मार्च से 5 अप्रैल, 1983 के बीच एक राष्ट्रीय कार्यशिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था इनसैट के शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए विषयों, प्रकरणों की खोज/चयन। इस कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञताओं और पृष्ठभूमि के 70 लोगों ने हिस्सा

लिया। उदाहरण के लिए शिक्षाशास्त्री, अध्यापक-शिक्षक, बालमनोवैज्ञानिक, विषय-विशेषज्ञ, मूल्यांकनकर्त्ता, अनुसंधानकर्त्ता, लेखक और उत्पादक, प्रसारणकर्त्ता, माध्यम के लोग और कक्षा में पढ़ाने वाले वास्तविक अध्यापक। इनमें सभी छः इनसैट राज्यों, शैक्षिक राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शैक्षिक दूरदर्शन कक्षों के प्रतिनिधि थे। इनके साथ ही स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर, आकाशवाणी, दूरदर्शन, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभाग तथा इकाइयाँ, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि थे।

(ii) शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए 26 से 30 अप्रैल 1983 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशिविर के दौरान विकसित किए गए कार्यक्रम विवरणों को संपादित करके सभी संबंधित संस्थानों में वितरित कर दिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उत्तर प्रदेश के शैक्षिक दूरदर्शन के आलेख लेखकों के लिए एक अभिविन्यास और चयन कार्यशिविर का 4 से 18 मई, 1984 तक आयोजन किया। इनसैट के संदर्भ में 1983-84 के लिए आयोजित चार कोर्स की शृंखला में प्रथम होने के कारण कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक दूरदर्शन आलेख लेखकों का एक ऐसा संघ बनाना था जिसका उपयोग औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति के संबंध में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम लिखने के लिए देश में दूरदर्शन केंद्रों, राज्य-उत्पादन केंद्रों और शैक्षिक प्रौद्योगिक केंद्रों द्वारा किया जा सके। कोर्स में उपस्थित 26 सहभागियों में से 16 आलेख लेखकों को 8 सप्ताह के इस शैक्षिक दूरदर्शन के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कोर्स के लिए पूर्णरूप से उत्तर प्रदेश से चुना गया।

इस शृंखला में शैक्षिक दूरदर्शन आलेख लेखकों के लिए दो अभिविन्यास एवं चयन कार्यशिविरों का नई दिल्ली में 1 से 15 फरवरी 1984 तक से तथा 17 फरवरी से 2 मार्च, 1984 तक क्रमशः आयोजन किया गया। इनमें से एक गुजरात के लिए था और एक महाराष्ट्र के लिए। 15 दिवस के अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण कोर्स में हिस्सा लेने वाले सभी 32 सहभागियों (15 गुजरात से और 17 महाराष्ट्र से) का चुनाव या तो खुले विज्ञापन अथवा साक्षात्कार द्वारा हुआ अथवा वे राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष और दूरदर्शन द्वारा प्रदत्त अथवा सिफारिश किए गए थे।

पिछले पाँच वर्षों में केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष द्वारा प्रशिक्षित शैक्षिक दूरदर्शन आलेख लेखकों की सूची को अद्यतन करके दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल तथा इसी प्रकार संबंधित सभी शैक्षिक प्रौद्योगिक कक्षों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को भेज दी गयी है। इन संगठनों से निवेदन किया गया कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के आलेख लिखने के लिए इन प्रशिक्षित आलेख-लेखकों का इस्तेमाल किया जाए।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के लिए शिक्षण अधिगम तकनीक में नवाचारी अभ्यास के संबंध में बहु-माध्यमी दृष्टिकोण पर एक छः दिवसीय कार्यशिविर प्रौढ़-शिक्षा कक्ष के शिक्षा निदेशालय, अंडमान और निकोबार आइलैंड के सहयोग से 11 से 16 मई, 1983 तक पोर्टब्लेयर में आयोजित किया गया। कार्यशिविर में 19 सहभागी उपस्थित थे।

परियोजना के प्रथम चरण में विश्व भारती, शांतिनिकेतन में 16 से 26 जून, 1983 तक एक कार्यशिविर का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक था “माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्वयं शिक्षक पेटिका यानि स्वधिगम शिक्षण सामग्री तैयार करना”। इसका उद्देश्य बेहतर और प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली में दृश्य-संप्रेषण के लिए मानसिक विकास तथा चाकबोर्ड के उचित प्रयोग के लिए सामग्री विकसित करना था। कार्य शिविर में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों से संबंधित 16 सहभागी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक दूरदर्शन के इस्तेमाल के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का राज्य स्तरीय दो दिवसीय अभिविन्यास 2 और 3 सितंबर, 1983 को आयोजित किया। कुल मिलाकर 43 सहभागी अभिविन्यास किए गए। इस प्रकार संसाधन व्यक्ति राज्य में इसी प्रकार के शिविरों का संचालन करके बदले में टी० वी० का वास्तविक इस्तेमाल करने वाले अध्यापकों और टी० वी० स्कूलों के अभिरक्षकों को समूहों में प्रशिक्षित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गयी। इसका प्रयोग संसाधन व्यक्ति टी० वी० इस्तेमाल करने वाले अध्यापकों तथा अभिरक्षकों के प्रशिक्षण में करेंगे।

(v) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 6 से 16 सितंबर, 1983 तक रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर में शिक्षक अध्यापकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी अभिविन्यास कोर्स आयोजित किया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के माध्यमिक स्तर के 36 शिक्षक-अध्यापकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

शिक्षक-अध्यापकों के लिए शिक्षा-प्रौद्योगिकी का एक अन्य अभिविन्यास कोर्स महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में 21 नवंबर से 1 दिसंबर, 1983 तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी वक्ष, बंबई में आयोजित किया गया। कोर्स में 30 सहभागी उपस्थित थे।

प्रौढ़-शिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों के लिए अधिगम खेल संबंधी एक कार्यशिविर सेवामंदिर के सहयोग से 21 से 25 नवंबर, 1983 तक उदयपुर में आयोजित किया गया। इसमें 15 सहभागी थे। इसमें साक्षरता आदि से संबंधित कुछ अधिगम खेल तैयार किए गए।

छठी कक्षा में भूगोल संबंधी कठिन अवधारणाओं को पढ़ाने संबंधी बहु-माध्यमी योजना के अंतर्गत एक पेटिका तैयार करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने दो कार्यशिविरों का आयोजन किया। एक कार्यशिविर नई दिल्ली में 5 से 8 सितंबर, 1984 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भूगोल के अध्यापन में कठिन अवधारणाओं की पहचान करना था। दूसरा कार्यशिविर 20 से 26 अक्टूबर 1983 तक कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, के भूगोल एवं क्षेत्रीय विकास-विभाग में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य छठी कक्षा में भूगोल की कठिन अवधारणाओं के अध्यापन संबंधी शिक्षण-सामग्री को विकसित करना था। इस परियोजना का उद्देश्य मनुष्य की वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया, विविध भौगोलिक अवस्थितियों के बीच पारस्परिक संबंध और क्रिया-प्रतिक्रिया के बीच कार्यकारण संबंध को उचित महत्व देते हुए कतिपय त्रुटियाँ दूर करना और शिक्षण-सामग्री का विकास करना था।

राजस्थान और अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से पत्राचार शिक्षा की

अध्ययन-सामग्री के लेखकों के लिए 27 जनवरी से 6 फरवरी, 1984 तक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य थे (i) दूर से दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित सैद्धांतिक अवधारणा प्रदान करना जिसमें दूर से दी जाने वाली शिक्षा की अवधारणा, दूर से दी जाने वाली शिक्षा संबंधी उप-प्रणाली, लेखन, संपादन, प्रूफ संशोधन तथा प्रैस के लिए पांडुलिपि तैयार करने संबंधी प्रवीणता और तकनीकी संबंधी अवधारणाएं भी शामिल हों, (ii) विभिन्न आकारों में पाठों का विकास। कार्यक्रम में 32 सहभागी उपस्थित थे।

(vi) "छठी कक्षा में भूगोल की कठिन अवधारणाओं के शिक्षण में बहु-माध्यमी पेट्रिका बनाने" संबंधी परियोजना के संबंध में शिक्षण-सामग्री के विकास और परीक्षण के लिए मद्रास विश्वविद्यालय में 15 से 21 फरवरी, 1984 तक एक कार्यशिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित 15 सहभागियों में रीडर्स, लैक्चरर्स, अध्यापक और पाठ्य-पुस्तक लेखक भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में देशीय अध्ययन संबंधी कार्यक्रम और सामग्री तैयार की गई।

(vii) 'शिक्षकों के लिए अधिगम खेल' संबंधी परियोजना के संबंध में सामाजिक सेवाओं के जेबियर प्रतिष्ठान, राँची में 20 से 25 फरवरी, 1984 तक एक कार्यशिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 15 सहभागी उपस्थित थे। कार्यशिविर में परियोजना संबंधी एक तालिका तैयार की गई।

(viii) लिटरेस हाउस, लखनऊ में 20 से 25 फरवरी, 1984 तक एक कार्यशिविर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दृश्य-संप्रेषण संबंधी आत्म-अधिगम शिक्षण सामग्री के रूप में एक ऐसे आदर्श औजार का विकास करना था जिसका उपयोग कक्षा में चाक-बोर्ड द्वारा किया जा सके। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम-बंगाल से 12 शिक्षक-अध्यापक इस कार्यशाला में उपस्थित थे। शिक्षण-अधिगम के दौरान चाक-बोर्ड के इस्तेमाल के विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श किया गया और इस बात के लिए कोशिश की गई कि कुछ ऐसे तरीके निकाले जाएं जिनसे अध्यापक में कुछ इस तरह का कौशल पैदा हो जिससे वह अमूर्त विचारों को मूर्त प्रतीकों द्वारा व्यक्त कर सके। ऐसे मूर्त प्रतीक जिनकी आवश्यकता बेहतर और प्रभावशाली शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में होती है।

(ix) शैक्षिक दूरदर्शन आलेखों की एक शृंखला तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष ने 28 फरवरी से 8 मार्च, 1984 तक एक कार्यशिविर का आयोजन किया। इस कार्य-शिविर में अध्यापकों के लिए तैयार किए जाने वाले लगभग एक दर्जन आलेखों का विकास किया गया।

राज्यों की ओर से शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष के अधिकारियों के लिए एक अनुकूलन कोर्स तथा कार्यशिविर नई दिल्ली में 12 से 15 मार्च, 1984 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष के अधिकारियों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं के अनुकूल बनाना, अपने राज्यों में शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की पहचान करना तथा इसकी परीक्षा और विचार-विमर्श करना कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी इन समस्याओं में से कुछ के साथ कैसे निबट सकती है। इस कार्यक्रम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों के अधिकारियों को अपने-अपने कक्षों में एक योजना के कार्यान्वयन में भी सहायता मिलती है।

शैक्षिक दूरदर्शन इनसैट कार्यक्रम

(i) शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण और प्रेषण

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इनसैट 1-B सैटलाइट प्रसारण सेवा का उपयोग आरंभ किया गया। कार्यक्रम कैपसुलों को दो राज्यों में प्रसारण के लिए उपग्रह दूरदर्शन केंद्रों में भेज दिया गया है। जहाँ तक नागपुर (महाराष्ट्र) कार्यक्रम का ताल्लुक है, इसके टेप्स हवाई जहाज के द्वारा महाराष्ट्र के तीन जिलों में भेज दिए गए हैं। यह 15 अक्टूबर, 1983 से आरंभ होने वाला है।

(ii) हैदराबाद, सम्बलपुर और नागपुर प्रसारण की समय-सारणी

उड़ीसा (सम्बलपुर) और आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) के लिए समग्र तिथिवार सारणी को अंतिम रूप देकर सभी दूरदर्शन केंद्रों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्षों और इससे संबंधित दूसरे विभागों के पास भेज दिया गया है। नागपुर के लिए प्रसारण समय-सारणी तैयार की गई। जहाँ तक केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तीन दिन की कार्यक्रम सारणी का सवाल था, एक समय सारणी तैयार की गई और कार्यक्रम कैपसुलों को उसी समय-सारणी के अनुसार भेजा गया।

अध्यापक को निर्देशित करने वाली टिप्पणियाँ

हैदराबाद और मुबनेखर से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, अध्यापक को निर्देशित करने वाली टिप्पणियाँ नियमित रूप से भेजी गईं।

शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की पूर्व-समीक्षा और क्षेत्र-परीक्षण

(i) अन्तः कार्यक्रम पूर्वोक्षण समिति ने गत वर्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गए सभी शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की शृंखला की पूर्व समीक्षा पूरी की। कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार संबंधी पूर्वोक्षण समिति की टिप्पणियों तथा सुझावों को दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माताओं के लिए उपलब्ध करवाया गया। पूर्वोक्षण समिति ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले नए कार्यक्रमों की पूर्व-समीक्षा आरंभ कर दी है।

(ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बनाए गए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के क्षेत्र-परीक्षण के लिए मानवडों और औजारों का एक सैट तैयार किया गया। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के क्षेत्र-परीक्षण की परख दिल्ली नगर-निगम की मध्यस्थता में आरंभ की गई। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को चुना गया।

कार्यक्रमों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इनसैट 1-बी के अंतर्गत आयोजित किए गए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का चौथी से पाँचवी कक्षा के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन संबलपुर (उड़ीसा) जिले में पूरा किया। यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षा देने में दूरदर्शन उपयोगी माध्यम है। उपलब्धि-

परीक्षण में टेलीविजन वाले स्कूलों के बच्चों ने बिना टेलीविजन वाले स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बावजूद लाभान्वित की मात्रा बहुत कम मात्र 3.2 प्रतिशत थी। अध्ययन से पता चलता है कि दूरदर्शन ने विविध सीमाओं और अवरोधों में काम किया। इसने शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता को कम किया। यदि ऐसा न होता तो इसके और भी संतोषजनक परिणाम होते।

अध्ययन की प्रमुख सिफारिशों में एक यह थी कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों की उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए एक पद्धति करने की आवश्यकता है। संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय उत्पन्न करने के लिए, शिक्षा के राज्य-विभागों में एक कक्ष बनाने के लिए प्रणाली का निरंतर संचारक्षण करने के लिए तथा शीघ्र कार्यवाही करने के लिए, आवश्यक है कि शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं से संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट कार्यों और जिम्मेदारियों के विषय में एक रूपरेखा तैयार की जाए। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के विषय में आवश्यक मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के लिए उड़ीसा के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के आँकड़े एकत्रित और विश्लेषित किए जा रहे हैं।

फिल्म यूनिट

फिल्म यूनिट ने चंडीगढ़, दिल्ली और बंगलौर में "अनग्रेडिड स्कूल" और "एस यू पी डब्लू" (SUPW) फिल्म की दो तिहाई शूटिंग पूरी कर ली है। 1983 के दिसंबर महीने में निगेटिव को संशोधन के लिए भेज दिया गया है। 'फोटोग्राफी की तकनीकें' संबंधी बनाई गई फिल्म की कच्ची रूपरेखा और फिल्म के टुकड़ों की शूटिंग पूरी कर ली गई।

रेडियो यूनिट

(i) शिक्षा में रेडियो के प्रयोग और इस साहसिक कार्य में शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के शामिल होने के संबंध में 25 मई, 1983 को एक सभा आयोजित की गयी। रेडियो के इस्तेमाल से होने वाली समस्याओं की जाँच के लिए आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल और केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष के साथ एक समिति स्थापित की गई। शैक्षिक रेडियो के पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक पाठ्यक्रम समिति का गठन किया गया।

(ii) आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण के उद्देश्य से रेडियो पॉयलट योजना के अंतर्गत 99 कार्यक्रम पुष्टि किए जा चुके हैं। इनमें से 16 श्रव्य कार्यक्रमों को पुनः संपादित किया गया और 38 नए कार्यक्रम बनाकर प्रसारित किए गए।

(iii) एक कार्यशिविर 27 से 29 जुलाई, 1983 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नौजवान बच्चों की राष्ट्रीय एकता और मूल्यों के विकास संबंधी विशिष्ट शिक्षा देने की परियोजना के लिए विषयों की पहचान और चयन करना था। कार्यशिविर में 19 कार्यक्रमों के विषयों को अंतिम रूप देकर कार्यक्रम विवरण में विकसित किया गया तथा लेखकों को इन कार्यक्रम विवरणों के आधार पर पाठ्यलिपि तैयार करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

(iv) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षा और मानसिक रूप से

किंचित् पिछड़े हुए सुविधाहीन बच्चों के दल के लिए श्रवण-टैप कार्यक्रमों का आदिरूप विकसित किया, बनाया और परीक्षित किया। परीक्षणों के परिणामों के आधार पर और उत्पादन आरंभ किया जाएगा।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र में तकनीकी सुविधाएँ : 1983-84

बिल्डिंग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अहाते में पुस्तकालय प्रखंड को एक स्टूडियो भवन में रूपांतरित करने का काम प्रगति पर है। भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, पूना और हैदराबाद में दूरदर्शन स्टूडियो की एक इमारत बनाने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ एक अनुबंध पत्र पहुँचा। भवन का डिजाइन तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा इसे अंतिम रूप दिया गया। अंतरिक्ष विभाग इससे संबंधित कार्यों की कानूनी कार्यवाही और विस्तृत योजना में लगा हुआ था। अहमदाबाद में शैक्षिक दूरदर्शन इमारत के संबंध में गुजरात सरकार ने निर्माण कार्य पहले से स्वयं ही आरंभ कर दिया है।

अंततः भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ और हैदराबाद में उपयुक्त भवनों की पहचान इसलिए की गई कि संबंधित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदें इन राज्यों में इन इमारतों को अस्थायी शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियो में रूपांतरित करने का काम जारी रख सकें। यह इसलिए जरूरी समझा गया क्योंकि स्थायी भवन बनने में कुछ समय लगता। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राज्य सरकारों के संपर्क में थी। इसने इन रूपांतरणों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन तैयार करने में सभी प्रकार की मदद की।

उपकरण

1. पिछले वित्तीय वर्ष में जी० सी० इ० एल० (GCEL) बड़ौदा को 3/4" और 1" की वीडियो रिकार्डिंग और संपादन सिस्टम प्रणाली मंगाने के आदेश दिए। इन आपूर्तियों के कुछ हिस्से विदेश से पहले ही बड़ौदा की फैक्ट्री में पहुँच गए थे तथा इनका परीक्षण भी कर लिया गया था। इन सभी आपूर्तियों का उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अहाते में स्थित केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष और शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियो को सुसज्जित करना था।

2. छः इनसैट राज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियो के लिए 3/4" और 1" के वीडियो रिकार्डिंग और संपादन प्रणाली के संबंध में जी० सी० इ० एल० (GCEL) बड़ौदा के साथ विचार-विमर्श किया गया।

3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के साथ तकनीकी विचार-विमर्श की एक शृंखला माला का आयोजन किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर स्टूडियो संबंधी रंगीन कैमरों और इससे संबंधित उपकरण का उत्तरोत्तर निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः उन्होंने केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष स्टूडियो और छः इनसैट राज्यों के लिए turn key आधार पर सभी आवश्यक सामग्री भेजने की इच्छा जाहिर की है।

4. हमारे हिंदी कार्यक्रमों के मूल-दृश्यों को इस्तेमाल करते हुए उड़िया, तेलुगू और मराठी में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का भाषा संबंधी डबिंग का काम प्रारंभ किया गया। केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष के पुराने (CCTV) उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणियों और शीर्षकों की केवल डबिंग के लिए एक अस्थायी स्टूडियो तैयार किया गया।

शिक्षण-साधन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने दृश्य-श्रव्य शिक्षण सामग्री संबंधी एक अखिल भारतीय गोष्ठी का 20 से 24 फरवरी तक आयोजन किया। इस गोष्ठी को आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य थे—

1. स्कूल स्तर के बच्चों का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के लिए दृश्य-श्रव्य सॉफ्टवेयर की विशेषता का प्रदर्शन।

2. इसके उत्पादन की कार्य-पद्धति पर विचार-विमर्श करना।

3. उच्चकोटि के सॉफ्टवेयर के उत्पादन, इसके द्विरूपण, वितरण और उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाओं पर विचार-विमर्श करना।

गोष्ठी में 16 सहभागियों ने हिस्सा लिया। 300 से ज्यादा शिक्षण-साधन जिनमें चार्ट्स, मॉडलस्, फोलियो, खेल, फिल्म पट्टियां, ऑडियो कैसेट, दृश्य-श्रवण पेट्टिका, फिल्म और कम्प्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का प्रदर्शन और विवेचन किया गया। दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और उत्पादकों ने कई संबंधित विषयों पर भाषण दिए।

गोष्ठी के अनुबद्ध के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 20 से 25 फरवरी, 1984 तक एक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरह की दृश्य-श्रवण सामग्री समान रूप से थी। 20 से 25 फरवरी, 1984 तक देश में इसका आयोजन कई व्यावसायिक संगठनों और शैक्षिक संगठनों ने किया। इस प्रदर्शनी में करीब 1000 लोग आए।

डब्ल्यू एच ओ (WHO) के दो अध्यक्षताओं के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी एक अभिविन्यास कार्यक्रम 11 से 15 अप्रैल, 1983 तक आयोजित कार्यक्रम में नेपाल की शैक्षिक प्रौद्योगिकी आवश्यकता का आकलन भी था।

अफगानिस्तान के ग्रामीण विकास विभाग के श्री पी० एम० शेरजाह को 13 से 18 मई, 1983 तक फोटोग्राफी संवर्धन और फिल्म पट्टियों के उत्पादन संबंधी अभिविन्यास-प्रशिक्षण दिया गया। श्री शेरजाह को यू० एन० (UN) वृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षण तकनीक के विकास के लिए केंद्र द्वारा नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया गया। उनके संक्षिप्तवास में उन्हें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विविध पक्षों से परिचित करवाया गया।

श्रीलंका से यू एन डी पी कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यक्षता श्री के डी० प्रेमरत्ने को 3 अक्टूबर से 2 दिसंबर 1983 तक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उनके देश की परियोजनाओं से संबंधित साधनों और उपकरणों की तैयारी संबंधी ऊपरी बातें शामिल थीं।

26 अप्रैल से 6 मई, 1983 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने फोटोग्राफिक निपुणता और इसके शैक्षिक स्टाफ की समालोचना के लिए एक कोर्स का आयोजन

किया। इस कोर्स का संचालन एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर श्री टी० काशीनाथ ने किया। इस कोर्स के दौरान श्री टी० काशीनाथ ने फोटोग्राफी के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कई व्याख्यान दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ चित्रों (फोटोओं) का विश्लेषण किया। प्रयोग के तौर पर सहभागियों ने चित्र, वाहन, पुल, पशु, पेड़ तथा गंदी बस्तियों आदि विषयों से संबंधित 200 फोटोग्राफ लिए।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और वीडियो कार्यक्रम के निर्माण में इसके व्यवहार से संबंधित एक प्रशिक्षण कोर्स 14 से 27 सितंबर, 1983 तक संचालित किया गया। संपूर्ण देश के स्वैच्छिक संगठनों में से दस सहभागियों को पांडुलिपि लिखने, वीडियो कार्यक्रमों की शूटिंग, स्टूडियो में वीडियो कैमरों का संचालन और आधे इंच के वीडियो कैसेट रिकार्डर (VCR) पर अंतिम रूप से कार्यक्रम के संपादन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। सहभागियों ने पांडुलिपियाँ तैयार कीं तथा सात छोटे कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा प्रवर्तित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के चार अध्यक्षों के लिए एक दो-दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इन अध्यक्षों को कम लागत की शिक्षण सामग्री तैयार करने संबंधी कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षण की स्थितियों में दृश्य, श्रव्य साधनों के निर्माण, उपयोग और विकास तथा फ्लैटल कट आउट्स और फ्लैप चार्टों के तैयार करने की तकनीकों के विशिष्ट संदर्भों से परिचित करवाया गया।

दृश्य-श्रव्य उपकरण के संचालन और संचारेक्षण के संबंध में एक अभिविन्यास प्रशिक्षण 16 से 21 मई, 1983 तक आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टैकनॉलाजी, कानपुर के पुस्तिकाध्यक्ष तथा महन्त हरकिशनदास विद्या निकेतन, मथुरा के दो अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया। ऊपर उल्लिखित अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन सहभागी संबंधित संस्थानों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों की सुलभता और उनकी आवश्यकता और 16 मि० मी० के फिल्म प्रोजेक्टर के परिचालन भाग पर निरीक्षण रखने के लिए किया गया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कम लागत की शिक्षण सामग्री तैयार करने के संबंध में राज्य शिक्षण संस्थान, सोलन (हिमाचल प्रदेश) में 27 से 29 जुलाई, 1983 तक एक गोष्ठी आयोजित की। उत्तरी क्षेत्र के सात राज्यों के करीब 21 प्रमुख व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। सहभागियों ने कम लागत से तैयार शिक्षण सामग्री के क्षेत्रीय स्तर पर विकास और उपयोग के संबंध में एक मॉडल प्लान की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस आदर्श योजना में शिक्षण सामग्री तैयार करने से संबंधित विषय, विधि और सामग्री शामिल थी और अध्यापक जिन्हें प्रखंड और जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् बिहार तथा पटना का दृश्य-श्रव्य उपकरणों के संचालन तथा संचारेक्षण तथा सहभागियों के लिए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करने में सहायता दी। यह कोर्स 25 जुलाई से 3 अगस्त, 1983 तक आयोजित किया गया।

दृश्य-श्रव्य उपकरण के संचालन और संचारेक्षण संबंधी एक तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स 1 से 9 सितंबर, 1983 तक संचालित किया गया। सिक्किम, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों से 13 सहभागियों ने कोर्स में हिस्सा लिया। इनके अतिरिक्त 5 स्थानीय सहभागी भी इसमें शामिल थे।

द्वितीय चरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अहमदाबाद जिले के एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूल के लिए आत्म शिक्षण संबंधी कार्ड बनाने के लिए वी० ए० एस० (VAS) कम्युनिटी साईंस सेन्टर, अहमदाबाद के सहयोग से एक कार्यशिविर 30 नवंबर से 6 दिसंबर, 1983 तक आयोजित किया। इसमें 22 प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों ने हिस्सा लिया। गणित के क्षेत्र में तैयार किए गए कार्डों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया (क) अवधारणात्मक अथवा सूचनात्मक कार्ड (ख) अभ्यास संबंधी कार्ड (ग) परीक्षण संबंधी कार्ड (घ) क्रियाकलाप संबंधी कार्ड। पूर्व आयोजित कार्यशाला में तैयार किए गए कार्डों की विषय-वस्तु के विश्लेषण को अंतिम रूप दिया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रशिक्षण कोर्स नई दिल्ली में टेप-स्लाइड के उत्पादन के संबंध में 2 से 16 फरवरी 1984 तक आयोजित किया गया। यह पाठ्यक्रम विशेष तौर से भारत के पश्चिमी क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सहभागियों को टेप-स्लाइड कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा अपने-अपने संस्थानों से स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए इसी प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करने के योग्य बनाना था। प्रशिक्षण कोर्स में राज्य शिक्षण संस्थानों और राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों तथा महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सी० आई० ई० टीम के 16 शिक्षक-अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इनके अतिरिक्त दिल्ली के स्कूलों के विज्ञान के छः अध्यापक-भी प्रशिक्षण कोर्स में उपस्थित थे। कोर्स के दौरान सहभागियों ने भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान और गणित विषयों में पाँच टेप-स्लाइडें तैयार कीं।

राजकीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर के सहयोग से टेप-स्लाइड सामग्री के विकास के लिए एक कार्यशिविर इम्फाल में 5 से 15 मार्च, 1984 तक आयोजित किया गया। राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और मणिपुर स्कूलों के 13 सहभागी कार्यशिविर में उपस्थित थे। कार्यशिविर के दौरान छः टेप-स्लाइड कार्यक्रम नीचे लिखे विषयों के क्षेत्र में प्रस्तुत की गईं—

- (i) फूल और इसके अंगों का कार्य (जीवविज्ञान)
- (ii) वाक्य संरचना (भाषा)
- (iii) भिन्न (fractions) (गणित)
- (iv) साधारण मशीन (भौतिकी)
- (v) मधुमक्खी (जीवविज्ञान)
- (vi) भारत की कृषीय पैदावार (समाज-विज्ञान)।

दृश्य-श्रव्य उपकरणों के संचालन, संचारेण और उपयोग के संबंध में एक प्रशिक्षण कोर्स क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में 5 से 10 मार्च, 1984 तक आयोजित किया गया। कर्नाटक के

विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों से 13 सहभागी पाठ्यक्रम में उपस्थित थे जिनके पास दृश्य-श्रव्य उपकरण थे। शिक्षण अधिगम की स्थितियों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों की दक्षता के बारे में जानकारी देना और उपकरणों के संचालन में प्रवीणता अर्जित करना कोर्स के मुख्य उद्देश्य थे। सहभागियों को सैद्धांतिक शिक्षा के अतिरिक्त गहन व्यावहारिक परीक्षण भी दिया गया।

प्राइमरी स्तर पर गणित की प्रयोगशाला संबंधी सामग्री के विकास के लिए 12 से 20 मार्च, 1984 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें दिल्ली के स्कूलों के 12 अध्यापकों ने हिस्सा लिया। सहभागी कुछ अवधारणाओं उदाहरणार्थ: अंक पद्धति, दशमलव, भिन्न इत्यादि संबंधी डिजाइन और मॉडल तैयार करने के अतिरिक्त मिडिल स्कूल स्तर संबंधी गणित शिक्षण सामग्री के परीक्षण में भी शामिल थे।

कार्यदल की बैठक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने मिडिल स्कूल स्तर के गणित विषय से संबंधित कम लागत से तैयार की जाने वाली शिक्षण सामग्री के संबंध में 10 से 28 मई, 1983 तक कार्यदल की तीन-सप्ताह तक की बैठक का आयोजन किया। बैठक का संचालन 'गणित शिक्षा की विकास संस्था' विजयवाड़ा के सहयोग से किया गया। इसमें 'डाउन टु अर्थ मैन्युएल' के प्रवर्तक और लेखक श्री एम० बी० एस० राव (राओ) व्यास ने भी हिस्सा लिया। दल ने शिक्षण सामग्री 50 चित्रों, और प्रत्येक के प्रशंसात्मक विवरणों के साथ मॉडल और चार्टों के रूप में 41 शिक्षण सामग्रियाँ विकसित कीं। 50 में से 10 चित्रों को अंतिम रूप अभी देना है। इस कार्य-दल की बैठक के पर्यालोचन के अंश के रूप में एक नियम-पुस्तिका तैयार की जाएगी। समी प्रकार की सामग्री निर्देशित करने वाले माडलस, चित्रों और तैयार करने की प्रक्रिया सामग्री के साथ होगी। परिणामस्वरूप पांडुलेख में विद्यमान सभी 50 चित्रों को नियम-पुस्तिका के मुद्रण के लिए निश्चित कर दिया जाएगा।

मिडिल और हाई स्कूल स्तर के गणित संबंधी शिक्षण-तैयार करने के लिए एक दूसरे कार्यकारी दल की बैठक 28 सितंबर से 13 अक्टूबर 1983 तक आयोजित की गई। कार्यकारी दल की यह बैठक कार्यक्रम का तीसरा चरण थी। इसमें प्रशंसात्मक विवरणों, डिजाइनों और माडलस के साथ गणित संबंधी 40 शिक्षण सामग्री पृथक रूप से तैयार की गई। कार्यकारी दल की इन बैठकों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि नियम-पुस्तिका तैयार करने और स्कूल के अध्यापकों तक इन विचारों को प्रचारित करने के लिए इस सामग्री का परीक्षण कर लिया जाए।

कार्यकारी दल की चौथी बैठक 4 से 12 जनवरी, 1984 तक हुई। गणित में अब तक 90 में से प्रत्येक सामग्री प्रशंसात्मक विवरणों और चित्रों के साथ विकसित की गई। बैठक के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि जहाँ तक संभव हो भौतिक मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित करें। गणित संबंधी विचारों को इसके विस्तृत परिप्रेक्ष्य में विकसित किया जा सके।

भौतिकी विषय में चार्टों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए 25 से 27 अगस्त, 1983 तक एक कार्यकारी दल की बैठक हुई। ये चार्ट नवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए तैयार किए गए। एक दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरा स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के दो विद्वान व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया। बैठक में 17 चार्टों पर विचार किया गया और अंतिम प्रदर्शन के लिए निश्चय किया गया।

संयोजकता संबंधी टेप-स्लाइडों के उत्पादन के संबंध में कार्यदल की एक बैठक 12 से 13 दिसंबर तक संचालित की गई। इसका उद्देश्य संयोजकता पर टेप-स्लाइड कार्यक्रम तैयार करना था। बैठक के दौरान संयोजकता संबंधी पूर्वविकसित पांडुलिपि को प्रदर्शन के लिए परिमार्जित तथा पूर्ण किया गया।

शिक्षण-साधन विभाग द्वारा तैयार किए गए सामान और मूल प्रतिरूपों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने राजकीय शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बनाए गए गणित से संबंधित कम लागत से तैयार किए गए शिक्षण साधनों का मूल्यांकन करने के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशिविर 9 से 11 अगस्त तक का संचालन किया। उपर्युक्त कार्यशाला में दो प्रवर व्यक्तियों सहित 17 सहभागी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने माध्यम स्कूल अवस्था तक के लिए भूगोल से संबंधित 20 चार्टों का एक सैट तैयार करवाया है। इन चार्टों के मूल्यांकन के लिए 19 से 20 दिसंबर, 1983 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 9 सहभागियों ने हिस्सा लिया। पढ़ाए जाने वाले छात्रों के संदर्भ में चार्टों के आकार-प्रकार, चार्टों के उपयोग और अन्तर्वस्तु की विशुद्धता के संदर्भ में चार्टों पर विचार-विमर्श किया गया। चार्टों में आवश्यक सुधारों और परिवर्तनों के लिए दल द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों का विश्लेषण किया गया।

इनसैट कार्यक्रमों के लिए शिक्षण-साधन विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्मों की डॉकिंग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई नीचे लिखी पांच फिल्मों को तेलगू, उड़िया, और मराठी भाषाओं में इनसैट कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रसारण के लिए डब किया गया—

- (i) पर्यावरण के द्वारा विज्ञान-शिक्षण—चट्टान, मिट्टी
- (ii) जानवरों की समझना
- (iii) पर्यावरण द्वारा शिक्षा
- (iv) विज्ञान का मतलब क्रिया है
- (v) राष्ट्रीय विज्ञान।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नामक परियोजना पर चित्रों और दस्तावेजों के माध्यम से तैयार किया गया एलबम

आधुनिक भारत के इतिहास के क्षेत्र में चित्रों तथा दस्तावेजों के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने के लिए 'भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' नामक एक परियोजना आरंभ की गई। एलबम में यूरोपियनों के भारत आगमन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के विभिन्न पक्षों पर विशेष प्रकाश डालते हुए करीब 80 खण्ड (पट्टियाँ) होंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित दो राष्ट्रीय कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर सामग्री को प्रेस में भेजने से पहले ही खण्डों को अन्तिम रूप देने संबंधी 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया था। चार प्रतिष्ठित इतिहासकारों द्वारा इसकी समीक्षा करवाने का निश्चय किया गया ताकि प्रकाशित होने पर परियोजना संबंधी कोई विवाद न खड़ा हो जाए। तब से अब तक समीक्षा समिति द्वारा खण्डों की समीक्षा पूरी की जा चुकी होगी। यह आशा की जाती है कि एलबम के रूप में प्रकाशित किए जाने वाले खण्डों का मुद्रण 1984-85 वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा।

वीडियो टेप कार्यक्रम

नीचे लिखी गई पाण्डुलिपियों को इनसैट के लिए वीडियो टेप्स तैयार करने के लिए निश्चित किया गया।

- (i) गौरी और गौतम का पम्प
- (ii) पेड़ों से फल
- (iii) जल
- (iv) मृदु जल।

क्रम संख्या (i) में उल्लिखित वीडियो टेप शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से तैयार की गई।

वीडियो टेप विकास संबंधी परियोजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, कलाकारों और साहित्यिक व्यक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किए गए—

- (i) फोटोग्राफर श्री० टी० काशीनाथ
- (ii) कवियित्री श्रीमती महादेवी
- (iii) नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० आइ० प्रिगोगिन
- (iv) सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यापक, अरविंद गुप्ता
- (v) विकासवादी, प्रो० स्टीफन गोल्ड।

जनसंख्या-शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की टेप-स्लाइड को 3/4" यू मैटिक (3/4" U-matic) की रंगीन वीडियो टेपों में रूपांतरित कर दिया गया है ताकि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा इसका प्रसारण संभव हो सके।

भारतीय नेताओं के चित्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं के 25

चित्रों का आदर्श सैट तैयार करने की परियोजना आरंभ की। प्रत्येक चित्र में संबंधित नेता, शिक्षा, संस्कृति, मानवता और राष्ट्रीय एकता से संबंधित अवतरण होगा। प्रथम सैट में सात नेताओं के चित्र थे। यह पिछले वर्ष पूरा हो गया था। दूसरे 18 नेताओं के अवतरणों और चित्रों से संबंधित कार्य भी पूरा हो गया है। ये अवतरण संबंधित नेताओं के भाषणों, पात्रों, आत्म-कथाओं, जीवनियों तथा प्राप्त दूसरे स्रोतों से चुने गए हैं।

केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल और मध्यप्रदेश के क्षेत्र-परामर्शदाता के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा तैयार की गई दूसरी शैक्षिक फिल्मों का भोपाल में 8 से 11 दिसंबर, 1983 तक एक फिल्म-मेला आयोजित किया गया। मेले का उद्देश्य अध्यापकों और विद्यार्थियों के शिक्षण में फिल्मों के प्रयोग संबंधी जानकारी देना था। इसका उद्देश्य अध्यापक शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण फिल्में तैयार करना तथा उसी प्रकार केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी के माध्यम से फिल्मों के वितरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका पर विशेष प्रकाश डालना था। इसके लाइब्रेरी भण्डार में 8000 से अधिक पुस्तकें हैं।

1983-84 वर्ष के दौरान 92 संस्थाओं ने केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी के सदस्य के रूप में नामांकन करवाया। इस प्रकार कुल सदस्यता बढ़कर 3905 हो गई। केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी के भण्डार में फिल्मों की कुल संख्या 8192 तक बढ़ाने के लिए 18 फिल्में और जोड़ी गईं। समीक्षा अवधि के दौरान पूरे देश भर में सदस्य संस्थानों को 10040 फिल्में वितरित की गईं।

3 से 4 जनवरी, 1984 तक पटना में आयोजित शिक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष और शिक्षण साधन विभाग की फिल्मों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

नवंबर 1983 के तीसरे सप्ताह में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में शिक्षण साधन विभाग और केंद्रीय प्रौद्योगिकी कक्ष द्वारा तैयार की गई फिल्में प्रदर्शित की गईं।

फिल्मों का उत्पादन

‘विज्ञान जीवन का हिस्सा है’ नामक फिल्म का निर्माण पूरा हो गया है। यह मिडिल स्कूल के विज्ञान के अध्यापकों के लिए बनाई गई थी। यह संघटित विज्ञान पाठ्यक्रम के लाभों पर प्रकाश डालती है, जबकि विज्ञान को स्थानीय वातावरण से संपूर्ण रूप में जोड़ने की जरूरत है।

फिल्मों की बिक्री

1983-84 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपनी शैक्षिक फिल्मों के 16 m. m. के प्रिंट 43,171.05 रुपये के बेचे हैं।

फिल्मों का पूर्वदर्शन और खरीद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्थापित की गई पूर्वदर्शन समिति द्वारा फिल्मों का पूर्वदर्शन और स्वीकरण किया गया ताकि केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी के लिए उनकी उलब्धि को संभव बनाया जा सके।

(i) ब्ल्यूज़ फॉर द रैड्ड लैनट	}	कार्ल सैगन द्वारा कास्मोज सीरिज
(ii) ट्रेवलर्स टेलस्		
(iii) द बैकबोन ऑफ नाइट		
(iv) द जर्निज इन स्पेस एण्ड टाईम		
(v) परसिस्टन्स ऑफ मेमॉरि		
(vi) द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ गैलेक्टिका		
(vii) इन्दुज वैली टु इन्दिरा गांधी	}	बी० बी० सी० द्वारा निर्मित
(viii) द इनफिनिट वेराइटी		
(ix) बिल्डिंग बॉडीज		
(x) कॉन्क्वैस्ट ऑफ द वाटरज		
(xi) इनवैजन ऑफ लैंड		
(xii) विकटर्स ऑफ द ड्राइलैंड		
(xiii) लॉर्ड्स ऑफ द एयर		
(xiv) द राइज ऑफ द मेमल्स		
(xv) केयर ऑफ द आइज		
(xvi) गोवर गैस प्लान्ट		
(xvii) सूरदास		

दृश्य-श्रव्य उपकरणों और सामग्री निर्देशिका का संशोधित संस्करण

देश भर से उपयोगी आँकड़ों को एकत्र करके दृश्य-श्रव्य उपकरण और सामग्री निर्देशिका का संशोधित संस्करण तैयार किया जा चुका है और अब यह छपने की हालत में है।

प्रदर्शनियाँ

शिक्षण-सामग्री विभाग ने विश्व हिन्दी सम्मेलन में अपनी दृश्य-श्रव्य सामग्री की एक प्रदर्शनी आयोजित की।

विभाग ने 1 और 2 मार्च, 1984 को वैज्ञानिक प्रगति के लिए भारतीय संस्थान द्वारा ताज पैलेस होटल में आयोजित प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।

कार्यशाला विभाग स्कूलों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के अनुसंधान और विकास कार्य, विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर साईंस किटों के बैच उत्पादन, आई० आई० टी० शिक्षार्थियों और राज्यों तथा यू० टीज (U. Ts.) और विदेशों के विदग्ध व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा ऑफिस उपकरणों के केंद्रीय संचयन और संचारेक्षण आदि क्रियाकलापों में लगी हुई थी।

डिजाइन और परिवर्धन (परिवर्धन)

बैरोमीटर, मोलिक्यूलर मॉडल्स, समुद्र-विज्ञान आदि से संबंधित मॉडल्स जैसे उपकरणों के सस्ते रूपांतरणों को बनाने के लिए अनुसंधान और परिवर्धन का कार्य प्रारंभ किया गया है। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में दो पैनल्स प्राइमरी स्तर पर विज्ञान के शिक्षण के लिए स्थानीय स्रोतों की सहायता से कम लागत से तैयार की गई शिक्षण सामग्री के उपयोग को चित्रित करते हुए विकसित और प्रदर्शित किए गए।

राष्ट्रीय विज्ञान मेले की सलाहकार समिति के परामर्श पर एक विज्ञान किट क्लब विकसित किया गया। इस नई किट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विशेषरूप से तैयार किए गए हाथ के औजार, उपकरण, बहुपयोगी औजार, उपभोग्य और प्रथमोपचार संबंधी उपकरणों सहित 58 मुद्दे थे। यह निर्माण-कार्य की उस श्रेणी को सुलभ बनाती है जिसकी जरूरत विज्ञान के विद्यार्थियों और अध्यापकों को सामान्य रूप से अपने प्रयोग तथा विज्ञान की प्रदर्शनीय वस्तुओं के निर्माण में पड़ती है। VI से VIII कक्षाओं के लिए संघटित विज्ञान किट पहले ही बना ली गई है और किट का प्रदर्शन स्कूल के अध्यापकों के समक्ष कर दिया गया है।

कार्यशाला ने बच्चों के राष्ट्रीय विज्ञान मेले, 1983 के लिए प्रदर्शनीय वस्तुएँ, पैनल्स तथा आधारों आदि का निर्माण और प्रदर्शन किया।

बैच उत्पादन

राज्य शिक्षा संस्थान जम्मू और राज्य शिक्षा संस्थान गोआ को 400 प्राथमिक विज्ञान किटें और दूसरे संस्थानों को 6 विज्ञान किटें भेजी गईं। करीब 3000 प्राथमिक विज्ञान किटें भेजने के लिए तैयार थीं।

प्रशिक्षण

आई० टी० आई० के सात शिक्षार्थियों और एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त शिक्षार्थी को प्रत्येक वर्ष विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ व्यवसायों के लिए आर० आई० (R. I.) कक्षाओं का संचालन विभाग में किया जाता है।

राज्यों और विदेशों से अल्पकालिक यात्रा के लिए आए कार्यकर्त्ताओं का डिजाइन विकास के पहलू से साक्षात्कार करवाया गया।

जुलाई, 1983 में भूटान के तीन विज्ञान शिक्षकों के एक दल को विज्ञान उपकरणों के डिजाइन विकास को दो सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया गया।

यह कार्यक्रम भूटान की विशिष्ट जरूरतों को जानने के लिए यूनिसेफ (U.N.I.C.E.F.) द्वारा प्रवर्तित किया। यह विज्ञान शिक्षण किट को डिजाइन करने और तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की परामर्श सेवा का इच्छुक था।

अंतर्देशीय अध्ययन के लिए यात्रा पर आई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 5 सदस्यों के

दल के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद् ने आतिथेयी का काम किया। कार्यशाला विभाग में क्रियाकलापों के अभिविन्यास के अतिरिक्त उन्हें अंबाला में विज्ञान उपकरण बनाने वाली कुछ बड़ी और मध्यम स्तर की प्राइवेट कंपनियाँ दिखाई गईं।

यूनेस्को द्वारा प्रवर्तित "प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान के अध्यापन के लिए स्थानीय स्रोतों के माध्यम से विज्ञान उपकरणों का निर्माण और विज्ञान उपकरणों के निर्माण में कार्यशाला की कार्य-प्रणाली और व्यवस्था" शीर्षक से एक कार्यशिविर का 15 से 30 दिसंबर, 1983 तक आयोजन किया गया। 22 राज्यों और यू० टी० (U. Ts.) ने सहभागी भेजे। संसाधन-व्यक्तियों के पैनल में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् संकाय के सदस्यों के अतिरिक्त दो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी थे।

27 फरवरी से 7 मार्च, 1984 तक विज्ञान-उपकरणों के निर्माण में केरल के 19 कार्यान्मुखी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विज्ञान क्लब किट की समीक्षा करने तथा सुझाव देने के लिए एक समीक्षा समिति नियुक्त की। समिति की बैठक 20 फरवरी, 1984 को हुई।

प्रकीर्ण

परिषद् के कार्यशाला विभाग ने एन० आई० ई० (N. I. E.) वाहनों के दस्तों, गरम-सरद मौसम संबंधी उपकरण, जन संबोधन व्यवस्था, विविध बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री आदि की मरम्मत तथा संचारक्षण का कार्य जारी रखा है। मरम्मत तथा रखरखाव संचारक्षण कार्यों के अतिरिक्त विभाग ने परिसर को सुन्दर बनाने के मार्गदर्शक नक्शे, संकेतक, शैडों के निर्माण आदि जैसे कार्य आरंभ किए हैं।

जनसंख्या शिक्षा

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना ने 1983-84 के दौरान चौथे वर्ष में प्रवेश किया। प्रथम चरण में, 1980-81 में नौ राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश इस परियोजना में शामिल हुए। 1981-82 में यह संख्या बढ़कर, इसके दूसरे चरण में, सोलह राज्यों और दो केंद्र शासित राज्यों तक पहुंच गई। 1982-83 तक आकर इक्कीस राज्य और सात केंद्र शासित राज्य इस योजना के क्रियान्वयन में शामिल हो गए। चौथा वर्ष वस्तुतः स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाला वर्ष था जिसमें इसके कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन तथा सामग्री के विकास पर जोर दिया गया।

परियोजना की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां

- ०० राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या शिक्षा कक्षों की संख्या सतरह से बढ़कर सत्ताईस हो गई।

- ०० बाईस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने जनसंख्या शिक्षा के लिए अपना पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। कुछ चुने हुए विषयों के स्कूल पाठ्यक्रम में इनके विचारों को विषयवस्तु के अंतर्गत ले लिया है।
- ०० अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सतरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रशिक्षण पेटिका का विकास किया है। इनसे अध्यापक शिक्षकों और विद्यालय प्रशासकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ०० गत वर्ष जनसंख्या शिक्षा में अभिविन्यस्त शिक्षा निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों की संख्या 3076 से बढ़कर 6404 हो गई।
- ०० जनसंख्या शिक्षा में अभिविन्यस्त की कुल संख्या अप्रत्याशित रूप से 3,14,352 से बढ़कर 50,000 हो गई। यह राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा जारी किए गए निर्देश का परिणाम था। इसकी अध्यक्षता, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव ने की थी। इस अभिविन्यास कार्यक्रम की अवधि दो से पांच साल तक की थी।
- ०० मध्य प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 12,000 छात्राध्यापकों को जनसंख्या शिक्षा में अभिविन्यस्त किया गया।
- ०० ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही थी तथा प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या इस क्रम में 1982-83 में 156 थी जो 1983-84 में बढ़कर 234 हो गई।
- ०० इन पुस्तकों की कुल संख्या, जिनमें मुद्रित तथा साइक्लोस्टाइल दोनों ही शामिल हैं, 9,44,450 हो गई जबकि 1982-83 में यह संख्या सिर्फ 2,98,875 थी।
- ०० दो सौ पचास से भी अधिक स्लाइडें जनसंख्या शिक्षा पर राज्यों ने (1982-83) तैयार कीं। इसका मॉडल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बनाया था।
- ०० राज्यों ने अपने आप 240 चार्टों तथा 24 पोस्टरों का विकास किया। उन लोगों ने ग्राफिक एड्स, तथा भाषण कार्ड, ट्रांस्पीरेंसी और आडियोटेप शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाए। छोटे परिवार का आदर्श लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ राज्यों ने कठपुतली कला का भी इस्तेमाल किया है। इस विषय पर एक राज्य ने एक समग्र नाटक लिखवाकर उसका मंचन करवाया।
- ०० जिन राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान कार्य शुरू कराया है उनकी संख्या 1982-83 में 5 थी जो बढ़कर 1983-84 में 13 हो गई। इस अवधि में अनुसंधान के विषयों की संख्या 17 से बढ़कर 34 हो गई।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

केंद्र में गतिविधियों का मुख्य जोर राज्य के परियोजना दलों को सहायता पहुंचाने का था ताकि अपने स्तर पर वे शिक्षण सामग्री को गुणात्मक रूप से बेहतर बना सकें। इस उद्देश्य को को पूरा करने के लिए उसने तीन भिन्न-भिन्न मोर्चों पर कार्य किया है—

1. नमूने के तौर पर सामग्री का विकास
2. राज्यों को प्रशिक्षण पेटिकाओं का वितरण

3. मूल्यांकन उपकरणों की एक बैटरी तैयार करना ।

नमूने के तौर पर सामग्री का विकास

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की जनसंख्या शिक्षा एकक ने औपचारिक-केतर शिक्षा क्षेत्र के लिए (आयु 9-14 वर्ष) जनसंख्या शिक्षा के बारे में शिक्षण सामग्री का विकास करके उसे राज्यों का वितरित कर दिया। यह दो अखिल भारतीय कार्यशालाओं का परिणाम था। ये कार्यशालाएं पंजाब कृषि विद्वद्विद्यालय, लुधियाना में और क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, बंगलौर में आयोजित की गई थीं।

दिल्ली और पंचमढ़ी में आयोजित दो अखिल भारतीय कार्यशालाओं में जनसंख्या शिक्षा पर अंग्रेजी तथा हिंदी में रेडियो और दूरदर्शन के लिए वार्तापाठ तैयार किए गए। सारे देश से इस विषय से संबंध रखने वाले विशेषज्ञों को इस कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने गैर प्रक्षेपीय शिक्षण-अधिगम सहायक सामग्री विकसित करने की परियोजना हाथ में ली है जिसका इस्तेमाल सामान्य कक्षा कक्ष में किया जा सके।

राज्य परियोजना दलों को प्रशिक्षण पेटिका का वितरण

हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रथक-पृथक राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई स्लाइडें टेप की गई व्याख्याएँ राज्यों को वितरित की गईं। इनमें 264 स्लाइडों के 100 सेट तथा 3 आडिओ टेप थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्यों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षण पेटिका के ताने-बाने के भीतर रखा जा सके। एक स्लाइड प्रोजेक्टर और एक टेपरेकार्डर भी प्रत्येक राज्य को दिया गया। इस सेट के साथ एक प्रशिक्षण पुस्तिका भी दी गई है। इस युक्ति का असर इस तथ्य से जाहिर होता है कि इस वर्ष के दौरान राज्यों ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य को अधिक गंभीरता से और बड़े पैमाने पर हाथ में लिया।

मूल्यांकन उपकरणों की माला का विकास

तीन स्तरों—अ, ब और स के लिए जनसंख्या सतर्कता परीक्षण को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये विद्यार्थियों की और अध्यापकों की जनसंख्या सतर्कता को जानने के लिए बनाए गए हैं। उनका क्रम इस प्रकार है—

‘अ’ स्तर का परीक्षण : प्राइमरी स्कूल के अध्यापक और हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए।

‘ब’ स्तर का परीक्षण : माध्यमिक स्कूल शिक्षक तथा स्नातक।

‘स’ स्तर का परीक्षण : उच्च माध्यमिक स्कूल के अध्यापक स्कूल प्रशासक तथा परियोजना कर्मचारी।

इन परीक्षणों में सिर्फ बोधात्मक पक्ष को ही ध्यान में नहीं रखा गया है बल्कि सहज तथा प्रभावात्मक पक्ष को भी। इन परीक्षणों के साथ एक पुस्तिका भी है जिसमें विस्तार से बताया

गया है कि इन परीक्षणों को कैसे चलाया जाए, प्रतिक्रिया का लेखाजोखा कैसे रखा जाए तथा परिणामों को किस प्रकार समग्र रूप दिया जाए।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने उपकरणों की दूसरी शृंखला के विकास का श्रीगणेश किया है। यह कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों के मूल्यांकन में मदद करेगा, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन, अध्यापकों के कक्षा तथा प्रदर्शन के पाठ तथा प्रशिक्षण सामग्री। इस उद्देश्य से वाराणसी में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा उपकरणों को वाल्टेयर की एक कार्यशाला में पुनः आजमाया गया। राज्यों ने जो सामग्री विकसित की थी उसमें से सर्वोत्तम सामग्री का चयन करने के लिए कार्यवाही की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों में गुणात्मक रूप से बेहतर सामग्री बनाने की प्रतियोगी भावना पैदा हुई।

महाराष्ट्र की अंतर्राज्यीय निरीक्षण यात्रा

राष्ट्रीय संचालन समिति के निर्णय के फलस्वरूप, चरण I और चरण II राज्यों के सभी निदेशकों और सभी संयोजकों को आमंत्रित किया गया, जिससे वे महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीतियों को निकट से देख सकें कि उसने किस तरह से इतना विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 जिलों के 170 केन्द्रों में एक ही सप्ताह में आयोजित किया।

माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों तक परियोजना का विस्तार

अब तक जो कार्यक्रम सिर्फ स्कूलों तक सीमित था देश में उसका विस्तार करके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचा दिया गया। इसमें सभी चार क्षेत्रीय कालेजों को शामिल करने का, तथा उन्हें संसाधन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया। बी० एड० तथा एम० एड० पाठ्यक्रम के लिए जनसंख्या शिक्षा संबंधी नमूने के रूप में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तथा सामान्य दिशा निर्देश का विकास करने के लिए अगस्त 1983 में उदयपुर में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। जनसंख्या शिक्षा में क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की गतिविधियों का ब्योरा 'अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण' अध्याय में दिया गया है।

राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक हमेशा की तरह हर छः महीने में एक बार होती है। इस समिति का अध्यक्ष सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार होता है। इन बैठकों में शिक्षा सचिवों, परियोजना निदेशकों, चुने हुए केंद्रीय मंत्रालयों और चोटी की शिक्षण निकायों ने हिस्सा लिया। समिति ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अध्यापकों, शिक्षा प्रशासकों तथा राज्य अधिकारियों की ओर से स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। समिति ने इस बात की सिफारिश की कि इस कार्यक्रम में अभिविन्यस्त होने वाले अध्यापकों के लक्ष्य का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। इसने यह भी महसूस किया कि चूंकि अब तक परियोजना की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है, अगली पंचवर्षीय योजना में भी प्रयास को जारी रखने की आवश्यकता है। आखिरी बैठक नवंबर 1983 में हुई।

त्रिपक्षीय प्रगति के मूल्यांकन के लिए बैठकें

यह बैठक साल में एक बार होती है और कार्यक्रम के प्रतिबद्ध तीनों ही पक्ष प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। इस वर्ष की बैठक 2 सितम्बर 1983 को हुई। इसमें भारत सरकार के अतिरिक्त 'यूनेस्को' और यू० एन० एफ० पी० ए० के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गतिविधियों के मूल्यांकन से यह नतीजा निकला कि यह अपनी किस्म की सबसे बड़ी और अत्यंत सफल विश्व की परियोजना थी। इस परियोजना के तहत हासिल किए गए अनुभवों की बहुत से विकासशील और तीसरी दुनियाँ के देश उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें प्रशंसा की खास बात विद्यालय की वर्तमान पद्धति के भीतर ही काम करना और बिना नया ढांचा खड़ा किए ही उपकरणों का इस्तेमाल था।

वर्तमान स्कूल विषयों पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने की युक्ति एक ऐसी विशेषता थी जिसने यूनेस्को और यू० एन० एफ० पी० ए० के प्रतिनिधियों को प्रभावित किया। विभिन्न स्कूल विषयों के लेखकों का अभिविन्यास ने इन प्रतिनिधियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। समिति ने इस कार्यक्रम को अगली पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाने की सिफारिश भी की।

परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की बैठकें

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन पर चार बैठकें हुईं।

- (1) केंद्रीय जनसंख्या शिक्षा एकक की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना की प्रगति मूल्यांकन समिति की बैठक।
- (2) चरण III राज्यों की प्रगति का लेखा-जोखा लेने के लिए प० प्र० मू० की बैठक।
- (3) चरण II तथा I राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प० प्र० मू० की बैठक।
- (4) केंद्रीय जनसंख्या शिक्षा एकक की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प० प्र० मू० की बैठक।

ये बैठकें दिल्ली, धारवाड़ और भोपाल में हुईं। इस अवसर पर प्रगति का मूल्यांकन किया गया तथा बजट अनुमानों के साथ-साथ गतिविधियों के लिए पुनः सारणी तैयार की गई। इन बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भारत सरकार के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक, यू० एन० एफ० पी० ए० का स्थानीय प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प० प्र० मू० की भोपाल बैठक ने अन्य बातों के साथ राज्य जनसंख्या शिक्षा परियोजना के निर्देशक नियमों पर भी बातचीत की जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य अंग के रूप में शामिल किया जाना था।

विदेशी शिष्टमण्डल और उनकी संबद्धता

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को कार्यालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद् से दो राज्य अधिकारियों को संबद्ध करने के लिए चुना। ये अधिकारी थे वियतनाम गणराज्य के वी० एन० विन्ह, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के सचिव और श्री एम० एक्स सैन, निदेशक, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना। यह दिसंबर 1983 में एक माह के लिए संबद्ध हुए थे। मुख्यालय में उनका गहन प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद उनको राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, शिक्षा विभाग, लखनऊ तथा दिल्ली और आगरा के निकटवर्ती स्कूल दिखाए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अपनाई गई युक्तियों से यह दल काफी प्रभावित हुआ, खास तौर से जिस रूप में परिषद् ने जनसंख्या शिक्षा का क्रियान्वित कर रखा है।

आठ सदस्यों के बंगला देश के एक शिष्टमंडल ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आठ दिन बिताए। इस दल ने कार्यक्रम को होते हुए देखकर प्रशंसा का भाव जाहिर किया। उन्होंने सक्रिय हालत में जो कार्यक्रम देखे वे इस प्रकार थे—पाठ्यक्रम का विकास, शैक्षिक सामग्री का निर्माण, विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम का संयोजन तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई मूल्यांकन तकनीकें।

यूनेस्को के अंतर्देशीय चल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, नेपाल और थाईलैण्ड के अध्येताओं के एक मिले-जुले दल ने एक सप्ताह तक भारत का दौरा किया। दल ने दो दिन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की केंद्रीय इकाई के साथ बिताए। उसके बाद इस दल ने उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजनाएं देखीं ताकि क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को वास्तविक रूप में वे देख सकें।

प्रीकृ शिक्षा के संबंध में अफगानिस्तान के एक आठ सदस्यों के दल ने भारत का दौरा किया। उन लोगों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के केंद्रीय जनसंख्या एकक को देखा ताकि वे जनसंख्या शिक्षा के अवयवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें।

दो सदस्यों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् देखने आया। इस आगमन का उद्देश्य था भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने की युक्तियों और पद्धतियों से अपने को परिचित कराना।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक तथा औपचारिकतर जनसंख्या शिक्षा की संगति पर एक सप्ताह की एक क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से यूनेस्को ने सहायता मांगी। 16-23 मई, 1983 तक संगोष्ठी का आयोजन बंगलौर में किया गया।

डॉ० ए० एल० एन० शर्मा, रीडर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, ने अंतर्देशीय चल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 27 नवंबर से 5 दिसंबर 1983 तक भाग लिया तथा यूनेस्को दल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करने के साथ वे थाईलैण्ड भी गए।

संचारेक्षण और संयोजन

चूँकि यह परियोजना देश के लगभग हर हिस्से में पहुँच चुकी है इसलिए संचारेक्षण और संयोजन का महत्व काफी बढ़ गया है। इस बात को सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार हो जो मूलतः राज्य की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यकर्त्ताओं ने प्रायः राज्यों का निरीक्षण दौरा किया, संगोष्ठियाँ, प० प्र० मू० की बैठकें तथा विदेशी शिष्टमण्डलों के निरीक्षण दौरो से इसमें काफी मदद मिली।

शैक्षिक मूल्यांकन

मूल्यांकन सारे शैक्षिक प्रयोगों का अविभाज्य अंग है। क्योंकि इस तरह के प्रयोग करने के लिए अपनाई गई युक्तियों तथा दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन के लिए इससे सामग्री मिलती है। शैक्षिक मूल्यांकन को हर हालत में वस्तुगत, विस्तृत, वैज्ञानिक तथा अविरल होना होता है। शैक्षिक मूल्यांकन विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् परीक्षा सुधार पर काम कर रही है। इसका आधार है— अनुसंधान, प्रशिक्षण और नमूने के तौर पर तैयार की गई मूल्यांकन सामग्री का विकास और विस्तार। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् स्कूल शिक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सहयोग से काम कर रही है।

मूल्यांकन पुस्तिकाओं की शृंखला के रूप में तथा विभिन्न विषयों में परीक्षण इकाइयों के रूप में पथ-प्रदर्शक सामग्री प्रयोग की जाती है। शैक्षिक मूल्यांकन पर तथा इससे संबद्ध अनेक उपविषयों पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं

को जिन्हें आवश्यकता होती है, परामर्शकारी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। लगातार आने वाले प्रकाशनों से यह कार्यक्रम और अधिक संपन्न होता है।

अनुसंधान

1980 और 1981 के बाह्य परीक्षा

परिणामों का विश्लेषण

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषदों से इस बात के लिए आंकड़े एकत्र किए गए कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। 1980 और 1981 में X, XI और XII कक्षाओं के अंत में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और कितनों को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। विद्यार्थियों की संख्या का संकलन, जिन्होंने 1980 और 1981 की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी पाई थी (माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में), विभिन्न परिषदों को जांच के लिए भेज दिया गया। अधिकांश परिषदों ने इन आंकड़ों की संख्या की पुष्टि कर दी है, जैसे ही सारी परिषदों की तरफ से इसकी पुष्टि हो जाती है, इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा परिषदों और माध्यमिक शिक्षा

परिषदों द्वारा प्रश्नपत्र बनाने तथा उत्तर-

पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रथा का अध्ययन

देश के विभिन्न राज्य शिक्षा परिषदों द्वारा प्रश्न पत्र बनाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने की प्रथा का अध्ययन हाथ में लिया गया। एक प्रश्नावली बनाकर उसे सभी राज्य शिक्षा परिषदों के पास भेजा गया ताकि आंकड़े एकत्र किए जा सकें।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के प्रत्याशियों की

जांच के निर्धारण के लिए कट स्कोर्स का अध्ययन

कक्षा X व XII के लिए 1982 के रा० प० ख०

परीक्षणों के आइटमों और टेस्ट स्कोरों का अध्ययन

दोनों परियोजनाओं के विश्लेषण के तरीके बनाए जा रहे हैं।

स्वीकृत आवासीय स्कूलों में भारत

सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति

योजना का गहन अध्ययन

मान्यता प्राप्त आवासीय स्कूलों में भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के कहने पर यह अध्ययन कार्य हाथ में लिया गया। विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए कई प्रश्नावलियाँ तैयार की गईं। छात्रों,

अभिभावकों तथा कई अन्य संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस योजना के सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। शिक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणी के लिए प्रतिवेदन दे दिया गया।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन और बच्चों के रचनात्मक कार्य में परिवर्तन

इस परियोजना को पूरा कर दिया गया है और अब इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विज्ञान प्रतिभा की खोज वाले विद्यार्थियों के निष्पादन का गहन अध्ययन

निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर प्रश्नावली के प्रथम भाग का विश्लेषण किया गया—पृष्ठभूमि में कार्य करने वाले घटक, अभिभावकों का दृष्टिकोण, विद्यालय तथा कॉलेज की अवधारणा, अध्यापक के बारे में अवधारणा आदि द्वितीय भाग का विश्लेषण हाथ में लिया गया है और इससे संबद्ध सामग्री की समीक्षा की जा रही है।

बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की शैक्षिक तथा व्यावसायिक आकांक्षाएं

दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय अध्यापकों की मदद से साक्षात्कार सारणी को जाँचा/परखा गया। विश्लेषण योजना पर कार्य चल रहा था।

विकास कार्य

प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में 'क्रिटेरियन-रेफरेंस' परीक्षणों का विकास

इस परियोजना के अंग के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कक्षा तीन के पर्यावरण अध्ययन विज्ञान के पाठ्यक्रम को अनुक्रम प्रदान किया गया, और किन विषयों का इसमें अध्ययन होना चाहिए उनको पहचाना गया। एक कार्यदल का गठन किया गया ताकि वह विभिन्न विषयों के विभिन्न अधिगम एककों में अभीप्सित अधिगम परिणामों तथा प्रमुख अवधारणाओं को विकसित करे। प्रत्येक अधिगम एकक पर 'क्रिटेरियन रेफरेंस' परीक्षण मार्गदर्शक परीक्षण के उद्देश्य से तैयार किए गए।

शैक्षिक उद्देश्यों पर परिसंवाद

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में 1 तथा 2 नवंबर 1983 को 'शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य' विषय पर दो दिनों का एक प्रसिंवाद आयोजित किया गया। इसमें पच्चे पढ़े गए और उन

पर बहस हुई। प्रस्तुत किए गए सुझावों के संदर्भ में पचास लेखकों से पचासों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया।

जीवविज्ञानों की मूल्यांकन पुस्तिका

जीवविज्ञानों की मूल्यांकन पुस्तिका की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 17 से 20 जनवरी 1984 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विषय के 14 विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

अर्थशास्त्र की मूल्यांकन पुस्तिका

नौ अध्याय वाली पुस्तिका का प्रथम प्रारूप तैयार किया जा चुका है। इसे टिप्पणी के लिए 35 विशेषज्ञों के पास भेजा जा रहा है। प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद इसे अंतिम रूप देकर मुद्रण के लिए भेज दिया जाएगा।

इतिहास की मूल्यांकन पुस्तिका

नई दिल्ली में 6 से 19 फरवरी 1984 के दौरान इतिहास की मूल्यांकन पुस्तिका की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक आरंभिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों, कालेजों तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के 9 विशेषज्ञ उपस्थित थे।

भूगोल की मूल्यांकन पुस्तिका

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली परिसर में भूगोल की मूल्यांकन पुस्तिका की पाण्डुलिपि पर एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इसमें विचार-विमर्श करने वाले विशेषज्ञ लोग थे।

अंग्रेजी की मूल्यांकन पुस्तिका

अंग्रेजी की मूल्यांकन पुस्तिका का प्रारूप तैयार किया गया। मई 1983 में 6 विषय विशेषज्ञों ने इस पर विचार-विमर्श किया। इसमें सुधार और परिवर्तन के लिए जो सुझाव आए उनको इसमें शामिल कर लिया गया और अंततः इसको छपने के लिए भेज दिया गया।

कक्षा IX तथा X के लिए नागरिकशास्त्र में एकक परीक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में 1-8 फरवरी 1984 के बीच कक्षा IX तथा X की नागरिकशास्त्र विषय की कक्षाओं के लिए एकक परीक्षण का विकास करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नागरिकशास्त्र में परीक्षण एकक बनाए गए। ठीक से समीक्षा करने के बाद इनको विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाएगा।

रसायनशास्त्र में +2 स्तर के लिए एकक परीक्षण

नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में 27 जनवरी से 3 फरवरी 1984 के बीच रसायनशास्त्र में कक्षा XI के लिए एकक परीक्षण विकसित करने के लिए एक कार्यशाला संचालित की गई। इस कार्यशाला में 26 लोगों ने भाग लिया। इसके दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की रसायनशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के आधार पर एकक परीक्षण विकसित किए गए। 12 से 18 मार्च 1984 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में एक छोटे से कार्यदल की बैठक हुई जिसमें इन परीक्षण एककों को परिष्कृत कर अंतिम रूप दिया गया।

कक्षा IX तथा X के लिए अंग्रेजी में आइटम बैंक

एक कार्यदल की बैठक 21-25 फरवरी 1984 के बीच हुई। इसका लक्ष्य माध्यमिक कक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा के आइटम बैंक का मूल्यांकन कर उसे अंतिम रूप देना था। इस बैंक को पहले आयोजित एक कार्यशाला में तैयार किया गया था। इस कार्यशाला में अंग्रेजी के तीन नामी अध्यापकों ने हिस्सा लिया।

समाज विज्ञान (+2 स्तर पर राजनीतिशास्त्र) के लिए मूल्यांकन पुस्तिका

अभी तक इस पुस्तिका के कुछ थोड़े से अध्याय विकसित किए गए हैं।

माध्यमिक स्कूल शिक्षा परिषदों की बाह्य परीक्षाओं के मूल्यांकन में सुधार

विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों की परीक्षा में सुधार लाने के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपना सहयोग जारी रखा। नीचे दी गई गति-विधियों में इस बात का संक्षेप में उल्लेख किया गया है—

राजस्थान शिक्षा परिषद् के साथ कार्य

राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सहयोग से 7-10 फरवरी 1984 के बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अजमेर में एक कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला जोधपुर की एक कार्यशाला में तैयार की गई सामग्री का परिष्कार करने के लिए आयोजित की गई थी। हर विषय में दो एकक परीक्षण भी तैयार किए गए। एक उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए और दूसरा माध्यमिक स्तर के लिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष विषयवार एककों को प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गए। इस कार्यशाला में सोलह व्यक्तियों ने भाग लिया।

बिहार शिक्षा परिषद् के साथ कार्य

जमशेदपुर में 21-28 मार्च 1984 के दौरान माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्चा बनाने की तक-

नीक के बारे में एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणित और विज्ञान में अध्यापकों ने वस्तुगत परीक्षण वाले प्रश्न बनाए।

जम्मू तथा कश्मीर परिषद् के साथ कार्य

जम्मू तथा कश्मीर शिक्षा परिषद् के प्रश्नपत्र बनाने वाले कार्यदल की बैठकें विज्ञान, समाज-विज्ञान तथा मानविकी विषयों के प्रश्नपत्र बनाने की तकनीक पर विचार करने के लिए आयोजित की गईं। नमूने के तौर पर प्रश्नपत्र बनाए गए। संबद्ध स्कूलों के पास परिषद् ने उन्हें विचारार्थ भेजा है।

कर्नाटक परिषद् के साथ कार्य

बंगलौर में सात दिनों की एक कार्यशाला में भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान और गणित में कर्नाटक शिक्षा परिषद् के 34 प्रश्नपत्र बनाने वालों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षार्थियों ने नमूने के रूप में प्रश्नपत्र बनाए। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका शीर्षक था 'प्रश्नपत्र बनाने की तकनीक'।

मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद् के साथ कार्य

सितंबर 1983 में आठ दिनों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद् के वर्तमान और भावी प्रश्नपत्र निर्माताओं को संतुलित प्रश्नपत्र निर्माण के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया। समाज विज्ञान के विषयों में नमूने के तौर पर प्रश्नपत्र तैयार कराए गए। इन प्रश्नपत्रों को छाप कर परिषद् संबद्ध स्कूलों को भेजेगी।

आइटम लेखकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

कलकत्ता में 15-29 फरवरी 1984 तक प्राविधिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में पूर्वी क्षेत्र के लिए गणित के मूल्यांक का 15 दिनों का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। कुल मिला कर 32 लोग असम, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से इसमें शामिल हुए। शैक्षिक मूल्यांकन में अभिविन्यास के अलावा परीक्षण आइटमों के निर्माण, एकक परीक्षण और नमूने के प्रश्नपत्र बनाने संबंधी बातों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

अर्थशास्त्र का शैक्षिक मूल्यांकन विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर, नई दिल्ली में 13-20 फरवरी तक आठ दिनों का अर्थ-शास्त्र के मूल्यांकन का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के 23 भागीदार उपस्थित थे। पाठ्यक्रम का उद्देश्य उन प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना था जो परिषदों को विभिन्न विषयों के संतुलित प्रश्नपत्र तैयार करने में मदद करेंगे।

दक्षिणी क्षेत्र के आइटम लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए विज्ञान में गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के लिए 29 फरवरी से 9 मार्च 1984 तक विज्ञान के आइटम लेखकों के लिए एक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पाण्डिचेरी और तमिलनाडु के 38 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शैक्षिक मूल्यांकन से संबंधित विविध अवधारणाओं पर भाषण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वस्तुगत प्रश्न तैयार किए गए।

दक्षिणी क्षेत्र के आइटम लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए गणित में गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के लिए 29 मार्च से 12 अप्रैल 1984 तक गणित के मूल्यांकन के लिए 12 दिनों का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया। कुल मिला कर 29 लोगों ने आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मूल्यांकन में अभिविन्यास के अलावा गणित में परीक्षण आइटम, एकक परीक्षण और नमूने के प्रश्नपत्र तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

विशेष कार्यक्रम

भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शैक्षिक मूल्यांकन पर तीन सप्ताह के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के निवेदन पर यह पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 21 अधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें स्कैड्रन लीडर तथा विंग कमाण्डर स्तर के अधिकारी थे। ये चयन प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रमाण पत्र तथा तरक्की इम्तिहानों से विभिन्न स्तरों पर संबद्ध थे। इस पाठ्यक्रम के मकसद थे, उन विविध पाठ्यक्रमों के उद्देश्यों को पहचानना जो एयर फोर्स में एयर मैन को पढ़ाया जाता है और विस्तृत नमूने के तौर पर इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्नपत्र बनाना।

परामर्श कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित श्रीलंका के एक अध्येता को आठ सप्ताह के लिए अपने साथ संबद्ध किया था। यह व्यक्ति यू० एन० डी० पी० परियोजना में मूल्यांकन सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। भारत के प्रशिक्षण से अध्येता को (व्यावसायिक विषयों के विशेष संदर्भ में) मूल्यांकन पद्धति की प्रक्रिया तथा रचना संबंधी उचित दृष्टि प्राप्त हुई।

कक्षा X के लिए अंग्रेजी विषय का संतुलित प्रश्नपत्र बनाने में दिल्ली के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के ओपेन स्कूलों को मदद दी गई। इन प्रश्नपत्रों को परिषद् ने छापा तथा इनको विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए उनमें वितरित किया गया। जून 1983 में दिल्ली प्रशासन की विज्ञान शाखा को सहायता दी गई। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान

में वस्तुनिष्ठ परीक्षण आइटम बनाने के लिए इसमें भाग लेने वालों को प्रशिक्षित किया गया।
लगभग 500 परीक्षण आइटम बनाए गए।

प्रकाशन

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन सामने आए :

1. इम्प्रूविंग प्रैक्टिकल इक्जामिनेशंस इन साइंस
2. यूनिट टेस्ट्स इन इंग्लिश फॉर क्लास XI
3. यूनिट टेस्ट्स इन इंग्लिश फॉर क्लास XII
4. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग
5. स्टैटिस्टिकल डाटा रिगार्डिंग फर्स्ट डिवीजनर्स इन बोर्ड्स ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एजुकेशन फॉर 1980 एंड 1981
6. एजुकेशनल आब्जेक्टिव्स इन एवैलुएशन
7. एजुकेशनल आब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशंस फॉर टेस्टिंग
8. इनडेपेंडेंट स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरिट स्कालरशिप स्कीम इन एप्रूव्ड रेजिडेंशल स्कूल्स
9. आब्जेक्टिव टेस्ट टीचिंग एंड टेस्टिंग (सैम्पुल टीचिंग लर्निंग यूनिट इन बायोलोजी)।

सर्वेक्षण, आंकड़ा संसाधन और प्रलेखन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् सर्वेक्षण कार्य करती है, आंकड़ा संसाधन सेवा प्रदान करती है तथा राज्यस्तर के उन अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है जो शैक्षिक नियोजन के प्रभारी अधिकारी हैं तथा राज्य शिक्षा संस्थानों के उन अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है जिन्हें निदर्श सर्वेक्षण पद्धतियों को शिक्षा में लागू करना है।

सर्वेक्षण द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं उनसे उन इलाकों में जहां स्कूल नहीं हैं, उनके लिए स्थान तय करने तथा शिक्षा की योजना बनाने में मदद मिलती है। सर्वेक्षण के बाद प्रखण्ड स्तर और उससे आगे शिक्षण सुविधाएँ नियोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, मुख्यालय, नई दिल्ली के एक बहुत बड़े संगणक केंद्र से सीमांत रूप से जुड़ा हुआ है। यह केंद्र LSI-11 संगणक तथा अन्य प्रकार के आंकड़ा संसाधन यंत्रों से लैस है जो इसकी आंकड़ा संसाधन क्षमताओं को काफी बढ़ा देते हैं तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए संगणक के इस्तेमाल की क्षमता भी इनसे

बढ़ जाती है। इस केंद्र में LSI-11/10 संसाधक हैं उनकी स्मृति क्षमता 320 K 16-BIT शब्दों की है।

शैक्षिक सर्वेक्षण

छात्रों के नामांकन तथा प्राइमरी स्तर पर उनको बनाए रखने की दर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने केयर द्वारा समर्थित छात्रों के नामांकन और प्राइमरी स्तर पर उन्हें स्कूल में बनाए रखने की दर के ऊपर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभावाधीन एक अध्ययन चलाया।

इस अध्ययन ने मध्याह्न भोजन के प्रभाव का लड़के और लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के ऊपर अलग-अलग अध्ययन किया। इस अध्ययन परिधि में लिए गए क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल शामिल थे।

सभी बारह राज्यों से एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अतिरिक्त, राज्यों को दो समूह में बांटा गया। उदाहरण के लिए वे राज्य जिनके इस कार्यक्रम में 'केयर' ने मदद की थी तथा साथ में उन्होंने अपनी ओर से भी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाए थे और दूसरे वे राज्य जहाँ यह कार्यक्रम सिर्फ केयर की मदद से चलाया गया था। आंकड़ों पर विचार करने में इस बात की जरूरी समझा गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक जिले को छोड़कर शेष को चार समूहों में बांट दिया जाए। इन चारों समूहों के आंकड़ों का विश्लेषण आरंभ किया गया इसमें जिले को माप की इकाई माना गया। हरियाणा और कर्नाटक में अलग से एक प्रखण्ड को माप की इकाई के रूप में लेकर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का छात्रों के दाखिले तथा उनको बनाए रखने के ऊपर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन तथा आकलन किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण में हर चरण का समाश्रयण विश्लेषण, चरता का विश्लेषण तथा सह-चरता विश्लेषण शामिल था।

जिला स्तर के अध्ययन से इस बात के संकेत मिले कि दाखिले की दर पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव जिला स्तर पर जरूर पड़े। लड़कियों के दाखिले में इसके विशेष प्रभाव को लक्षित किया जा सकता है। हरियाणा तथा कर्नाटक में प्रखण्ड स्तर पर किए गए अध्ययन से न सिर्फ उपर्युक्त खोजों की पुष्टि होती है बल्कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा दाखिले की संख्या का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इस बात की भी पुष्टि होती है। जिन राज्यों की अधिक संख्यक जनता आर्थिक रूप से विपन्न है उन राज्यों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निश्चित प्रभाव के संकेत मिले हैं। छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में मध्याह्न भोजन के प्रभाव के साक्ष्य उतने निर्णायक नहीं थे जितने दाखिले की संख्या बढ़ाने संबंधी साक्ष्य थे।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्राइमरी स्तर पर गतिरोध और बीच में विद्यालय छोड़ देने की दरों का अध्ययन

प्राइमरी स्तर पर लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गतिरोध तथा बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास एक अध्ययन में किया गया। लेकिन इसमें उनके कारणों की पड़ताल नहीं की गई। पुनः संरचित कोहार्ट पद्धति को इस दर का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। निम्नलिखित राज्यों को इस अध्ययन में शामिल किया गया था :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. जम्मू और कश्मीर
5. मध्य प्रदेश
6. उड़ीसा
7. राजस्थान
8. उत्तर प्रदेश
9. पश्चिम बंगाल
10. हिमाचल प्रदेश।

राज्य सरकार के आग्रह पर हिमाचल प्रदेश को, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य नहीं है, इस अध्ययन में शामिल किया गया था। इस अध्ययन में जिस निदर्श डिजाइन का इस्तेमाल किया गया वह विविध चरणों पर स्तरीकृत योजना थी। आंकड़ों के गलत वर्गीकरण से उत्पन्न दोष को रोकने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि जिला स्तर के अधिकारियों की मदद से अनुसंधान दल द्वारा दस प्रतिशत स्कूलों की वहीं पर निदर्श परीक्षा की जाए, इसमें एक प्रतिशत स्कूलों की परीक्षा अनुसंधान इकाई के सदस्य अकेले करें और इसमें परियोजना राज्य प्रभारी को भी शामिल किया जाए। बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में आंकड़े इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया गया। जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह कार्य काफी प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के चयन में विलंब के कारण असम में आंकड़े एकत्र करने का काम हाथ में नहीं लिया जा सका।

लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन

यह अध्ययन आठ राज्यों में हाथ में लिया गया जहाँ प्राइमरी स्कूलों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन बहुत ज्यादा कम है। इसका उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि वे कौन से घटक हैं जिनके कारण स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बहुत पीछे है, इसका उद्देश्य यह भी है कि इस बात का पता लगाया जाए कि किन उपायों द्वारा लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों को इस अध्ययन के लिए चुना गया :

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. जम्मू तथा काश्मीर
5. मध्य प्रदेश
6. उड़ीसा
7. राजस्थान
8. उत्तर प्रदेश।

इस अध्ययन की परिधि में कुल 27 जिलों को लिया गया है जो इन राज्यों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राइमरी स्तर की लड़कियों के नामांकन के प्रतिशत के आधार पर एक-एक क्षेत्र के एक-एक जिले का चुनाव किया गया है। इस प्रकार की विशेषताओं जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति की अधिकता को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। इस अध्ययन से लड़कियों की शिक्षा के विषय में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का निदर्श सर्वेक्षण

इस अध्ययन के दो अंग हैं—प्रधान रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति वाली आबादी के इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करना और इसकी वजह का पता लगाना कि इन समुदायों के बच्चे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लेते अथवा यदि दाखिला लेते भी हैं तो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त किए बिना ही स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। आंकड़े एकत्र करने के लिए चार प्रकार के फार्मों का उपयोग किया गया—आवासीय सूचना फार्म, स्कूल सूचना फार्म, अध्यापकीय सम्मति फार्म तथा साक्षात्कार सारणी। यह अध्ययन राजस्थान राज्य के भरतपुर तथा डूंगरपुर जिलों तक ही सीमित है। आंकड़ों को एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जा चुका है।

आंकड़ा संसाधन

आंकड़ा संसाधन विषय में निम्नांकित गतिविधियां शामिल हैं—कार्डों तथा टेपों के ऊपर आंकड़ों का अंतरण, पद्धतियों का डिजाइन करण, संगणक कार्यक्रम का विकास और संगणक के माध्यम से आंकड़ों का संसाधन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की विभिन्न एककों/विभागों द्वारा हाथ में ली गई कई अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के सामान्य से लेकर जटिल स्वरूप वाले सांख्यिकीय विश्लेषण किए गए। वॉ IX तथा X के लिए गत वर्षों की तरह ही 1983 की राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज परीक्षा का परिणाम इस पर तैयार किया गया।

अनुसंधान करने वालों को अपनी परियोजना को डिजाइन करने में, विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकों के इस्तेमाल में, विश्लेषण योजना के विकास तथा परिणामों की व्याख्या करने में इस एकक ने परामर्श भी दिया है और मदद भी।

संगोष्ठीयां

‘शैक्षिक सांख्यिकी संग्रह के लिए निदर्श सर्वेक्षण पद्धति का परीक्षात्मक उपयोग’ विषय पर संगोष्ठी

शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को के सहयोग से निदर्श सर्वेक्षण पद्धति के उपयोग पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शैक्षिक आंकड़ों के संकलन की तत्काल और विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने की क्षमता को परखना इसका उद्देश्य था।

आंकड़ों के एकत्रीकरण और संकलन में आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में आंकड़ों की रिक्तपूर्ति तथा आंकड़ों की परिशुद्धता को जांचने में निदर्श सर्वेक्षण की भूमिका पर भी विचार किया गया। चार राज्यों के परियोजना प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक सांख्यिकीय एकत्र करने के लिए बड़े पैमाने पर निदर्श सर्वेक्षण के आयोजन में उठने वाले सैद्धांतिक और व्यावहारिक मुद्दों पर इस संगोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया। बीस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सत्ताईस प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इनके साथ ही शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, योजना आयोग का शिक्षा अनुभाग तथा यूनेस्को और स्कैप के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे।

प्रशिक्षण

शिक्षा में निदर्श सर्वेक्षण पद्धति के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य शिक्षा संस्थानों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के योजना अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 10/12 दिनों का हर साल शिक्षा में निदर्श सर्वेक्षण पद्धति के व्यवहार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। इस प्रकार का चौथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज, मैसूर में 12-22 दिसंबर 1983 के दौरान आयोजित किया गया। कुल मिलाकर चौदह राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से 18 प्रतिनिधियों ने इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।

प्रकाशन

निम्नांकित सामग्री का प्रकाशन किया गया—

1. शिक्षा में निदर्श सर्वेक्षण की भूमिका ।
2. प्राइमरी स्तर पर दाखिले तथा छात्रों को बीच में न छोड़ने की प्रक्रिया पर मध्याह्न भोजन का प्रभाव ।

दो रिपोर्टें, जिनमें से एक में परिणामों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है तथा इसका एक संक्षिप्त रूप 'मिमियोग्राफ' के रूप में प्रकाशित किए गए ।

पुस्तकालय और प्रलेखन

पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक काम करने वाले अनुसंधाताओं की सभी प्रकार की संभावित सहायता करता रहा । रिपोर्टधीन वर्ष का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया जा रहा है—

पुस्तकों आदि की कुल संख्या 1,24,208

1983-84 के दौरान पुस्तकों की बढ़ोतरी

◦ पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक के लिए खरीदी गई पुस्तकों की संख्या	2,521
◦ अनुदान में प्राप्त पुस्तकें	244
◦ परियोजना में खरीदी गई पुस्तकें	186
पत्रिकाएं जिन्हें जिल्द बांधकर पुस्तकालय में रखा गया	364
कुल नई पुस्तकों की संख्या	3,315

पत्रिकाएं

(i) पत्रिकाएं जिनका चंदा भेजा गया	330
(ii) पत्रिकाएं जो प्राप्त हुईं (विनिमय में)	20
(iii) अनुदान में प्राप्त पत्रिकाएं	161
(iv) कुल आने वाले समाचार-पत्र	16
कुल योग	527

प्रलेखन सेवाएं

निम्नांकित प्रलेखन सेवाएं प्रदान की गईं—

(i) प्राप्ति सूची	10 अंकों की
(ii) वर्तमान विषय वस्तु	12 अंकों की

- (iii) तैयार की गई प्रेस कतरनें
(iv) लेखों की सूची

1135
1 अंक

रिप्रोग्राफी

पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक ने अपनी फोटो कापीइंग बड़े पैमाने पर जारी रखी तथा 7000 प्रतियां बनाकर विद्वानों तथा विभिन्न संकाय सदस्यों को दी गई।

पुस्तक प्रदर्शनियां

शिक्षक-शिक्षण विभाग के सहयोग से विशेष शिक्षा से संबंधित पुस्तकों की एक प्रदर्शनी इस एकक ने आयोजित की। 500 से ज्यादा पुस्तकें, जो इस विषय पर अधुनातन जानकारी देती थीं, प्रदर्शित की गईं।

प्रचार और संदर्भ

- | | |
|--|-------|
| (i) नए नामांकित सदस्यों की संख्या (एन० सी० ई० आर० टी०) | 137 |
| (ii) बाहर के नामांकित सदस्य | 102 |
| (iii) अस्थायी तौर पर नामांकित सदस्य | 80 |
| (iv) सदस्यों की कुल संख्या | 2099 |
| (v) परामर्श सुविधा पाने वाले लोगों की संख्या | 14624 |

पुस्तकालय खुलने के समय का विस्तार

पुस्तकालय की सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों की लगातार मांग करने पर पुस्तकालय खुलने की अवधि बढ़ा दी गई तथा 1.7.83 से खुलने का समय 9 बजे प्रातः से 8 बजे सायंकाल तक कर दिया गया।

रखरखाव सेवाएं

- स्वीकृत नियमों का पालन करते हुए फटी पुरानी खस्ताहाल पुस्तकों को पुस्तकालय से अलग कर दिया गया। ये पुस्तकें इस्तेमाल योग्य नहीं थीं
- | | |
|---|------|
| जिल्द बांधी गई पुस्तकों की संख्या | 550 |
| जिल्द बांधी गई पत्रिकाओं की संख्या | 2500 |
| स्टाक की जांच चरणवार, शेल्फ सूची के आधार पर जारी रखी गयी। | 343 |

महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

एक प्रकाशन संगृहीत किया गया। इस प्रकाशन का शीर्षक था 'सेलेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑन टीचर्स'। 'शिक्षक का राष्ट्रीय आयोग' के कहने पर यह कार्य हाथ में लिया गया था। यह

अपने विषय का बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसमें 374 एन्स्ट्रैक्टस हैं, इस संकलन की पृष्ठ संख्या 336 है।

कर्मचारी विकास

(i) श्री के० एल० लूथरा (अध्यक्ष) ने अखिल भारतीय पुस्तकालय अधिवेशन में हिस्सा लिया। यह अधिवेशन मैसूर में दिसंबर 1983 में हुआ था।

(ii) श्री के० एल० लूथरा को भारतीय पुस्तकालय संघ (स्कूल तथा बच्चों के पुस्तकालय) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री के० एल० लूथरा को भारतीय पुस्तकालय संघ की परिषद् का सदस्य बनाया गया है।

(iv) श्री ए० के० मुखर्जी ने यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक संगोष्ठी में संसाधन व्यक्ति के रूप में काम किया। इसका आयोजन ग्वालियर के लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ने नवंबर 1983 में किया था। इसमें विषय रखा था—“शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन तथा प्रलेखन केंद्र”।

अनुसंधान और नवाचार

अनुसंधान और अनुसंधान को सहारा प्रदान करना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। परिषद् के क्षेत्रीय कालेज, उसके विभाग और उसके एकक तो शोध कार्य हाथ में लेते ही हैं, बाहरी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शैक्षिक अनुसंधान में मदद करती है। यह जूनियर फेलोशिप (कनिष्ठ अध्ययन वृत्तियाँ) भी देती है जिससे शैक्षिक समस्याओं की खोज की जा सके और समूचे देश में सुयोग्य शोधार्थियों के समुदाय तैयार हो सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, जिन अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेती है अथवा जिनके लिए सहायता देती है, वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति अनुसंधान कार्य में मदद करने वाली प्रधान निकाय है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इस समिति में सभी विश्वविद्यालयों,

शोध संस्थानों के शिक्षा तथा उससे संबद्ध विषयों के विख्यात विशेषज्ञ और शोधकर्ता तथा राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों के प्रतिनिधियों को मिलाकर यह समिति बनी है। इसके साथ इसमें विभागों तथा एककों के अध्यक्ष भी होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों और नवाचार और अनुसंधान समिति के प्रोफेसर इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति के मुख्य कार्यों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है—

- शिक्षा तथा उससे संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान तथा नवाचारी परियोजनाओं की मदद करना।
- शिक्षा में अनुसंधान कार्य के लिए फेलोशिप देना।
- पी-एच० डी० के शोध प्रबंधों तथा अनुसंधान मोनोग्राफ आदि के प्रकाशन के लिए वित्तीय अनुदान देना।
- अनुसंधान में पाए गए निष्कर्षों को समय-समय पर प्रचारित करना और शैक्षिक अनुसंधान पर बैठकों का आयोजन करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को अपने विभिन्न विभागों/एककों से जो अनुसंधान प्रस्ताव मिलते हैं, उनका मूल्यांकन एक जांच समिति करती है अथवा बाहरी और परिषद् के सदस्यों की एक समिति करती है जिसके अध्यक्ष परिषद् के संयुक्त निदेशक होते हैं। प्रस्तावों के मूल्यांकन का मुख्य निष्कर्ष उस प्रस्ताव की सार्थकता तथा प्रस्तुत की गई रूपरेखा की परिपूर्णता आदि को माना जाता है।

दूसरी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले शोध प्रस्तावों तथा प्रकाशन अनुदान की अर्जियों का मूल्यांकन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विद्वान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और शैक्षिक नवाचार समिति दोनों ही शैक्षिक समस्याओं पर पी०-एच० डी० उपाधि के लिए किए जाने वाले अनुसंधान के लिए जूनियर फेलोशिप देते हैं।

सम्मेलन/संगोष्ठियां/व्याख्यान

आठ वक्ताओं को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान व्याख्यान मालाओं के अंतर्गत आमंत्रित किया गया। उनके व्याख्यानों के विषयों की परिधि बहुत विस्तृत थी। विभिन्न प्रख्यात विद्वानों के नाम तथा उन्होंने जिन-जिन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए उनकी सूची नीचे दी जा रही है:

व्याख्याता	विषय	तिथि
1	2	3
प्रो० हैरी मैकमोहन न्यू अल्बर्ट विश्वविद्यालय उत्तरी आयरलैंड (यू० के०)	शिक्षा में माइक्रो संगणक	6.4.1983

1	2	3
प्रो० जे० पी० दास सेंटर फार दि स्टडी आफ मॅटल रिटर्नमेंशन, यूनिवर्सिटी आफ अलबर्टा, एडमॉन्टन, कनाडा	सांस्कृतिक दृष्टि से कमजोर या अधिगम की दृष्टि से अयोग्य बच्चे	29.4.1983
प्रो० माइकेल आस्टन नेशनल कोऑर्डिनेटर फार कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, शिक्षा तथा विज्ञान विभाग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा कार्यक्रम, हर्टफोर्ड शायर (यू० के०)	शिक्षा में माइक्रो संगणक की वर्तमान हैसियत	25.7.1983
प्रो० स्कवेयर्स एडवाइजर फार कंप्यूटर्स इन एजु- केशन फार दि काउंटी आफ डेवन (यू० के०)	संगणक सहायित अधिगम संभावनाओं की समीक्षा	26.7.1983
प्रो० रीथा क्लार्क किंग मेट्रोपोलिटैन स्टेट यूनिवर्सिटी मिनी पोलिस (यू० एस० ए०)	इण्डिविजुअल कारपोरेट आइडेंटिटी : ह्याट ऑर आप्शनंस एंड इनिशिएटिव्स	26.9.1983
प्रो० ह्यू हेव्स शिक्षा विभाग, लन्दन विश्व- विद्यालय	विकासशील देशों में शिक्षा- पाठ्यक्रम का विकास	27.9.1983
प्रो० बेट्टी ऐन लेवी, मनोविज्ञान के प्रोफेसर मकमास्टर विश्वविद्यालय, कनाडा	बच्चों में पथन प्रवाह : शोध निष्कर्ष	17.11.1983
प्रो० पॉली हिल्ल पॉली हिल्ल एशोसिएट्स भट्टावा, कनाडा	बच्चों के लिए रचनात्मक केंद्र	28.12.1983

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं

नीचे दी गई तालिका में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण दिया गया है। इसके तत्काल बाद इन परियोजनाओं में प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों का सार संक्षेप में दिया गया है।

परियोजना का विषय	प्रमुख अन्वेषक
छात्रों की उपलब्धि पर मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी का प्रभाव	डॉ० आर० सी० हुडा इंदौर
वाराणसी क्षेत्र के सहशिक्षा विद्यालयों में अध्ययन करने वाली लड़कियों की समस्या	डॉ० (श्रीमती) कमला राय वाराणसी
प्राइमरी स्तर के छात्रों के समाजमितीय हैसियत पर शिक्षक की प्रत्याशाओं का अध्ययन	डॉ० एन० सी० डौंडियाल अल्मोड़ा
बड़ौदा जिले के कमजोर वर्गों के विशेष संदर्भ में समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक समस्याएं	डॉ० एस० डी० जोशी बड़ौदा
'एक शिक्षक वाला स्कूल तथा विकास के लिए योजना' का आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ० एम० जी० माली गार्गोट, कोल्हापुर
औपचारिकेतर पद्धतियों के द्वारा भौतिकी शिक्षा	डॉ० के० एन० सिंहल उदयपुर
स्कूल विषयों के लिए प्रभावशाली शिक्षण पद्धतियों का विकास	प्रो० के० एस० गुप्त कलकत्ता

छात्रों की उपलब्धियों पर मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजी का प्रभाव

आर० सी० हूब

इस अध्ययन के उद्देश्यों को नीचे संक्षेप में दिया गया है—

- गणित में छात्रोपलब्धियों के संदर्भ में एम० एल० एस० तथा परंपरागत शिक्षण पद्धति की प्रभावशालिता का अध्ययन।
- एम० एल० एस० तथा परंपरागत पद्धतियों से पढ़ाने पर, प्रतिभा, सामाजिक-आर्थिक हैसियत तथा गणित में प्राक्-उपलब्धि के संदर्भ में, गणित विषय में छात्रों की उपलब्धि का अध्ययन।

(iii) एम० एल० एस० की वजह से गणित के प्रति छात्रों में रुख परिवर्तन का अध्ययन ।

इस अध्ययन में नमूने के रूप में 55 छात्रों को, जो 11-13 वर्ष की आयु-वर्ग के थे, लिया गया । ये छात्र इंदौर के कक्षा VI के राजकीय बाल मिडिल स्कूल के दो वर्गों (सेक्शंस) के थे । इनकी सामाजिक-आर्थिक हैसियत सामान्य से भी निचले स्तर की थी ।

इस अध्ययन से जो बातें ज्ञात हुई वे इस प्रकार हैं—(1) जिन छात्रों को एम० एल० एस० पद्धति से गणित पढ़ाई गई उनकी उपलब्धि उन छात्रों से अधिक थी जिनको परंपरागत तरीके से यह विषय सिखाया गया । (2) यहां तक कि प्रतिभा, समाजार्थिक हैसियत तथा प्राक्-उपलब्धि की दृष्टि प्रारंभिक सांख्यिकीय अंतर के लिए इनको समायोजित किया गया तो एम० एल० एस० समूह का निष्पादन काफी बेहतर था । (3) पाठन के समय गणित के प्रति आत्म-अवधारणा और रुख में किसी महत्वपूर्ण सुधार तथा परिवर्तन के लक्षण नहीं दिखे । इसके विपरीत जिन छात्रों को एम० एल० एस० पद्धति से गणित विषय पढ़ाया गया उनकी उपलब्धियां काफी ऊंची और महत्वपूर्ण थीं । (4) गणित अध्यापन की एम० एल० एस० प्रणाली शब्देतर रचनात्मक को बढ़ाने में अधिक प्रभावशाली साबित हुई । जैसे, प्रवाह, नमनीयता, मौलिकता, विस्तारण तथा शब्देतर रचनाशीलता के कुल अंक । (5) एम० एल० एस० प्रणाली से गणित पढ़ाने पर छात्रों की शाब्दिक रचनाशीलता, जैसे प्रवाह, नमनीयता मौलिकता तथा संयुक्त रचनात्मकता में पर्याप्त सुधार हुआ ।

वाराणसी क्षेत्र के सहशिक्षा विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की समस्याओं का अध्ययन

डॉ० (श्रीमती) कमला राय

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) सह-शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाली तरुण वय वाली लड़कियों की समस्याओं का पता लगाना । वे समस्याएँ हैं—स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, वित्तीय स्थिति, रोजगार और रहन-सहन की दशाएं, सामाजिक और मनोरंजनात्मक गतिविधियां, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंध, प्रेमार्चना (शादी के लिए), सेक्स और शादी, घर तथा परिवार, नैतिकताएं और धर्म, काम तथा विद्यालय के बीच सामंजस्य, रोजगार तथा शिक्षा संबंधी भविष्य तथा पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया, (ii) इस क्षेत्र की कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तरुण वय की लड़कियों की समस्याओं का अध्ययन करना, (iii) सहशिक्षा विद्यालयों तथा कन्या विद्यालयों की तरुण वय वाली लड़कियों की समस्याओं की तुलना करना, (iv) कन्या विद्यालयों तथा सहशिक्षा विद्यालयों की तरुण वय की लड़कियों के सामंजस्य की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, (v) सहशिक्षा विद्यालय तथा कन्या विद्यालय की तरुण वय की लड़कियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा सामंजस्य की समस्याओं के बीच संबंधों का अध्ययन करना, (vi) अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक हैसियत की तरुण वय की लड़कियों की दोनों प्रकार के स्कूलों में सामंजस्य की समस्याओं का अध्ययन करना, (vii) समस्याओं में नगर तथा गांवों का भेद तथा सहशिक्षा विद्यालयों में सामंजस्य की समस्याओं का पता लगाना ।

नमूने के तौर पर सहशिक्षा विद्यालय की 1016 तथा कन्या विद्यालय की 912 लड़कियों को लिया गया। ये लड़कियाँ कक्षा IX, X, XI, XII की थीं तथा वाराणसी क्षेत्र के गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, जौनपुर तथा मिर्जापुर जिलों से अध्ययन के लिए इन्हें चुना गया था।

इस अध्ययन के कुछ नतीजे इस प्रकार हैं: (i) सहशिक्षा विद्यालय की लड़कियाँ जिस तरह की समस्याओं का सामना करती हैं वे तीन क्षेत्रों में प्रमुख हैं, सामाजिक और मनो-रंजनात्मक गतिविधियाँ, विवाहार्थ प्रेमार्चना, सेक्स शादी तथा वित्त, रहन-सहन की स्थितियाँ और रोजगार। (ii) जो लड़कियाँ बालिका विद्यालयों में पढ़ रही थीं उनको सबसे अधिक इन समस्याओं से मुकाबला करना पड़ता था जैसे सामाजिक तथा मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ, विवाहार्थ प्रेमार्चना, सेक्स तथा शादी, घर तथा परिवार। इसके विपरीत सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संबंधों की, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रक्रिया संबंधी तथा धर्म और नैतिकता की समस्या उनके सामने नहीं के बराबर थी। (iii) सहशिक्षा स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियाँ, कन्या विद्यालयों की लड़कियों की तुलना में काफी अच्छे घरों की थीं। स्वास्थ्य, भावनात्मक तथा दूसरे तरह की सामंजस्यात्मक स्थितियाँ उनकी काफी बेहतर थीं। (iv) सामंजस्य तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच के संबंध सकारात्मक थे। (v) बालिका विद्यालयों की जो लड़कियाँ सामाजिक आर्थिक हैसियत के लिहाज से अच्छे परिवारों की थीं उनका भावात्मक तथा घरेलू सामंजस्य उन्हीं स्कूलों की मध्यम वित्त श्रेणी की लड़कियों की तुलना में खराब था। (vi) कन्या विद्यालयों की उच्च सामाजिक-आर्थिक हैसियत की लड़कियों का घरेलू सामंजस्य उसी विद्यालय की निम्न हैसियत की लड़कियों से खराब था। (vii) सह शिक्षा विद्यालयों की उच्च सामाजिक आर्थिक हैसियत की लड़कियों का समग्र सामंजस्य बेहतर था। घर, स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर उनका सामंजस्य उन्हीं की तरह की कन्या विद्यालयों की लड़कियों से बेहतर था। (viii) मध्यवित्त स्थितियों वाली सहशिक्षा की लड़कियों का उन्हीं की हैसियत की बालिका विद्यालय की लड़कियों की तुलना में घरेलू तथा भावात्मक तालमेल बेहतर था। (ix) इसी प्रकार सहशिक्षा विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों का, उसी हैसियत की कन्या विद्यालयों की लड़कियों की तुलना में घरेलू, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा भावात्मक क्षेत्रों में तथा विद्यालय में भी बेहतर तालमेल था।

प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी के समाजमितीय हैसियत

पर अध्यापक की प्रत्याशाओं के प्रभाव का अध्ययन

एन० सी० डोंडियाल

इस अध्ययन का लक्ष्य था—छात्रों के समाजमितीय हैसियत पर अध्यापक की प्रत्याशाओं के प्रभाव का अध्ययन। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) लोकप्रिय तथा उपेक्षितों की पहचान, (ii) लोकप्रिय तथा उपेक्षितों के प्रयोगात्मक संकेत, (iii) अध्यापक द्वारा प्रयोग के आधार पर उपलब्ध घनात्मक तथा ऋणात्मक प्रत्याशाओं के प्रभाव का अध्ययन, (iv) लोकप्रिय तथा उपेक्षितों के समाजमितीय हैसियत पर प्रयोगों द्वारा प्राप्त घनात्मक तथा ऋणात्मक प्रत्याशाओं के प्रभाव का आकलन, (v) छात्रों की कुछ विशेषताओं के संदर्भ

में टीचर द्वारा लोकप्रिय तथा उपेक्षित के वर्गीकरण पर प्रयोग के आधार पर प्राप्त ऋणात्मक और धनात्मक प्रत्याशाओं के प्रभाव का आकलन करना।

नैनीताल तथा अल्मोड़ा के 15 प्राइमरी स्कूलों के कक्षा IV तथा V के बच्चों का अध्ययन किया गया।

इस अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनमें से कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं—(i) लोकप्रिय छात्रों के समाजमितीय हैसियत के प्राप्तांक पर प्रयोग के आधार पर प्रेरित धनात्मक प्रत्याशाओं का कोई उल्लेखनीय असर नहीं था, भावात्मक विस्तार तथा अध्यापक के रेटिंग पर भी कोई असर नहीं था। जहां तक उपेक्षितों का मामला है, उनमें महत्वपूर्ण सुधार अध्यापक के रेटिंग के अंकों तक सीमित था। (ii) भावात्मक के विस्तार के प्राप्तांक पर अभिप्रेरित ऋणात्मक प्रत्याशाओं का कोई उल्लेखनीय असर नहीं था। साथ ही अध्यापक के रेटिंग प्राप्तांकों पर चाहे वे लोकप्रिय छात्र हों या उपेक्षित, दोनों पर ही कोई खास प्रभाव नहीं था। अध्यापक की नकारात्मक प्रत्याशा का असर न तो लोकप्रिय और न उपेक्षित विद्यार्थी के भावात्मक प्रसार पर दिखाई पड़ा। प्रत्याशाओं की नकारात्मक भूमिका का परिणाम लोकप्रिय छात्रों की सामाजिक ग्रहणशीलता के विकास के रूप में दिखाई पड़ा। (iii) अध्यापक की प्रत्याशा की नकारात्मक भूमिका ने काफी ज्यादा हद तक उनकी सामाजिक ग्रहणशीलता का काम कर दिया जबकि अध्यापक की प्रत्याशा की नकारात्मक भूमिका का असर लोकप्रिय छात्रों की समाजमितीय स्थिति पर एकदम नहीं था। (iv) यह पाया गया कि अध्यापक की धनात्मक प्रत्याशा कुछ बातों के सुधार को काफी सुकर बना देती है जैसे समाजमितीय हैसियत, भावात्मक विस्तार का स्तर और अध्यापक की रेटिंग का प्राप्तांक। इसके विपरीत नकारात्मक प्रत्याशाओं ने कक्षा IV के लोकप्रिय छात्रों की समाजमितीय हैसियत में बदलाव पैदा किया तथा कक्षा V के लोकप्रिय छात्रों की सामाजिक ग्रहणशीलता को विकसित किया। नकारात्मक भूमिका के मामले में अध्यापक रेटिंग प्राप्तांक के संदर्भ में ग्रेड के आगे कोई विचलन प्राप्त नहीं हो सका। (v) जहां अधिक उम्र के लोकप्रिय छात्रों में अध्यापक की प्रत्याशा की धनात्मक भूमिका ने उनके समाजमितीय हैसियत और सामाजिक ग्रहणशीलता के स्तर को सुधारने में मदद की, नकारात्मक भूमिका के कारण निम्न आयु वर्ग के बच्चों में सुधार आया। (vi) अध्यापक की धनात्मक और ऋणात्मक प्रत्याशाओं के प्रभाव द्वारा उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित करने में उपेक्षितों के लिए लिंग कोई महत्व का घटक नहीं था। (vii) अध्यापक की प्रत्याशा की धनात्मक और ऋणात्मक भूमिका के प्रभाव को, विशेष रूप से धनात्मक प्रभाव को समाजमितीय हैसियत तथा सामाजिक ग्रहणशीलता स्तर पर निर्धारित करने से एक उपेक्षित छात्र की आयु उसकी कक्षा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। (viii) अध्यापकों द्वारा नकारात्मक भूमिका की स्वीकृत स्तर ने, अध्यापक द्वारा लोकप्रिय छात्रों के रेटिंग प्राप्तांकों व उसकी प्रत्याशा की नकारात्मक प्रभावितता पर असर डाला। दोनों लोकप्रिय प्रयोगात्मक समूहों का अतिक्रमण कर यह विकासांतर पैदा करने में प्रभावहीन साबित हुआ।

बड़ौदा जिले के कमजोर तबकों की सापेक्षता में समाज के कमजोर तबकों की शैक्षिक समस्याओं का अनुशीलन

एस० जी० जोशी

राज्य द्वारा सभी नागरिकों को समान अवसर देने की काशिशों के बावजूद शिक्षा की जो सुविधाएँ दी गई हैं, समाज का एक हिस्सा उसका लाभ नहीं उठा सका है। इस अध्ययन में इन बातों की कोशिश की गई है कि (i) उन घटकों का पता लगाना जिनसे कमजोर तबके समाज में शिक्षा से लाभ नहीं ले पाते। (ii) यह पता लगाना कि किस सीमा तक प्रत्येक घटक उनके शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में बाधक है। (iii) समाज के इस तबके के लिए शैक्षिक नवाचार योजना का सुझाव पेश करना।

इसकी प्रमुख उपपत्तियाँ इस प्रकार थीं—(i) अभिभावकों की शिक्षा का स्तर नीचा था और किसी-किसी मामले में तो यह शून्य था। मुख्य रूप से अभिभावक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले थे तथा उनकी आय का कोई पुष्टा स्रोत नहीं था और सीमित साधनों की वजह से घर का परिवेश अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं था। (ii) गांव के शिक्षित सदस्य बाहर नौकरी करने के लिए लगातार गांव छोड़कर चले जाते रहे। यद्यपि पड़ोसियों से संबंध मधुर रहे, फिर भी गरीब तबकों के बच्चों को न तो उनका साथ मिला और न उनकी सहायता या प्रोत्साहन जिससे वे अध्ययन कर सकें। (iii) एस० एस० सी० स्तर तक तो पढ़ने की छात्रों में ललक थी, उसके बाद वे अपने पिता का व्यवसाय अपनाते थे जैसे खेतों में मजदूरी करना। (iv) विद्यार्थियों में संकोच और अस्वीकार का भाव बहुत कम तथा आत्मावधारणा काफी ऊँची थी। (v) अध्यापक तथा विद्यालय के प्रति छात्रों ने पसंदगी जाहिर की। इसके साथ ही अन्य कई दृष्टियों से उनको विद्यालय अच्छा लगा जैसे स्कूल का समय तथा घंटों की अवधि, उनके भावी जीवन में स्कूल का स्थान, नियम आदि। खेतों में काम करने की अपेक्षा स्कूल जाना अच्छा लगता था। अपने प्रति अध्यापक का रुख भी उन्हें पसंद था। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, कक्षा में सहपाठियों का उनसे संबंध तथा गृहकार्य में और अध्ययन में उनकी दिलचस्पी, सब उन्हें अच्छे लगे। (vi) आमतौर पर अभिभावकों में शिक्षा और विद्यालय के प्रति रुख अनुकूल था। उनमें यह भावना थी कि शिक्षा से आदमी बेहतर नागरिक बनता है। वे नहीं चाहते थे कि बच्चे आगे चलकर पैतृक व्यवसाय अपनाएँ। यद्यपि अभिभावक कोई शैक्षिक मदद करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वे सहयोग तथा प्रोत्साहन देने के लिए अपने बच्चों की शिक्षा के मामले में काफी उत्सुक दिखाई पड़े। (vii) अध्यापकों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कमजोर तबकों के बच्चों के लिए पृथक शैक्षिक कार्यक्रम दोनों समूहों के लिए सहायक होगा। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि कमजोर तबके के बच्चों में पढ़ने की अभिरूचि थी। (viii) अध्यापकों के अनुसार कमजोर तबकों के बच्चों की शिक्षा में समस्याएँ थीं—सामान्य से भी कम प्रतिभा, कम समझदारी, सीमित अनुभव तथा गरीबी के कारण शिक्षा का निम्न स्तर। (ix) गुजराती, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अधिगम की दिक्कतों का विश्लेषण करने पर गैर-कमजोर तबकों के बच्चों को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था किंतु जहाँ तक सामाजिक विषय में कृषि का ज्ञान

अर्जित करने का यह प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान तथा विज्ञान में सामाजिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान का मामला है, कमजोर वर्ग के छात्रों को कम या बराबर के स्तर की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

एक अध्यापक वाले स्कूलों का आलोचनात्मक अध्ययन और उनके विकास की योजना

एम० जी० माली

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) एक अध्यापक वाले स्कूलों की भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना, (ii) किस हद तक बर्बादी होती है तथा कितने छात्रों का वर्ष खराब होता है, इसका अध्ययन करना, (iii) संगठनात्मक ढाँचों तथा शिक्षण पद्धति का अध्ययन करना, (iv) जिला परिषदों की नीतियों तथा प्रशासन की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना, (v) सामान्य दिक्कतों का अध्ययन, जिनका प्रायः सामना करना पड़ता है, (vi) बिना ग्रेड वाली इकाइयों को जाँचना जिससे धन तथा समय दोनों की क्षति को रोका जा सके, (vii) एक अध्यापक वाले विद्यालय के सुधार के लिए उचित योजना सुझाना।

इस सर्वेक्षण में निम्नांकित तथ्य सामने आए—(i) तालुका में कुल 98 स्कूल थे। इनमें से सिर्फ 6 स्कूलों के पास अपने इस्तेमाल के लिए अलग भवन थे। इनमें से 54 के पास भवन तो पर्याप्त थे लेकिन उनमें सिर्फ 35 भवन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक थे। (ii) इनमें सिर्फ दो स्कूलों के पास अपने खेल के मैदान थे। (iii) इन 98 स्कूलों में कुल 160 श्यामपट्ट थे। इनमें कुल 80 काम लायक स्थिति में थे, कुल 6 स्कूलों में मुड़ने वाले श्यामपट्ट थे। (iv) इनमें जो 98 अध्यापक कार्यरत थे उनमें से मात्र 9 अध्यापकों के पास पाठ्यक्रम की एक-एक प्रति थी, जिसका वे इस्तेमाल करते थे, शेष अध्यापकों को इसकी आवश्यकता की जानकारी भी नहीं थी। केवल 16 स्कूलों में पर्याप्त संख्या में पाठ्यपुस्तकें थीं। (v) इस तरह के विद्यालयों में स्कूलों में अध्यापकों की कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि इस स्थिति में या तो उनको अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता था अथवा उनको रोज स्कूल तक आने के लिए यात्रा पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश प्रशिक्षित थे लेकिन इस तरह के स्कूलों को चलाने का उन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं था। उन्हें उचित पद्धतियों की जानकारी नहीं थी। वे न तो छात्रों को व्यस्त रखने योग्य उनको कोई काम दे सकते थे न जब वे एक कक्षा में होते तो दूसरी कक्षा को व्यस्त रखने के लिए कोई उपाय करते थे। अध्यापकों को यह भी पता नहीं था कि चारों कक्षाओं के लिए एक ही समय सारणी कैसे बनाई जाती है। (vi) एक अध्यापक वाले स्कूल का निरीक्षण नहीं के बराबर था या नाममात्र को था क्योंकि निरीक्षण कर्मचारी सुदूर गांवों में स्थित स्कूलों में जाने से बचना चाहते थे क्योंकि गांवों में सुविधाओं का अभाव था। (vii) यद्यपि हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी पास करने के बाद अधिकांश अध्यापक पूर्व-सेवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे लेकिन इनमें से किसी को भी एक अध्यापक वाले स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। (viii) कक्षा I में 819 लड़कों और 368 लड़कियों ने दाखिला लिया, इनमें से सिर्फ 227 लड़कों और 45 लड़कियों ने कक्षा

IV तक की शिक्षा पूरी की। कक्षा I से 71.3 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, बाकी छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया। कक्षा II, III और IV में भी स्थिति ऐसी ही थी। (ix) लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने के वार्षिक तथा सामाजिक कारणों के अतिरिक्त छात्रों के विद्यालय छोड़ने का कारण उनका उत्तीर्ण न होना और खराब आर्थिक स्थिति थी। बताया गया कि प्राथमिक विस्तार केंद्र, जो जी० के० संस्थान, गार्गोटी से संबद्ध था, बिना स्तरों वाला आदर्श प्राइमरी स्कूल था जहां पर उचित कार्यभार तैयार करने की दक्षता में विकास के बाद तथा अभिविन्यास के बाद अनेक प्रकार की पद्धतियों को लेकर प्रयोग किए गए। मसलन—व्यक्तिगत शिक्षण-अधिगम समूह पद्धति, स्तरवार शिक्षण पद्धति तथा स्वाध्याय पद्धति। भौतिक सुविधाओं की योजना के बाद यह बात भी सुझाई गई कि छात्र के निष्पादन को परखने के लिए परीक्षण का भी उपयोग किया जा सकता है।

औपचारिकतर पद्धतियों से शारीरिक शिक्षा के० एन० सिंघल

इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार थे—(i) उच्चतर माध्यमिक स्तर और कॉलेज के प्रथम वर्ष स्तर पर विज्ञान के छात्रों और अध्यापकों की अकादमिक समस्याओं का अभिज्ञान, (ii) प्राप्त उत्तरों के सुझाव के अनुसार क्रियाभिमुख कार्यक्रम।

राजस्थान और बाहर के कुछ राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को एक प्रश्नावली भेज कर सामान्य रूप से विज्ञान तथा विशेष रूप से भौतिकी के छात्रों की जो उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा प्रथम वर्ष कॉलेज स्तर के हैं अकादमिक समस्याओं का पता लगाया गया। कार्यक्रम के आरंभ होने के पूर्व भाग लेने वालों में साइक्लोस्टाइल्ड सामग्री वितरित की गई। पहले कार्यक्रम में सम्मिलित बातें इस प्रकार थीं—नामांकन, छात्रों के पाठ्यक्रम का स्तर, भौतिकी पाठ्यक्रम का अभिविन्यास, शिक्षण पद्धति और तकनीकें, सुविधाओं का उपयोग तथा पुस्तकों का प्रकाशन जैसे प्रश्नों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। दूसरे कार्यक्रम की बातें इस प्रकार थीं—प्रतियोगिता शृंखलाएँ, प्रतिभा परीक्षण तथा छोटे-मोटे अनुसंधानात्मक प्रयोग। तीसरे कार्यक्रम में सामान्य दिलचस्पी के शीर्षकों पर अंतर्विषयीय व्याख्यान शामिल थे। राजस्थान तथा उसके बाहर के छात्रों, अध्यापकों, व्याख्याताओं तथा आचार्यों को स्तरीय पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर बड़ी संख्या में तैयार करके दिए गए। इसका उद्देश्य उनमें भौतिकी के लिए दिलचस्पी पैदा करना था। पांचवें कार्यक्रम में अध्यापकों को साइक्लोस्टाइल्ड सामग्री दी गई। ये वह अध्यापक थे जो अल्पकालीन पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले सके थे क्योंकि जहां ये पढ़ाते थे, वहां इनका कोई स्थानापन्न अध्यापक नहीं मिल सका था। छठे कार्यक्रम में पुस्तकालय आंदोलनों की शुरुआत की गई, इसमें खास दिलचस्पी वाले विषयों की पुस्तकें खासतौर पर हिंदी पुस्तकें प्रदर्शित की गईं। इसके बाद एक-एक साल के लिए लोगों में उन्हें वितरित कर दिया गया। सातवें कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापकों और छात्रों को कॉलेजों के निकट लाने के अलावा आधुनिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए। पाठ्यक्रम को एकतरफा बदलने की जगह 250 छात्रों और अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं से

अकादमिक निकायों को अवगत करा दिया गया जिससे वे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कर सकें।

आठवें कार्यक्रम से उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर जो सुझाव दिए गए वे इस प्रकार थे—(i) भौतिकी की बेहतर समझदारी को उत्प्रेरित करने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। (ii) कम से कम एक महीने में एक बार विशेषज्ञों द्वारा अंतर्विषयीय व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए। (iii) विचार प्रधान प्रश्न संबंधी सामग्री कनिष्ठ अध्यापकों को दी जानी चाहिए तथा वर्ष में एक बार व्याख्यान गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। (iv) चुने हुए छात्रों के लिए अल्पावधि के पाठ्यक्रम, अवकाश के दिनों में आयोजित किए जाने चाहिए। (v) औपचारिकेतर पद्धतियों के साथ औपचारिक पद्धतियां भी प्रयोग में लाई जानी चाहिए। औपचारिक पद्धति की कमजोरियों को औपचारिकेतर पद्धति को अपना कर कम किया जाना चाहिए।

स्कूल विषयों के लिए प्रभावशाली शिक्षण पद्धति का विकास

के० एस० गुप्त

इस दिशा निर्देशक अध्ययन का लक्ष्य समस्याओं का सांख्यिकी अन्वेषण करके एक अध्यापक के प्रभावी व्यवहार संबंधी आयाम के विषय में सुझाव देना था ताकि प्रभावशाली शिक्षण पद्धति की संकल्पना विकसित की जा सके और बाद में प्रयोग द्वारा उसका परीक्षण किया जा सके।

सुविधा के लिए चार औसत स्कूलों—दो लड़के और दो लड़कियों—को विचार के लिए चुना गया, इनमें से कक्षा IX के 180 विद्यार्थियों को जिनमें आधे लड़के आधी लड़कियां थीं, का चयन किया गया। सातों विषयों में से प्रत्येक के शिक्षण उद्देश्य के बारे में सहमति पर पहुंचने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई। यह सर्वेक्षण की तरह का सह-संबंधात्मक अध्ययन था जिसमें एक-एक समूह का अध्ययन किया गया था ताकि अध्यापकों के व्यवहार संबंधी संभावित आयामों को अलग-अलग किया जा सके।

अध्यापन के उद्देश्यों और पद्धति विषयक मदों को अध्यापक के व्यवहार के रूप में पुनर्नि-योजित किया गया और लिफ्ट जैसे पांच बिंदुओं वाले आठ दृष्टिकोण के पैमाने विकसित किए गए। इनमें से एक पैमाने का संबंध अध्यापक के सामान्य व्यवहार से था और अन्य सात विभिन्न विषयों के लिए थे।

खोजों से जो संकेत मिले वे इस प्रकार थे—(i) गतिशीलता, अर्थपूर्णता और सक्षम रूप से हरकत में लाने की शक्ति, सामान्य अध्यापक व्यवहार के प्रशस्त आयाम थे। (ii) बंगाली तथा मातृभाषा के लिए अध्यापक व्यवहार के आयाम थे, भाषागत संरचना, विचारों का मूर्तीकरण और प्रशंसा। (iii) गणित के लिए, गणितात्मक तर्क, अभ्यासगत सुविधाएं, तथा प्रशंसा को खोजा गया। (iv) भौतिक विज्ञानों के लिए जिन व्यावहारिक आयामों को खोजा गया वे हैं—मूर्तीकरण, प्रशंसा तथा वैज्ञानिक साहस। (v) जीव विज्ञान के अध्यापक के व्यावहारिक पक्ष थे, मूर्तीकरण तथा प्रशंसा। (vi) वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, मूर्तीकरण तथा प्रशंसा भूगोल अध्यापक की व्यवहार विषयक आयाम थे। (vii) इतिहास में तीन

समूहों का अभिज्ञान व्यवहार के आयामों के संदर्भ में हुआ, मूर्तीकरण, सामाजिक चेतना और आत्मगत अंतर्दृष्टि। (viii) जहाँ तक द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रश्न है, जो व्यवहार देखने को मिला उसकी विशेषताएँ हैं—विचारों का मूर्तन, भाषाई प्रतिभा, भाषागत संरचना तथा प्रशंसा।

विभागीय परियोजनाएँ

एक विभागीय परियोजना का काम पूरा किया गया। इस परियोजना का नाम था—“स्वीकृत माध्यमिक आवासीय स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना का गहन अध्ययन।” इसमें प्रमुख अनुसंधाता थे, डॉ० के० वी० राव और श्री जे० पी० मित्तल। निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

स्वीकृत माध्यमिक आवासीय स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना का गहन अध्ययन

के० वी० राव, जे० पी० मित्तल

यह अध्ययन निम्नांकित बातें जानने के उद्देश्य से किया गया था : (i) योग्यता वाले छात्रों के अकादमिक निष्पादन में सुधार, (ii) बच्चों के राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता के साथ व्यक्तित्व के विकास की मात्रा। इस अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार थे—(i) विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ली गई प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज्यादा विविधता थी। विविधा के पक्ष थे—प्राप्तांक, इसके परिणामस्वरूप विषयों का चुनाव तथा प्रश्न-पत्रों की समयावधि, प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा का माध्यम। (ii) जिन स्कूलों को चुना गया है उनमें से एक तिहाई में +2 स्तर की पढ़ाई नहीं होती है। अधिकांश स्कूल अंग्रेजी माध्यम के थे। इनमें मुश्किल से ही किसी में हिंदी माध्यम था, इनमें से नगण्य संख्या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम की थी और कुछ में अंग्रेजी माध्यम के साथ क्षेत्रीय भाषाओं की कक्षाएँ भी लगती थीं। इसके फलस्वरूप अधिकांश विद्यार्थियों को संप्रेषण तथा कक्षा के शिक्षण को समझने में दिक्कतें पेश आती थीं क्योंकि उनमें भाषा समझने की क्षमता नहीं थी, फलस्वरूप अपने को वे समायोजित नहीं कर पाते और कभी-कभी अध्ययन छोड़ कर बीच में ही चले जाते। (iii) यद्यपि सभी स्वीकृत खर्चों को वहन करने का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय पर था, कुछ स्कूल कुछ सुविधाओं के लिए पैसे लेते थे, यदि पैसा नहीं दिया गया तो छात्र को उस सुविधा से वंचित होना पड़ता था। इन अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने में अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। (iv) माध्यम परिवर्तन के अलावा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के विभिन्न कारणों में नई भाषा का सीखना, सह-पाठ्य क्रियाएँ तथा अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन के अभाव को छात्रों ने खराब अकादमिक निष्पादन का कारण बताया। जो व्यक्तिगत कारण बताए गए, वे थे—खराब स्वास्थ्य, नए परिवेश के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थता, वित्तीय कठिनाइयाँ, स्वेच्छा से कक्षा IX में पढ़ने के लिए (राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में), जिससे श्रेणी सुधर सके और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिले के अवसर में सुधार हो, अथवा किसी संस्था में किसी विषय की अनुपलब्धता,

अथवा किसी खास विषय में स्थान की अनुपलब्धता। (v) सुधारात्मक शिक्षा से सत्रह प्रतिशत विद्यार्थी संतुष्ट नहीं थे। दूसरी समस्याएं थीं—विद्यालय का प्रतिकूल वातावरण, कठोर अनुशासन और कभी-कभी अनुशासनहीनता, खराब पढ़ाई, खराब खाना, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं, सह-पाठ्य क्रियाओं पर अनावश्यक बल, रहन-सहन की शैली तथा अति-रिक्त शुल्क। छोड़ने वालों ने ऐसा महसूस किया था कि खेलकूद में उन्होंने कुशलता हासिल कर ली थी, आत्माभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, अच्छे सलीके तथा कुछ सामाजिक और एकता के गुण भी स्कूलों में सीख लिया था। (vi) अधिकांश अभिभावकों ने, इनमें स्कूल बीच में छोड़ देने वालों के अभिभावक भी हैं, ऐसा महसूस किया कि आवासीय स्कूल जीवन में छात्र में पढ़ने की अच्छी आदतें, अच्छे सलीके, आत्मानुशासन, रचनात्मक दृष्टि, आत्मविश्वास, सामाजिकता और स्वस्थ रहन-सहन की आदतों का विकास हुआ। (vii) बहुत से प्रधानाचार्यों ने ऐसा महसूस किया कि कुछ वर्षों में चुने हुए छात्रों की योग्यता में गिरावट आई।

उनका सुझाव था कि सभी स्वीकृत खर्चों को मंत्रालय को लौटा देना चाहिए। विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए स्वीकृत राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों को +2 स्तर के स्कूलों में रखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय वातावरण बनाने की खातिर हर स्कूल में विभिन्न राज्यों के छात्रों को दाखिला मिलना चाहिए, स्कूलों से परामर्श करने के बाद ही उनको स्कूलों में भर्ती करना चाहिए, गैर-अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों को गैर-अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही रखना चाहिए और मानकीकृत परीक्षणों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए।

नई परियोजनाएं

परियोजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए परिषद् के बाहर की उन्नीस और परिषद् के अंतर्गत की सत्रह योजनाओं को स्वीकृत किया गया। परियोजनाओं की सूची नीचे दी जा रही है—

परियोजना का नाम	प्रमुख अनुसंधानकर्ता
गत पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में औसत परिणामों को सतत दशनि वाले महत्वपूर्ण-सह-संबंधक.....।	डॉ० एस० एम० गुप्त, कुरुक्षेत्र
आंध्र प्रदेश के मानसिक रूप से पिछड़े लोगों के विशेष शिक्षण कार्यक्रम—स्कूलों और सेवाओं का मूल्यांकन सर्वेक्षण	डॉ० (श्रीमती) डॉली शिनाय, हैदराबाद

परियोजना का नाम	प्रमुख अनुसंधानकर्ता
नगरीय और ग्रामीण जनजातीय पृष्ठभूमि में अधिगम—स्मृति उपलब्धि तथा शैक्षिक अभिरुचि पर इसके प्रभाव के अध्ययन के लिए वर्ग परिवेश का विश्लेषण	डॉ० एस० एन० उपाध्याय, रायपुर
चित्तूर जिले में औपचारिकतर शिक्षा कार्य-क्रम की प्रभाविता का अध्ययन	डॉ० एन० बैकटया, तिरुपति
संथाली भाषा की सामाजिक भाषिकी का अध्ययन	डॉ० डी० पी० मुखर्जी, शांतिनिकेतन
वाणिज्य विषयों में +2 और +3 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण का अध्ययन	श्री एच० बी० गोखले, नागपुर
प्राइमरी स्कूल अध्यापकों अकादमिक उपकरणों के स्तर का अनुसंधान	डॉ० टी० आर० शर्मा, पटियाला
प्रतियोगिता मूलक उत्प्रेरणा और पहल, अभिरुचि और सहयोग की प्रवृत्ति वाली उत्प्रेरणा की सापेक्ष प्रभाविता का तुलनात्मक अध्ययन	प्रो० एस० बी० मल्हारा, जलगांव
उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में गणित में अधिगम परिणामों का अध्ययन	डॉ० जे० पी० श्रीवास्तव, मेरठ
केंद्रीय विद्यालयों में परीक्षा की सतत मूल्यांकन प्रणाली का आकलन	श्री आर० एस० राव, संभलपुर
शिक्षा अध्यापकों, अन्य छात्रों और संस्थाओं के प्रति अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का रुख	डॉ० (श्रीमती) के० के० ललितम्भा, त्रिवेंद्रम्
ग्रामीण युवक के लिए वैकल्पिक विकास के मॉडल को दर्शाने वाली ग्रामीण संपन्नता शिक्षा परियोजनाएं, आत्माधिगम की युक्तियां और उनके जीवन के लिए सार्थक विषय	श्री आर० एन० जोशी, बंबई

परियोजना का नाम	प्रमुख अनुसंधानकर्ता
कुछ चुने हुए चरों के संदर्भ में भिन्न प्रतिभा वाले किशोरों और उनकी पृष्ठभूमि का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० अरुण के० गुप्त, जम्मू
संगीत में छात्रों की उपलब्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत शिक्षण तथा संस्थागत शिक्षण के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० गौरी कुप्पुस्वामी, मैसूर
प्रवेश स्तर की विशेषताओं, अधिगम आवश्यकताओं का आकलन तथा औपचारिकतर शिक्षार्थियों की अभिरुचि का विश्लेषण	श्री अच्युतानंद नायक, फकीरपुर (उड़ीसा)
अधिगम में दिक्कत का सामना करने वाले बच्चों के लिए कक्षा के शिक्षण कार्यक्रम का विकास	डॉ० (श्रीमती) पी० मोहिते, बड़ौदा
रचनात्मक प्रशिक्षण वाले शैक्षिक सामग्री में संरचनाओं की किया-प्रतिक्रिया	डॉ० सुदेश गारवर, चण्डीगढ़
दो नैदानिक परीक्षणों की रचना और उनका मानकीकरण, एक बंगाली (मातृभाषा में) तथा दूसरा गणित में (पश्चिम बंगाल के स्कूलों में कक्षा III, IV तथा V के पिछड़े हुए बच्चों के साथ इस्तेमाल के लिए)	डॉ० एस० आचार्य, कलकत्ता
अलजबरा इकाई में हाई स्कूल छात्रों के निष्पादन पर औपचारिक शिक्षण का प्रभाव — एक मास्टरी अधिगम दृष्टिकोण	डॉ० बी० वी० अदकोली, गोवा
एम० एस-सी० की शिक्षा के छात्रों का फालो-अप	डॉ० (श्रीमती) गिरिजा मीहम्मद मिया
दिल्ली और आसपास के विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों में चलाए जाने वाले पुस्तकेतर पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु का अध्ययन	डॉ० बी० पी० गुप्त डॉ० के० आर० पी० सिंह

परियोजना का नाम	प्रमुख अनुसंधानकर्ता
गणित शिक्षण में +2 स्तर पर सामान्य अवधारणात्मक गलतियाँ तथा आसान पद्धतियों और तकनीकों का उपचार के लिए आविष्कारों का विश्लेषण	श्री एस० सी० दास
बाधित बच्चों (मूक-बधिर) के अवधारणात्मक विकास के लिए सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग का खोजपूर्ण अध्ययन	श्री एम० शर्मा
अनुसूचित जाति के हाई स्कूल छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजना का अध्ययन	डा० जे० एस० गौड़
पिछली पाँच शताब्दियों में राजस्थान में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गणित की सहायक पुस्तक की सामग्री का विकास	डा० एच० एन० गुप्त
विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण योग्यता तथा परिकल्पना निर्माण योग्यता के विकास के लिए सामग्री पर आधारित आत्मशिक्षण प्रक्रिया का विकास, वैद्य बनाना और परीक्षण करना	डॉ० ए० प्रेवाल
सांस्थानिक परिसरों में सहकारी औपचारिक केंद्रों के लिए एक प्रयोगात्मक मॉडल	डा० बी० भालचंद्र
आर० सी० ई० (मैसूर) कार्यक्रम की स्वीकृति, सजगता और प्रभाव	डा० एस० दण्डपाणि डा० डी० एस० बाबू डा० (कु०) ताप्ती दत्त
अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और उनकी सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अंतःसंबंधों का अध्ययन	डॉ० बी० पी० अबस्थी
राजस्थान में इतिहास शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० वी० के० रायना

परियोजना का नाम	प्रमुख अनुसंधानकर्ता
प्राइमरी स्तर पर (कक्षा III से V तक के लिए) पर्यावरण अध्ययन में क्राइटेरियन रेफरेंस परीक्षण का विकास	डॉ० प्रीतम सिंह
शिक्षा के शिक्षणात्मक, विकासात्मक और सामाजिक उद्देश्यों के प्रकाश में कक्षा 10-12 के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन—एक प्रारंभिक अन्वेषण	डॉ० बाक़र मेहदी
भारत में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में शोध का सर्वेक्षण	डॉ० एन० के० जांगीरा
स्कूल शिक्षा में प्राइमरी स्तर से माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम के दबाव का अध्ययन	डॉ० जी० एल० अरोड़ा
छात्रों और शिक्षकों के मूल्यामिविन्यास के विकास में (वर्गीकृत युक्तियों के प्रयोग से) मूल्य शिक्षण की प्रभाविता	डॉ० आर० सी० दास डॉ० एल० सी० सिंह
प्राइमरी स्तर पर नामांकन और अपव्यय पर प्रलोभन योजना के प्रभाव का आकलन	डॉ० आर० आर० सक्सेना

शोध प्रबंधों और प्रबंधों के प्रकाशन के लिए अनुदान

निम्नलिखित पी-एच० डी० के शोध प्रबंधों और प्रबंधों को एरिक की सहायता से प्रकाशित किया गया।

परियोजना का नाम	लेखक का नाम
1. व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाली संस्थाओं के प्रशासन में संकाय सदस्यों की भागीदारी का अध्ययन	डॉ० आर० सी० श्रीवास्तव, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. प्राथमिक विद्यालयों की अध्यापिकाओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनकी कार्य संतुष्टि	डॉ० (श्रीमती) करुणा शाह, वाराणसी

परियोजना का नाम	लेखक का नाम
3. रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शैक्षिक विचारों तथा शिक्षा में समकालीन विचारों और व्यवहारों के संदर्भ में उनकी सार्थकता का अध्ययन	डॉ० एस० एस० राय, शांतिनिकेतन
4. समस्या प्रधान बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताएं	डॉ० श्याम कृष्ण, गोरखपुर
5. गुजरात राज्य के माध्यमिक स्कूलों के नवाचारी अध्यापकों की विशेषताओं का अध्ययन	डॉ० किशोर एम० शाह, गुजरात
6. समेकित आरंभिक हिंदी शब्दावली	प्रो० उदयशंकर तथा डॉ० जे० एन० कौशिक, कुरुक्षेत्र
7. प्राइमरी कक्षा के नए छात्रों में संबोधात्मक विकास का पल्लवन	डॉ० (श्रीमती) टी० पद्मिनी, मैसूर
8. शिक्षण संस्थानों की स्थिति (स्थान) का अध्ययन—शिक्षण संस्थाओं का अध्ययन	डॉ० एम० एल० मखीजा, डबोक, उदयपुर
9. शिक्षण का स्वरूप (प्रबंध)	डॉ० आर० पी० सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
10. सामाजिक आर्थिक हैसियत पर शिक्षा का प्रभाव (आय का ढांचा और शिक्षा)	डॉ० बी० एम० मोदी, अहमदाबाद
11. सन्नाटे को भेदते हुए—छोटे बधिर बच्चों के शिक्षकों के लिए निर्देश पुस्तिका	सुश्री मेनका पार्थसारथी, मद्रास
12. नागा भाषा भाषी छात्रों की हिंदी सीखने की समस्याएं	डॉ० आर० के० कुमार, मिजोरम

निम्नलिखित शोध प्रबंधों/प्रबंधों को प्रकाशित करने के लिए सहायता की स्वीकृति परिषद् की ओर से दी गई—

शीर्षक	लेखक का नाम
मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा का प्रशासन तथा स्वतंत्रता के बाद के बंगाल में प्रा० शि० के प्रशासन पर इसके असर की पड़ताल	डॉ० विश्वरंजन पुरकैत, हुगली (पश्चिम बंगाल)
भारत में राजभाषा की समस्या	डॉ० के० एल० गांधी, नई दिल्ली
नए संदर्भ में गांधी के शिक्षादर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन	डॉ० कमला द्विवेदी, गोरखपुर
कृषि शिक्षण की पद्धतियाँ—सुधारों का विश्लेषण	डॉ० एम० पी० गुप्त, संभलपुर
समय परिप्रेक्ष्य, अवधारणात्मक टेपो तथा विलंबित पुरस्कार के लिए प्राथमिकता—एक विकासात्मक अनुशीलन	डॉ० (श्रीमती) मंजु श्रीवास्तव, गोरखपुर
जाति के विशेष संदर्भ में कुमायूँ विश्व-विद्यालय के स्नातक छात्रों के शैक्षिक विकास का समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) वीणा शाह, श्रीनगर, गढ़वाल
1950 से बाद के 25 वर्षों के दौरान तमिल-नाडु में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अध्ययन	डॉ० एस० पबिकयम, दुटिकोरिन
भारतीय व्यक्तित्व की खूबियाँ	डॉ० (श्रीमती) इन्दु बवे, उदयपुर
उपलब्धि की सापेक्षता में पठन योग्यता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) प्रमजीत, दिल्ली
मदुरै, कामराज विश्वविद्यालय के पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव तथा उसका कार्यक्रम	डॉ० (श्रीमती) जे० के० पिल्लै, मदुरै
व्यक्ति के इंद्रियबोध पर स्टिमुलस प्रस्तुतीकरण पद्धति का प्रभाव	डॉ० मिठाईलाल गुप्त, गोरखपुर

शीर्षक	लेखक का नाम
उत्तरी पूर्वी भारत के मिजो जनजाति के मध्य शिक्षा के विकास का अध्ययन	डॉ० के० पी० नाथ, एजावल
व्यष्टि शिक्षण के संदर्भ में प्रभावशाली ढंग से प्रश्न करने पर बहुमाध्यमी पेटिका का विकास तथा परीक्षण	डॉ० एस० सी० शाह, सुरत
कॉलेज के छात्रों के व्यग्रता स्तर के व्यक्तित्व चरों (लक्षण तथा आवश्यकता) तथा जमांकिकीय सह संबंधकों (लिंग, क्षेत्र तथा एस० ई० एस०) का अध्ययन	डॉ० आर० एस० सिंह, देवरिया (उ०प्र०)
दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों के सह-शिक्षा वाले माध्यमिक स्कूलों में व्यष्टि-शिक्षण तकनीकों और अधिगम की परंपरागत तकनीकों की प्रभाविता का तुलनात्मक अध्ययन	प्रो० एम० आर० पालीवाल, बीकानेर
इन्वेण्टरीड इण्टरेस्ट का विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ० पी० एस० एस० भसीन, नई दिल्ली
व्यक्तित्व और अकादमिक भविष्यवाणी	डॉ० जी० एन० पी० श्रीवास्तव, भोपाल
इंटलेक्ट मॉडल के गिल्फोर्ड स्ट्रक्चर कैटेगोरी के संदर्भ में दिल्ली के स्कूलों के कक्षा X के छात्रों की अलजबरा में उपलब्धि का मूल्यांकन	डॉ० सी० पी० एस० चौहान, वाराणसी
प्राइमरी स्कूलों के ड्राप-आउट्स पर गैर-स्तरीकृत इकाइयों का प्रभाव	डॉ० जी० एस० पिल्लै, मद्रास
ब्रिटिशकालीन भारत में (1854-99) शैक्षिक नीति का विकास	डॉ० बी० बी० अग्रवाल, दिल्ली
भारत के तथा विदेश के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ० वीरेंद्रसिंह, उदयपुर

शिक्षा मनोविज्ञान

परिषद् में शिक्षा मनोविज्ञान में चलाए जा रहे अनुसंधान कार्यक्रम के तीन प्रमुख पहलू हैं (अ) शिक्षार्थी (ब) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (स) शिक्षण-अधिगम परिस्थिति। आर्थिक रूप से वंचित, सामाजिक रूप से वंचित और विकलांगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

अनुसंधान परियोजनाएं

ड्राप-आउट प्रक्रिया तथा ड्राप-आउट की

विशेषताओं का देशांतरीय अन्वेषण

इस देशांतरीय अध्ययन का उद्देश्य इस बात की परीक्षा करना है कि कैसे छात्रों और संस्थाओं की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का छात्रों के स्कूल छोड़कर जाने से संबंध है। अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि इस प्रक्रिया को किस तरह रोका जाए इसके लिए सुझाव देना। 'दि रिडिल ऑफ डाइसिलेक्सी' शीर्षक से एक पर्चा तैयार करके वितरित किया गया। चूंकि यह देशांतरीय अध्ययन था अतः नीचे जिन आंकड़ों को दिया गया है, उनको भी संकलित किया गया—

- (i) शिक्षक निर्धारण मापनी (शिक्षकों द्वारा मापक सूचना)।
- (ii) कक्षा IV तथा V के लिए सत्र 1983-84 के लिए उपलब्ध अंक, इनको कार्डों के ऊपर तथा मास्टर शीट पर लिख लिया गया।
- (iii) स्कूल छोड़ जाने वालों के नाम
केस स्टडी के लिए विषय समूह मानदण्ड तैयार किए गए। केस स्टडी का लिखना जारी रहेगा।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय तथा पाठ्यक्रम के

अंतर्गत विषय के चुनाव के लिए मानदण्ड का विकास करना

रिपोर्ट लेखन का काम प्रगति पर था।

माध्यमिक स्कूल स्तर पर व्यावसायीकरण के लिए व्यावसायिक

खोज कार्यक्रम की प्रभाविता की जांच पड़ताल

इस अध्ययन का उद्देश्य 'सेकेण्डरी स्कूल स्तर पर व्यावसायिक खोज कार्यक्रम' की प्रभाविता की जांच पड़ताल करना है। इसके दो मुख्य हिस्से हैं: (i) आत्मान्वेषण (ii) व्यावसायिक खोज।

इस समूह के छात्रों के लिए एक फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इन फिल्मों का उद्देश्य व्यवसाय संबंधी सूचनाएं देना था। प्रत्येक फिल्म प्रदर्शन के बाद छात्रों से बातचीत

का कार्यक्रम रखा गया था। क्षेत्र भ्रमण के लिए छात्रों को फैक्ट्रियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को दिखाने के लिए ले जाया गया।

‘स्व’ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता, आवश्यकता, परिपक्वता तथा अवकाश के समय की गतिविधियों पर आत्मसूचना के परिप्रेक्ष्य में अपने आपको समझने के लिए प्रयोग करने वाले समूह के व्यक्तियों ने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की व्याख्या की।

प्रारंभिक कक्षा के छात्रों के कक्षा के व्यवहार और बोधात्मक क्रियाओं को आनुषंगिक प्रबंधों द्वारा सुधारना

इस अनुसंधान परियोजना का उद्देश्य है आनुषंगिक प्रबंध तकनीक क्षमता की परीक्षा करना और यह जानना कि प्रारंभिक कक्षा के छात्रों के कक्षा व्यवहार तथा बोधात्मक क्रियाओं के सुधार में यह कितना असरदार साबित होती है। इन तकनीकों का प्रभावी प्रयोग छात्रों को स्कूल उपलब्धि तथा व्यवहार के उच्च स्तर के लिए उत्प्रेरित कर सकती है, इस प्रकार स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार ला सकती है। प्रयोग के बाद के लिए आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं।

प्रेक्षाध्यान-प्रभावशालिता के द्वारा जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण

यह परियोजना तुलसी अध्यात्मिक निदम तथा राजस्थान शिक्षा निदेशालय ने मिलकर हाथ में ली है। इसका उद्देश्य प्रेक्षाध्यान (जिसकी बकालत आचार्य तुलसी ने की है) के जरिए जीवन विज्ञान में प्रशिक्षण क्षमता का अनुशीलन करना है। मूल्यांकनपरक अध्ययन को हाथ में लेने के लिए परिषद् सहमत हो गई है। इसके अनुसंधान में ट्रीटमेण्ट परीक्षण के पूर्व और बाद की डिजाइन शामिल हैं। दो तरह से जीवन विज्ञान परीक्षण की प्रभाविता को जांचा व परखा गया है।

(क) बारह स्कूलों का क्षेत्राध्ययन, (ख) जोधपुर में स्थित एक स्कूल के बीस छात्रों का गहन अध्ययन।

जिन चरों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए गए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है : 8 मनोवैज्ञानिक चर, 4 शरीर वैज्ञानिक चर तथा सामान्य स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े। परियोजना के लिए आंकड़े एकत्र करके तथा उनको कोड करके उन्हें मास्टरशीट पर अंकित किया जा चुका है। ‘गहन अध्ययन’ के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। ‘सामान्य अध्ययन’ के आंकड़ों का संगणक द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है।

प्रतिभा की खोज

प्रतिभा की खोज और विकास राष्ट्र की एक सहत्वपूर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज योजना का आयोजन करता है। जिसका मुख्य लक्ष्य है कक्षा X, XI और XII के अंत में प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना और सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देना ताकि उनकी प्रतिभा का विकास हो और वे अपने-अपने विषय की ओर साथ ही राष्ट्र की सेवा कर सकें। अतीत की तरफ 1983 में भी परिषद् ने राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा का आयोजन किया। प्रतिभावान छात्रों के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिषद् ने छात्रवृत्तियों की संख्या 550 से बढ़ाकर 750 कर दी है।

यह राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा 8 मई, 1983 को भारत में 445 केंद्रों पर और विदेश में एक केंद्र (बहरेन) पर सम्पन्न हुई। कुल 74,108 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए—कक्षा X के 42,964; कक्षा XI के 5,744 और कक्षा XII के 25,400 छात्र। अनुसूचित जाति/

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	X					XI					XII				
		स	उ	च	स	उ	स	उ	च	स	उ	स	उ	च	स	उ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	आंध्र प्रदेश	2780	26	13	36	01	—	1561	13	08						
2.	असम	188	01	01	08	—	—	186	—	—						
3.	बिहार	6868	144	77	10	—	—	2138	56	20						
4.	गुजरात	1463	09	04	01	—	—	1047	05	03						
5.	हरियाणा	574	03	02	385	17	10	326	04	—						
6.	हिमाचल प्रदेश	277	01	—	96	01	01	70	01	01						
7.	जम्मू-कश्मीर	110	—	—	64	02	—	120	—	—						
8.	कर्नाटक	1891	17	08	01	—	—	1076	24	09						
9.	केरल	1760	15	07	—	—	—	761	03	01						
10.	मध्य प्रदेश	539	12	05	2016	24	09	138	06	03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	महाराष्ट्र	5199	134	64	01	—	—	2262	43	19
12.	मणिपुर	30	01	01	—	—	—	39	—	—
13.	मेघालय	68	—	—	—	—	—	23	—	—
14.	नागालैण्ड	06	—	—	—	—	—	05	—	—
15.	उड़ीसा	2308	22	11	250	18	06	1329	02	02
16.	पंजाब	628	06	03	355	26	16	240	06	03
17.	राजस्थान	2720	34	20	2218	152	89	308	09	04
18.	सिक्किम	20	—	—	01	—	—	11	—	—
19.	तमिलनाडु	2460	28	17	19	—	—	2463	25	15
20.	त्रिपुरा	27	01	01	—	—	—	26	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	5366	27	11	24	—	—	4317	37	22
22.	प० बंगाल	2074	31	14	03	—	—	1867	25	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	अंडमान-निकोबार	51	01	—	—	—	—	58	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	39	—	—	—	—	—	13	—	—
25.	चंडीगढ़	409	08	07	224	45	19	186	05	01
26.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	4809	177	109	32	01	—	4609	188	95
28.	गोवा, दमन, द्यू	106	—	—	—	—	—	62	01	01
29.	लक्षद्वीप	07	—	—	—	—	—	04	—	—
30.	मिजोरम	08	—	—	—	—	—	07	—	—
31.	पांडिचेरी	159	—	—	—	—	—	143	01	01
32.	विदेश	20	—	—	—	—	—	05	—	—
		42964	698	375	5744	287	150	25400	455	225

कुल सम्मिलित = 74108, कुल साक्षात्कार में उपस्थित = 1440, कुल चयनित = 750

जनजातियों के 75 छात्रों समेत 750 छात्र छात्रवृत्ति के लिए चुने गये।

वर्ष 1983 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के, कक्षा X, XI और XII के उम्मीदवार छात्रों की राज्यवार विस्तृत जानकारी पृष्ठ 193, 194 और 195 की तालिकाओं में दी गयी है।

संकेताक्षर—	सम्मिलित	स
	साक्षात्कार में उपस्थित	उ
	चुने गये	च

नयी योजना लागू करने की तैयारियाँ

1984 की परीक्षाओं को 13 मई, 1984 को आयोजित करने की तैयारियाँ की गयीं। 1984 की परीक्षा देश भर में 445 और विदेशों में 5 (ग्रैंट बिट्टेन, तेहरान, बहरैन, मस्कट और नेपाल) केंद्रों पर आयोजित होंगी। इस संबंध में लिखित परीक्षा के लिए मूल्यांकन-उपकरणों के विकास के लिए भी कार्य किया गया। यह परीक्षा पुराने प्रतिमान के अनुसार अंतिम परीक्षा होगी और इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा में कक्षा XI और XII के छात्र नहीं बैठ सकेंगे। इस तरह 12 वर्ष-प्रतिमान के कक्षा XI के और 11 वर्ष-प्रतिमान के कक्षा X के छात्रों के 1984 की परीक्षा में बैठने की छूट दी गयी है ताकि नयी योजना के लागू किये जाने से पहले प्रत्येक योग्य उम्मीदवार को कम-से-कम एक अवसर और मिल सके।

यह निश्चय किया गया है कि वर्ष 1985 से राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा को विकेंद्रीकृत कर दिया जायेगा। संशोधित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों के लिए चयन का कार्य कक्षा X के बाद ही दो चरणों में किया जायेगा। पहले चरण में चयन राज्यों द्वारा लिखित परीक्षाओं के माध्यम से किया जायेगा जो अक्टूबर-नवंबर, 1984 में किसी वक्त होंगी, और उसके आधार पर उम्मीदवारों की एक पूर्वनिर्धारित संख्या का अनुमोदन करके दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उनकी सूची रा० शै० अ० एवं प्रशिक्षण परिषद् को भेजी जायेगी। विभिन्न राज्यों व संघशासित क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित उम्मीदवारों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा मई 1985 में संपन्न होगी और उनमें से छात्रवृत्ति-योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन केंद्रों की एक सीमित संख्या पर परिषद् द्वारा किया जायगा। संशोधित योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए, विभिन्न राज्यों के संपर्क अधिकारियों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन अप्रैल 1983 में परिषद् के परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विभिन्न अकादमीय, प्रशासनिक और वित्तीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श हुआ। योजना के क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे उपायों के संदर्भ में परिषद् राज्यों से निरंतर संपर्क बनाये हुए है। आइटम लेखकों के प्रशिक्षण में राज्यों की सहायता की दृष्टि से परिषद् अभिविन्यास कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के लिए इस प्रकार की कार्य-शालाएं सम्पन्न हो चुकी हैं।

लिखित परीक्षाओं में सुधार

राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा के मापांकन-मूल्य में और सुधार लाने के लिए, प्रत्येक विषय

में पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों के संगत प्रमुख विषय-क्षेत्रों की पहचान करने के बाद, लिखित परीक्षाओं के लिए वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किये गये हैं। कुल 34 प्रारूप तैयार किये गये हैं जिनमें से 8 कक्षा X और 13 कक्षा XI और XII के लिए हैं।

प्रतिभा का पोषण

प्रतिभाशाली छात्रों के पोषण के लिए, परिषद् ने विभिन्न स्थानों में 79 स्नातक छात्रवृत्ति विजेताओं के लिए, जो विभिन्न विश्वविद्यालय विभागों में मूल विज्ञानों का अध्ययन कर रहे हैं, 5 ग्रीष्म स्कूलों का आयोजन किया। इसी तरह उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मूल विज्ञानों का अध्ययन कर रहे 13 परास्नातक छात्रवृत्ति-विजेताओं के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 ग्रीष्म प्लेसमेंट कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

छात्रवृत्तियों का भुगतान

लगभग 2700 रा० प्र० ख० छात्रवृत्ति-विजेताओं को 79.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज के लिए समीक्षा-समिति का गठन

सातवीं पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपाध्यक्ष प्रो० रईस अहमद की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

प्रस्तावित समीक्षा समिति की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए और कार्यात्मक रणनीति निर्धारित करने के लिए फरवरी 1984 में अध्यक्ष के साथ पहली मीटिंग हुई।

समीक्षा समिति की दूसरी मीटिंग रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने और विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यों के निर्धारण के लिए, 22 मार्च, 1984 को हुई। और अधिक विषयों तक योजना को विस्तारित करने, विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यचर्याएँ प्रस्तावित करने, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने, छात्रवृत्ति की दर का पुनर्निरीक्षण और विवेकीकरण करने, कोटा के आधार पर छात्रवृत्तियाँ सुरक्षित करने, चयन के लिए अतिरिक्त परीक्षण उपायों का उपयोग करने, चयन के लिए मूल्यांकन पद्धति में सुधार लाने, प्रतिभा का पोषण करने, आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर समिति ने विचार-विमर्श किया।

विस्तार और राज्यों के साथ सहयोग-कार्य

विस्तार कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के संबद्ध महाविद्यालयों, विभागों और यूनिटों का एक प्रमुख कार्य है। इसमें अन्य बातों के अलावा राज्य शैक्षिक अधिकरणों, शिक्षक समुदाय आदि के साथ मिलकर कार्य करना सम्मिलित है। पीछे विभिन्न अध्यायों में परिषद् के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों की रिपोर्टें देते समय, विस्तार कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय और परिषद् की फील्ड यूनिटें, अनुदर्शी सामग्री, क्लासरूम व्यवहार आदि के सुधार हेतु, विस्तार कार्यक्रमों और नवाचार को प्रोत्साहन देने में सहायक होती हैं।

समुदाय गायन को एक जनआंदोलन के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत, परिषद् भारत के विभिन्न भागों के संगीत शिक्षकों के लिए समुदाय गायन के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता रहा है और इस तरह देश के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों तक

आंदोलन को ले जाता रहा है। समीक्षित वर्ष में देश के विभिन्न भागों में इस योजना के अंतर्गत आयोजित शिविरों की सूचना नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	स्थान	अवधि
1.	पांडिचेरी	10-19 मई, 1983
2.	मद्रास	16-25 मई, 1983
3.	त्रिवेंद्रम्	27 मई-5 जून, 1983
4.	इलाहाबाद	5-14 जुलाई, 1983
5.	दिल्ली	24 अगस्त-3 सितंबर, 1983
6.	इरुफाल	22 सितंबर-1 अक्टूबर, 1983
7.	गोवा	4-13 जनवरी, 1984
8.	नई दिल्ली	8-18 फरवरी, 1984

भागीदारों में 15 गीतों के कैसेटों का वितरण भी किया गया।

1983 में बाल-दिवस के अवसर पर 10,000 से अधिक बच्चों की एक रैली में बच्चों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नयी दिल्ली में असमी, मराठी, तमिल, उर्दू और हिंदी भाषा के चुने हुए समुदाय गीतों का गायन किया। इस कार्यक्रम में परिषद् ने दिल्ली प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के 130 अध्यापकों को सामुदायिक गायन का प्रशिक्षण देकर और फिर अपने-अपने स्कूलों के बच्चों को इन गीतों के गायन की शिक्षा देने में उनकी सहायता करके अपना योगदान दिया। 'आओ, साथ गाएँ' नामक हिंदी और अंग्रेजी पुस्तिका, जिसे परिषद् ने तैयार किया है, भी रैली में वितरित की गयी।

मूल लिपि में चुने हुए समुदाय गीतों की एक पुस्तक, जिसमें हिंदी व अंग्रेजी में उनके अर्थ और वाचन भी दिये गये हैं, तैयारी के क्रम में थी। यह पुस्तक परिषद् द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों में भाग लेने वाले अध्यापकों में वितरण के लिए थी।

स्कूल शिक्षा में परिमाणात्मक विस्तार और गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से अध्यापक संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेने के प्रयास परिषद् द्वारा 1974 से ही किये जाते रहे हैं। अखिल-भारतीय प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों को प्रारंभिक शिक्षा की अधुनातन प्रवृत्तियों से परिचित कराने के लिए समय-समय पर अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

वर्ष 1983-84 में उपरोक्त फेडरेशन के पदाधिकारियों के लिए तीन अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन पटना, उदयपुर और नयी दिल्ली में किया गया, जिनमें से प्रत्येक पांच दिन का था। पटना में 200, उदयपुर में 100 और नयी दिल्ली में 100, अर्थात् देश भर के कुल 400 अध्यापकों को भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया। इस कोर्स के दौरान शिक्षण-अधिगम की नयी रणनीतियों का विवेचन किया गया। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में प्रारंभिक स्कूल अध्यापकों की भूमिका पर

विशेष बल दिया गया।

प्रायोगिक परियोजना की योजना में माध्यमिक और प्रारंभिक स्कूलों के अध्यापकों को वित्तीय सहायता के लिए 52 प्रस्ताव अहमदाबाद फील्ड कार्यालय को प्राप्त हुए। इनमें से 16 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया और समीक्षित वर्ष में उनको वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। 20 से 24 मार्च, 1984 तक केंद्रीय विद्यालय शैवाग, अहमदाबाद में फील्ड कार्यालय ने प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने से संबंधित, एक पंचदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। दादरा और नागर हवेली के 5 अध्यापकों समेत 15 अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यालय ने 26 से 30 मार्च, 1984 तक, गुजरात राज्य स्कूली पाठ्यपुस्तक बोर्ड के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से, 'नैतिक शिक्षा एवं मानवीय मूल्य' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया। 5 और 6 जनवरी, 1984 को बड़ौदा में रा० प्रौ० अ० एवं प्र० परिषद् के प्रकाशनों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। जनपद बुलसर के चिखली तालुका के कक्षा X के छात्रों के लाभ के लिए 'थोकेशनल नीड्स एंड इंटेरेस्ट्स आफ एस० सी०/एस० टी० स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक गाइडेंस टू दि स्टूडेंट्स आफ चिखली तालुका' नाम से एक शोध परियोजना भी आरंभ की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत चिखली तालुका मुख्यतः अनुसूचित जाति/जनजातियों की आबादी वाला एक तालुका है। 13 मार्च 1984 को एक सेमिनार और 16 मार्च 1984 को एक व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

इलाहाबाद कार्यालय ने प्रायोगिक परियोजनाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान परियोजना-प्रारूपों की तैयारी की गयी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उ० प्र० के सहयोग से कार्यालय ने विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मूल्यांकन प्रणालियों के सुधार और प्रश्नपत्रों की तैयारी के विषय पर दो कार्यशालाओं का आयोजन भी किया।

बंगलूर फील्ड कार्यालय ने परिषद् के कार्यक्रमों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न जनपदों में अनेक मीटिंगों का आयोजन किया। 'स्कूल निरीक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिककरण' पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम के आयोजन में भी कार्यालय ने अपना सहयोग दिया।

स्कूलों में प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता संबंधी 53 प्रस्ताव भोपाल फील्ड कार्यालय को प्राप्त हुए। चयन समिति ने 28 प्रस्तावों का अनुमोदन किया और 13 संस्थाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृति की गयी। यह कार्यालय अनौपचारिक शिक्षा के 10 केंद्र भी चला रहा है। इन केंद्रों के लिए हिंदी में स्वअधिगम पेट्रीकाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। जनसंख्या शिक्षा पर फील्ड सलाहकार द्वारा आरंभ की गयी एक एरिक शोध परियोजना प्रगति के पथ पर है। पियर ग्रुप विचार-विमर्श के लिए अनुदर्शी सामग्री विकसित की गयी और उनका पुनरुत्पादन हो रहा है इसके अतिरिक्त, 2 से 6 फरवरी, 1984 तक जबलपुर में कक्षा I से V और VI से VIII के लिए मध्य प्रदेश के लिए एक आवश्यकता केंद्रित स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी इस कार्यालय ने किया है।

मुवनेश्वर फील्ड कार्यालय को प्राथमिक शिक्षकों से 86 और माध्यमिक शिक्षकों से 13

प्रस्ताव प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत मिले। प्रयोग व नवाचार के लिए 28 प्राथमिक स्कूलों और 2 माध्यमिक स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गयी। गंजाम, फूलबनी, कालाहांडी और कोरापुर जैसे पिछड़े जनपदों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इसमें प्रारंभिक स्कूलों के 29 अध्यापकों ने भाग लिया और अनेक उत्तम परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार हुई।

कलकत्ता फील्ड कार्यालय अपने क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों से संबद्ध रहा। इनमें हैं पूर्वी क्षेत्र की पी० ई० सी० आर० परियोजना में भाग ले रहे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की क्षेत्रीय मीटिंग; पूर्वी क्षेत्र के गणित के आइटम लेखकों के लिए गहन प्रशिक्षण कोर्स; एन० टी० एस० साक्षात्कार; आदि।

चंडीगढ़ फील्ड कार्यालय को प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए। फील्ड सलाहकार द्वारा नियुक्त चयन समिति ने अंततः 10 परियोजनाओं का अनुमोदन किया और संबंधित स्कूलों को वित्तीय सहायता जारी की गयी। बड़ी कक्षाओं के लिए रणनीति के विषय पर 17-19 फरवरी, 1984 को, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुखों के लिए, एक कार्यशाला का आयोजन भी कार्यालय ने किया। कार्यशाला की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। चंडीगढ़ में 5 जनवरी, 1984 से आरंभ प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण विषय पर एक तीन-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी इस कार्यालय ने किया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 30 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। भागीदारों ने विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में अनेक उपायों का अनुमोदन किया। इनमें स्कूलों में अनस्तरित शिक्षण परियोजना का परीक्षण किए जाने का अनुमोदन भी सम्मिलित है।

गोहाटी फील्ड कार्यालय का क्षेत्र बहुत व्यापक है और असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इसमें आ जाते हैं। इन सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक अधिकरणों से कार्यालय ने संपर्क बनाये रखा और परिषद् के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता की।

प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम से अध्यापकों को परिचित कराने के लिए विजयनगरम में एक-दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद फील्ड कार्यालय ने किया। इस कार्यशाला में 17 परियोजना-प्रस्तावों को विकसित किया गया। 5-6 मार्च, 1984 को स्कूलों के प्राचार्यों और अध्यापकों के लिए एस० यू० पी० डब्ल्यू० पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन भी इस कार्यालय ने किया।

जयपुर फील्ड कार्यालय ने एक प्रस्ताव प्रेषित किया कि राजस्थान में पिछले 500 वर्षों में तैयार गणित संबंधी सामग्री के संग्रह व उपयोग के लिए एरिक सहायता प्रदान करे। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुस्तकालयों, संग्रहालयों और व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त की जा रही है। इसमें पढ़ा गणित, साहूकारी गणित आदि की हस्तलिखित पांडुलिपियां भी शामिल हैं। प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्ताव भी कार्यालय द्वारा आमंत्रित किये गये। प्राप्त प्रस्तावों की एक समिति ने छानबीन की। समीक्षित वर्ष में 10 प्रायोगिक परियोजनाएं पूरी हुईं।

अनुदर्शन और मूल्यांकन के पक्षों पर एक तीन-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मद्रास फील्ड कार्यालय द्वारा किया गया। विज्ञान शिक्षण के पक्षों पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला और निदान-उपचार शिक्षण पर एक पंचदिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी इसने किया।

पटना फील्ड कार्यालय को प्रायोगिक परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत 34 प्रस्ताव प्राप्त हुए। फील्ड सलाहकार द्वारा गठित चयन समिति ने अनुदान-सहायता के लिए 11 प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

खिलौना-बनाओ प्रतियोगिता, राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के कार्यक्रमों में पूणे फील्ड कार्यालय ने भाग लिया और परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग दिया।

शिलांग फील्ड कार्यालय का कार्यक्षेत्र मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कार्यालय ने सहयोग दिया। इसमें राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा और राज्यस्तरीय खिलौना-बनाओ प्रतियोगिता सम्मिलित हैं। कार्यालय ने राज्यों और संघशासित क्षेत्र को भी उनके कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता की।

हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिमला में एक नयी फील्ड यूनिट परिषद् द्वारा स्थापित की गयी। 19 अक्टूबर, 1983 से शिमला में कार्य करना इसने आरंभ कर दिया है। राज्य में परिषद् के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में यह फील्ड कार्यालय सक्रिय है।

श्रीनगर फील्ड कार्यालय राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन से संबद्ध रहा जिसका उद्देश्य राज्य में 10+2 प्रतिमान लागू करना है। सामाजिक विज्ञानों की माध्यमिक स्तरीय पाठ्यचर्या को अंतिम रूप देने में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की सहायता भी इस कार्यालय ने की। राज्य में परिषद् के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से भी कार्यालय संबद्ध रहा।

त्रिवेन्द्रम फील्ड कार्यालय विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से संबद्ध रहा, जैसे लक्षद्वीप के अध्यापकों का अभिविन्यास, बारकला में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, कैरियर मास्टर्स का अभिविन्यास, शिक्षा के व्यावसायीकरण पर कार्यशाला, सामाजिक विज्ञान क्लबों की स्थापना के लिए हाई स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण, आदि।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में परिषद् यूनेस्को और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी संपर्क बनाये रखती है। स्कूल स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के अपने प्रयासों में परिषद् को यू० एन० डी० पी०, यूनेस्को आदि अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों से सहायता मिलती रही है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों, जिनका संबंध स्कूल शिक्षा से होता है, के क्रियान्वयन में परिषद् एक प्रमुख अधिकरण का कार्य करती है। एशियन प्रोग्राम्स फार एजुकेशनल इन्नोवेशन्स फार डवलपमेंट (APEID) के लिए राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में भी परिषद् कार्य करती है। अन्य बातों के साथ सचिवालय कार्य में शामिल हैं— शिक्षा निदेशकों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों व राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों, और ए० पी० ई० आई० डी० के अन्य संबंधित केंद्रों के साथ संचार-व्यवस्था स्थापित करना; सूचना/प्रलेखन सेवाएं उपलब्ध कराना; ए० पी० ई० आई० डी० द्वारा

जारी विभिन्न कार्यक्रमों का विकास और मूल्यांकन, और ए० पी० ई० आई० डी० द्वारा जारी या सहायता प्राप्त नवाचार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना ।

यूनेस्को/ए० पा० ई० आई० डी०

यूनेस्को कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष या ए० पी० ई० आई० डी० के माध्यम से भाग लेकर और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनों के रूप में परिषद् यूनेस्को की गतिविधियों में भागीदारी करती है। प्रत्यक्ष भागीदारी में सम्मिलित हैं— अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं/सिम्पोजिया आदि में भाग लेने के लिए परिषद् के अधिकारियों का भेजा जाना, और विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों में विदेशी राष्ट्रीयों को प्रशिक्षण देना । समीक्षित वर्ष में, परिषद् के निम्न अधिकारियों ने यूनेस्को की गतिविधियों में भाग लिया ।

विदेशों में परिषद् के अधिकारियों की गतिविधियाँ

प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास सेल के रीडर श्री एस० एच० खान ने प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के आगे के प्रशिक्षण से संबंधित यूनेस्को उप-क्षेत्रीय सेमिनार (1-10 जून, 1983, ढाका, बांगला देश) में भाग लिया ।

अनीपचारिक, शिक्षा विभाग के रीडर डा० पी० दासगुप्ता ने, जापानी फंड-इन-ट्रस्ट व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम-विकास हेतु एक गतिमान टीम प्रशिक्षण कार्यक्रम (24-29 जुलाई, 1983, बैंकाक, थाइलैंड) में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया ।

विज्ञान एवं गणित शिक्षण विभाग के प्रोफेसर डा० ए० एन० बोस ने बांगला देश के माध्यमिक स्कूल विज्ञान-शिक्षण परियोजना हेतु तकनीकी सहायता अध्ययन के सलाहकार रूप में बांगला देश का भ्रमण किया । यह कार्यक्रम ढाका में 6 जून से 5 अगस्त, 1983 तक आर० ओ० ई० ए० पी० के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक के समर्थन से आयोजित किया गया था ।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल के रीडर डा० डी० सी० उपरेटी ने डबलिन में 8-12 अगस्त, 1983 को आयोजित सामुदायिक शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया ।

शैक्षिक मनोविज्ञान यूनिट के प्रमुख प्रो० ए० शर्मा और पाठ्यक्रम समूह के रीडर डा० डी० पी० गुप्ता ने 'बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति' विषय पर ए० पी० ई० आई० डी० के तकनीकी कार्यकारी दल की मीटिंग (बैंकाक, 6-12 सितंबर, 1983) में भाग लिया ।

पी० सी० डी० सी० की प्रमुख श्रीमती आदर्श खन्ना ने जीवनपर्यन्त शिक्षा की अवधारणा पर यूनेस्को शिक्षा संस्थान द्वारा हैम्बर्ग, जर्मनी में आयोजित सेमिनार (12-15 सितंबर, 1983) में भाग लिया ।

डी० ई० एस० एम० के रीडर डा० जे० मित्रा ने 'विज्ञान सबके लिए' विषय पर बैंकाक में 20-26 सितंबर, 1983 को आयोजित यूनेस्को क्षेत्रीय मीटिंग में भाग लिया ।

परिषद् के निदेशक डा० पी० एल० मलहोत्रा ने वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में 4-12 अक्टूबर 1983 को यूनेस्को के लिए न्यूजीलैंड राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित पाठ्यपुस्तकों और पठन सामग्रियों से संबंधित यूनेस्को क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लिया।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर की रीडर डा० (श्रीमती) अमृत कौर और क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर के रीडर डा० एस० सी० चतुर्वेदी ने ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षण में भाग लिया। 4 अक्टूबर, 1983 से आरंभ यह प्रशिक्षण 6 माह का था और ग्रेट ब्रिटेन में कोलम्बो योजना के अंतर्गत विकलांगों के शिक्षण/विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में था।

क्षे० शि० म०, भोपाल के प्राध्यापक डा० ए० बी० सक्सेना ने ब्रिटिश कौंसिल के टी० सी० टी० पी० कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन में शैक्षिक अध्ययन (पर्यावरण अध्ययन) के एक डिप्लोमा में भाग लिया जो 28 सितंबर, 1983 से आरंभ होकर 10 माह तक चला।

क्षे० शि० म०, भोपाल के प्राध्यापक श्री एस० के० गुप्ता ने ब्रिटिश कौंसिल के टी० सी० टी० पी० कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिक्षा संबंधी यू० के० एसोसिएटशिप स्टडी के प्रशिक्षण में भाग लिया जो ग्रेट ब्रिटेन में 4 अक्टूबर, 1983 से आरंभ होकर 9 माह तक चला।

क्षे० शि० म०, भोपाल की प्राध्यापिका डा० (श्रीमती) एस० मुखोपाध्याय ने भी इसी कार्यक्रम के तहत ग्रेट ब्रिटेन में एक प्रशिक्षण में भाग लिया जो 3 अक्टूबर, 1983 से आरंभ होकर 10 माह तक चला।

परिषद् के प्रकाशन विभाग के मुख्य उत्पादन अधिकारी श्री यू० प्रभाकर राव ने बच्चों के लिए शैक्षिक प्रकाशन के एक प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया जिसे यूनेस्को के एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र ने, यूनेस्को के लिए जापानी राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से, टोक्यो, जापान में 27 सितंबर से 20 अक्टूबर, 1983 तक आयोजित किया था।

डी० ई० एस० एम० के रीडर डा० डी० लाहिड़ी ने ब्रेटिसलवा (चेकोस्लोवाकिया) में 17-21 अक्टूबर, 1983 को आयोजित विज्ञान अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के विषय पर यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया।

डी० ई० एस० एम० के प्रो० ए० के० जलालुद्दीन ने शोध परिणामों के विनिमय के विशेष संदर्भ में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान पर एक क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लिया जो टोक्यो (जापान) में 9 से 25 नवंबर, 1983 तक आयोजित हुआ था।

परिषद् के सहनिदेशक डा० टी० एन० घर ने बैंकाक में 9 से 23 नवंबर 1983 तक आयोजित ए० पी० ई० आई० डी० की क्षेत्रीय मीटिंग में सलाहकार रूप में भाग लिया। यह मीटिंग शिक्षा के सार्वजनीकरण संबंधी राष्ट्रीय अध्ययनकर्त्ताओं की थी और इन अध्ययनों की समीक्षा के लिए थी। उन्होंने मीटिंग में सलाहकार के रूप में भी कार्य किया।

परिषद् के केप ग्रुप के प्राध्यापक डा० एम० पी० रस्तोगी ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण कार्यक्रम के नियोजन एवं प्रबंध पर ढाका में 16-29 नवंबर, 1983 को आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

परिषद् की व्यावसायिक शिक्षा यूनिट के प्राध्यापक डा० ए० के० धोते ने 14 अक्टूबर से 12 नवंबर, 1983 तक थाईलैंड, जापान और कोरियाई गणतंत्र का भ्रमण किया। यह भ्रमण संबंधित देशों के स्कूल पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा के एक अंग रूप में कार्यानुभव का अध्ययन

करने के लिए था और इसे यूनेस्को के तत्त्वावधान में आयोजित किया गया था।

डी० ई० एस० एम० की रीडर श्रीमती एस० भट्टाचार्य ने, चुनी हुई प्रयोगशाला तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री के विकास पर, 15-30 दिसंबर, 1983 को पेनांग (मलेशिया) में आयोजित एक उपक्षेत्रीय कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर के प्राध्यापक डा० जे० क्रे० महापात्र और क्षे० शि० म०, मैसूर के रीडर डा० ए० सी० बनर्जी ने पेनांग (मलेशिया) में 19-29 दिसंबर, 1983 को इसी विषय पर आयोजित एक उपक्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

डी० ई० एस० एम० के प्रो० डा० ए० के० जलालुद्दीन ने मालदीव के मौलिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता अभिकर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी एक कार्यशाला में सलाहकार रूप में भाग लिया जो 26 दिसंबर, 1983 से मालदीव में आरंभ होकर एक सप्ताह तक चली।

कार्यशाला विभाग के प्रमुख श्री पी० के० भट्टाचार्य ने जापानी फंड-इन-ट्रस्ट के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा की गतिमान प्रशिक्षण टीम में कार्यक्रम के अंतर्गत फिलीपीन का 21 से 25 नवंबर, 1983 तक और थाइलैंड का 26 नवंबर से 1 दिसंबर, 1983 तक भ्रमण किया।

पाठ्यक्रम समूह के रीडर डा० जी० एल० अरोरा ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अध्ययन से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लिया जिसे एन० आई० ई० आर०, जापान ने यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के सहयोग से 28 फरवरी से 15 मार्च, 1984 तक आयोजित किया था।

परिषद् में विदेशी अतिथि

दूसरे देशों के विशेषज्ञों के लिए परिषद् ने निम्न भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय, बार्बाडोस के एक्सट्रा-क्यूरल विभाग के निदेशक डा० ब्रैडले ई० नील्स ने 8 अप्रैल, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। परिषद् की गतिविधियों और कार्यक्रमों से उनको परिचित कराया गया।

नेपाल से विश्व स्वास्थ्य संगठन के दो अध्येताओं—श्री द्वारका राम श्रेष्ठ और श्री गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ—ने ए० वी० शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन सहायक सामग्री विभाग द्वारा आयोजित एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 11 से 15 अप्रैल 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया।

पाकिस्तान से यूनेस्को अध्येता प्रो० एस० एम० तक्वीमुल-हक ने, नीपा के अपने कार्यक्रम के एक अंग रूप में, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं और पाठ्यक्रम विकास केंद्रों के कार्यकलापों का अध्ययन करने के लिए, 27 और 28 मई, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया।

यूक्रेन से यूनेस्को अध्येता श्री ओलेग शेमेनेट्स ने भाषाओं के मनोवैज्ञानिक शिक्षाशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय पक्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान के संगठन का अध्ययन करने के लिए 13 जून, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया।

इंस्टीट्यूट फार दि प्रोमोशन आफ टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकाक के संकाय

प्रमुख और अनुसंधान एवं मूल्यांकन विभाग के अध्यक्ष डा० अनान चंकावी ने परिषद् की विज्ञान प्रतिभा-खोज परियोजना का अध्ययन, ए० पी० ई० आई० डी० के संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत करने के लिए, 23 जून से 7 जुलाई, 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया।

अफगानिस्तान से चार यूनेस्को अध्येताओं—श्री भरत अली अतापूर, श्री ए० एच० समदी, श्री एम० आर० आइहेद और श्री ए० ब्यू० रहमानी—भौतिकशास्त्र, जीवविज्ञान, और रसायनशास्त्र में प्रशिक्षण के लिए 30 जून, 1983 से दो माह तक परिषद् के अतिथि रहे।

नीपा में अध्ययन के लिए आये 40 भागीदारों के एक गुप—भारत के विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से 31, श्रीलंका और भूटान से चार-चार, और मारीशस से एक—ने परिषद् की गतिविधियों और कार्यक्रमों से परिचय प्राप्त करने के लिए 5 जुलाई, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया।

श्रीलंका की सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधार परियोजना के स्टाफ को यूनेस्को के सहयोग से परिषद् द्वारा प्रशिक्षित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए श्रीलंका के यूनेस्को सलाहकार श्री आर० ए० ब्राउनस्मिथ 15 जुलाई, 1983 को परिषद् में पधारे।

भूटान की एक तीन-सदस्यीय टीम, जिसमें श्री जी० आर० मोहन, श्री फूब रिन्धेन और कुमारी केंसंग दोमा थे, ने परिषद् के कार्यशाला विभाग द्वारा आयोजित प्राथमिक विज्ञान किटों से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लिया जो 19 जुलाई, 1983 से आरंभ होकर एक सप्ताह तक चला।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए 19 से 23 जुलाई, 1983 तक बांग्लादेश के सात व्यक्तियों—श्री अनीसुर्रहमान, श्री तैमूरहमान, श्री अब्दुल हगुआल खान, श्री अब्दुल माजिद, श्री मुजीबुर्रहमान, श्री ताहिर मियाँ और श्री अब्दुर्रज्जगुल ने परिषद् का भ्रमण किया।

बांग्लादेश के ही सात व्यक्तियों—श्री ए० पी० एम० खलीलुर्रहमान, श्री एस० एम० शम्सुलहक, श्री एस० एस० ए० मन्नान, श्री अब्दुर्रशीद खान, श्री कमालुद्दीन अहमद तालुकदार, श्री सखावत हुसैन खांडोकर और श्री इकबाल अहमद ने 15 से 21 अगस्त, 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया।

बहरैन के विभिन्न स्कूलों के 8 छात्र और अध्यापक ने 4 अगस्त, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। परिषद् के कार्यक्रमों और गतिविधियों से उनको परिचित कराने के लिए सहनिदेशक ने उनके साथ एक मीटिंग की।

फिजी के वरिष्ठ शिक्षाशास्त्री श्री पारस राम ने 5 अगस्त, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। परिषद् के अध्यापक-शिक्षण कार्यक्रम से परिचय प्राप्त करने के लिए अध्यापक-शिक्षण विभाग के संकाय सदस्यों से उन्होंने मेट की।

मैट्रोपोलिटन स्टेट विश्वविद्यालय, मिनीएपोलिस, संयुक्त राज्य अमरीका के अध्यक्ष प्रो० रिथ क्लार्क किंग ने 26 सितंबर, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। परिषद् के कार्यक्रमों और गतिविधियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया और अपने विश्वविद्यालय द्वारा

चलाये जा रहे नवाचार कोसों पर एक व्याख्यान भी उन्होंने दिया।

लंदन विश्वविद्यालय के शिक्षा संस्थान के श्री ह्यू ह्वेस ने 26-27 सितंबर, 1983 की परिषद् का भ्रमण किया और परिषद् के कार्यक्रमों व गतिविधियों से परिचय प्राप्त किया।

एशियाई विकास बैंक, मनीला के शिक्षा-विशेषज्ञ डा० मोतीलाल शर्मा ने 10 अक्टूबर, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। यह भ्रमण सर्वेक्षण यूनिट में भारत में शिक्षा के विषय पर एक खोज अध्ययन के लिए था।

श्रीलंका से यूनेस्को अध्येता डा० के० डी० प्रेमरत्न ने 2 अक्टूबर, 1983 से आरंभ होने वाले तीन माह के अध्यापन-सहायक सामग्री एवं पाठ्यक्रम विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में परिषद् का भ्रमण किया।

श्रीलंका से यूनेस्को अध्येता श्री पी० ए० वी० परेरा मापन एवं मूल्यांकन संबंधी अध्ययन के लिए 31 अक्टूबर, 1983 से दो माह तक परिषद् के अतिथि रहे।

एन० आई० ई० आर०, जापान के उपमहानिदेशक श्री टी० योकू ने 27 नवंबर से 2 दिसंबर, 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया। भ्रमण का उद्देश्य था विचारों का आदान-प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा और अध्यापक-प्रशिक्षण की प्रणाली और कार्यक्रमों का अध्ययन करना, और साथ ही देश की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा गतिविधियों का प्रेक्षण करना। उन्होंने तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास का भ्रमण भी किया।

माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी संस्थान, मारीशस के शिक्षा अधिकारी श्री जे० एल० आर० पुट्टी ने, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान (जीवविज्ञान और कृषि) संबंधी यूनेस्को अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत, 14 से 17 दिसंबर, 1984 तक परिषद् का भ्रमण किया।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए बांग्लादेश के 8 शिक्षकों ने 25 से 31 दिसंबर, 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया। यह टीम क्षे० शि० म०, अजमेर भी गयी।

जनसंख्या शिक्षा संबंधी यूनेस्को संबद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत वियतनाम के श्री माइयुन सेन और श्री यू मजोज बिन्ह 28 नवंबर से 24 दिसंबर, 1983 तक परिषद् के अतिथि रहे।

श्रीलंका के यूनेस्को अध्येता श्री वाई० पी० डब्ल्यू० फेरांडो व्यावसायिक शिक्षा संबंधी 6 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए 13 दिसंबर, 1983 से 28 जनवरी, 1984 तक परिषद् के अतिथि रहे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, टोक्यो के विज्ञान-शिक्षा अध्यापन सहायक सामग्री एवं सामग्री शोध केंद्र के वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता प्रभाग के श्री नोरीकायू ओसामी ने 15 से 24 दिसंबर, 1983 तक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में भाग लिया जो प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण हेतु स्थानीय संघाधनों से विज्ञान-उपकरणों के विकास से संबंधित थी।

तंजानिया के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री महामहिम श्री जैक्सन एम० मक्वाटे और उनके साथ जंजीबार के शिक्षा उपमंत्री महामहिम श्री मियोजी वेसा इंदारौस ने संघीय शिक्षा मंत्री के निमंत्रण पर अपने भारत भ्रमण के दौरान 10 फरवरी, 1984 को परिषद् का आतिथ्य ग्रहण किया। परिषद् के निदेशक के साथ भ्रमणकारी महामहिमगण की एक मीटिंग हुई

जिसमें संकाय के वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे। महामहिमगण को स्कूल शिक्षा क क्षेत्र में परिषद् के कार्यक्रमों व गतिविधियों से परिचित कराया गया।

मारीशस शिक्षा संस्थान के 9 प्रमुख व्यक्ति प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रम के 8 सप्ताह के एक प्रशिक्षण के लिए 23 फरवरी से 18 अप्रैल, 1984 तक परिषद् के अतिथि रहे।

शिक्षा मंत्रालय, सोमालिया के महानिदेशक श्री उस्मान अली जामा और योजना-निदेशक श्री हुसैन मुहम्मद ने एक अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 28-29 फरवरी, 1984 को परिषद् का भ्रमण किया।

ए० पी० ई० आई० डी० के सहयोगी केंद्र के रूप में परिषद् के कार्यक्रम

रा० शि० अ० एवं प्र० परिषद् ने, ए० पी० ई० आई० डी० के सहयोगी केंद्र के रूप में, निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया—

शिक्षा पर आंकड़े संग्रहित करने और उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण करने के लिए निदर्शन विधियों के प्रायोगिक उपयोग पर कार्यकारी दल की एक मीटिंग रा० शि० संस्थान परिसर में 19 से 25 अप्रैल, 1983 तक हुई।

जापानी फंड-इन-ट्रस्ट के अंतर्गत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी एक गतिमान प्रशिक्षण टीम परियोजना की एक अंतर्देशीय कार्यशाला का आयोजन क्षे० शि० म०, भोपाल में 5 से 25 अप्रैल, 1983 तक किया गया।

औपचारिक एवं अनौपचारिक जनसंख्या-शिक्षा की एकजुटता कार्यक्रम संबंधी एक क्षेत्रीय सेमिनार बंगलौर में 16 से 23 मई, 1983 तक आयोजित की गई।

रसायनशास्त्र-पाठ्यक्रम एवं अध्यापन सामग्री के सुधार पर एक राष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कार्यशाला रा० शि० संस्थान परिसर में 20 से 27 सितंबर, 1983 तक आयोजित की गयी।

प्रारंभिक बचपन की देखभाल व शिक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन रा० शि० संस्थान परिसर में 22 से 29 नवंबर, 1983 तक हुआ।

जापानी फंड-इन-ट्रस्ट के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा की गतिमान प्रशिक्षण टीम—प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण के लिए स्थानीय संसाधनों से विज्ञान-उपकरणों के विकास पर एक कार्यशाला रा० शि० संस्थान परिसर में 15 से 24 दिसंबर, 1983 तक आयोजित की गयी।

बच्चों, विशेषतः बंचित समूहों के बच्चों की अधिगम-समस्याओं पर प्रमुख व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय चालक प्रशिक्षण कार्यशाला रा० शि० संस्थान परिसर में 15 से 24 दिसंबर 1983 तक आयोजित की गयी।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यशाला, रा० शि० संस्थान परिसर में 20-21 दिसंबर, 1983 को आयोजित की गयी।

दृश्य विकलांगों की विशेष शिक्षा/एकीकृत शिक्षा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन रा० शि० संस्थान परिसर में 5 से 16 मार्च, 1984 तक किया गया। थाइलैंड के दो विशेषज्ञों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

परिषद् की यूनेस्को परियोजनाएँ

समीक्षित वर्ष में निम्न अध्ययनों के लिए परिषद् ने यूनेस्को के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये—

प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

“स्टेटस आफ रीसेंट डवलपमेंट्स एंड न्यू ट्रेंड्स इन टीचिंग-लर्निंग मेथड्स एंड टेक्नीक्स” पर राष्ट्रीय केस अध्ययन।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण पर एक राष्ट्रीय अध्ययन की तैयारी और इसी विषय पर किये गये अध्ययनों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन।

माध्यमिक स्कूलों के लिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों और पर्यावरण शिक्षा के अधीक्षकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रायोगिक माड्यूल की तैयारी।

बच्चों, विशेषतः वंचित समूहों के बच्चों की अधिगम-समस्याओं पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला।

अध्यापक-शिक्षकों, अधीक्षकों और वरिष्ठ विशेष-शिक्षा के अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला।

व्यापार व वाणिज्य शिक्षा के पाठ्यक्रम और अनुदर्शी सामग्री के विकास और मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

‘इनवायरनमेंटल प्रोब्लम्स इन सीटीज—ऐन एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन माड्यूल’ शीर्षक वाली एक पांडुलिपि की स्वीकृति।

प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण के लिए स्थानीय संसाधनों से विज्ञान-उपकरणों के विकास पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

औपचारिक एवं अनौपचारिक जनसंख्या शिक्षा की एकजुटता पर एक क्षेत्रीय सेमिनार।

रसायनशास्त्र के पाठ्यक्रमों व अध्यापन सामग्रियों के सुधार पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला।

भारत में सामान्य शिक्षा संबंधी कार्यानुभव का राष्ट्रीय अध्ययन।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को लागू करने वाले महत्वपूर्ण अधिकरणों में से परिषद् भी एक है। ऐसे एक अधिकरण के रूप में परिषद् अपने प्रतिनिधि मंडल नवाचारी शैक्षिक विकासों के अध्ययन के लिए दूसरे देशों में भेजती है और उनके साथ इस तरह द्विपक्षीय विचार-प्रवाह में भाग लेती है। शैक्षिक सामग्रियों—पाठ्यपुस्तकों, पूरक पठन सामग्रियों, शोधग्रंथों, फिल्मों, फिल्मों की टुकड़ियों—आदि का अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान भी, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सांस्कृतिक विनिमय अनुबंधों के प्रावधानों के अंतर्गत, परिषद् द्वारा किया जाता है।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत बाहर भेजे गये परिषद् के अधिकारियों और

भारत भ्रमण के लिए आये विदेशी अतिथियों की सूचना निम्नानुसार है।

परिषद् के अतिथि

शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केनिया के उपनिदेशक श्री जे० ए० लिजेम्बे ने, भारत-केनिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1981-83 की धारा 5 के अंतर्गत, स्कूलपूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, अध्यापक-प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्रों में अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए, 19 से 24 नवंबर, 1983 तक परिषद् का भ्रमण किया।

उच्चतर और विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा के सोवियत उपमंत्री महामहिम प्रो० एन० एस० इगोरोव; मिर प्रकाशन गृह, मास्को के निदेशक श्री वी० पी० कार्तसेव; प्रगति प्रकाशन, मास्को के मुख्य संपादक श्री ए० के० वेलित्चेव; उच्चतर और विशेषीकृत माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की विभाग प्रमुख श्रीमती एस० वी० आंद्रीवा; और विदेशी भाषा संस्थान, मास्को के अध्यापक श्री जी० ए० ओर्लोव पर आधारित सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने 24 दिसंबर, 1983 को परिषद् का भ्रमण किया। 19 से 28 दिसंबर, 1983 तक आयोजित भारत-सोवियत पाठ्यपुस्तक बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने के लिए यह प्रतिनिधिमंडल भारत आया था।

प्रतिनिधिमंडल

भारत-य० ज० लो० ग० सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1980-82 (1983 तक विस्तारित) की धारा I के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा संबंधी अनुभवों का आदान-प्रदान करने, संपर्क स्थापित करने और य० ज० लो० ग० के साथ सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, परिषद् के संकाय प्रमुख (ए) डा० आर० सी० दास ने यमन जन लोकतांत्रिक गणराज्य का भ्रमण 21 से 28 दिसंबर, 1983 तक किया।

भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1983-84 के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक सलाहकार (तकनीकी) की अध्यक्षता में 11 से 22 अक्टूबर, 1983 तक सोवियत संघ का भ्रमण करने वाले पांच-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में परिषद् की व्यावसायिक शिक्षा यूनिट के अध्यक्ष डा० ए० के० मिश्र भी एक सदस्य के रूप में सम्मिलित रहे। इस भ्रमण का उद्देश्य सोवियत संघ में व्यावसायिक प्रशिक्षण का अध्ययन करना था।

भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, 1983-84 की धारा 32 और 35 के अंतर्गत 11 नवंबर, 1983 से आरंभ करके दो सप्ताह तक सोवियत संघ का भ्रमण करने वाले एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में ई० वी० जी० यूनिट की रीडर डा० (श्रीमती) आशा भटनागर; क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर के रीडर डा० एम० वी० रामजी और क्षे० शि० म०, मैसूर के प्राध्यापक श्री एस० बालाकृष्णैया भी सदस्य रूप में सम्मिलित रहे और उन्होंने क्रमशः व्यावसायिक शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और विद्यालयेतर गतिविधियों का अध्ययन किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य शिक्षा संस्थान, पूणे के शैक्षिक अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष प्रो० ए० जे० पवार कर रहे थे।

प्रकाशन परिषद् की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। इसमें स्कूल स्तर की पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तकें, अध्यापक निर्देशिकाएं, शोध प्रबंध, पत्रिकाएं तथा अध्यापकों के लिए दूसरी शिक्षण सामग्री प्रकाशित की जाती है। परिषद् के प्रकाशनों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

1. स्कूल पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं और स्वीकृत सहायक पुस्तकें।
2. 14-17 वर्ष की आयुवर्ग के लिए सहायक पाठ्य सामग्री।
3. अध्यापक निर्देशिका, अध्यापक पुस्तिकाएं तथा अन्य शिक्षण सामग्री।
4. शोध अध्ययन तथा प्रबंध।
5. शिक्षा की बैठकों की रिपोर्टें तथा संगोष्ठियों की बैठकों के विवरण।
6. सूचना पैम्फलेट्स पुस्तिकाएं, परिचय पुस्तिकाएं, फोल्डर्स आदि।
7. शैक्षिक पत्रिकाएं।

इस वर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के कुल 254 प्रकाशन निकले जिन्हें नीचे दिया गया है :

प्रकाशनों की श्रेणी	कुल संख्या
प्रथम संस्करण वाली पाठ्यपुस्तकें/ स्वीकृत सहायक पुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएं	5
पाठ्यपुस्तकों/अभ्यास पुस्तिकाओं/स्वीकृत सहायक पुस्तकों का पुनर्मुद्रण	183
दूसरे सरकारी अभिकरणों के लिए पाठ्यपुस्तकें/ अभ्यास पुस्तिकाएं	10
अनुसंधान प्रबंध/रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशन	40
पत्र-पत्रिकाएं (अंकों की संख्या)	16
योग	254

इन प्रकाशनों की एक सूची इस अध्याय के अंत में दी गई है।

वितरण

पिछले वर्षों की तरह ही परिषद् के प्रकाशनों को वितरित करने और बेचने का काम सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा किया जाता रहा है। परिषद् के लिए यह राष्ट्रीय वितरक के रूप में कार्य करते हैं। नई दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पटना, लखनऊ में इनके बिक्री तथा वितरण केंद्र हैं। यहाँ से सारे देश की जरूरतों के मुताबिक वितरण का कार्य चलता है।

गत वर्षों की भाँति ही परिषद् ने अपनी पत्रिकाओं का वितरण और बिक्री कार्य स्वयं किया। उपर्युक्त बिक्री तथा वितरण व्यवस्था के अलावा देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में परिषद् ने अपनी पुस्तकों का विज्ञापन दिया। उसकी प्रतिक्रिया में विभिन्न संस्थाओं और स्कूलों से पुस्तकों की आपूर्ति के आदेश प्राप्त हुए। उनको पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति परिषद् ने स्वयं की।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 266 आदेश प्राप्त हुए तथा इनको कार्यान्वित किया गया। इसमें से 12 आदेश विद्यालयों के, 13 सैनिक स्कूलों के, 22 तिब्बती केंद्रीय विद्यालयों के तथा 190 आदेश अन्य स्कूलों के थे। इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पुस्तक विक्रेताओं के आदेश भी शामिल हैं। 29 आदेश अरुणाचल के जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के थे। सत्र 1983-84 के लिए सिक्किम के शिक्षा निदेशालय को पुस्तकें भेजी गईं। इनके अलावा 9 पाठ्य पुस्तकें—हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में, थोक में सीधे जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड को बेची गईं। ये पुस्तकें कक्षा IX-X के लिए थीं। 5 पाठ्यपुस्तकें गणित की थीं जो उड़ीसा सरकार को,

(उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिए) कक्षा XI-XII के लिए भेजी गई।

पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपने प्रकाशनों को निम्नांकित पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया —

- | | |
|--|---|
| 1. बाल पुस्तक मेला, रफी मार्ग
नई दिल्ली | (सितंबर 1983 में बाल पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित) |
| 2. हिंदी पुस्तक मेला, तृतीय
विश्व हिंदी सम्मेलन, इंद्रप्रस्थ
स्टेडियम, नई दिल्ली | (अक्टूबर 1983 में भारतीय राष्ट्रीय
पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित) |
| 3. प्रथम राष्ट्रीय बाल पुस्तक
प्रदर्शनी, कलकत्ता | (नवंबर 1983 में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक
न्यास द्वारा आयोजित) |
| 4. राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी,
लखनऊ | (नवंबर 1983, में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित) |
| 5. विद्यालय भोजन कार्यक्रम,
पोषण तथा शिक्षा पर
कार्यशाला, कोयंबतूर | (दिसंबर 1983 में यूनेस्को द्वारा आयोजित) |
| 6. राष्ट्रीय प्राइमरी शिक्षा पर
14 वां सम्मेलन, पटना | (जनवरी 1984 में राष्ट्रीय प्राइमरी शिक्षा
सम्मेलन द्वारा आयोजित) |
| 7. छठवां विश्व पुस्तक मेला,
दिल्ली | (भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा
फरवरी 1984 में आयोजित) |

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत के माध्यम से अपने चुने हुए प्रकाशनों को भेजकर परिषद् ने निम्नांकित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/पुस्तक प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया —

- | | |
|--|----------------------|
| 1. भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी, पीकिंग | अप्रैल, 1983 |
| 2. अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी, अंकारा | अप्रैल, 1983 |
| 3. पंद्रहवां सिगापुर पुस्तक समारोह,
सिगापुर | सितंबर, 1983 |
| 4. चौथा मास्को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक
मेला, मास्को | सितंबर, 1983 |
| 5. मलेशिया पुस्तक मेला, मलेशिया | सितंबर, अक्टूबर 1983 |

- | | |
|---|----------------------|
| 6. भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी,
तेहरान | सितंबर-अक्टूबर, 1983 |
| 7. पैतीसवां फ्रैंकफूर्त पुस्तक मेला,
फ्रैंकफूर्त | अक्टूबर, 1983 |
| 8. द्वितीय मध्य पूर्व पुस्तक मेला,
बहरीन | दिसंबर, 1983 |
| 9. सोलहवां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला,
कायरो | जनवरी-फरवरी, 1984 |
| 10. भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी,
रंगून | मार्च, 1984 |

बिक्री

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को अपने प्रकाशनों की बिक्री से 2, 36, 91, 292.00 रुपए प्राप्त हुए। विदेशों में भी 225.60 डालर तथा 13.15 पाउंड की बिक्री हुई। 'सभ्यता की कहानी' पुस्तक की रॉयल्टी के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को जापान की मैसर्स तीको-कू शायोन कं० लिमिटेड से अमरीकी डालर में 357.63 डालर प्राप्त हुए।

राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को प्रतिलिप्यंतरण का अधिकार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों में कई राज्य स्तर के अभिकरणों ने दिलचस्पी प्रदर्शित की। नीचे दिए गए चार्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि किस राज्याभिकरण ने रुचि दिखाई तथा उसे पुस्तक को थोड़ा बहुत परिवर्तन करके छापने का अधिकार दिया गया।

हिमाचल प्रदेश

सचिव,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,
शिमला।

'आओ पढ़ें और समझें' पुस्तक से रोगों की रोकथाम और 'धरती से चाँद तक' पाठों को उनकी रीडर 'हिम बालक माला, पुस्तक V' में शामिल करने के लिए।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,
मोपाल।

मध्य प्रदेश के कक्षा IX-X के छात्रों के लिए परिषद् की 'काव्य भारती', 'गद्य भारती' तथा 'कहानी संकलन' पुस्तकों का मुद्रण और वितरण।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक तथा
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
पुणे।

कक्षा XII की पुस्तकपालन की अभ्यास पुस्तिका को
प्रकाशन तथा वितरण का अधिकार। इसकी
पांडुलिपि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल और
मैसूर ने मिलकर तैयार की थी।

पत्रिकाएँ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की प्रकाशन गतिविधियों में पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वे काफी बड़ी संख्या में पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं— इनमें प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से लेकर शोधार्थी तक शामिल हैं। केंद्रीय स्तर पर जो शैक्षिक नीतियाँ अपनाई जाती हैं अथवा जिन नीतियों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं उनसे स्कूल से पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा प्रशासकों को 'दि प्राइमरी टीचर' (अंग्रेजी) और 'प्राइमरी शिक्षक' (हिंदी) परिचित कराते हैं। प्रारंभिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी विचारों और व्यवहारों के बारे में भी उनको इनसे सूचना मिलती है। इनसे उनको कक्षा में इस्तेमाल करने के लिए काफी सार्थक और प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध होती है। दोनों ही पत्रिकाएँ त्रैमासिक हैं।

इंडियन एजुकेशनल रिव्यू : शोधकर्ताओं, अध्येताओं, अध्यापकों तथा शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने वाले अन्य लोगों की अनुभवों के आदान-प्रदान का माध्यम प्रदान करने में तथा शिक्षा के क्षेत्र की खोजों के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण माध्यम की भूमिका अदा करती है। यह पत्रिका त्रैमासिक है।

दि जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन : यह पत्रिका अध्यापकों को, अध्यापक शिक्षकों को तथा शोधार्थियों को मंच प्रदान करती है। समसामयिक शैक्षिक दृष्टि और समस्याओं पर बहस के द्वारा शिक्षा में मौलिक और समीक्षात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। यह पत्रिका द्वैमासिक प्रकाशित होती है।

स्कूल साइंस : विज्ञान शिक्षा की यह त्रैमासिक पत्रिका है। विज्ञान शिक्षा के विविध पक्षों पर खुली बहस के लिए यह मंच का काम करती है। साइंस शिक्षा की समस्याओं, उसके भावी क्षेत्र, तथा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के व्यक्तिगत विज्ञान अनुभवों पर बातचीत का भी यह माध्यम है।

भारतीय आधुनिक शिक्षा : यह पत्रिका नई है। इसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया है। यह शिक्षाशास्त्रियों, अनुसंधाताओं तथा नीति निर्माताओं के उस तबके की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता की पूर्ति करती है जो अपना काम हिंदी माध्यम से करता है। इस पत्रिका में शोध प्रधान लेखों तथा समकालीन शैक्षिक विषयों पर लिखे गए विद्वत्तापूर्ण व्याख्याओं पर बल दिया जाता है। यह पत्रिका त्रैमासिक है तथा इसका प्रकाशन उन्हीं नियमों के तहत होता है जिन नियमों के तहत 'जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन' छपता है।

वर्तमान वर्ष के दौरान इन पत्रिकाओं में जो अंक प्रकाशित हुए हैं उनका ब्योरा नीचे दिया गया है :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. दि प्राइमरी टीचर | जुलाई 1982, अक्टूबर 1982 |
| 2. प्राइमरी शिक्षक | अप्रैल 1982, जुलाई 1982 |
| 3. जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन | नवंबर 1982, जनवरी 1983, मार्च 1983, मई 1983 और जुलाई 1983 |
| 4. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू | अप्रैल 1983, जुलाई 1983, और जनवरी 1984 |
| 5. स्कूल साइंस | मार्च 1982 जुलाई 1982, और सितंबर 1982 |
| 6. भारतीय आधुनिक शिक्षा | जुलाई 1983 |

पत्रिका कक्ष के कार्य विधि को व्यवस्थित रूप देने के लिए पिछले समय में एकत्र हुए काम को पूरा करने में मदद देने के लिए परिषद् ने कुछ ढांचागत परिवर्तन किए और पत्रिका कक्ष को स्वतःपूर्ण एकक बनाया गया। इतना ही नहीं पत्रिका कक्ष के अकादमिक तथा संपादकीय विभाग को और सुदृढ़ किया गया।

‘इंडियन एजुकेशनल रिव्यू’ ‘स्कूल साइंस’ तथा ‘जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन’ को खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली है तथा इसको चंदा भेजने वाले लोग निम्नांकित स्थानों में हैं— इंग्लैंड, कनाडा, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमरीका, थाईलैंड, बहरीन, दुबई, आमान, मलेशिया, डेनमार्क, यू० एस० एस० आर०, पश्चिमी जर्मनी, न्यूजीलैंड, इराक, कुवैत, हालैंड तथा बर्मा। ये दो पत्रिकाएँ आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, जापान और बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों को भी भेजी जाती हैं।

अगस्त 1983 में यूनेस्को के इंटरनेशनल ब्यूरो आफ एजुकेशन, जिनेवा द्वारा प्रकाशित ‘इंटरनेशनल बुलेटिन ऑफ बिब्लियोग्राफी आन एजुकेशन,’ में शामिल करने के लिए ‘इंडियन एजुकेशनल रिव्यू’ को चुना गया। लुसियाना स्टेट विश्वविद्यालय श्रेवपोर्ट (यू० एस० ए०) के निमंत्रण पर जर्नल साहित्य के प्रदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने हिस्सा लिया। नवंबर 1983 में, साउथ वेस्टर्न फिलासफी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी के 34 वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने इसका आयोजन किया था।

प्रकाशन सूची

(पत्रिकाओं को छोड़ कर)

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	प्रका० माह	प्रका० वर्ष
1	2	3	4
कक्षा I			
पाठ्यपुस्तकें			
1.	बाल भारती भाग I	(पुनर्मुद्रण)	जनवरी 1984
2.	लेट्स लर्न इंगलिश, बुक I (एस० एस०)	(पुनर्मुद्रण)	मई 1983
3.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल, बुक I	(पु० मु०)	मार्च 1984
अभ्यास पुस्तिकाएं			
4.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती, भाग I	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
5.	वर्क बुक टु लेट्स लर्न इंगलिश, बुक I (एस० एस०)	(पु० मु०)	मार्च 1984
कक्षा II			
पाठ्यपुस्तकें			
6.	बालभारती, भाग II	(पु० मु०)	मार्च 1984
7.	लेट्स लर्न इंगलिश, बुक II (एस० एस०)	(पु० मु०)	मई 1983
8.	लेट्स लर्न इंगलिश, बुक II (एस० एस०)	(पु० मु०)	जनवरी 1984
9.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल, बुक II	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
10.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल, बुक II	(पु० मु०)	जनवरी 1984
अभ्यास पुस्तिकाएं			
11.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती, भाग II	(पु० मु०)	जनवरी 1984
12.	वर्क बुक फॉर लेट्स लर्न इंगलिश, बुक II (एस० एस०)	(पु० मु०)	मार्च 1984

1	2	3	4
कक्षा III			
पाठ्यपुस्तकें			
13.	बाल भारती, भाग III	(पु० मु०)	मार्च 1984
14.	मैथेमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल्स, बुक III	(पु० मु०)	जनवरी 1984
15.	एनवायरनमेंटल स्टडीज फार क्लास III, पार्ट I	(पु० मु०)	मई 1983
16.	एनवायरनमेंट स्टडीज, फार क्लास III पार्ट I	(पु० मु०)	मार्च 1984
17.	पर्यावरण अध्ययन कक्षा III के लिए भाग I	(पु० मु०)	मार्च 1984
18.	एनवायरनमेंटल स्टडीज फार क्लास III पार्ट II	(पु० मु०)	मार्च 1984
19.	पर्यावरण विज्ञान भाग II कक्षा III के लिए	(पु० मु०)	मार्च —
अभ्यास पुस्तिका			
20.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती III	(पु० मु०)	दिसंबर 1983
कक्षा IV			
पाठ्यपुस्तकें			
21.	बाल भारती भाग IV	(पु० मु०)	मार्च 1984
22.	मैथेमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल्स, बुक IV	(पु० मु०)	मई 1983
23.	मैथेमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल्स, बुक IV	(पु० मु०)	जनवरी 1984
24.	एनवायरनमेंटल स्टडीज पार्ट I	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
25.	पर्यावरण अध्ययन भाग I	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
26.	पर्यावरण अध्ययन भाग I	(पु० मु०)	मार्च 1984
27.	पर्यावरण अध्ययन भाग II	(पु० मु०)	फरवरी 1984
अभ्यास पुस्तिकाएं			
28.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग IV	(पु० मु०)	दिसंबर 1983
29.	वर्क बुक फार इंगलिश रीडर बुक I एस० एस०	(पु० मु०)	मई 1983

पु० मु० = पुनर्मुद्रण

एस० एस० = स्पेशल सिरीज इन इंगलिश रीडर

1	2	3	4
30.	वर्क बुक फार इंगलिश रीडर बुक I (एस० एस०) (पु० मु०)	मार्च	1984

कक्षा V

पाठ्यपुस्तकें

31.	बालभारती भाग V (पु० मु०)	मार्च	1984
32.	इंगलिश रीडर बुक II (एस० एस०) (पु० मु०)	मई	1983
33.	मैथेमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल्स बुक V (प्रथम संस्करण)	जून	1983
34.	मैथेमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल्स बुक V (पु० मु०)	दिसंबर	1983
35.	सोशल स्टडीज बुक III-इंडिया एंड दि वर्ल्ड (पु० मु०)	मार्च	1984

अभ्यास पुस्तिकाएं

36.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग V (पु० मु०)	मई	1983
37.	अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग V (पु० मु०)	दिसंबर	1983
38.	अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग I (प्रथम संस्करण)	मई	1983
39.	अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
40.	वर्क बुक फार इंगलिश रीडर बुक II (एस० एस०) (पु० मु०)	मई	1983
41.	वर्क बुक फार इंगलिश रीडर बुक II (एस० एस०) (पु० मु०)	मार्च	1984

स्वीकृत सहायक पुस्तकें

42.	रीड फार प्लेजर बुक II (पु० मु०)	मार्च	1984
-----	---------------------------------	-------	------

कक्षा VI

पाठ्यपुस्तकें

43.	भारती भाग I (पु० मु०)	मई	1983
44.	स्वस्ति भाग II (पु० मु०)	मार्च	1984
45.	इंगलिश रीडर बुक III (एस० एस०) (पु० मु०)	मई	1983
46.	इंगलिश रीडर बुक III (एस० एस०) (पु० मु०)	मार्च	1984
47.	मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, बुक I (पु० मु०)	मई	1983
48.	गणित माध्यमिक स्कूलों के लिए भाग I (पु० मु०)	जनवरी	1984

1	2	3	4
49.	लैंड्स एंड पीपुल पार्ट I (पु० मु०)	जून	1983
50.	देश और उनके निवासी भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
51.	हिस्ट्री एंड सिविल्स पार्ट I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
52.	हिस्ट्री एंड सिविल्स पार्ट I (पु० मु०)	मार्च	1984
53.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
54.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
55.	लर्निंग साइंस पार्ट I (पु० मु०)	मई	1983
56.	लर्निंग साइंस पार्ट I (पु० मु०)	मार्च	1984
57.	आओ विज्ञान सीखें भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
58.	स्टेप्स टु इंगलिश I, इंगलिश रीडर फार क्लास VI (प्रथम सं०)	मई	1983

कक्षा VII

पाठ्यपुस्तकें

59.	भारती भाग II (पु० मु०)	मई	1983
60.	मैथमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, बुक II भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
61.	मैथमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, बुक II, भाग I (पु० मु०)	मई	1983
62.	मैथमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, बुक II भाग II (पु० मु०)	मार्च	1984
63.	गणित माध्यमिक स्कूलों के लिए पुस्तक II, भाग II (पु० मु०)	अप्रैल	1983
64.	हिस्ट्री एंड सिविल्स, पार्ट II (पु० मु०)	जून	1983
65.	इतिहास और नागरिक शास्त्र, भाग II (पु० मु०)	अप्रैल	1983
66.	लैंड्स एंड पीपुल भाग II (पु० मु०)	जून	1983
67.	देश और उनके निवासी, भाग II (पु० मु०)	जून	1983
68.	लर्निंग साइंस भाग II (पु० मु०)	अप्रैल	1983
69.	लर्निंग साइंस भाग II (पु० मु०)	मार्च	1984
70.	आओ विज्ञान सीखें (पु० मु०)	मई	1983

स्वीकृत सहायक पुस्तकें

71.	नया जीवन (पु० मु०)	मार्च	1984
72.	रीड फार प्लेजर, पुस्तक IV (पु० मु०)	मार्च	1984

1	2	3	4
कक्षा VIII			
पाठ्यपुस्तकें			
73.	भारती भाग III	(पु० मु०)	मई 1983
74.	स्वस्ति भाग IV	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
75.	मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, पुस्तक III, भाग I	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
76.	मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, पुस्तक III, भाग I	(पु० मु०)	मार्च 1984
77.	गणित माध्यमिक स्कूलों के लिए, पुस्तक III, भाग I	(पु० मु०)	अप्रैल 1984
78.	मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, पुस्तक III, भाग II	(पु० मु०)	मई 1983
79.	मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स, पुस्तक III, भाग II	(पु० मु०)	मार्च 1984
80.	गणित माध्यमिक स्कूलों के लिए, पुस्तक III, भाग II	(पु० मु०)	मई 1983
81.	इंगलिश रीडर बुक V (एस० एस०)	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
82.	हिस्ट्री एंड सिविल्स, भाग III	(पु० मु०)	मई 1983
83.	हिस्ट्री एंड सिविल्स भाग III	(पु० मु०)	मार्च 1984
84.	इतिहास और नागरिक शास्त्र, भाग III	(पु० मु०)	मार्च 1984
85.	लैंड एंड पीपुल, भाग III	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
86.	लैंड एंड पीपुल, भाग III	(पु० मु०)	मार्च 1984
87.	देश और उनके निवासी, भाग III	(पु० मु०)	मई 1983
88.	देश और उनके निवासी, भाग III	(पु० मु०)	मार्च 1984
89.	लर्निंग साइंस, भाग III	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
90.	आओ विज्ञान सीखें, भाग III	(पु० मु०)	मई 1983
स्वीकृत सहायक पुस्तकें			
91.	त्रिविधा	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
92.	त्रिविधा	(पु० मु०)	जनवरी 1984
93.	रीड फार प्लेजर पुस्तक V	(पु० मु०)	मई 1983

1	2	3	4
94.	रीड फोर प्लेजर पुस्तक V अभ्यास पुस्तिका	(पु० मु०) मार्च	1984
95.	अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग IV कक्षा IX पाठ्यपुस्तकें	(प्रथम संस्करण) अप्रैल	1983
96.	मैथेमेटिक्स पार्ट I (ए कोर्स)	(पु० मु०) मई	1983
97.	मैथेमेटिक्स, पार्ट I (ए कोर्स)	(पु० मु०) मार्च	1984
98.	गणित भाग I ('एक' पाठ्यक्रम)	(पु० मु०) मई	1983
99.	दि स्टोरी आफ सिविलाइजेशन वाल्यूम I	(पु० मु०) जुलाई	1983
100.	मैन एंड एनवायरनमेंट	(पु० मु०) जून	1983
101.	मनुष्य और वातावरण	(पु० मु०) अगस्त	1983
102.	साइंस, भाग I ('बी' पाठ्यक्रम)	(पु० मु०) मई	1983
	कक्षा IX-X		
103.	बी एंड अवर गवर्नमेंट	(पु० मु०) अप्रैल	1983
104.	हम और हमारा शासन	(पु० मु०) मई	1983
	कक्षा X		
105.	मैथेमेटिक्स, पार्ट II ('ए' कोर्स)	(पु० मु०) मई	1983
106.	मैथेमेटिक्स, पार्ट II ('ए' कोर्स)	(पु० मु०) मार्च	1984
107.	इंडिया आन दि मूव	(पु० मु०) मई	1983
108.	दि स्टोरी आफ सिविलाइजेशन वाल्यूम II	(पु० मु०) जुलाई	1983
109.	सभ्यता की कहानी भाग II	(पु० मु०) मई	1983
110.	सभ्यता की कहानी भाग II	(पु० मु०) मार्च	1984
111.	फिफथ स्टेप टु इंगलिश रीडर ('बी' कोर्स)	(पु० मु०) मार्च	1984
	कक्षा XI		
112.	हिंदी प्रतिनिधि एकांकी	(पु० मु०) अप्रैल	1983
113.	इंगलिश रीडर पार्ट I (कोर)	(पु० मु०) मार्च	1983
114.	इंगलिश सप्लिमेंटरी रीडर पार्ट I (कोर)	(पु० मु०) जून	1983
115.	फाइव वन ऐक्ट प्लेज	(पु० मु०) मई	1983

1	2	3	4
116.	संस्कृत भाषा एवं साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (पु० मु०)	जून	1983
117.	रंगिणी (पु० मु०)	जून	1983
118.	मैथेमेटिक्स बुक I (पु० मु०)	जून	1983
119.	गणित भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
120.	मैथेमेटिक्स बुक II (पु० मु०)	जून	1983
121.	गणित भाग II (पु० मु०)	अप्रैल	1983
122.	केमिस्ट्री भाग I (पु० मु०)	मई	1983
123.	केमिस्ट्री भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
124.	बायलोजी भाग I (पु० मु०)	मई	1983
125.	बायलोजी भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
126.	एंसिएंट इंडिया (पु० मु०)	अप्रैल	1983
127.	एंसिएंट इंडिया (पु० मु०)	मार्च	1984
128.	मेडिएल इंडिया भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
129.	मेडिएल इंडिया भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
130.	मध्यकालीन भारत भाग I (पु० मु०)	मार्च	1984
131.	फाउण्डेशंस आफ पोलिटिकल साइंस (पु० मु०)	मई	1983
132.	पोलिटिकल सिस्टम (पु० मु०)	अप्रैल	1983
133.	पोलिटिकल सिस्टम (पु० मु०)	मार्च	1983
134.	एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स (पु० मु०)	अप्रैल	1983
135.	इवोल्यूशन आफ इंडियन इकानमी (पु० मु०)	अप्रैल	1983
136.	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (पु० मु०)	मई	1983
137.	भौतिक भूगोल के आधार (पु० मु०)	मई	1983
138.	फील्ड वर्क लैबोरेटरी टेकनीक्स इन ज्याग्रफी (पु० मु०)	अप्रैल	1983
139.	ज्याग्रफी वर्क बुक (पु० मु०)	अप्रैल	1983
140.	भूगोल अभ्यास पुस्तिका (पु० मु०)	मई	1983
141.	भारत का सामान्य भूगोल भाग I (पु० मु०)	अप्रैल	1983
142.	जेनरल ज्याग्रफी आफ इंडिया पार्ट I (पु० मु०)	मई	1983
143.	साइकालोजी—एन इंट्रोडक्शन टु ह्यूमन बिहेवियर (पु० मु०)	जून	1983

(प्रथम संस्करण)

1	2	3	4
---	---	---	---

कक्षा XI-XII

144. पारिजात	(पु० मु०)	मार्च	1984
145. चयनिका	(पु० मु०)	मई	1983
146. चयनिका	(पु० मु०)	मार्च	1983
147. फिजिक्स	(पु० मु०)	अगस्त	1983
148. इंगलिश रीडर II (कोर)	(पु० मु०)	मई	1983
149. इंगलिश रीडर II (कोर)	(पु० मु०)	मार्च	1984

कक्षा XII

150. निबंध भारती	(पु० मु०)	मार्च	1983
151. विविधा	(पु० मु०)	मार्च	1984
153. इंगलिश सप्लिमेंटरी रीडर पार्ट II (कोर)	(पु० मु०)	मई	1983
154. आख्यानिका	(पु० मु०)	मई	1983
155. मैथेमेटिक्स बुक III	(पु० मु०)	मई	1983
156. गणित भाग III	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
157. मैथेमेटिक्स, बुक IV	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
158. गणित भाग IV	(पु० मु०)	मई	1983
159. मैथेमेटिक्स बुक V	(पु० मु०)	मई	1983
160. गणित भाग V	(पु० मु०)	जून	1983
161. गणित भाग V	(पु० मु०)	मार्च	1984
162. केमिस्ट्री II	(पु० मु०)	मई	1983
163. बायलोजी पार्ट II वाल्यू I	(पु० मु०)	मई	1983
164. बायलोजी पार्ट II वाल्यू II	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
165. मेडिएवल इंडिया पार्ट II	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
166. मध्यकालीन भारत भाग II	(पु० मु०)	मार्च	1984
167. माडर्न इंडिया	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
168. इंडियन कांस्टीट्यूशन एंड दि गवर्नमेंट	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
169. भारतीय संविधान और शासन	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
170. इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क	(पु० मु०)	मई	1983
171. नेशनल एकाउंटिंग	(पु० मु०)	अप्रैल	1983
172. ऐन इंट्रोडक्शन टु इकनामिक थ्योरी	(पु० मु०)	अप्रैल	1983

1	2	3	4
173.	ह्यूमन एंड इकनामिक ज्योग्राफी	(पु० मु०) अप्रैल	1983
174.	मानव व आर्थिक भूगोल	(पु० मु०) मई	1983
175.	ज्योग्राफी आफ इंडिया पार्ट II	(पु० मु०) अप्रैल	1983
176.	भारत का भूगोल भाग II	(पु० मु०) मई	1983
177.	चाइल्ड साइकालोजी	(पु० मु०) जून	1983

उर्दू पाठ्यपुस्तकें

कक्षा I

178.	रियाजी (गणित) बुक I	अप्रैल	1983
------	---------------------	--------	------

कक्षा VI

179.	हिसाब भाग I	(पु० मु०) सितंबर	1983
180.	तारीख और इल्म-इ-शहरीयत भाग I	(पु० मु०) सितंबर	1983
181.	मुमालिक और उनके वारिधे भाग I	(पु० मु०) सितंबर	1983

कक्षा VIII

182.	हिसाब (गणित) पुस्तक III, भाग I	(पु० मु०) अगस्त	1983
------	--------------------------------	-----------------	------

कक्षा IX

183.	रियाजी (गणित), भाग I	(पु० मु०) अक्टू०	1983
184.	साइंस पार्ट I ('बी' कोर्स)	(पु० मु०) जून	1983
185.	इनसान और माहौल	(पु० मु०) जुलाई	1983
186.	तहजीब की कहानी वाल्यू० I	(पु० मु०) जुलाई	1983

कक्षा IX-X

187.	हम और हमारी हुकूमत	(पु० मु०) मई	1983
------	--------------------	--------------	------

कक्षा XI

188.	क्रदीम हिंदुस्तान	(पु० मु०) जनवरी	1984
------	-------------------	-----------------	------

दूसरे राज्यों/संस्थाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएं

189.	इंगलिश रीडर बुक II फार दि ओपेन स्कूल (प्रथम संस्करण)	अप्रैल	1983
190.	अरुण भारती, भाग I	(पु० मु०) जुलाई	1983
191.	अभ्यास पुस्तिका, अरुण भारती भाग I	(पु० मु०) जुलाई	1983
192.	अरुण भारती, भाग II	(पु० मु०) अगस्त	1983

1	2	3	4
193.	अभ्यास पुस्तिका अरुण भारती भाग II	(पु० मु०)	जून 1983
194.	गद्य भारती	(पु० मु०)	मार्च 1984
195.	काव्य भारती	(पु० मु०)	मार्च 1984
196.	इंगलिश रीडर बुक VI (एस० एस०)	(पु० मु०)	अप्रैल 1983
197.	इंगलिश रीडर बुक VI (एस० एस०)	(पु० मु०)	मार्च 1984
198.	साओरा भाषा की प्रवेशिका	(प्रथम संस्करण)	जुलाई 1983

सहायक पुस्तकें

1.	थियेटर की कहानी (उर्दू)	सितंबर	1983
2.	साइंस एंड मैन	फरवरी	1984
3.	पोयम्स : सुब्रह्मण्यम् भारती		
4.	कविताएं : सुब्रह्मण्यम् भारती (हिंदी)		

शोध प्रबंध तथा अन्य प्रकाशन

1.	लर्निंग टु अर्न	अप्रैल	1983
2.	एस० यू० पी० डब्ल्यू० सोर्स बुक वाल्यू० III	अप्रैल	1983
3.	कला संबंधी व्यवसाय	अप्रैल	1983
4.	पढ़ने को कैसे सुधारें	अप्रैल	1983
5.	खेल क्षेत्र के व्यवसाय	अप्रैल	1983
6.	प्रभावकारी अध्ययन कैसे करें	मई	1983
7.	अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर कैसे रहें	मई	1983
8.	टीचर्स गाइड टु नॉन-फार्मल एजुकेशन प्रोग्राम (एजग्रुप 9-14 इयर्स)	मई	1983
9.	साइकालोजी आफ दि चाइल्ड एंड करिक्यूलम	मई	1983
10.	हमारे शिक्षक	मई	1983
11.	जीवशास्त्रीय व वनस्पतिशास्त्रीय व्यवसाय	मई	1983
12.	आडिट रिपोर्ट (1981-82)	जून	1983
13.	रिसर्च आन इक्जामिनेशंस इन इंडिया	जून	1983
14.	नेशनल सेमिनार आन पापुलेशन एजुकेशन	जुलाई	1983
15.	नेशनल बिब्लियोग्राफी आन पापुलेशन एजुकेशन	जुलाई	1983
16.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1981-82)	अगस्त	1983
17.	यूनिट टेस्ट्स इन इंगलिश फार क्लास XI	अगस्त	1983

1	2	3	4
18.	नई किरन (उर्दू प्राइमर) फार नॉन-फार्मल एजुकेशन	अगस्त	1983
19.	कारोबारी हिसाब भाग I (उर्दू) फार नॉन-फार्मल एजुकेशन	अगस्त	1983
20.	दि टीचर एंड एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी	सितंबर	1983
21.	यूनिट टेस्ट्स इन इंग्लिश फार क्लास XII	सितंबर	1983
22.	पढ़ो और बढ़ो—उर्दू प्राइमर फार ब्वायज	सितंबर	1983
23.	नई रोशनी—उर्दू प्राइमर फार गर्ल्स नॉन-फार्मल एजुकेशन	अक्टूबर	1983
24.	नई किरन—प्राइमर गाइड फार नॉन-फार्मल एजुकेशन	अक्टूबर	1983
25.	प्ले वे ऐक्टिविटीज इन प्राइमरी स्कूल्स	अक्टूबर	1983
26.	नेशनल साइंस एक्सीबिशन फार चिल्ड्रेन 1983	नवंबर	1983
27.	दि इफेक्ट आफ एनवायरनमेंटल प्रोसेस वरेएबुल्स आन स्कूल अचीवमेंट्स (5½ से 11 वर्ष के लिए) वाराणसी केंद्र की रिपोर्ट	नवंबर	1983
28.	दि स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग आफ साइंस माडल्स 1983	नवंबर	1983
29.	क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग—ए मोनोग्राफ	नवंबर	1983
30.	स्टडी आफ वर्ल्ड प्रान्बल्स इन स्कूल्स, जून 1982-मार्च 1983 इंडिया रिपोर्ट	नवंबर	1983
31.	एन० सी० ई० आर० टी० ऐनुअल रिपोर्ट 1982-83		
32.	एन० सी० ई० आर० टी० वार्षिक रिपोर्ट 1982-83		
33.	डेवलपमेंटल नार्म्स आफ इंडियन चिल्ड्रेन (2½ वर्ष-5 वर्ष) भाग IV, लैंग्वेज डेवलपमेंट	फरवरी	1984
34.	टीचिंग आफ साइंस इन सेकेण्डरी स्कूल्स	मार्च	1984
35.	एजुकेशन, सोशल वैल्यूज एंड सोशल वर्क—दि टास्क फार दि न्यू जेनेरेशन	मार्च	1984
36.	गाइडलाइन्स फार एजुकेशनल एंड साइकालोजिकल टेस्ट रिव्यूज	मार्च	1984

प्रशासन, वित्त और कल्याणकारी गतिविधियाँ

प्रशासनिक और कल्याणकारी गतिविधियाँ

रा० प्रौ० अ० और प्र० परिषद् का सचिवालय परिषद् की निश्चित नियमावलियों और कार्य-प्रणालियों के अनुसार संस्था-संचालन के अपने उत्तरदायित्व को निभाता रहा। परिषद् के विभिन्न अंगों के सक्षम और प्रभावशाली संचालन के लिए आवश्यक सहयोग उसकी ओर से मिलता रहा।

स्टाफ के कल्याण के लिए परिषद् के सचिवालय ने खेलकूद और क्रीड़ा के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन देना जारी रखा।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और रा० शि० संस्थान स्टाफ का तीसरा अंतर्महाविद्यालयी टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी, 1984 तक क्षे० शि० म०, अजमेर में आयोजित हुआ। इसमें कबड्डी, बालीबाल, टेबुल टेनिस, बास्केट बाल और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ हुईं।

चारों क्षे० शि० महाविद्यालयों और रा० शि० संस्थान की टीमों ने इसमें भाग लिया। कुल 130 से अधिक खिलाड़ी इन खेलों में उतरे। उन्होंने इनमें गहरी रुचि ली और खेल में खिलाड़ीपन की भावना का परिचय दिया। टूर्नामेंट बहुत ही सफल रहा।

परिषद् के दिल्ली स्थित कर्मचारियों की तीव्र आवश्यकताओं को देखते हुए टाइप I से V तक के 104 और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का निर्णय लिया गया। 24 दुकानों और एक पोस्ट आफिस वाले एक परिसर को भी अनुमोदित किया गया ताकि रा० शि० संस्थान परिसर के कर्मचारियों और निवासियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

रा० शि० संस्थान अतिथिशाला में 10 और कमरों के निर्माण और लिफ्ट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी कार्यों की योजनाओं और व्यय के अनुमान संबंधी वक्तव्यों को परिषद् ने अनुमोदित किया है और केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुछ राशि दी जा चुकी है।

परिषद् के प्रयासों से उसके 'बी,' 'सी' और 'डी' वर्गीय अधिकारियों के लाभ के लिए जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना 1 अप्रैल, 1982 से ही लागू हो चुकी थी। चूंकि परिषद् के 'ए' वर्गीय अधिकारियों ने अपने लिए भी ऐसी एक योजना आरंभ किये जाने का अनुरोध फिर से दुहराया था, परिषद् ने इस संबंध में जीवन बीमा निगम से बातचीत की। परिषद् के 'ए' वर्गीय अधिकारियों के लिए भी अब ऐसी ही एक योजना 1 अप्रैल, 1984 से लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के परिसर को सुंदर बनाने तथा सुधारने के लिए प्रयास किए गए। कुछ खाली भूमि पर उद्यान लगाए गए, कुछ उद्यानों का सुधार किया गया और जगह-जगह परिसर में वृक्ष लगाए गए। बच्चों के लिए एक उद्यान बनाया गया है तथा एक छोटा-सा पार्क बनाने की योजना है।

सी० पी० डब्ल्यू० डी० के उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के परिसर को दिल्ली को दूसरा सर्वोत्तम परिसर घोषित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में एक हजार और वृक्षों को लगाने की योजना है।

दिल्ली नगर निगम के सक्रिय सहयोग के कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को दो इंच का अतिरिक्त मोटा पानी का पाइप दिया गया है, इससे पीने के पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी।

सितंबर 1986 के प्रथम सप्ताह में परिषद् ने रजत जयंती समारोह आयोजित करने के लिए रूपरेखा बनाने की योजना बनाई है। इसकी विस्तृत योजना बनाने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं।

हिंदी का प्रयोग

परिषद् के हिंदी सेल ने वर्ष 1983-84 में अधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए निम्न कार्य संपन्न किये।

सामग्री की तैयारी और उसका वितरण

सेल ने निम्न पुस्तकें जुटायीं और परिषद् के विभिन्न विभागों और यूनिटों में उनको वितरित किया।

- (i) 'आधिकारिक भाषा कानून, 1963'—हिंदी और अंग्रेजी संस्करण ।
- (ii) डा० कामिल बुल्के कृत 'कांप्रेहेन्सिव इंगलिश-हिंदी डिक्शनरी' 110 प्रतियाँ ।

सर्वेक्षण

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का अधिकतम उपयोग करने वाले परिषद् के विभाग की पहचान के लिए, रनिंग शीट्स प्रदान करने के उद्देश्य से, सेल ने एक सर्वेक्षण का आयोजन किया। इस सर्वेक्षण में दो प्रश्नावलियाँ वितरित की गयीं जिनमें 22 बातों पर आवश्यक सूचना मांगी गयी थी।

सलाह और मार्गदर्शन

हिंदी में टिप्पणियाँ और पत्र लिखने, सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने और विभागीय उपकरणों को हिंदी में तैयार करने के संदर्भ में विभिन्न विभागों और प्रशासनिक प्रखंडों को सेल द्वारा सहायता और सलाह उपलब्ध करायी गयीं।

उ० प्र० सरकार द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित कुछ सामग्री का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने और हिंदी में शोध उपकरणों की तैयारी के संबंध में सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किये गये। शोध उपकरणों के अनुवाद में 65 प्रश्नों के हिंदी-अंग्रेजी तुल्य शब्दों का विकास किया गया।

आई० आई० टी० नई दिल्ली के एक छात्र को कंप्यूटर विज्ञान संबंधी कुछ अंग्रेजी शब्दों के तुल्य हिंदी शब्द निर्धारित करने में सहायता दी गयी और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली के शोध छात्रों को अनेक हिंदी शब्दों के सही हिंदी उच्चारण के संबंध में सहयोग प्रदान किया गया।

स्टाफ का चयन

परिषद् में अनुवादकों के तीन नये स्थान बनाये गये। इन स्थानों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित कार्य जारी है।

पुरस्कार-योजना

परिषद् के हिंदी का अधिकतम उपयोग करने वाली यूनिट को एक रनिंग शीट और एक प्रशंसा प्रमाण-पत्र हर वर्ष दिया जाता है। समीक्षित वर्ष में यह शीट और प्रमाण-पत्र इस्टैबलिश सेक्शन, संख्या 4 को प्रदान किये गये।

अखिल-भारतीय हिंदी टंकड़, हिंदी स्टेनोग्राफी, हिंदी लेखन (टिप्पणी) और ड्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं में, जो केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा आयोजित की जाती हैं, परिषद् के कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के मध्य संपर्क कार्यालय के रूप में भी सेल ने कार्य किया।

“शिक्षा शोध” (हिंदी) को परिषद् के तार संबंधी पते के रूप में पंजीकृत कराया गया।

परिषद् ने अपने स्टाफ से निवेदन किया है कि वे अपने कार्यों में हिंदी का अधिकतम उपयोग करें।

अधिकारिक भाषा संबंधी संसदीय समिति में जमा करने के लिए परिषद् से संबंधित सूचनाएँ एकत्र की गयीं। 26 अक्टूबर, 1983 को परिषद् के निदेशक ने ये सूचनाएँ उपरोक्त समिति को हस्तांतरित कीं।

अधिकारिक भाषा व्यवहार समिति की तीन त्रैमासिक मीटिंगें हुईं, और त्रैमासिक एवं वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये गये। 1984-85 के लिए 6 कार्यक्रम तैयार किये गये। इन कार्यक्रमों के लागू होने पर परिषद् के कर्मचारी हिंदी टंकण, हिंदी स्टेनोग्राफी और हिंदी टिप्पणी-लेखन एवं ड्राफ्टिंग में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। अंग्रेजी के शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों आदि के तुल्य हिंदी शब्दों आदि के संग्रह के लिए अलग से पुस्तकालय फाइलें होंगी। परिषद् के अंदर हिंदी में किये गये कार्य का एक सर्वेक्षण किया जायेगा ताकि उसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय (अधिकारिक भाषा विभाग) को नियमित रूप से आवश्यक सूचनाएँ भेजी जा सकें।

विस्त

लेखा संबंधी वस्तुव्य की रूपरेखा अगले पृष्ठों की तालिका में दी गयी है।

रा० श्रे० अ० और प्र० परिषद् के आय और भुगतान का संश्लेषित लेखा

आय	रकम रुपये में	भुगतान	रकम रुपये में
अथ शेष	1,00,50,354.00	अधिकारियों का वेतन	
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध	1,05,34,109.00 } 1,10,22,027.00 4,87,918.00 }
गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध	9,11,98,684.00 } 11,63,33,251.00 2,51,34,567.00 }	प्रतिष्ठान का वेतन	
		गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध	92,54,496.00 } 96,41,137.00 3,86,641.00 }
विशिष्ट अनुदानों से संबंधित अनुदान और वापसी (सूची संलग्न)	6,29,66,768.00	भत्ता और मानदेय	
गैर-योजनाबद्ध आय		गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध	2,36,85,163.00 } 2,48,68,387.00 11,83,224.00 }
परिषद् भवन का किराया ऋण/एस० टी० आई० पर व्याज अतिरिक्त भुगतान की वापसी जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ० निवेश पर प्राप्त व्याज	10,63,519.00 1,38,928.00 10,71,366.00 20,62,126.00 19,36,86,312.00	यात्रा भत्ता गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध अन्य शुल्क गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध कार्यक्रम गैर-योजनाबद्ध योजना बद्ध	10,56,378.00 } 11,11,216.00 54,838.00 } 1,27,63,673.00 } 1,34,01,999.00 6,38,326.00 }
			5,34,28,624.00 } 6,16,91,796.00 82,63,172.00 } 12,17,36,562.00

पूर्व योग	19,36,86,312-00	12,17,36,562-00
पुस्तकों व पत्रिकाओं के विक्रय से प्राप्त आय	2,36,54,346-00	छात्रवृत्ति/अध्ययन वृत्ति
विज्ञान पेटिकाओं का विक्रय	3,92,713-00	गैर-योजनाबद्ध
शुल्कादि	6,11,681-00	योजनाबद्ध
अवकाश वेतन और पेंशन-अशदान	1,43,561-00	उपकरण व फर्नीचर
रायल्टी	87,215-00	गैर योजनाबद्ध
सी० जी० एच०एस०	38,441-00	योजनाबद्ध
अन्य आय	19,82,649-00	भूमि एवं भवन
		गैर-योजनाबद्ध
		योजनाबद्ध
आय-योजनाबद्ध	30,00,000-00	अन्य भुगतान
अन्य आय	22,35,96,918-00	पेंशन एवं ग्रेच्युटी
		विज्ञापन
		सी० जी० एच० एस०
		गैर-योजनाबद्ध
		योजनाबद्ध
		भवन का किराया
		ऑडिट शुल्क
		3,82,977-00
		26,719-00
		4,09,696-00
		6,318-00
		72,710-00
		14,78,40,569-00

पूर्व योग	22,35,96,918-00	14,78,40,569-00
जी० पी० एफ० का व्याज/सी० पी० एफ० में		
परिषद का अंशदान		32,42,025-00
अवकाश-वेतन व पेंशन-योगदान		28,803-00
अवतम ऋण		15,210-00
अव्य भुगतान		
	गैर-योजनाबद्ध योजनाबद्ध	88,283-00 13,181-00
विशिष्ट अनुदानों से संबंधित व्यय		
	(सूची संलग्न) के लिए	5,09,63,713-00
मोटरकार एवं स्कूटर संबंधी अग्रिम	1,43,880-00	मोटरकार/स्कूटर के लिए अग्रिम 1,11,515-00
अन्य वाहन संबंधी अग्रिम	47,613-00	अन्य वाहनों के लिए अग्रिम 43,551-00
मकान-निर्माण संबंधी अग्रिम	12,59,454-00	मकान-निर्माण के लिए अग्रिम 31,94,055-00
पंखा संबंधी अग्रिम	(—)	पंखा के लिए अग्रिम 1,500-00
त्यौहार संबंधी अग्रिम	2,16,804-00	त्यौहार के लिए अग्रिम 2,23,332-00
यात्रा भत्ता/स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	37,289-00	यात्रा भत्ता/स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन 63,282-00
बाढ़ संबंधी अग्रिम	(—)	अन्य अग्रिम 5,000-00
गर्म वस्त्रों संबंधी अग्रिम	(—)	गर्म कपड़ों के लिए अग्रिम 1,000-00
	22,52,59,982-00	20,58,35,019-00

पूर्व योग	22,52,59,982.00	20,58,35,019.00
स्थायी अग्रिम	8,000.00 कैदीन के लिए अग्रिम राशि	6,000.00
अन्य अग्रिम राशियां	45,736.00 स्थायी अग्रिम	10,100.00
फंड व सी० डी० एस० लेखा		
सामान्य भविष्य निधि	75,20,044.00 सामान्य भविष्य निधि	48,37,151.00
संचयी भविष्य निधि	31,53,253.00 संचयी भविष्य निधि	12,68,786.00
अनिवार्य जमा योजना	1,32,459.00 अनिवार्य जमा योजना	3,02,835.00
जमा राशियां		
बयाना की राशि और एस० डी०	4,23,460.00 बयाना की राशि और एस० डी०	3,95,781.00
जमानत की राशि	87,362.00 जमानत की राशि	57,095.00
अन्य जमा राशियां	4,75,373.00 अन्य जमा राशियां	3,85,049.00
सामूहिक बीमा योजना	2,56,880.00 सामूहिक बीमा योजना	1,79,587.00
सी० पी० एफ०/जी० पी० एफ० निवेश	36,34,400.00 जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ० निवेश	
अल्पावधि निवेश	निवेश	41,21,500.00
	4,15,00,000.00 अल्पावधि निवेश	4,15,00,000.00
	जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ०	
	फंड को स्थानांतरण	41,24,000.00
उत्त	19,931.00 उत्त	95,503.00
	28,25,16,880.00	26,31,06,406.00

पूर्व योग	28,25,16,880-00	26,31,06,406 00
धनप्रेषण		
अनिवार्य जमा योजना संबंधी धनप्रेषण	5,642-00 अनिवार्य जमा योजना	
जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ० संबंधी धनप्रेषण	1,14,084-00 जी० पी० एफ०/सी० पी० एफ०	5,601-00
पी० एल० आई० संबंधी धनप्रेषण	94,183-00 पी० एल० आई० संबंधी धनप्रेषण	1,27,899-00
आयकर संबंधी धनप्रेषण	3,93,705-00 आयकर संबंधी धनप्रेषण	32,452-00
अन्य धनप्रेषण	36,735-00 अन्य धनप्रेषण	4,00,623-00
एस० ओ० धनप्रेषण	17,47,640-00 एस० ओ० धनप्रेषण	2,40,948-00
आवर्ती धनप्रेषण	10,63,58,253-00 आवर्ती धनप्रेषण	16,56,894-00
	10,64,48,253-00	10,63,58,253-00
	ट्रांजिट 90,000-00	
मृत्यु राहत कोष	34,418-00 मृत्यु राहत कोष	38,087-00
सी० टी० एस० धनप्रेषण	1,00,752-00 सी० टी० एस०	80,015-00
	39,14,02,292-00	37,20,47,178-00
	अंत बैलेंस 1,93,45,514-00	1,93,55,114-00
	ट्रांजिट 9,600-00	
		39,14,02,292-00

1983-84 की अवधि में विविध अनुदानों के आय और भुगतान का समेकित लेखा

	आय	भुगतान
1. यूनिसेफ विशेष कोष	38,86,404.93	20,82,782.36
2. पी० ई० यू० के लिए शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय		
अनुदान	1,03,00,000.00	
रिफंड	1,11,370.15	88,17,000.12
3. यूनेस्को-प्रायोगिक उपयोग पर कार्यकारी दल की मीटिंग का आयोजन, शैक्षिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए निदर्श पद्धति का इस्तेमाल (685.071) अनुदान	29,930.00	
रिफंड	8,469.00	19,000.00
4. बिना स्कूली शिक्षा या अपूर्ण स्कूली शिक्षा वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूनेस्को की संयुक्त नवाचार परियोजना	—	7,150.00
5. सामयिक विश्व समस्या संबंधी सामग्री का क्रियान्वयन और मूल्यांकन—यूनेस्को	504.00	6,634.50
रिफंड		

	आय	भुगतान
6. ए० पी० ई० आई० डी०—यूनेस्को अध्ययन दल की मीटिंग, स्कूल पूर्व शिक्षा के संबंध में, कोट नं० 118.57		
अनुदान	16,488.00	
रिफंड	6,683.38	15,800.00
7. यूनिसेफ—8 चुने हुए राज्यों में बालिकाओं के पिछड़ेपन की शिक्षा का अध्ययन		
रिफंड	1,097.75	25,532.30
8. यूनेस्को—जापानी फंड के अंतर्गत व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी परियोजना के लिए अंतर्देशीय प्रशिक्षण कार्यशाला (508.532 L)		
अनुदान	67,308.90	67,175.00
9. यूनेस्को—बैंकक में आयोजित होने वाले औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा संबंधी क्षेत्रीय सेमिनार सम्मेलन		
अनुदान	39,465.00	
रिफंड	2,073.00	32,310.94
10. यूनेस्को—ग्राफिक संचार		
500 डालर अनुदान	4,995.00	—

	आय	भुगतान
11. यूनेस्को—दोपहर का भोजन		
रिफंड		
12. यूनेस्को का विशिष्ट अनुदान—शिक्षा कार्यक्रम और पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम में और उनसे उत्पन्न लिगीय रूढ़ियों की पहचान और उनके उन्मूलन से संबंधित क्षेत्रीय मार्गदर्शिका की तैयारी (514.621)	31,306.00	42,668.90
13. यूनेस्को—दो माह की अवधि के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान के एक यूनेस्को अध्येता की व्यवस्था	15,090.00	3,664.50
अनुदान	40,000.00	
रिफंड	5,306.28	
14. यूनेस्को—पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री के सुधार संबंधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला (507.305)		
अनुदान	20,130.85	
रिफंड {	1,207.20	
	26.73	
	1,233.93	
	21,364.78	24,684.00

	आय	भुगतान
15. यूनेस्को—बांग्लादेश के लिए 15 से 21 अगस्त, 1983 तक भारत की विभिन्न संस्थाओं के भ्रमण-अध्ययन कार्यक्रम		
अनुदान	25,000.00	
रिफंड	2,560.35	5,000.00
16. यूनेस्को (1000 डालर) — देश में विज्ञान-शिक्षण के प्रति रुचि का अध्ययन		
अनुदान	10,167.75	6,850.00
17. यूनेस्को—प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा के लिए अध्यापकों और अधीक्षकों के लिए प्रायोगिक आदर्श सेवा-कालीन प्रशिक्षण की तैयारी (514.006)		
रिफंड	65.38	2,050.00
18. डा० प्रेम कासाजी, कार्य-निदेशक, आर० सी० ई० आई० एंड डी०, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू से प्राप्त विशिष्ट अनुदान		
अनुदान	932.35	932.35
19. यूनेस्को—रुश डी० अ० एवं प्र० परिषद से डा० ए० चांक्वी का संबद्धता कार्यक्रम		
अनुदान	843.90	

	आय	भुगतान
20. यूनेस्को—व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित मौलिक विज्ञानों का स्तर ऊपर उठाना—गणित में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स (507.5383)		
रिफंड	30,146.62	—
21. यूनेस्को—विज्ञान उपकरणों की रूपरेखा के निर्धारण और विकास के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम		
अनुदान	4,975.00	
रिफंड	2,684.31	4,975.00
22. यूनेस्को—जीव विज्ञान शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण गतिविधियाँ		
रिफंड	130.55	
समार्योजन अनुदान	1,604.20	
	(—) 1,473.65	9,970.00
23. यू० एन० डी० पी०—श्रीलंका में सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के संदर्भ में श्री प्रेम मित्र/श्री पी० ए० बी० पेरसा/श्री एम० पी० जेड. फ्लोडिज का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीचिंग एड्स विभाग में)		
अनुदान	35,000.00	
रिफंड	1,807.87	36,807.87
		12,911.00

	आय	भुगतान
24. यूनेस्को—भारत में सामान्य शिक्षा के कार्यानुभव का राष्ट्रीय अध्ययन	अनुदान 13,452.00	2,273.30
25. यूनेस्को—स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा संबंधी सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापकों के सेवापूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रायोगिक मॉड्यूल	अनुदान 4,975.00	—
26. सी० ई० टी० हेतु इनसेट कार्यक्रम के लिए शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय	3,82,02,000.00	3,75,36,290.20
27. सी० ई० टी० हेतु इनसेट कार्यक्रम के लिए प्राप्त	82,00,000.00	—
28. यूनेस्को—चालक परियोजना प्रायोगिकी शिक्षा	अनुदान 66,470.00	66,470.00
29. यूनेस्को—प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय अध्ययन	अनुदान 52,356.02 रिफंड 21,566.79	29,560.00

	आय	भुगतान
30. यूनेस्को—बच्चों (विशेषकर वंचित वर्गों के) की अविगम समस्या पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला		
रिफंड		
31. यूनेस्को—कार्यशाला के आयोजन के व्यय की पूर्ति	15,706.80	46,700.00
32. यूनेस्को—दो वियतनामी शिक्षकों के लिए जनसंख्या शिक्षा संबंधी संबद्धता कार्यक्रम	25,150.00	30,000.00
	2,012.00	—
33. यूनेस्को—प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों व अधीक्षकों के लिए प्रायोगिक आदर्श सेवाकालीन प्रशिक्षण. (514,000)	15,090.00	—
34. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्—डा० (श्रीमती) जीनत रबीद को भुगतान के लिए	9,100.00	5,500.00
35. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्—भारतीय शिक्षा में हुए पी-एच० डी० अनुसंधानों के सार संक्षेप के प्रकाशन के लिए	5,000.00	—
36. यूनेस्को—विशेष शिक्षा पर कार्यशाला, जापानी फंड (117,252)	26,624.06	—
अनुदान		

	आय	अनुदान
37. यूनेस्को—जीव विज्ञान शिक्षा में अध्येता के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण की गतिविधियां, मूल्यांकन में परीक्षण के लिए प्रारूपों का पुनर्स्थापन (525.039)	5,324.82	—
अनुदान		
38. यूनेस्को—बच्चों की देखरेख की शिक्षा पर आयोजित कार्य-शाला के व्यय की पूर्ति (507/352 : 3)	37,413.10	37,413.10
39. यूनेस्को—6-14/15 आयु वर्ग तक के लिए शिक्षा के सर्व-जनीकरण के अध्ययन	960.15	7,989.00
अनुदान		
40. यूनेस्को—कम लागत का अध्ययन	—	798.16
41. सामुदायिक गायन कार्यक्रम के लिए शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय से	15,63,000.00	15,63,000.00
42. शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय—ग्रामीण एवं नगरीय वातावरणों में आरंभिक स्तर के अध्यापकों का तुलनात्मक अध्ययन 10000/- + 6000/-	—	5,419.90
43. व्यावसायिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम के आयोजन हेतु शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त विशिष्ट अनुदान	—	4,19,810.73
योग	6,29,66,767.92	5,09,63,712.66

परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सहायता देने की योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षा और शैक्षिक नव परिवर्तनों के क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयासों के महत्त्व को सदैव मान्यता प्रदान की है। शैक्षिक संस्थानों एवं अध्यापकों/प्रशिक्षकों के साथ व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं का घनिष्ठ सम्पर्क, देश में शैक्षिक कार्याकल्प लाने में अच्छे उत्प्रेरक का सा काम करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शै० अ० और प्र० म० व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना पिछले अनेक वर्षों से उसी रूप में चलाती आई है जिस रूप में पहले शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ऐसी योजना चलाता था।

योजना के मुख्य विवरण, जैसे कि वे वर्तमान में कार्यान्वित हो रहे हैं, नीचे दिए जा रहे हैं—

1. उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- (i) शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए स्वयंसेवी प्रयासों को बनाए रखना और बढ़ावा देना।
- (ii) व्यावसायिक प्रकृति की अच्छे स्तर वाली ऐसी पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देना जो शैक्षिक नव परिवर्तनों को प्रसारित-प्रचारित करने में सहायक हों।
- (iii) स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा में विस्तार-कार्यों को बढ़ावा देना।

2. पात्रता की शर्तें

(क) संगठन

- (i) कोई व्यावसायिक शैक्षिक संगठन (व्या० शै० सं०) इस योजना के अंतर्गत रा० शै० अ० और प्र० म० का अनुदान पाने का पात्र तभी होगा यदि वह—

(क) संस्था पंजीकरण अधिनियम (1960 का XXI अधिनियम) के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, अथवा

(ख) आज के मान्यता प्राप्त कानून के अंतर्गत एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है, अथवा

(ग) शैक्षिक गतिविधियों को चलाने और बढ़ावा देने के कार्य में संलग्न एक प्रतिष्ठित संस्थान है।

किसी राज्य सरकार, या स्थानीय निकाय द्वारा चलाए जा रहे अथवा राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम अथवा राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव के अंतर्गत स्थापित कोई संस्था इस योजना के अंतर्गत सहायता पाने की हकदार नहीं होगी।

- (ii) उस संगठन को स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए सामान्यतः राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करना चाहिए। केवल अपवाद स्वरूप मामलों में, निधियां उपलब्ध होने पर, राज्य स्तर पर कार्यरत व्या० शै० सं० के आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
- (iii) यह योजना बिना किसी धर्म, जाति, बिरादरी, नस्ल, लिंग अथवा भाषा के भेदभाव के भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
- (iv) राज्य सरकार से अनुदान पाने के लिए जहां मान्यता आवश्यक हो वहां उस संगठन को मान्यता-प्राप्त होना चाहिए।
- (v) उस संगठन का समुचित गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए जिसके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो तथा एक लिखित संविधान के रूप में रखा गया हो।
- (vi) योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए आवेदन करने के पूर्व उसे कम से कम एक वर्ष तक सामान्यतः काम करता हुआ होना चाहिए।
- (vii) आवेदन के दिन उसकी सदस्य-संख्या कम से कम पचास होनी चाहिए।
- (viii) उसे किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए लाभ अर्जित करने वाला नहीं होना चाहिए।

(ख) कार्यकलाप

(i) सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलापों को रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी—

- (क) व्या० शै० संगठनों की वार्षिक सभाएं बंशते कि उनकी एक निश्चित विषय-वस्तु हो जो किसी राष्ट्रीय शैक्षिक समस्या से संबद्ध हो व जिससे राष्ट्रीय परिषद् को वास्ता हो और/या वह उसके कार्यों को पोषित करे और रा० शै० अनुसंधान और प्र० प० के उद्देश्यों की पूर्ति में उपयोगी हो।

- (ख) शैक्षिक साहित्य का उत्पादन जिसमें व्यावसायिक पत्रिकाएं शामिल हैं किन्तु पाठ्य सामग्री नहीं।
- (ग) ऐसी शैक्षिक प्रदर्शनियां जो शैक्षिक नव परिवर्तनों या समसामयिक विषयों पर शैक्षिक विकासों से संबद्ध हों।
- (ii) सामान्यतः नीचे लिखी बातों पर अनुदान नहीं दिए जाएंगे—
- (क) ऐसी परिचर्चाएं या कार्यगोष्ठियां जैसी रा० शै० अ० और प्र० प० प्रायः आयोजित कर सकती है या करती रहती है।
- (ख) अनुसंधान परियोजनाएं।

3. अनुदान की मात्रा

अनुदान पाने वाले संगठन पूरी तरह रा० शै० अ० और प्र० प० पर ही निर्भर न हो जाएं, इस विचार से इस योजना के अंतर्गत जो सहायता दी जाएगी वह आंशिक ही होगी, जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है—

- (i) किसी वर्ष में किसी कार्यक्रमलाप पर जो खर्च आता है उसके 60% से अधिक का सहायता अनुदान परिषद् सामान्यतः नहीं देगी।
- (ii) बाकी बच रहे खर्च का 40% संगठन को दूसरे स्रोतों से जुटाना होगा जैसे कि किसी अन्य संगठन से अनुदान प्राप्त कर या पत्रिकाओं के मामले में बिक्री, वार्षिक चंदा या विज्ञापन शुल्क से जुटाकर। हां, यदि दूसरे स्रोतों से खर्च के 40% से अधिक आय हो जाए तो परिषद् अपने हिस्से का अनुदान उसी अनुपात से घटा देगी।
- (iii) यदि किसी तरह एक वर्ष में वास्तविक खर्च के 60% से अधिक का भुगतान परिषद् की ओर से हो जाए, या अन्य स्रोत से वह कम हो—इनमें जो भी कम होगी, वह रकम अगले वर्ष के अनुदान से काट ली जाएगी अथवा समंजित कर ली जाएगी।

उदाहरण :

मान लीजिए किसी कार्यक्रमलाप पर पूरा खर्च रु० 1700 आया और रा० शै० अ० और प्र० प० का अनुदान रु० 1500 है तथा अन्य स्रोत से हुई आय रु० 900 है।

- (क) खर्च का 60% = रु० 1020
- (ख) अन्य स्रोतों की आय काट कर (1700—900) रु० 800
काटी जाने वाली राशि
- (क) और (ख) में जो कम हो उसे अनुदान की राशि में से घटाएं यथा
रु० 1500—800 = 700 रु०।

4. आवेदन करने की विधि

- (i) व्या० शै० सं० को छपे हुए फार्मों की दो प्रतिलिपियां पूरी तरह भर कर भेजी जाती हैं।
- (ii) प्रत्येक कार्यक्रम/अथवा गतिविधि के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है।
- (iii) प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजना आवश्यक है—
 - (क) संगठन-संस्थान का प्रास्पेक्टस अथवा उसकी गतिविधियों तथा उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण।
 - (ख) संगठन का संविधान।
 - (ग) अंतिम वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति।
 - (घ) यदि आवेदन किसी पत्रिका/सामग्री के प्रकाशन अनुदान के लिए है, तो पहले की छपी पत्रिका के अंकों की प्रतियां/पहले के प्रकाशन।
 - (ङ) संगठन के पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन और उसके साथ संगठन के अध्यक्ष/सचिव और लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट) आदि द्वारा हस्ताक्षरित एक उपयोग प्रमाण-पत्र।

जिन कार्यक्रमों के लिए अनुदान पहले दिया जा चुका है उसके खर्च की बाबत अलग से उसी फार्म पर एक उपयोग प्रमाण-पत्र और/अथवा खर्च का विवरण-पत्र भी भेजना चाहिए।

०० उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कोई अनुदान मंजूर नहीं होगा।

5. सामान्य

- (i) यदि अनुदान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए हो तो व्या० शै० सं० के लिए परिषद् का एक विज्ञापन निःशुल्क छापना अनिवार्य होगा।
- (ii) वार्षिक सभा/सम्मेलन के लिए अनुदान के मामले में संगठन को राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिनिधियों को सम्मेलन से संबद्ध करना होगा।
- (iii) संस्थान/संगठन को अनुदान से अर्जित पूर्ण अथवा आंशिक परिसंपत्तियों का एक लेखा-जोखा रखना होगा, इस तरह की परिसंपत्ति को रा० शै० अ० और प्र० प० की पुर्वानुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता, न ही उसे जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया था, उसके अलावा किसी और तरह से खर्च किया जा सकता है। ऐसा संस्थान/संगठन यदि किसी समय काम करना बन्द कर दे, तो उसकी वे परिसंपत्तियां रा० शै० अ० और प्र० प० के पास चली जाएंगी।
- (iv) भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जांच परीक्षण के लिए संस्थान के लेखा-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को तैयार रखना होगा।

- (v) यदि रा० शै० अ० और प्र० प० को कभी ऐसा लगे कि अनुमोदित राशि को उन कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है जिनके लिए उसे लिया गया था तो परिषद् को अधिकार होगा कि वह अनुदान देना बंद कर दे और दी गई राशि को वापस ले ले।
- (vi) रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों में संगठन को मितव्ययिता से चलना होगा।
- (vii) अनुदान के लिए आवेदन रा० शै० अ० और प्र० प० के सचिव के पास भेजना चाहिए।

विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सन् 1983-84 के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा पत्रिका-प्रकाशन के लिए दिए गए अनुदान

क्रम संख्या	संगठन का नाम-पता	पत्रिका का नाम	अनुदान राशि
1	2	3	4
1.	एस० आई० टी० यू० काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मद्रास-600028	एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन	3,000 रु०
2.	इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3, फर्स्ट ट्रस्ट लिंक स्ट्रीट, मांडवेलीपक्कम मद्रास-600028	इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग	5,000 रु०
3.	एसोसिएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथेमेटिक्स टीचिंग, 25 फर्न रोड, कलकत्ता-29	इंडियन जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स टीचिंग	4,000 रु०

1	2	3	4
4.	एसोसिएशन फॉर दि प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन, नं० 3, फर्स्ट ट्रस्ट लिंक स्ट्रीट, मांडवेलीपक्कम, मद्रास-600028	जूनियर साइंटिस्ट	4,500 रु०
5.	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रि-स्कूल एजुकेशन, लेडी इर्विन कॉलेज, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली	बालक	2,500 रु०
6.	बंगीय विज्ञान परिषद्, पी-23, आर० आर० स्ट्रीट, कलकत्ता	ज्ञान-ओ-विज्ञान	3,500 रु०
7.	इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन द्वारा टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, बंबई-400005	फिजिक्स न्यूज	5,000 रु०
8.	आल इंडिया साइंस टीचर्स एसोसिएशन द्वारा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली-110016	विज्ञान शिक्षक	1,500 रु०

**विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सन् 1983-84 के दौरान
रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा सम्मेलन आदि आयोजित करने के
लिए दिए गए अनुदान**

क्रम संख्या	संगठन का नाम-पता	उद्देश्य	अनुदान-राशि
1.	आल इंडिया सेकंडरी टीचर्स फेडरेशन, महंतपाड़ा, कटक	अखिल भारतीय सम्मेलन	4,000 रु०
2.	डा० जाकिर हुसैन एजुकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन, 7, रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली	वार्षिक सम्मेलन	5,000 रु०
3.	इंडियन एकेडमी ऑफ़ सोशल साइंसेज, 555-ई, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	आठवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस	6,000 रु०
4.	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रि- स्कूल एजुकेशन, लेडी इर्विन कालेज, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली	19 वां वार्षिक सम्मेलन	4,000 रु०
5.	इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, एस-601, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092	वार्षिक सम्मेलन	4,000 रु०
6.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ़ पब्लिक को ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवेलपमेंट, 5 सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	एफ्रो-एशियन कांफ्रेंस	5,000 रु०
7.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ एजुकेशनल प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	पांचवां कामनवेल्थ क्षेत्रीय सम्मेलन	5,000 रु०
8.	नेशनल पैरेंट टीचर्स एसो- सिएशन, नई दिल्ली	10 वां वार्षिक सम्मेलन	5,000 रु०

परिशिष्ट-ख

राज्यों में परिषद् के क्षेत्र-सलाहकारों के पते

पते	राज्य/संघ क्षेत्र
1. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), जू रोड, गौहाटी-781024	असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड
2. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), एस० आई० ई० बिल्डिंग, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम-695012	केरल लक्षद्वीप
3. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), 3-6-69/बी/7 अवन्तीनगर, बशीरबाग, हैदराबाद-500029	आंध्र प्रदेश
4. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), ए० 33, प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004	राजस्थान
5. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), एम० आई० जी० 161, ब्लाक नं० 6, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल-462017	मध्य प्रदेश
6. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), 555/ई, मसफोईगंज, इलाहाबाद-211002	उत्तर प्रदेश

7.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), होमी भाभा होस्टल, क्षे० शि० म० कैम्पस, भुवनेश्वर-751007	उड़ीसा
8.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), 621, 80 फ्रीट रोड, II ब्लॉक राजाजी नगर, बैंगलूर-560010	कर्नाटक
9.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), 1-बी, चन्द्रा कॉलोनी (समर्पण प्लैटों के पास) (लॉ कॉलेज के पीछे), अहमदाबाद-380006	गुजरात दादरा व नागर हवेली
10.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), नं० 32, हिंदी प्रचार सभा स्ट्रीट, त्यागराज नगर, मद्रास-600017	तमिलनाडु पांडिचेरी
11.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), 128/2, कोथरुड, कर्वे रोड, (भारति मंदिर बस स्टॉप के पास), पुणे-411029	महाराष्ट्र गोआ, दमन व दिउ
12.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), कंकड़ बास, पत्रकार नगर, पटना-800016	बिहार
13.	क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०), पी०-23, सी० आई० टी० रोड, स्कीम 55, कलकत्ता-700014	पश्चिमी बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिक्किम

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 14. | क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०),
मकान नं० 23, सैक्टर-8 (ए),
चंडीगढ़-190008 | पंजाब
चंडीगढ़
हरियाणा |
| 15. | क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०),
निजाम मंजिल,
शेरे कश्मीर कॉलोनी,
सैक्टर-2, क्रमर बाड़ी,
श्रीनगर-190010 | जम्मू और कश्मीर |
| 16. | क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०),
बाँयसी रोड,
डा० लैतुमछा,
शिलॉङ-795003 | त्रिपुरा
मिज़ोरम
मेघालय |
| 17. | क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०),
लक्ष्मी भवन,
संजौली चौक के पास,
शिमला। | हिमाचल प्रदेश |

परिशिष्ट-ग

समितियों की संरचना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यों की सूची
(सामान्य निकाय)

- | | |
|--|---|
| (i) मंत्री, शिक्षा मंत्रालय
अध्यक्ष—(पदेन) | 1. श्रीमती शीला कौल
राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 |
| (ii) अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग —
(पदेन) | 2. डॉ० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110001 |
| (iii) सचिव, शिक्षा मंत्रालय—
(पदेन) | 3. श्रीमती सरला श्रेवाल
सचिव, भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 |
| (iv) भारत सरकार द्वारा नामजद चार
विश्वविद्यालयों के उपकुलपति,
प्रत्येक क्षेत्र से एक | 4. प्रो० एस० हमीद
उपकुलपति
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़
5. श्री आर० के० कनबरकर
उपकुलपति
शिवाजी विश्वविद्यालय
कोल्हापुर-416004
6. प्रो० बी० एस० रामकृष्ण
उपकुलपति
हैदराबाद विश्वविद्यालय
हैदराबाद-500001 |

7. डा० बी० के० सुकुमारन नायर
उपकुलपति
केरल विश्वविद्यालय
त्रिवेन्द्रम-695001

(v) राज्य/विधानांगों वाले संघ-राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहाँ के शिक्षा-मंत्री (या उसके प्रतिनिधि) होंगे और दिल्ली के मामले में मुख्य कार्यकारी पार्षद (अथवा उसके प्रतिनिधि) होंगे।

8. शिक्षामंत्री
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद
9. शिक्षामंत्री
असम
दिसपुर
10. शिक्षामंत्री
बिहार
पटना
11. शिक्षामंत्री
गुजरात
अहमदाबाद
12. शिक्षामंत्री
हरियाणा
चंडीगढ़
13. शिक्षामंत्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला
14. शिक्षामंत्री
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर
15. शिक्षामंत्री
केरल
त्रिवेन्द्रम
16. शिक्षामंत्री
मध्य प्रदेश
भोपाल
17. शिक्षामंत्री
महाराष्ट्र
बम्बई

18. शिक्षामंत्री
मणिपुर
इम्फाल
19. शिक्षामंत्री
मेघालय
शिलाङ
20. शिक्षामंत्री
कर्नाटक
बैंगलूर
21. शिक्षामंत्री
नागालैंड
कोहिमा
22. शिक्षामंत्री
उड़ीसा
भुवनेश्वर
23. शिक्षामंत्री
राजस्थान
जयपुर
24. शिक्षामंत्री
पंजाब
चंडीगढ़
25. शिक्षामंत्री
तमिलनाडु
मद्रास
26. शिक्षामंत्री
त्रिपुरा सरकार
अगरतला
27. शिक्षामंत्री
सिक्किम
गङ्टोक
28. शिक्षामंत्री
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

29. शिक्षामंत्री
पश्चिमी बंगाल
कलकत्ता
30. मुख्य कार्यकारी पार्श्वद
दिल्ली प्रशासन
दिल्ली
31. शिक्षामंत्री
गोआ, दमन और दिउ की सरकार
पणजी (गोआ)
32. शिक्षामंत्री
मिजोरम
ऐजल
33. शिक्षामंत्री
पांडिचेरी सरकार
पांडिचेरी

(vi) कायकारी समिति के सभी सदस्य
जो ऊपर शामिल नहीं हैं।

34.
35. श्री पी० के० थुंगन
उपमंत्री, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
36. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
37. प्रो० डा० एन० वेदमणि मैनुअल
टी० सी० 15/1369
बलुतकड
त्रिवेंद्रम
38. प्रो० बी० जी० कुलकर्णी
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस
एजुकेशन, होमी भाभा रोड
बम्बई-400005

39. बी० एम० जोशी
प्रिंसिपल
श्री एम० एम० प्यूपिल्स
ओन स्कूल और शारदा मंदिर,
स्वामी विवेकानन्द मार्ग, खार
बम्बई-400052
40. श्री एम० एस० दीक्षित
प्रिंसिपल, हीरालाल बी० एन० कालेज
छिब्ररामऊ
फर्रुखाबाद
41. डॉ० टी० एन० घर
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
42. प्रो० पी० एन० दवे
सेंट्रल कोऑर्डिनेटर,
यूनिसेफ एसिस्टेड प्रोजेक्ट्स
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
43. डॉ० जे० एस० राजपूत
प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल-462013
44. डा० (श्रीमती) शकुंतला भट्टाचार्य
रीडर, विज्ञान एवं गणित
शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
45. पी० के० पटनायक
संयुक्त सचिव
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

46. श्री मनमोहन सिंह
वित्त सलाहकार
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्,
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
- (vii) (क) अध्यक्ष
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी
एजुकेशन, नई दिल्ली
(पदेन)
47. अध्यक्ष
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी
एजुकेशन, 17-बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002
- (ख) आयुक्त, के० वि० सं०
नई दिल्ली
(पदेन)
48. आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नेहरू हाउस
4, बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002
- (ग) निदेशक
के० स्वा० शि० ब्यूरो
नई दिल्ली
(पदेन)
49. निदेशक
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
- (घ) उप महानिदेशक
(कृषि शिक्षा)
भा० कृ० अ० प०
कृषि मंत्रालय
नई दिल्ली (पदेन)
50. उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
कृषि मंत्रालय
कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली-110001
- (ङ) प्रशिक्षण निदेशक
प्र० रो० म०, श्रम मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
(पदेन)
51. प्रशिक्षण निदेशक
प्रशिक्षण और रोजगार महानिदेशालय
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
- (च) प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग
योजना आयोग, नई दिल्ली
(पदेन)
52. शिक्षा सलाहकार
योजना आयोग, योजना भवन
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

- (viii) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे। इनकी संख्या 6 से अधिक नहीं होगी और इनमें से कम-से-कम 4 स्कूल अध्यापक होंगे।

53. श्री एम० रामास्वामी
हेडमास्टर, टी० वी० एस०
आयंगर हायर सेकंडरी स्कूल
मदुरै (तमिलनाडु)

54. श्री केदारनाथ सिंह
विज्ञान शिक्षक
के० के० विद्या मंदिर, धारवाड़
वैशाली (बिहार)

55. श्रीमती सलमा फिरदौस
प्रिंसिपल
हायर सेकंडरी स्कूल
कोताबी बाग
श्रीनगर

56. श्री वीरसिंह
डिवीजनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ़
एजुकेशन, जबलपुर डिवीजन
जबलपुर (मध्य प्रदेश)

57. डा० एन० के० उपासनी
अवैतनिक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
एस० एन० डी० टी० यूनिवर्सिटी
बम्बई-400020

58. डा० (कुमारी) एम० डॉली शेनॉय
1-2-212/6/1, गगन महल रोड
दुमालगुडा
हैदराबाद

(ix) विशेष आमन्त्रित

59. सेक्रेटरी
कौंसिल ऑफ़ इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट
इक्जामिनेशन, प्रगति भवन
तीसरी मंजिल
47, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली-110019

60. सचिव
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली-110016

(सचिव)

कार्यकारी समिति

- | | |
|---|--|
| <p>(i) परिषद् का अध्यक्ष जो कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।</p> | <p>1. श्रीमती शीला कौल
राज्यमंत्री
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001</p> |
| <p>(ii) (अ) शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री जो कार्यकारी समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा।</p> | |
| <p>(आ) शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—
रा० शै० अ० और प्र० प०
के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत</p> | <p>2. श्री पी० के० शुंगत
शिक्षा उपमंत्री, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001</p> |
| <p>(इ) परिषद् के निदेशक</p> | <p>3. डा० पी० एल० मल्होत्रा (निदेशक)
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली-110016</p> |
| <p>(ई) सचिव, शिक्षा मंत्रालय—
पदेन</p> | <p>4. श्रीमती सरला ग्रेवाल
सचिव, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
(2-11-1982 से)</p> |
| <p>(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के अध्यक्ष (पदेन सदस्य)</p> | <p>5. श्रीमती माधुरी आर० शाह
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110001</p> |

(iv) रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा-विद जो स्कूल शिक्षा में विशेष रुचि रखते हों, तथा जिनमें से दो स्कूल अध्यापक होंगे।

6. प्रो० बी० जी० कुलकर्णी
प्रोजेक्ट डायरेक्टर
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर
साइंस एजुकेशन, भाभा रोड
बम्बई-400005

7. डा० एन० वेदमणि मैनुअल
टी० सी० 15/1369
वलुतकड
त्रिवेंद्रम

8. श्री बी० एम० जोशी
प्रिंसिपल, श्री एम० एम० प्यूपिल्स
ओन स्कूल और शारदा मंदिर
स्वामी विवेकानन्द रोड, खार
बम्बई-400005

9. श्री एम० एस० दीक्षित, प्रिंसिपल
हीरालाल बी० एन० कालेज
छिबरामऊ, फर्रुखाबाद

(v) परिषद् के संयुक्त निदेशक

10. डा० टी० एन० धर
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

(vi) रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामजद परिषद् की संकाय के तीन सदस्य जिनमें से कम से कम दो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के होंगे।

11. प्रो० पी० एन० दवे
सेंट्रल कोऑर्डिनेटर
यूनिसेफ एसिस्टेड प्रोजेक्ट्स
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

12. डा० जे० एस० राजपूत
प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल-462013

13. डा० (श्रीमती) शकुंतला भट्टाचार्य
रीडर, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
- (vii) शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि
14. संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा)
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
- (viii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
जो परिषद् का वित्त सलाहकार
होगा।
15. श्री मनमोहन सिंह
वित्त सलाहकार
रा० शै० अ० और प्र० प०
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
16. सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

संस्थापन समिति

- (i) निदेशक, रा० शै० अ० और
प्र० प०
(अध्यक्ष)
1. डा० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016
(अध्यक्ष)
- (ii) संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ०
और प्र० प०
2. डा० टी० एन० धर
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

- (iii) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
- (iv) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षाविद जिनमें से कम से कम एक वैज्ञानिक होगा
- (v) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का एक प्रतिनिधि
- (vi) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
- (vii) परिषद् के नियमित शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में से एक-एक (कुल दो) प्रतिनिधि
3. श्री वाइ० एन० चतुर्वेदी
संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा)
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
4. डा० एच० सी० खरे
गणित विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद-211002
5. प्रो० एम० एम० पुरी
राजनीतिक विज्ञान विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़-160014
6. प्रो० एस० आनंद लक्ष्मी
निदेशक, लेडी इर्विन
कालेज, सिकंदरा रोड
नई दिल्ली
7. प्रो० एम० आई० सभादत्ती
भौतिकी विभाग
कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़-580003
8. डा० एस० एन० दत्ता
प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा
महाविद्यालय, अजमेर
9. श्री एस० एच० खात
रीडर, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली-110016
10. श्री आर० पी० सबसेना
लेक्चरर
क्षे० शि० म०, भोपाल
11. श्री प्रबोध कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
सा० वि० एवं मा० शि० वि०
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली-110016

(viii) वित्त सलाहकार, रा० शै० अ०
और प्र० प०

12. श्री मनमोहन सिंह
वित्त सलाहकार
रा० शै० अ० और प्र० प०
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

(ix) सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प०
(सदस्य-संयोजक)

13. श्री सी० रामचंद्रन
सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (सदस्य-संयोजक)

वित्त समिति

1. डा० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

(पदेन अध्यक्ष)

4. श्री जे० बीर राघवन
शिक्षा सलाहकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

2. श्री मनमोहन सिंह
वित्त सलाहकार
रा० शै० अ० और प्र० प०
शिक्षा मंत्रालय
कमरा नं० 109 'सी', शास्त्री भवन
नई दिल्ली

(पदेन सदस्य)

5. डा० पी० सी० मुखर्जी
प्रो० वाइस चांसलर
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

3. श्री पी० के० पटनायक
संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा)
शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

6. श्री सी० रामचंद्रन
सचिव
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (संयोजक)

भवन तथा निर्माण समिति

- | | |
|---|---|
| (i) निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०
(पदेन अध्यक्ष) | 1. डा० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (अध्यक्ष) |
| (ii) संयुक्त निदेशक
रा० शै० अ० और प्र० प०
(पदेन उपाध्यक्ष) | 2. डा० टी० एन० धर
संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (उपाध्यक्ष) |
| (iii) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण
विभाग अथवा उसके द्वारा
मनोनीत व्यक्ति | 3. श्री एम० एल० कालरा
सुपरिटेन्डिंग सर्वेयर ऑफ वर्क्स
(फूड), सी० पी० डब्ल्यू० डी०
इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली |
| (iv) वित्त मंत्रालय (वर्क्स) का एक
प्रतिनिधि | 4. श्री ए० के० सक्सेना
सहायक वित्त सलाहकार
(वर्क्स)
निर्माण भवन (III मंजिल)
नई दिल्ली |
| (v) परिषद् का परामर्शी वास्तुक | 5. श्री आइ० डी० रस्तोगी
ज्येष्ठ वास्तुक
के० लो० नि० विभाग, निर्माण भवन
नई दिल्ली |
| (vi) परिषद् का वित्त सलाहकार अथवा
उत्तरे द्वारा मनोनीत व्यक्ति | 6. श्री मनमोहन सिंह
वित्त सलाहकार, रा० शै० अ० और
प्र० प०, कमरा नं० 109 'सी'
शास्त्री भवन, नई दिल्ली |
| (vii) शिक्षा मंत्रालय
द्वारा मनोनीत व्यक्ति | 7. संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली |
| (viii) कोई प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) | 8. श्री आर० ए० खेमानी
मुख्य इंजीनियर
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास भवन एनेक्सी
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली |

(ix) कोई प्रतिष्ठित बिजली इंजीनियर
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)

(x) समिति द्वारा मनोनीत
कार्यकारी समिति का सदस्य

(xi) सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प०
(सदस्य सचिव)

9. श्री टी० कृष्णमूर्ति
सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर
दिल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिक सर्किल-1
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
इंद्रप्रस्थ भवन, इंद्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली

10. श्री एस० एच० खान
रीडर, पी० सी० डी० सी०
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

11. सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य सचिव)

कार्यक्रम सलाहकार समिति

1. डा० पी० एल० मल्होत्रा
निदेशक, रा० शै० अ०
और प्र० प०
नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. डा० टी० एन० घर
सह निदेशक, रा० शै० अ०
और प्र० प०
नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)

3. प्रो० सी० एल० कुंडू
शिक्षा विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
कुरुक्षेत्र

4. प्रो० एन० मल्ल रेड्डी
शिक्षा विभाग
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

5. प्रो० (श्रीमती) विमल अग्रवाल
शिक्षा विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

6. प्रो० एस० नारायण राव
मनोविज्ञान विभाग
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति

7. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
महेन्द्र, पटना

8. निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
सोलन
(हि० प्र०),

9. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, मेघालय
शिलाङ्ग
10. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
उदयपुर
11. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
6, डी० पी० आई० कंपाउंड
कालेज रोड
मद्रास
12. अध्यक्ष
मापन और मूल्यांकन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
13. अध्यक्ष
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
14. अध्यक्ष
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी
शिक्षा विभाग, रा० शै० अ०
और प्र० प०, नई दिल्ली
15. अध्यक्ष
अध्यापक-शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
16. अध्यक्ष
वर्कशॉप विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
17. अध्यक्ष
प्रकाशन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
18. अध्यक्ष
शिक्षण साधन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
19. अध्यक्ष
प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम वर्ग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
20. अध्यक्ष
पाठ्यक्रम वर्ग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
21. अध्यक्ष
अनौपचारिक शिक्षा वर्ग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
22. अध्यक्ष
शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन
एकक, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
23. अध्यक्ष
शिशु अध्ययन एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
24. अध्यक्ष
शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

25. अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
शिक्षा एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
26. अध्यक्ष
स्त्री शिक्षा एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
27. अध्यक्ष
जनसंख्या शिक्षा एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
28. अध्यक्ष
विस्तार एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
29. अध्यक्ष
योजना, समन्वय और मूल्यांकन
एकक, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
30. अध्यक्ष
शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
31. अध्यक्ष
सर्वेक्षण और आधार सामग्री प्रक्रिया
एकक, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
32. अध्यक्ष
पुस्तकालय और प्रलेखन एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
33. अध्यक्ष
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
34. अध्यक्ष
प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
35. अध्यक्ष
पत्रिका प्रकोष्ठ
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
36. प्रिंसिपल
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
37. प्रो० के० एन० सक्सेना
अध्यापक शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
38. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
39. प्रो० (श्रीमती) स्नेहलता शुक्ल
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
40. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
अजमेर

- | | |
|---|---|
| <p>41. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर</p> <p>42. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल</p> <p>43. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर-570006</p> <p>44. प्रो० ए० एन० माहेश्वरी
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर-570006</p> <p>45. प्रो० अनिल विद्यालंकार
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी
शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली</p> | <p>46. श्री तिलकराज
रीडर
शिक्षण साधन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली</p> <p>47. प्रो० के० सी० पंडा
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर-571007</p> <p>48. प्रो० एस० टी० वी० गोविंद आचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल</p> <p>49. प्रो० एन० वैद्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
अजमेर-305001</p> <p>50. डा० के० वी० राव
सापन एवं मूल्यांकन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली</p> |
|---|---|

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

- | | |
|---|----------------|
| <p>1. निदेशक, सहनिदेशक</p> <p>2. डीन (अनुसंधान)</p> <p>3. डीन (शैक्षणिक)</p> <p>4. डीन (समन्वय)</p> <p>5. सदस्य सचिव, शै० अ० और न० स०</p> <p>6. रा० शि० सं० के सभी विभागों के अध्यक्ष</p> <p>7. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के प्रिंसिपल</p> <p>8. रा० शै० अ० और प्र० प० के निदेशक द्वारा नामजद राज्य शिक्षा संस्थानों के दो व्यक्ति :</p> | <p>संरक्षक</p> |
|---|----------------|

(i) निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

आलिया प्राइमरी स्कूल, आंध्र स्पोर्ट्स काउंसिल के सामने, हैदराबाद-500001

(ii) प्रिंसिपल

राज्य शिक्षा संस्थान

जोरहट

असम

9. रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामजद विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों के आठ व्यक्ति :

(i) डा० पार्थ मुखर्जी

प्रो० आई० एस० आई०

सनसनवाल मार्ग

नई दिल्ली-110016

(ii) डा० टी० वी० नाइफ

निदेशक

जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान

गुजरात विद्यापीठ

अहमदाबाद

(iii) प्रो० ए० एल० नागर

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

(iv) प्रो० आगा अशरफ अली,

डीन और अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

(v) प्रो० (श्रीमती) विमल अग्रवाल

प्रो० अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ

(vi) डा० आर० श्रीनिवासन

प्रोफेसर, शिक्षा विभाग

लक्ष्मी शिक्षा महाविद्यालय, गांधी ग्राम

भदुरै

(vii) डा० बी० के० राय बर्मन
वरिष्ठ प्रोफेसर
सामाजिक विकास अनुसंधान परिषद्
53, लोदी इस्टेट
नई दिल्ली-110003

(viii) प्रो० बी० आर० कांबले
अध्यक्ष, इतिहास विभाग
शिवाजी विश्वविद्यालय
कोल्हापुर

10. स्थायी आमंत्रित—रा० शै० अ० और प्र० प० के निदेशक द्वारा नामजद
10 प्रोफेसर।

पर्यावरणीय शिक्षा के लिए सलाहकार समिति

1. अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग एवं प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
2. अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग तथा जनसंख्या शिक्षा एकक
3. अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक
4. अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
5. अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम वर्ग
6. अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक
7. अध्यक्ष, योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक
8. अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
9. अध्यक्ष, शिक्षण साधन विभाग
10. अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग
11. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर या उनके प्रतिनिधि
12. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर या उनके प्रतिनिधि
13. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल या उनके प्रतिनिधि
14. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर या उनके प्रतिनिधि
15. डा० एम० एस० खापर्डे, रीडर (कार्यक्रम)
16. श्री गोपबन्धु गुरु
रीडर, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक

17. डा० बृजेश दत्त आत्रेय
रीडर, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग
18. डा० उत्पल मलिक
परियोजना समन्वयक, यूनिसेफ परियोजना (स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरणीय स्वच्छता) विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग
19. अध्यक्ष, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (संयोजक)

पुस्तकालय सलाहकार समिति

1. प्रो० बी० एस० पारख, डीन (शैक्षणिक) (अध्यक्ष)
2. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन (सदस्य)
विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग
3. प्रो० पी० एन० दबे (सदस्य)
अध्यक्ष, केप वर्ग
4. प्रो० अनिल विद्यालंकार (सदस्य)
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
5. प्रो० चौधरी हेमकांत मिश्र (सदस्य)
सदस्य-सचिव, एरिक
6. प्रो० (श्रीमती) स्नेहलता शुक्ल (सदस्य)
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
7. डा० (कुमारी) सरोजिनी बिसारिया (सदस्य)
अध्यक्ष, स्त्री शिक्षा एकक
8. डा० एम० एस० खापर्डे (सदस्य)
रीडर (कार्यक्रम)
9. प्रोफेशनल सीनियर (सदस्य)
लाइब्रेरी एंड डाक्यूमेंटेशन यूनिट
10. लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि (सदस्य)
11. अध्यक्ष, लाइब्रेरी एंड डाक्यूमेंटेशन यूनिट (संयोजक)

समन्वय-समितियाँ

1. पाठ्यक्रम-विकास के लिए समन्वय-समिति

- (क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
- (ख) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
- (ग) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक
- (घ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग
- (ङ) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग
- (च) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
- (छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
- (ज) अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक
- (झ) प्रो० अनिल विद्यालंकार
- (ञ) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
- (ट) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग (संयोजक)
- (ठ) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपल अथवा उनके प्रतिनिधि

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए समन्वय-समिति

- (क) अध्यक्ष, शिक्षण-साधन विभाग
- (ख) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
- (ग) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
- (घ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग
- (ङ) अध्यक्ष, विस्तार एकक; राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रगति से संबद्ध क्षेत्र सलाहकार
- (च) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
- (छ) प्रिंसिपल शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (संयोजक)
- (ज) प्रो० (श्रीमती) स्नेहलता शुक्ल
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (झ) क्षेत्रीय शिक्षा म० के प्रिंसिपल अथवा उनके प्रतिनिधि

3. अनौपचारिक शिक्षा के लिए समन्वय क्रिया समिति

- (क) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग
- (ख) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
- (ग) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
- (घ) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक
- (ङ) अध्यक्ष, विस्तार एकक
- (च) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग
- (छ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग
- (ज) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
- (झ) श्री ए० ए० सी० लाल
- (ञ) प्रो० कृष्ण गोपाल रस्तोगी (संयोजक)
- (ट) क्षे० शि० म० के प्रिंसिपल अथवा उनके प्रतिनिधि
- (ठ) सा० वि० एवं मा० शि० वि० के अध्यक्ष
- (ड) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के प्रिंसिपल
- (ढ) अध्यक्ष, अ० शि० वि०
- (ण) अध्यक्ष, शि० सा० वि०।

4. मापन और मूल्यांकन के लिए समन्वय-समिति

- (क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
- (ख) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
- (ग) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग
- (घ) अध्यक्ष, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
- (ङ) अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
- (च) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम वर्ग
- (छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
- (ज) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग
- (झ) अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक
- (ञ) प्रो० श्रीमती स्नेहलता शुक्ल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (ट) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
- (ठ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग (संयोजक)
- (ड) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपल अथवा उनके प्रतिनिधि

5. अध्यापक-शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों के लिए समन्वय-समिति

- (क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
- (ख) अध्यक्ष, शिक्षण-साधन विभाग
- (ग) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम वर्ग
- (घ) अध्यक्ष, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
- (ङ) अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक
- (च) प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र
- (छ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग
- (ज) अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
- (झ) अध्यक्ष, योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक
- (ञ) अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक
- (ट) रीडर (कार्यक्रम)
- (ठ) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
- (ड) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
- (ढ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग (संयोजक)
- (ण) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपल अथवा उनके प्रतिनिधि।

‘स्कूल साइंस’ पत्रिका की सलाहकार समिति

- | | |
|---|--|
| 1. प्रो० बी० एन० उडगांवकर
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा रोड
बंबई (अध्यक्ष) | 4. प्रो० पी० टी० नरसिंहन
रसायन विभाग, आई० आई० टी०
कानपुर (सदस्य) |
| 2. प्रो० जी० एन० रामचंद्रन,
एफ० आर० एस०, इंडियन
इंस्टीच्यूट आफ साइंस
बंगलूर (सदस्य) | 5. प्रो० यू० एन० सिंह, वाइस चांसलर
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (सदस्य) |
| 3. प्रो० (श्रीमती) अर्चना शर्मा
वनस्पति शास्त्र विभाग
कलकत्ता विश्वविद्यालय
कलकत्ता (सदस्य) | 6. प्रो० सी० एल० आनंद
नार्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी
शिलाङ (सदस्य) |

7. डा० आर० जी० लागू
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, होमी भाभा
सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा रोड
बंबई (सदस्य)
8. श्री० एस० पी० अंकुष
सम्पादक, 'साइंस रिपोर्टर'
सी० एस० आई० आर०
नई दिल्ली (सदस्य)
9. श्री समरजित कर
सहायक संपादक 'साइंस कल्चर'
92 आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय रोड
कलकत्ता (सदस्य)
10. श्री जे० सी० डैनियल
संपादक, जर्नल ऑफ बायो नेचुरल
हिस्ट्री सोसायटी, हर्नबिल हाउस
शहीद भगतसिंह रोड
बंबई (सदस्य)
11. प्रो० ए० एन० बोस
डीन (समन्वय)
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)
12. अध्यक्ष
पत्रिका प्रकोष्ठ
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)
13. अध्यक्ष
प्रकाशन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)
14. अध्यक्ष
वि० एवं ग० शि० वि०
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)
15. डा० एम० एस० खापर्डे
रीडर (कार्यक्रम)
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)
16. डी० लाहिड़ी
रीडर, विज्ञान एवं गणित शिक्षा
विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली (सदस्य)

परिशिष्ट-घ

समितियों द्वारा 1983-84 के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय

कार्यकारिणी समिति (2 जुलाई, तथा 22 नवंबर, 1983)

परिषद् की साठवीं तथा इकसठवीं कार्यकारिणी समिति की बैठकें क्रमशः 2 जुलाई और 22 नवंबर, 1983 को हुईं।

नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों पर चर्चा के दौरान, निदेशक महोदय ने समिति को बताया कि नैतिक शिक्षा पर काम को निपटाने के लिए एक छोटा-सा दल गठित किया जा चुका है। इस दल में डा० आर० एम० कालरा, प्रोफेसर शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, डॉ० शेशाद्रि, प्रोफेसर, शिक्षा, आर० सी० ई०, मैसूर; तथा डा० एस० टी० वी० जी० आचार्यलु, रीडर, आर० सी० ई०, भुवनेश्वर भी शामिल हैं। नैतिक शिक्षा पर पुस्तकें तैयार करने का कार्य इनको सौंपा जाएगा। यह कार्य 'इंडियन काउंसिल फॉर फिलासोफिकल रिसर्च' के सहयोग से किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि हर हालत में छः महीनों के भीतर यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए।

समिति ने निर्णय लिया कि 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज' नाम की छात्रवृत्तियों की संख्या 550 से बढ़कर 750 की जानी चाहिए तथा इसको 1983 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों से लागू किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्तियों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए।

पांच पुस्तकों की कीमतें कम की गई हैं इसकी समिति ने सराहना की, किंतु इसने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की मूल्य पद्धति की गंभीर समीक्षा का सुझाव दिया। कार्यकारिणी समिति ने मूल्य नीति की समीक्षा के बाद मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को अधिकार दिया।

परिषद् में वर्तमान समय में प्रचलित श्रेणी तथा प्रोन्नति नीति की समीक्षा के लिए बनी 'एक व्यक्ति' समिति की रिपोर्ट पर कार्यकारिणी ने विचार किया तथा स्टैगनेशन को दूर करने के लिए (गैर अकादमिक कर्मचारी वर्ग स और द के, जिसमें भावी पदों के लिए चयन-पद भी शामिल हैं जो एक ही ग्रेड में 14 वर्ष सेवा कर चुके हैं) तथा उनके लिए विशेष इनक्रीमेंट की स्वीकृति मिली जो अधिकतम वेतनमान पर पिछले दो वर्षों से रुके हुए हैं।

कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि गैर अकादमिक सदस्यों के लिए परिषद् केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारी पैटर्न का अनुसरण करती है, इसलिए सुपरिटेण्डेंट/स्पेशल

असिस्टेंट के पदों को विभिन्न चरणों में एस० ओ०/ए० पी० सी० में बदल दिया जाए।

कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू होने वाली यू० जी० सी० की अकादमिक स्टाफ की मेरिट प्रमोशन योजना को परिषद् के अकादमिक कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत होने वाले लाभ 1 जनवरी 1983 से लागू माना जाएगा। इस योजना के लागू करने में आर० सी० ई० को शामिल करके परिषद् के सभी अकादमिक कर्मचारी एक इकाई के रूप में समझे जाएंगे।

कार्यकारिणी ने एक वर्ष में अकादमिक स्टाफ के लिए अधिकतम 15 दिनों के अकादमिक अवकाश की स्वीकृति दी। विशेष परिस्थिति में निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह 5 दिन का वर्ष में अतिरिक्त अवकाश इसके लिए स्वीकृत करें।

कार्यकारिणी ने स्वीकृति दी कि 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज' के डिग्री के दूसरे स्तर के मेडिसिन तथा इंजिनियरिंग के छात्रों को रु० 400 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा सकती है।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन कार्यक्रम की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कार्यकारिणी समिति ने महसूस किया कि सभी राज्यों में काम को निपटाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। यह तय किया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर, इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए तथा यह राज्य सरकारों द्वारा समीक्षित पाठ्यपुस्तकों पर पुनः दृष्टिपात करें।

वित्त समिति (21 जुलाई तथा 18 नवंबर, 1983)

वित्त समिति की साठवीं तथा इकसठवीं बैठकें क्रमशः 21 जुलाई और 18 नवंबर 1983 को हुईं।

समिति ने सलाह दी कि आंतरिक लेखा परीक्षण को सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए तथा इसे पूरा करने के लिए परवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। समिति की यह इच्छा थी कि इस प्रकार की प्रगति रिपोर्टें समिति को समय-समय पर भविष्य में भी भेजी जानी चाहिए।

समिति का यह निर्णय था कि क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में स्वास्थ्य अधिकारी के पद को सी० जी० एच० एस० के प्रथम श्रेणी कनिष्ठ के समकक्ष माना जाना चाहिए तथा जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर यहां भेजे जाते हैं, उनका अपना वेतनमान उन्हें मिलना चाहिए तथा इसके साथ प्रतिनियुक्ति भत्ता भी जो नियमों के तहत स्वीकृत है दिया जाना चाहिए।

'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा' को परिचालित करने के लिए समिति ने पारिश्रमिक की संशोधित दरें स्वीकार कर लीं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान को वित्त समिति ने स्वीकृति दे दी। इसका ढांचा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिए जाने वाले वेतनमान जैसा होगा तथा यह 1 अप्रैल 1980 से लागू समझा जाएगा। इसमें शर्त यह होगी कि सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा जिसमें योग्यताएँ तथा नियुक्ति शर्तें मुख्य होंगी।

एक गोदाम के निर्माण के प्रस्ताव को वित्त समिति ने स्वीकृति दी जिसका आधार क्षेत्र 1,35,000 वर्ग फीट होगा तथा इसको विविध चरणों में बनाया जाएगा तथा इसकी लागत लगभग रु० 2,21,79,000 होगी। प्रथम चरण में बनने वाले गोदाम का अनुमानित क्षेत्र 90,000 वर्ग फीट होगा, इसकी लागत 1,47,80,000 बैठेगी। इसका निर्माण-कार्य सुविधानुसार तथा कोष की उपलब्धता को देखकर आरंभ किया जाएगा।

समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि परिषद् की आमद को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए, विशेष रूप से इसकी पाठ्यपुस्तकों तथा इसके प्रकाशनों की बिक्री द्वारा। पाठ्यपुस्तकों की बिक्री के लिए अधिक स्रोत तलाशने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों से संबद्ध डी० एम० स्कूलों में 650-1200 के वेतनमान के प्रधानाचार्यों के पद बनाने के प्रस्ताव को समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

विभिन्न श्रेणियों के कलाकारों, कलाकर्मियों, लेखकों, समीक्षकों, तकनीकी तथा उत्पादन क्रिड तथा अन्य दूरदर्शन माध्यम और दूसरे व्यक्तियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक/मानदेय के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जिनकी सेवाओं का इस्तेमाल शिक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के बनाने में किया जाता है।

एक बड़े सभा कक्ष के निर्माण के प्रस्ताव को भी समिति ने स्वीकृति दे दी जिसमें 100 से 120 तक की संख्या में लोग बैठ सकें। फिर भी इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिया गया कि इसके लिए धन की व्यवस्था बजट में बचत करके की जानी चाहिए।

संस्थापन समिति (13 मई, 1983 तथा 18 मार्च, 1984)

संस्थापन समिति की पंद्रहवीं तथा सोलहवीं बैठकें क्रमशः 13 मई 1983, तथा 18 मार्च 1984 को हुईं।

संस्थापन समिति ने यह सिफारिश पेश की कि मेरिट प्रमोशन स्कीम को एन० सी० ई० आर० टी० के अकादमिक स्टाफ पर लागू किया जा सकता है जिसे दिल्ली के तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए स्वीकार किया जा चुका है।

संस्थापन समिति ने सिफारिश की कि व्याख्याताओं के वेतनमान का मूल्यांकन स्तर समाप्त किया जाना चाहिए।

समिति ने यह प्रस्ताव मान लिया कि निदेशक के निजी सचिव का पद विशेष सहायक ग्रेड I के समतुल्य है (जिसे सहायक कार्यक्रम संयोजक कहा जाता है)।

समिति ने इस बात की सिफारिश की कि अध्ययन अवकाश के जो नियम अकादमिक कर्मचारियों पर लागू होता है उसे परिषद् के वरिष्ठ तथा कनिष्ठ पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

समिति ने द्वारपाल तथा मुख्य चौकीदार के लिए विशेष वेतन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

भवन तथा कार्य समिति (30 जुलाई, 1983)

भवन तथा कार्य समिति की बैठक 30 जुलाई 1983 को हुई। निम्नलिखित प्रस्तावों

को समिति ने स्वीकृति प्रदान की—

1. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर तथा भोपाल के पुस्तकालय भवनों का विस्तार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में कार्यशाला विभाग की गाड़ियों के लिए एक शेड का निर्माण।
3. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अतिथि-गृह के पांचों मंजिलों पर एक लिफ्ट और दो कमरों की व्यवस्था करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में 104 आवासों का निर्माण करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में एक नलकूप लगवाना।
6. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल के महिला छात्रावास का विस्तार।
7. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान परिसर में एक सुविधाजनक विपणन केंद्र तथा एक कम्प्यूनिटी हाल का निर्माण।
8. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में 10 बी टाइप भवन तथा 10 सी टाइप भवनों का निर्माण।
9. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल के कीर्ति निकेतन छात्रावास के प्रसाधन ब्लाक का पुर्ननिर्माण।

समिति ने यह सुझाव दिया कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के क्षेत्र अधिकारियों को एक महीने में एक बार इन भवनों की जांच अवश्य करनी चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सामान्य निकाय की बैठक (23 दिसंबर 1983)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सामान्य निकाय की बीसवीं बैठक 23 दिसंबर 1983 को हुई जिसकी अध्यक्षता राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती शीला कौल ने की जो परिषद् की अध्यक्ष भी हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की अध्यक्षा ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि यद्यपि शिक्षा में काफी प्रगति हो चुकी है फिर भी शैक्षिक विकास का प्राथमिकता का कार्य सभी अभिकरणों के अथक और सतत प्रयास के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। विशेष रूप से राज्य सरकारों के सहयोग के बगैर जिनकी स्कूल शिक्षा में कार्यक्रम को लागू करने की आरंभिक जिम्मेदारी थी। मंत्री महोदया का सुभाव था कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य-पुस्तकें तथा दूसरे प्रकार की शैक्षिक सामग्री के विकास में राज्य परिषद् द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि परिषद् सामुदायिक गीतों के कार्यान्वयन में भी लगी हुई है जिसे राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण वाहक पाया गया है। इस कार्य का समारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अध्यक्ष महोदया ने शिक्षा के मूल्याभि-विन्यास के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया तथा इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इससंदर्भ में जिस कार्य को परिषद् ने आरंभ किया था वह बहुत ही सुदृढ़ गति से आगे बढ़ रहा

है। 'शिक्षा और मूल्य' पर परिषद् द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष डॉ० दौलत सिंह कोठारी हैं। ऐसी आशा की गई थी कि नैतिक शिक्षा पर शीघ्र ही कुछ पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। इस पर कार्य पहले से ही आरंभ हो चुका है।

अध्यक्षा ने स्कूलों में सामान्य पाठ्यपुस्तकों की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और गणित जैसे विषयों में जिनकी अंतर्वस्तु सार्वभौमिक होती है, इससे सबके लिए एक ही पाठ्यपुस्तक तैयार करने का काम सरल हो जाता है, यहां तक कि इतिहास और नागरिक शास्त्र, भूगोल जैसे विषयों में भी 'केंद्रीय अंतर्वस्तु' जैसी चीज की बात सोची जा सकती है। जिनको बिना स्थानीयता का विचार किए ही सभी स्कूलों के लिए कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस प्रकार की केंद्रीय अंतर्वस्तु की एक मिसाल स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हो सकता है जिसे इस देश के सभी स्कूलों में अध्ययन के लिए अनिवार्य विषय बनाया जा सकता है। एक बार यदि इसे मुद्दे पर सहमति हो जाए तो यह संभव हो जाएगा कि हम एक ऐसा तरीका निकाल सकें जिसमें सबके लिए सामान्य पाठ्य सामग्री तैयार की जा सके।

अध्यक्षा ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न स्रोतों से जो सूचनाएँ उपलब्ध हैं, बच्चों से उनका साक्षात्कार होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने आगे कहा, बच्चों में पढ़ने के प्रति रूचि प्रोत्साहित की जानी चाहिए। स्वाध्याय कक्षा में सीखने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिषद् एक नवाचारी परियोजना आरंभ करने जा रही है इसका नाम है— 'सीखने के लिए पढ़ना'। इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं—बच्चों में पुस्तकों के प्रति अभिरूचि विकसित करना, उनको आत्मशिक्षण के लिए तैयार करना, तथा जो भी पाठ्य-सामग्री रोचक है उसे उनको उपलब्ध करना। निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सीधी देख-रेख में इस परियोजना की प्रणाली पर काम हो रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों के लिए रोचक पाठ्यसामग्री के विकास हेतु राज्य स्तर के अभिकरण बनाए जाएं।

सामान्य निकाय ने 1982-83 की परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप को मंजूरी दे दी जैसा कि कार्यकारिणी समिति ने उसके समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था।

विचार-विमर्श के दौरान सामान्य निकाय की बैठक में निम्नांकित सुझाव सम्मुख आए—

1. शिक्षा के क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी महत्वपूर्ण काम हुआ है वह अपने वास्तविक रूप में कक्षा तक नहीं पहुंचा है। इस उद्देश्य के लिए नई योजना तथा नए प्रकार के सहयोगी प्रयास के विषय में सोचने की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की मुख्य भूमिका होगी। इस उपमा को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कृषि विस्तार कार्य के अनुभव ने शोध के निष्कर्षों को शोध संस्थानों से किसानों के खेतों तक पहुंचाया है।

2. सभी सदस्यों का यह विचार था कि यूनिसेफ द्वारा दत्त सहायता से राज्यों को काफी लाभ हुआ है जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से हुआ था। इनको सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहना चाहिए। फिर भी यह सुझाया गया कि कई गुना प्रभाव के लिए इन परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जाना चाहिए और इनके लिए उचित ढंग से वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इसके विषय में सहायता कर सकती है। इस कार्य को एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना चाहिए, यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व था तथा अकेले भारत सरकार अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इसको अंजाम नहीं दे सकते थे।

4. दृष्टि विहीनों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा विकलांग बच्चों के लिए तैयार किए गए शिक्षा के कुछ पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस्तेमाल कर सकती थी। इस कार्यक्रम को विकलांग बच्चों की शिक्षा के समग्र कार्यक्रम को विकसित तथा क्रियान्वित करने के दौरान किया जा सकता था।

5. स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर के योगदान को पर्याप्त महत्त्व दिया जाना चाहिए, खास तौर पर उस समय जब हम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ा रहे हों। जो सामग्री क्षेत्रीय योगदान से संबंध रखती हो उसे पाठ्यपुस्तकों में तभी शामिल किया जाना चाहिए जब राष्ट्रीय स्तर पर उसको जाँचा परखा जा चुका हो।

